© भारत सरकार प्रथम सस्करण, वर्ष 1969

प्रस्तुत पुस्तक सर्व थी जार्ज एलिन और अनिवन लिमेटिड द्वारा प्रकाशित कैनेथ के॰ कुरीहारा की अग्रेजी पुंस्तक Keynsian Theory of Economic Development के सन् 1961 मे प्रकाशित संस्करण का हिन्दी अनुवाद है तथा इस पुस्तक का अनुवाद और पुनरीक्षण भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की मानक ग्रंथो की प्रकाशन योजना के असर्गत बैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के शतप्रतिशत अनुदान से हुआ है।

मृहय : इ॰ 4.10 पैसे Price : Rs. 4.10 Paise

प्रधान प्रकाशन अधिकारी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयीग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा राकेश प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

प्रस्तावना

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमें उच्चकोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक-से-अधिक संख्या में तैयार किए जाएँ। भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा है और उसने इसे वड़े पैमाने पर करने की योजना वनाई है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे हैं। यह काम अधिकतर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से प्रारंभ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं अपने अधीन भी करवा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनुदित और नए साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है तािक भारत की सभी शिक्षा-संस्थाओं में एक हो पारिभाषित शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

वार्थिक विकास का केन्सीय सिद्धान्त नामक पुस्तक हिंदी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके मूल लेखक कैनेथ के० कुरीहारा और अनुवादक श्री लाल मोहर राय हैं। आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन संबंधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायगा।

वाव राम सक्सेना

अध्यक्ष

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

नई दिल्ली मार्च, 1969

प्रावकथन

इस पुस्तक का उद्देश्य सामान्य रूप से आर्थिक विकास एवं विशेष रूप से अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास की तकनीकी सम्भावनाओं एवं सीमाओ का स्पष्टीकरण है। इस विचार-वस्तु को तीव बनाने के लिए, इस पुस्तक में आधोपात हमने स्वेच्छ्या अल्प-विकसित एव विकसित अर्थ-व्ययस्थाओं की विकास-मन्बन्धी विभिन्न समस्याओं का तुलनात्मक विवेचन किया है। प्रस्तुत सामाजिक एव सांस्कु-तिक परिस्थितियों में, परिचालन की दृष्टि से, आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण उप करणों की व्यादया करना हमारी प्रधान अभिक्षित रही है। तदनुसार, हमने उन माध्य परिवित्तयों के बीच के उन सम्बन्धों को चुना है, जिन पर प्रति-व्यक्ति वास्तविक आया की वृद्धि मुद्ध रूप से निभंद करती है और ऐसी मान्यताओं के आधार पर विश्लेषण के योग्य सरल और उपादेय परिणाम निकल सकता है। इसके लिए, विभिन्न अध्यायों को, जो यद्यपि अपने-आप में अपूर्ण हैं, इस रूप में नियोजित किया है कि यं सयुक्त रूप से एक सैद्धान्तिक समग्रता की स्थापना कर सके और अल्प-विकसित देशों के औद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम की पूरी योजना के निर्माण में सहायक हो सकें।

अभिस्वीकृति के तौर पर इस पुस्तक के शीपंक मे व्यक्त केन्सीय ढीने के उल्लेख के प्रति हम अपने पूर्व-स्नेह को कई आधार पर न्यायोचित ठहरा सकते हैं। प्रयमतः, और समसामियक रूप में यह पुस्तक आ० एफ० हैरोड तथा श्रीमती जीन रॉबिन्सन का, जिन्होंने, जैसा कि केन्स के पारगत शिष्यों से कोई भी आशा कर सकता है, केन्स के अल्पकालीन सिद्धान्त को दीर्धकालिक तथा गत्यात्मक बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अधिक ऋणी है। यह पुस्तक विशेष रूप से हैरोड के विकास-सम्बन्धी विश्लेषण के लिए मार्ग तैयार करने वाले उपकरणो तथा अल्प-विकसित देशों में कैन्सीय गत्यात्मकता के सम्मावित प्रयोगों के सम्बन्ध में श्रीमती जीन रॉबिन्सन के चुनौतीपूर्ण सुभाव के वगैर नहीं लिखी गयी होतो, * किन्तु जैसा कि पाठक

^{*} श्रीमती रॉविंग्सन का सुभाव इनके "मि॰ हैरोड्स डायनेमिक्स" इकानामिक जनरल (मार्च, 1949) मे पाया जाएगा। श्रीमती रॉबिंग्सन की नयी पुस्तक "दि एकुमुलेशन ऑफ कैपिटल" हमे प्राप्त होने के पूर्व इस पुस्तक का बड़ा भाग तैयार हो चुका था। फिर भी इनकी नयी पुस्तक के सम्बन्ध मे मेरी विलिम्बत

आगे चल कर देखेंगे, हमें इनकी रचनाओं में प्रयुक्त विश्लेषण के विशिष्ट उपकरणों से असहमित प्रकट करने में तिनक भी हिचिकिचाहर नहीं रही है। यद्यपि यह पुस्तक शी हैरोड तथा श्रीमती रॉबिन्सन की केन्सीयोत्तर भावना से लिखी गई है। तथापि इसके श्रीपंक में 'केन्सीयन्त्र' शब्द का प्रयोग इसे अन्य पुस्तकों से विशिष्ट बनाने के लिए किया गया है, जो स्पष्ट रूप से नव संस्थापकीय, "मार्बिसयन" या "शूम्पीटेरियन" है।

द्वितीयतः, अल्प-विकसित देशों ने आर्थिक विकास के प्रति केन्स के तकनीकी, बहुराष्ट्रीय निर्देलीय रुख द्वारा प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त उसकी दूर दिष्ट के प्रति यह रचना अपनी प्रारम्भिक अवधारणा तथा आधारभृत प्रेरणा के लिए आभारनत है। यह एक अपूर्व दूरद्दि है, जो पुनर्निर्माण तथा विकास के निर्मित अन्तर्राब्दीय वैंक के सामान्य सिद्धान्तों में, जिनका केन्स वौद्धिक शिल्पी माना जाता था, स्यायी रूप से समाविष्ट है। तृतीयतः, फलम्लक विश्लेषण और नीति के लक्ष्य के रूप में आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता जान पड़ती है, जो "केन्सीय सिकयाबाद" के अनुरूप हो, जिसे ए० सी० पीगू ने एक ऐसे आदर्श-निर्माण की संज्ञा दी है, जो पूर्वानुमानों की सहायता एवं नीति-सम्बन्धी मार्ग-निर्देशन के लिए सांख्य-कीय माप के हेतु ग्रहणशील तथ्यों के साथ निकटता रखता। चतुर्थतः, केन्स के नाम से सम्बद्ध राष्ट्रीय आय-विश्लेपण और राष्ट्रीय आर्थिक राजकीशल (statesman ship) ने परम्पराओं से बहुत अधिक अपसरण के बग़ैर अस्थायी समर्थ मांग की समस्या को मख्यतः समाधान योग्य बना दिया है। इससे प्रत्येक मिश्रित राजकीय-सह-निजी अर्थ-व्यवस्था अव विश्वासपूर्वक तकनीकी सीमाओं के अन्तर्गत, किन्तु अस्यापित्व के द्वारा विस्थिति होने की अनिवार्यता के भय के वग़ैर प्रगति के लक्ष्य की दर को प्राप्त करने तथा उसे स्थिर वनाये रखने की दीर्घकालीन समस्या का समाधान निकाल सकती है।

अन्ततः, सामान्य सिद्धान्त (जेनरल थियरी) के अन्तिम अध्याय में वर्णित केन्स का सामाजिक दर्शन आर्थिक विकास के उस प्रतिफल, जो मानव मूल्यों के प्रति चेतनता से ओत-प्रोत, द्रुतगित से औद्योगिक विकास के लिए अत्यिधक उत्साह पर सुदृढ़ रूप से आधृत है, के मार्ग दर्शन के हेतु अपरिहार्य प्रकाश-गृह के रूप में जान पड़ता है। यह रूप एक ऐसे विश्वव्यापी आर्थिक विकास का प्रतिरूप है, जिसे केन्स ने हितीय यद्ध के वाद स्थापित होने वाले राष्ट्रों के नये प्रजातन्त्र के लिए सीचा था।

कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी स्वयं हमारे चिन्तन को यदि प्रभावित नहीं

प्रतिकिया इस पुस्तक के चौथे अध्याय में प्राप्त होगी। हैरोड की सुप्रसिद्ध पुस्तक "टूवार्ड्स ए डायन्नेमिक इकॉनोमिक्स" के सम्बन्ध में चर्चा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

किया है, तो उत्तेजित अवश्य किया है, जैसा कि पाठक इस पुस्तक के आरम्भिक अध्याय मे वर्णित पूर्वीधिकारियो तथा अन्त मे दी गई सन्दर्भ-प्रन्य-सूची से अनुमान लगा सकते है। फिर भी, हम कुछ ब्यक्तियों के प्रति, जो केन्स के विचारों के विस्तार तथा उनके अगल में लाए जाने के हाल के हमारे प्रयास में व्यक्तिग्त रूप से सहायक रहे है, विशेष तौर से सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। हम कोलम्बिया-विश्वविद्या-लय के प्रोफेसर विलियम भाइकरे की तकनीकी ब्योरे पर सतर्क एव उपयोगी आलो-चनाओं के लिए पूर्ववत् बहुत अधिक ऋणी है। रजर-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बोडस माइकेल ने अनेग्जेन्डर हैमिस्टन के नेत्रव मे अमेरिका के प्रारम्भिक विकास की शिक्षा-प्रद गाथाओं द्वारा हमारी क्लपना की प्रज्वलित किया है। जबकि प्रोफे-सर रावट अनेगुजेन्डर ने सिद्धान्तों के सभी स्तरों पर लैटिन अमेरिका की विकासो-न्मख अर्थ-व्यवस्या के आनुभविक आंकडे हमारे लिए प्रस्तुत किये हैं। इओआ स्टेट कॉलेज के प्रोफेमर गरहाड़ टिटनर ने बहत सारी तकनीकी बातो की आलोचना स मुक्ते लाभान्वित किया है। कोयटा विश्वविद्यालय के आर्थिक विकास-अनुसधान-केन्द्र तथा ओसाना विश्वविद्यालय के सामाजिक एवं आधिक अनुसन्धान संस्थान के क्रमशः प्रो० हिडाओ ओया तथा सिन्ची इचीमुरा ने जापान की औद्योगिक प्रगति के अपने आत्मीय ज्ञान के आधार पर हमे बहुमूल्य सुभाव दिया है। सदा की तरह, ग्रिनेल कॉलेज के प्रेसिडेक्ट हावर्ड बोवेन ने मुर्फ उचित प्रोत्साहन प्रदान किया है। मेरी पत्नी, 'के' ने उस प्रकार की सहायता एवं सहानुभृति दी है, जिसकी आवश्यकता हर-एक लेखक को गम्भीर रचनाओं के विक्षुब्ध क्या में बहुत अधिक होती है।

इन सभी मित्रो एवं सहयोगियों के हम बहुत अनुगृहीत हैं, किन्तु फिर भी, पाठकों द्वारा इस पुस्तक में पाये जाने वाले किसी भी अवगुण के लिए इनमें से किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अपने लेखों को समग्र अथवा आधिक रूप में पुनः उद्धृत करने की अनुमित के लिए निम्निलिखित पित्रकाओं के सम्पादकों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहने है: 'दि इंडियन जनरल ऑक इकॉनामिक्स,' 'दि इंडियन इकॉनामिक जनरल,' 'दि मेट्टोकोनामिका,' 'दि फाइना-सेन पिल्लिस' (नीदरलँड्स), 'दि इकॉनामिक स्टडीज क्वाटंलीं' (जापान) तथा 'दि इकॉनामिक बोकली' (भारत) ।

विषय-सूची

प्राप्कथन		पृष्ठ
1. संस्थापक एवं संस्थापकोत्तर पूर्वाधिकारी	•••	1
संस्थापक अन्तर्दं िट एवं अग्रद्धि	*.* *	1
संस्थापकोत्तर सिद्धान्त	***	6
2. अस्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की संरचना	•••	14
अस्प-आर्थिक विकास के सूचक		14
विकास के संरचनात्मक निर्धारक तत्त्व	•••	22
3. विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम गति		29
जनसंख्या की वृद्धि एवं जीवन-मान	***	29
अपेक्षित पूँजी-संचय	•••	38
4. पूँजी-संचय एवं उत्पादन-सामर्थ्य	•••	42
क्षमता-निर्माण की प्रक्रिया		42
हैरोड-डोमर मॉडल पर टिप्पणी	***	49
रॉविन्सन मॉडल पर टिप्पणी	***	60
5. आर्थिक-विकास में टेक्नोलॉजिकल भूमिका	144	68
श्रम की उत्पादकता पर टेक्नोलॉजी-सम्बंधी प्रभाव	•••	69
श्रम बचाने एवं श्रम का प्रयोग करने वाले तकनीकों पर प्रभाव	•••	74
क्षमता-वृद्धि पर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रभाव		76
 अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में दुहरी वेरोजगारी 	•••	87
केन्सीय वेरोजगारी की चक्रीय वृद्धि	•••	89
ग़ैर-केन्सीय वेरोजगारी की दीर्घकालिक वृद्धि		95
छिपी हुई बेरोजगारी पर अनुलेख	•••	104
7. आर्थिक विकास में पुनर्वितरणात्मक भूमिका	•••	108
आय का पनवितरण एवं बचत-अनुपात	***	110

 आधिक विकास में मौद्रिक भूमिका 	•••	121
साख, ब्याज एव विकास	***	122
स्फीति एव विकास	•••	130
9. आर्थिक विकास में विसीय मूमिका	•••	141
अधिकतम विकास के लिए वित्तीय कियाएँ	***	141
स्थायी विकास के लिए वित्तीय कियाएँ	***	150
10. विदेशी स्थापार एवं आधिक विकास	***	158
विदेशी व्यापार एवं माँग में वृद्धि	•••	159
सन्तुलित विकास के लिए प्राचलीय कियाएँ	***	164
11. केन्सीयोत्तर विकास-सिद्धान्तो पर उपसंहार	••	175
राज्य के विकासात्मक कार्य	•••	175
सन्तुमन विकास की प्रकृति एवं यत्र	***	179
परिशिष्ट-सयुक्त राष्ट्र एव आधिक विकास	•••	186

अध्याय 1

संस्थापक एवं संस्थापकोत्तर पूर्वाधिकारी

अर्थशास्त्र के सिद्धान्त की अन्य शाखाओं की तरह आर्थिक विकास के आधुनिक सिद्धान्त का भी अपना एक अनन्य इतिहास है, जो एक साथ ही वर्तमान
विकास के सिद्धान्त-निर्माण का अनुदर्शी तथा अति यथार्थवादो आदर्श-निर्माण का
अग्रदर्शी है। इस क्षेत्र-विशेष में आर्थिक विचारधारा के आत्मिनिष्ठ इतिहास से
विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक विकास के वस्तु-निष्ठ इतिहास का एक समीचीन
एवं समानपूर्ण नैकट्य है। अपेक्षाकृत एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इस
प्रारम्भिक अध्याय में ऐतिहासिक दृष्टि से विषमजातीय, किन्तु मूलतः समजातीय
मानव-समुदायों के आर्थिक विकास की प्रकृति एवं कारणों के सम्बन्ध में संस्थापक
एवं संस्थापकोत्तर विचारधाराओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। आर्थिक विकास के
विधिष्ट क्षेत्र में समकालीन विचारधारा एवं कार्यक्रम-निर्धारण पर संस्थापक एवं
संस्थापकोत्तर प्रभावों को इंगित करने के लिए पूर्वाधिकारियों का निम्नविवृत रूप में
चुनाव किया गया है।

संस्थापक अंतर्दृ ष्टि एवं अग्रदृष्टि

आदम स्मिथ (1723-1790)

यह केवल संयोग की वात नहीं है कि आदम स्मिथ, जो न केवल ग्रेट-ब्रिटेन जैसे पहले से ही सर्वाधिक उन्तत औद्योगिक राष्ट्र में संस्थापक-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक थे, अपितु आर्थिक प्रगति की सामान्य प्रकृति एवं पूँजीवादी विकास के विशिष्ट कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। इनमें पहले की सामान्यता दूसरे की विशिष्टता से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समसामयिक विकासवादी सिद्धान्त के प्रतिपादक आर्थिक प्रगति के सैद्धांतिक लक्ष्यार्थों का स्वागत या तिरस्कार करने की अपेक्षा, इसकी प्राविधिक शर्तों की परिपूर्ति में अधिक रुचि रखते हैं। इस सम्बन्ध में आदम स्मिथ की प्रधान चुटि यह थी कि वे सब समयों तथा स्थानों के लिए संगत स्थायी तत्वों तथा उन तत्वों के वीच, जो सीमित 'वैयक्तिक पूँजीवाद' पर लागू हो सकते हैं, स्पष्टरूप से विभेद नहीं कर सके।

अतएव, उनकी अवंध-नीति, अधिकतम प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार, वैयक्तिक तथा सार्वजनिक हितों में सामजस्य लाने वाला उपक्रमी तथा वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय सद्गुण के रूप में मितव्ययिता, आधुनिक सैंद्धांतिकों के लिए विशुद्ध पूँजीवाद के मार्ग पर आधिक विकास के उचित निर्देश-सयंत्र के रूप में वार्य करती है। फिर भी आदम स्मिथ के 'वेल्थ आफ नेशन्स' को किसी प्रकार की आधिक व्यवस्था में सम्बद्ध किये वगैर समसामयिक समाजों के आधिक विकास के लिए अनुपयुक्त बतलाना भूल होगी। क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रथ में इस सामान्य प्रस्ताव की भी चर्चा की गई है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में अभिवृद्धि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है

(क) प्राविधिक श्रम-विभाजन से आवद्ध श्रम की उत्पादन-क्षमता, तथा (ख) सास्थानिक तौर पर निर्धारित मित्रव्यय से आवद्ध पूंजी-सचय। इस प्रस्ताव की व्यापक मान्यता को बोर्ड चुनौती नहीं दे सकता। फिर भी राष्ट्रीय सम्पत्ति की स्वचालित एव अवाध वृद्धि को अनुक्रमवद्ध करने वाली तकनीकी प्रपत्ति और पूंजी-सचय जिस अदृश्य प्रवित हारा सुनिष्चित होता है, उम पर आदम स्मिथ की निर्भरता के सम्बन्ध में अधिकाश व्यक्ति सदेह व्यक्त कर सकते है। आदम स्मिथ का यह प्रस्ताव केन्स के इस अनुदर्शन की प्रत्याशा है कि पूर्व-पूंजीवादी युग में प्रपत्ति की दर की धीमी गति इन दो अवरोधक कारणों का परिणाम थी: (क) प्रमुख प्राविधिक उन्तित नी अनुपस्थिति तथा (ख) पूंजी-सचय का अभाव। इम प्रकार आदम-स्मिथ को राष्ट्रों के औद्योगीकरण में पूंजी की मात्रा एवं गुण के निर्णायक महत्व पर पुरोगामी जोर देने का श्रेय दिया जा सकता है। थाँमस राबर्ट माल्थस (1760-1835)

आदम हिमय की तरह, किन्तु डेविड रिकाडों (जिनका सम्बन्ध मुख्यतः एक दी हुई निपज के वितरण मे था) के प्रतिकृत, केम्बिज के अर्थशास्त्रियों मे अप्रगण्य रावर्ट माल्यस वा ध्यान निपज के परिमाण एव सम्पत्ति मे वृद्धि के तात्कालिक कारणों की ओर पहले से ही स्थिर हो चुका था। फिर भी अनियमित गति (आधुनिक भाषा मे चकीय विकास) से सम्बद्ध आर्थिक विकास की प्राविधिक मम्भावना के अव-सोकन मे माल्यस का स्मिथ मे मतभेद था। मतभेद इस बात पर था कि अब और कहाँ बचत के सचय, जिस पर आर्थिक प्रगति मुख्य रूप से निभर करती है, को इतनी तीव गित से बढ़िया जाम, जिससे कि उपभोष्य माग मे कभी हो जाय और उत्पादन-सम्बन्धी मामान्य प्रेरणा क्षीण हो जाय। सक्षेप मे बैसे समाज, जिसकी समर्थ माग का आचरण 'से' के बाजार नियम के अनुकृत नही होता, सम्पत्ति के अस्थिर एवं अशात वृद्धि के सम्बन्ध मे माल्यस का ऐसा ही विचार है। यह विचार माल्यस को पुस्तक 'प्रिंसिपुस्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनामी' में ब्यक्त किया गया है। सामान्यत इस विचार की जानकारी मुख्य रूप से केन्स के प्रयत्नी में हो हो पाई।

 ⁽क) देखे जे० एम० केन्स, एसेज इन परसुएशन, रूपर्ट हार्ट डेविस, लंदन, 1952
 पू० 360 ।

⁽प) देखे, 'एसेज इन बायप्रफी' केन्स द्वारा वर्णित माल्यस की आकर्षक एव प्रभाव-णाली जीवनी, होराइजन प्रेम, न्यूयाकं, 1951 पू० स० 81-124।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के दिष्टकोण से माल्यस की एक अधिक आकर्षक अन्य रचना 'ऐन एसे ओन दि प्रिन्सिपुल्स ऑफ पाप्लेशन एज इट एफेक्टस दि पयुचर इम्प्रवमेन्ट आफ सोसाइटी' है। इस पुस्तक में माल्यस ने अत्यन्त आक्वर्य-चिकत कर देने वाला यह विचार प्रस्तुत किया कि वैसी परिस्थितियों में, जहाँ जन-संख्या की वृद्धि अनियंत्रित तथा पूँजी का संचय अवंध नीति से होता है, वहाँ पूँजी अथवा जीवन-निर्वाह के साधनों को अपेक्षा जनसंख्या में अधिक दर से वृद्धि होती है। यहाँ माल्यस का विचार मानर्स के 'औद्योगिक आरक्षित सेना' के सिद्धान्त (संरचनारमक अपूर्ण रोजगारी) का पूर्वानमान है; क्योंकि मार्क्स का यह विचार विना किसी तात्पर्य का नहीं है। वस्तुत:, जैसा कि केन्स ने वतलाया है, यह विचार माल्यस के इस निजी सिद्धान्त से निकटतम साद्य्य रखता है, जिसके अनुसार प्रजीवादी समाज में समर्थ माँग निपज का साथ देने में असफल हो सकती है। फिर भी, मार्स के ठीक विपरीत मात्थम का यह विचार था कि निवंध-नीति पर आधृत पूँजी निर्माण की व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय जन्म-दर का युक्तिपूर्ण नियंत्रण जनाधिक्य की तथाकथित समस्या का उचित निदान है। केन्स के अनुसार माल्यस पहला अर्थशास्त्री था, जिसने, दीर्घकालीन आर्थिक विश्लेपण के लिए इस वात को (केन्स की भाषा में) 'जोरदार महत्त्व' दिया था कि प्रदत्त आधार के बदले जनसंख्या के गत्यात्मक प्रतिपादन को एक परिवर्तनशील आधार माना जाय। इस प्रकार का प्रतिपादन जनाधिक्य से पीडित अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है।

फ्रेंडरिक लिस्ट (1789-1846)

अपने समय की औद्योगिक दृष्टि से अविकसित जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हुए, फ्रेडिरिक लिस्ट सामान्य रूप से आर्थिक राष्ट्रीयता तथा विशिष्ट रूप से संरक्षण-वाद के आधार पर औद्योगीकरण का प्रधान समर्थक वन गया। आज भी उसके आर्थिक-विकास के सिद्धान्त को आधुनिक अल्पृतिकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों, जो राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के प्रभुत्व में हैं, का प्रवल समर्थन प्राप्त है।

अपनी पुस्तक 'दास नेशनल सिस्टम दर पोलिटिश्चेन ओकानामी' (Das National System der politischen Okonomie) में लिस्ट ने आधिक विकास के सिद्धान्त में एक नये तत्व का समावेश किया। उसने देशी शिशु-उद्योगों के विकास को विशिष्ट रूप से प्रोत्साहन देने के लिए तव तक संरक्षणात्मक 'टेरिफ' प्रदान करने

^{1.} केन्स, वहीं, 107-108।

आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं पर लिस्ट के प्रभाव के लिए देखें 'नाइचेल्स डें विडा बाई देसारोलो इकानोमिको' (आर्थिक विकास पर एक परिसंवाद) मेक्सिको-विश्वविद्यालय के नेशनल स्कूल आफ इकानॉमिक्स में 1953 ।

की भीति को सँढातिक औचित्य प्रदान किया, जब तक कि ये तुलनात्मक लाभ के आधार पर विदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना न कर मर्थे। तिस्ट के सरक्षणवाद के आधार पर औद्योगीकरण के सिद्धान्त ने, उसके बौद्धिक शिशु, हेनती सी० केरे े के माध्यम से अमेरिया के निर्माणकारी उद्योगों के आधित विवास में प्रोगामी महस्य का वार्य किया।

यद्यपि तिस्ट ने संरक्षित उद्योगों के आरमपानी सीमात उद्योग वनने के सतरे के विरुद्ध कोई मुद्द सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, फिर भी उसने सेये राष्ट्रों के आधिक विकास में निर्णायक प्रेरणात्मक शक्ति के रूप में राष्ट्रीयता के तन्य की और ध्यान आकृष्ट किया। यह एक ऐसा तत्व है, जिसकी अवहेलना आदम-स्मिष तथा मुरुक व्यापार के अन्य समर्थकों ने की थी और जिन्होंने विश्व व्यापी पूर्ण रोज-गारी और पूर्ण विकास के अस्तित्व को मौन रूप में स्थीकार कर लिया था। अपूर्ण विकास एवं मुश्क व्यापार की असगतता-सम्बन्धी अपनी मौनिक अन्तर्द्रांटि के कारण लिस्ट का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थणाम्य के इतिहास में उसी प्रकार अन्य स्वान है, जिस प्रकार अपूर्ण रोजगार एव मुश्क व्यापार की असगतना की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के कारण केन्स का। सरक्षण की विशेष कार्यान्वित सम्बन्धी प्राविधिक श्रुटियों को बढ़ा-चढ़ाकर उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए, जहाँ लिस्ट का व्यापक योगदान ही गुम हो जाय।

कार्ल मार्क्स (1818-1893)

आर्थिक विकास के मिद्धान्त के क्षेत्र मे मावसं की ये तीन महत्वपूर्ण देत हैं; यथा व्यापन रूप में इतिहास की आर्थिक व्याट्या प्रस्तुत करना, अपेक्षाकृत सकुचित रूप में पूँजीवादी विकास की प्रेरणात्मक शक्तियों की व्याट्या करना तथा आयोजित विकास-रूपी एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करना। जैसा कि एक लेखक वा कहना है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के हेतु अंकजित सिद्धान्त के प्रतिपादन-सम्बन्धी कार्ज मार्क्स के प्रयास की महत्त्वाकाक्षा उन सभी वस्तुओं से बढी-चढी थी, जिनके लिए सस्थापक अर्थशास्त्रियों ने उद्योग किया था।

अपनी पुस्तक 'क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल इकॉनामी' के प्राक्कथन में मार्क्स ने ऐतिहासिक विकास के भौतिक अवधारण को रूप-रेखा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार

मेरे सहयोगी प्रो॰ ब्रोदस माईकेल ने मुक्ते यह सूचना दी कि लिस्ट हेनरी केरे के पिता मैथु केरे के घनिष्ठ मित्र थे । मैथु करे ने संरचनात्मक 'टैरिफ' के द्वारा अमेरिका के औद्योगीकरण में लिस्ट, जो उस ममय अमेरिका आये थे, का बौदिक समर्थन प्राप्त किया ।

² देले, टी० हैबलेमो का 'ए स्टडी इन दि थियरी आफ इकानामिक इनोल्युशन', नाथं हालैंड पब्लिशिंग कम्पनी, अमस्टरडम, 1954, पू० 12 ।

आधिक सस्थाएँ सामाजिक विकास का परिणाम होते हुए भी स्वयं सामाजिक विकास की गति को प्रभावित करने में सक्षम हैं। शायद इसी विचारघारा से शुम्पीटर को आधिक विश्लेपण के लिए ऐतिहासिक घटनाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के वहिजनित समिष्ट की जगह अंतर्जानत परिवर्त्तनों के रूप में व्याख्या की प्रेरणा मिली थी। सामान्यत: यही दृष्टिकोण व्यापक रूप से समकालीन रचनाओं के अंतर-अनुशासनीय उपागमों में पाया जाता है। अपनी प्रमुख कृति 'कैपिटल' में मार्क्स ने इस वात की व्याख्या की है कि पूँजीवादी विकास की विश्वुच्य प्रक्रिया इन तत्त्वों पर निर्भर करती है: (क) मजदूरों के उपभोग के व्यय पर मुनाफाखोरों की वचतें, (ख) मुनाफ के लिए प्रतियोगिता से प्रेरित, किन्तु अपूर्ण उपभोग तथा अत्यधिक विनियोग के परिणामस्वस्प विनियोग की सुविधाओं में हास से अवरोधित नयी पूँजी में उस वचत का विनियोग तथा (ग) श्रमिकों की समाजकास्त्रीय आधार पर निर्धारित संख्या एवं प्रविधि द्वारा निर्धारित उत्पादकता। पूँजीवादी विकास का यह मार्क्सवादी सिद्धान्त कई आधुनिक दीर्घकालीन सिद्धान्तों का पूर्वानुमान करता है, जैसे केन्स एवं हेन्सन के स्थिरता के सिद्धान्त हो अपर एवं हैरोड का गरयात्मक सिद्धान्त , शुम्पीटर केलेकी,

मानसं के रीति-विधान की व्याख्या को शुम्पीटर द्वारा मौन रूप से मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में देखें— 'कैपिटलिज्म, सोसलिज्म एंड डेमोकेसी, हारपर ऐंड ग्रदर्स न्यूयार्क, 1942 तथा 'टेन ग्रेट इकनामिस्ट्सः फ्राम मार्क्स टू केन्स' आक्सफोर्ड, न्यूयार्क, 1954 ।

जैसा कि हम शिकागो-विश्वविद्यालय के "इकानामिक डेवलपमेंट ऐंड कलचरल चेन्जेज' के पृथ्ठों में पाते हैं।

अध्युनिक मार्क्सवादी व्याख्या के लिए देखें पी० स्वीजी का 'दि थियरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट', ऑक्सफोर्ड, व्यूयार्क, 1944 ।

^{4.} देखें जे० एम० केन्स का 'सम इकातामिक कन्सीवयुनेशेज ऑफ ए डिक्लाइनिंग पापुलेशन इपूगेनिक्स रिब्यू', अप्रैल, 1937, ए० एच० हैन्सन का इकानामिक प्रोग्रेस एंड डिक्लाइनिंग पोपुलेशन ग्रोथ, 'अमेरिकन इकानामिक रिब्यु' मार्च, 1939।

^{5.} देखें आर० एफ० हैरोड का 'ट्याड्स ए डाइनिमिक इकानामिक्स' मैकमिलन, लंदन, 1948, इ० डी० डोमर 'इक्सेपैन्यन एंड इम्पलायमेंट', अमेरिकन इकाना-मिक रिव्यू मार्च, 1947।

कालडोर एवं गोडवीन का चक्रीय विकास का सिद्धान्त¹, तथा श्रीमती जॉन रोविन्सन का सेरचनात्मक अपूर्ण रोजगार का सिद्धांत²।

किन्तु आश्चर्यं की वात है कि आयोजित विकास के सम्बन्ध में मादर्स द्वारा उसकी गौण रचनाओं में ब्यक्त किये गए विचारों के विकास का प्रभाव ही सोवियत हस सथा चीन की मुख्य भूमि जैसे देशों के वास्तविक आर्थिक विकास पर अत्यधिक पड़ा है। आयोजित विकास के मम्बन्ध में मान्से के विचार उन पिछड़े देशों को भी अधिक जँचने है, जो अत्यधिक राष्ट्रीय प्रयास तथा विकसित राष्ट्रों से अनावश्यक विलगाव के जोखिम पर तीन्न गति से औद्योगीकरण चाहते हैं। अय यह देखना है कि भावी पीडी अपेक्षाकृत किस भावना से कमोवेश सबकं ग्रहण करनी है—मार्क्स की उस भावना से, जिसके अनुसार आयोजित विकास के हेतु उत्पादन के साधनों पर राजकीय स्वामित्व को एक इतिहास-प्रसिद्ध अनिवार्य कर्त माना आता है अथवा केन्स की उम भावना से, जिसके अनुसार इन साधनों पर राजकीय नियन्नण को आर्थिक दृष्टि से वाछित माना जाता है।

सस्थापकोत्तर सिद्धान्त

जॉन मेनार्ड केन्स (I883--1946)

जो केन्स का नाम केवल अल्पकाल के समर्थन में उसके इस प्रमुख कथन कि 'दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं' से याद करते है, उन्हें दीर्घकाल के सम्बन्ध

गें ए० शुम्पीटर, ब्युजिनेस साइकित्स, मैग्रयू-हिल न्यूयार्क 1938, एम० कैले की, 'थियरी ऑफ इकानामिक जायनिष्यस' राइनहार्ट, न्यूयार्क 1951 (विशेषत: छठा खड), एन० कैलडोर 'दि रिलेशन ऑफ इकानामिक ग्रोथ एड साइकिलक्स फलकचुएमन' इकानामिक जरनल, मार्च, 1954, आर० ए० गोडदिन, 'ए मोडल आफ साइकिलक्ल ग्रोथ, 'दि ब्यूखिनेस साइकिल इन दि पोस्ट-घार बस्डं' इ० लदवर्ग द्वारा सपादित, मैकमिलन लदन, 1955।

² देखें इनके केल्कुलेटेड इकानामिक पेपर्स, केली, न्यूयार्क 1951 में 'मानसं एड केन्स' लया इनका 'एन एसे इन माक्सियन इकानामिक्स' लदन 1942।

देखे, एम० बोनफ्रेबनर का 'इकॉनामिक डेवलटमेट एंड कल्चरल चेन्ज्ञ, लदन, 1942 'दि अपील ऑफ कनिक्मकेशन इन इकानामिक डेवलटमेट'।

⁴ मानसं के इन परिकल्पित विचारो तथा उसके निश्चित आर्थिक सिद्धान्तों के साराण के लिए देखे ए० रोल का 'ए हिस्ट्रो ऑफ इकानामिक थॉट' (तृतीय संस्करण) का छठा अध्याय पेरनटिश हाल, न्यूयाकं, 1956।

इनके स्वामित्व की तुलना मे नियत्रण की अभिकृति के कारणों के लिए 'जनरल थियरी' की पृष्ठ-संख्या 378-81 देखें।

उसकी देन को जानकर थोड़ा-वहुत आश्चर्य हो सकता है। निश्चय ही, केन्स की सर्वाधिक प्रमुख सैद्धांतिक देन अल्पकालीन आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में ही है। किन्तु जैसा कि उसकी विभिन्त रचनाओं के पाठक जानते हैं, उसका 'अल्पकाल' भी इतना छोटा नहीं था कि उसे 'दीर्घकाल' में जाने के लिए किसी विशेष प्रकास की आनश्यकता पड़ती। साथ ही, केन्स की अंतर्वृष्टि एवं सिद्धान्त अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से, विशेषतः उनसे, जो सत्तावादी प्रणाली की जगह गणतंत्रवादी प्रणाली से अपना विकास करना चाहती हैं, सामान्यतः माने जाने की अपेक्षा अधिक सम्बद्ध हैं। 1 अतः, आर्थिक विकास के सिद्धान्त के सम्बन्ध में केन्स की क्या देन है ? इसका कम-से-कम निम्नलिखित उत्तर है:

केन्स की व्यापक अंतर्वृं िटयों से हम प्रारम्भ करें। अपने 'इकानामिक पोसि-विलिटिज ऑफ आवर ग्रेंड चिल्ड्रेन' (1930) शीर्पक लेख में केन्स ने यह सुभाव दिया था कि भविष्य में आर्थिक गित की प्रगति निम्निलिखित वातों पर निर्भर करेगी: (क) जनसंख्या को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति, (ख) युद्ध एवं नागरिक मतभेदों को दूर करने का हमारा निश्चय, (ग) विज्ञान से सम्बद्ध सभी वातों को विज्ञान के जिम्मे सुपूर्व करने की हमारी इच्छा, तथा (घ) हमारे उत्पादन एवं उप-भोग के बीच की सीमा के द्वारा निर्धारित संचय की गित। इसमें हम आर्थिक प्रगति की मीलिक शतों की व्यापक रूप-रेखा पाते हैं, जिसमें एक ओर संस्थापक विचारों के पांडित्य तथा दूसरी ओर समसामयिक लेखकों के जटिल विकास-प्रतिमानों का पूरा-पूरा समावेण है। ऐसी व्यापक अंतः प्रज्ञा अंतर्वृं िट को कियात्मक महत्व देने के कार्य का भार केन्सोत्तर अर्थशास्त्रियों के लिए छोड़ दिया गया। किन्तु जैसा कि हम शोझ ही देखेंगे, स्वयं केन्स ने आर्थिक प्रगति की निर्धारित दर से सम्बद्ध मापनीय एवं परीक्षणीय प्राक्कत्पना की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ किया था।

केन्स ने पूँजीवादी विकास का कोई कमबद्ध विश्लेपण नहीं किया, किन्तु अपनी पुस्तक 'जेनरल थियरी' में कई छिट-फुट तथा विषयांतरिक टिप्पणी की, जिनकी तुलना मानसं के पूर्ववर्णित विचारों एवं शुम्पीटर के अनुवर्णित सिद्धान्तों से करना बहुत ही रोचक होगा। पूँजीवाद के भविष्य की संभावनाओं के सम्बन्ध में यदि मानसं मंदी का भविष्यवन्ता था, तो केन्स को तेजी का भविष्यवन्ता कहा जा सकता है।

^{1.} अर्ड-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं पर केन्स के सुस्पष्ट प्रभावों की व्याख्या के लिए देखें, जयपुर के दिसम्बर, 1953 ई० के इण्डियन इकानामिक एसोसिएमन का 'केन्सीनियन इकानामिक्स इन रिलेशन टू अंडरडेवलपड कौन्ट्रीज'। साथ ही, केन्स की 10वीं वरसी के उपलक्ष में प्रकाशित जुलाई 1956 ई० का 'इण्डियन जरमल ऑफ इकानामिक्स' भी देखें।

देखें इनका 'इसेंज इन परसुएशन' पृष्ठ 373 ।

क्योंकि केन्स ने पंजीवादी व्यवस्था को तत्त्वतः एक ऐसी व्यवस्था माना है, जिसमे ऐसे सुधार किये जा सकते है, ऐसी तरककी लाई जा सकती है, जिससे यह मानव-प्रगति के आर्थिक आनन्द के उस गतब्य स्थान की ओर जाने में बाधक न होकर सहा-यक हो सके, जहाँ धन का सचय कोई विशेष सामाजिक महत्व नहीं रखता तथा आध्यात्मिक एव क्लात्मक उन्नति-सम्बन्धी प्रयत्न निर्विरोध गति पा सकता है । इसके ठीक विपरीत मानसं (और शम्पीटर भी) पंजीवाद को सारभत रूप मे एक ऐसी रचना मानता है, जो अनमानत आत्मनाश का बीज रखता हुआ क्षय ग्रस्त होने के लिए और अपने अस्तित्व से रहित होने के लिए वृद्धिशील होता है। फिर भी, कैन्स के 'स्थिरता के सिद्धान्त' ने मावसं के 'विघटन के सिद्धान्त', प्रतिवल-प्राप्त चिरकालिक अपूर्ण उपभोग, अति उत्पादन, मुनाफे की घटती हुई दीर्घकालिक दर जैसे अतर्जातत तत्त्वो को आधुनिक अभिव्यक्ति दी। किन्तु, इनमें प्रधान व्यावहारिक सतर यह है कि केन्स ने आयोजिन राजकीय त्रिया द्वारा अवैधनीतिक पूँजीवाद के समोधन मे इसके निदान की खोज की, जविक मानमें ने यह कहकर कि इससे अनिवार्यत: एव निरपवाद रूप से सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के बदल केवल पूँजीवादी वर्ग को ही लाभ होता है, किसी अथवा सभी प्रकार की राजकीय कियाओं को दृढता के साथ अस्वीकार किया ।

केन्स के अपेक्षाकृत अधिक प्राविधिक पक्ष की ओर ध्यान देने पर हम प्रथमतः एव सर्वोपिर समर्थ माँग के सिद्धान्त को पाते हैं, जिसके वगैर हैरोड के सिद्धान्त का उद्भव सम्भव ही नही था। वयोकि स्तर के रूप में यह केन्स के यचत-विनियोग सतुलन की स्थैतिक दशा से, जैसा कि हिक्स ने वतलाया, अनुपात के रूप में हैरोड के वचत-विनियोग सतुलन की गत्यात्मक दशा और फलत', जैसा कि अगले अध्यायों में व्याख्या की जायगी, हैरोड के 'वाछित विकास-दर' तक जाने की ओर पहला तकंसगत कदम है। हैरोड का मूल गत्यात्मक लेख दोनो कारणों से ध्याना-कर्पक है, प्रथमतः तो हेरोड को इतनी अधिक कल्पना एव पूर्व दृष्टि प्राप्त थी कि ऐसे समय में, जबिक सभी समसामयिक लेखक अल्पकालीन विचारों में ही तल्लीन थे, वह अपना ध्यान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन विचारों की ओर लगा सका। डितीय 'इकानामिक जनरल' के सपादक के रूप में केन्स ने स्पट्तिया उदारतापूर्वक एवं यौद्धिक

तुलना कीजिए, 'पोस्ट-केन्सीयन इकानामिक्स' (के० कुरोहारा द्वारा संपादित), रजर-विश्वविद्यालय प्रेस एव एलेन एंड अनिवन, 1954 में प्रकाशित, एस० सुरु (S Jsuru) का लेख 'केन्स वरसेज मावसं'. वि मेथोडोलोजी ऑफ एप्रीगेट्स'।

^{2.} देखें, ई, 1949 ई॰ के इकानामिका में प्रकाणित इनका 'मि॰ हैरोड्स डायनिमक थियरी'।

देखे, मार्च, 1939 के इकानामिक जरतल भे इतका निवंध 'एन एसे इन डायन-मिक थियरी' ।

क्षमता का परिचय देते हुए अपने शिष्य के लेख को प्रकाशित कर दिया, जिसमें वचत की माँग के ह्रासमान पहलू, जिस पर केन्स स्वयं जोर देते थे, के विरुद्ध क्षमताकारक पहलुओं पर जोर दिया गया था। हैरोड के विकास-सम्बन्धी आदर्श की ही तरह, डोमर ने भी केन्स के गुणक सिद्धान्त (विनियोग की माँग अथवा आय-प्रभाव) एवं उत्पादकता के संस्थापक सिद्धान्त (विनियोग के सिगमा-प्रभाव) के संश्लेषण का प्रयास किया।

पूर्ति की दी हुई दशाओं में (विशेपतः पूँजी स्थायी स्टॉक के साथ), जब एक वार उत्पादन का स्तर प्रभावकारी गाँग के द्वारा निर्धारित होता है तो केन्स के अल्पकालीन सिद्धान्त की ही तरह दूसरा तार्किक प्रश्न यह होता है : यदि पूँजी के स्टॉक में वृद्धि से पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन हो जाय तो उस निपज का क्या होगा ? गत्यात्मक अर्थशास्त्र में इस प्रकार का प्रश्न होता है तथा उसका जवाब भी दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार श्रीमती जाँन राँविन्सन ने प्रासंगिक ढँग से कहा है कि यह इस विरोधाभास की व्याख्या करता है कि केन्स की 'जनरल थिपरी' का रूप स्थैतिक होते हुए भी इसने गत्यात्मक समस्याओं के विश्लेषण के लिए मार्ग तैयार किया है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती रॉविन्सन के साथ-साथ नस्के ने गत्यात्मक अर्थशास्त्र को अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की दिशा में मोड दिया । दोनों ने ही विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विनियोग-सम्बन्धी मांग एवं पूँजी-निर्माण के कारणात्मक महत्त्व पर जोर दिया । अब भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पुँजी में अभिवृद्धि, जैसा कि संस्थापक अर्थशास्त्रियों का विचार था, उपभोग में कमी के वगैर नहीं हो सकती अथवा जैसा कि केन्स ने कहा है, उपभोग में साथ-साथ वृद्धि के वगैर असम्भव है, अथवा जैसा कि नस्के⁵ का विचार है उपभोग में जिना किसी प्रकार के परिवर्तन के भी सम्भव है।

केन्सका राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी विश्लेषण विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने का न्युनतम आधार है। साथ ही यह वचत, उपभोग, विनियोग, रोजगार तथा परि-

^{1.} देखें डोमर-का वहीं।

^{2.} द्राप्टन्य 'दि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर एसेज' लंदन, 1952 के प्राक्तथन में।

आर० नस्कों, प्रोक्लेम्स ऑफ कैपिटल फारमेशन इन अंडरडेवलण्ड कौन्ट्रीज' व्लेकवेल, ओक्सफोर्ड, 1953 ।

जे० रॉबिन्सन-का मार्च, 1949 के 'इकानामिक जरनल में मि० होरोड्स डायना-मिक्स' तथा 'दि रेट आफ इंटररेस्ट' इत्यादि ।

^{5.} नस्के के विचारों की विस्तारपूर्वक व्याख्या सम्भाव्य वचत के रूप में छिपी हुई वेरोजगारी के सम्बन्ध में की जाएगी। नस् केके 'संतुलित विकास' के सिद्धान्त के व्यापक मूल्यांकन के लिए 11वां अध्याय देखें।

चालन की दृष्टि से अधिक विकास के महत्त्वपूर्ण अन्य परिवर्तियों के अनुमान का प्राविधिक आधार है। यहा इस साधारण वात की चर्चा केवल इसलिए की गई है कि कभी-कभी व्यवहार में मनुष्य इसकी अपेक्षा करते है तथा यह जानने की कोशिश भी नहीं करने कि राष्ट्रीय आध की गणना के सैद्धातिक आधार का उद्गम क्या है ?

वास्तव मे, कोई भी व्यक्ति परिचालन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तरीके से आधिक विकास की चर्चा केन्स के 'जनरल थियरी' में उद्धृत मात्रा एव फलनीय सम्बन्ध की चर्चा किये वर्गेर नहीं कर सकता। किन्तु, जैसा कि हैरोड ने कहा है दीर्घ-कालीन विश्लेषण में इन परिवर्तींगणों को जनसंख्या, प्रविधि तथा साधन जैसी मौलिक शर्ती से पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही, केन्स की राष्ट्रीय आय का विश्लेषण इस बात की सतत याद दिलाता है कि बिना किसी सिद्धान्न अथवा स्वीकार्य प्राक्कल्पना के, जिससे कि राष्ट्रीय आय के अवयवों (उपभोग एव विनियोग) की प्रवृत्ति की सार्थंक व्याद्या में सुगमता हो और विशेषत जिससे प्राविधिक सीमाओं के अन्दर वास्तिक अर्ब-विकसित देशों के सफल औद्योगीकरण को निर्देश मिल सके, निसी साहियकीय सामग्री का सग्रह एव माप-सम्बन्धी प्रविधि की सूक्ष्मता बहुत उपयोगी सिद्ध मही हुआ करती।

केन्स की अन्तिम महत्वपूर्ण देन पूर्नानर्माण एव विकासाधं, विश्व-वंक की स्थापना के विचारों से सम्बद्ध है। हैरोड ने केन्स के जीवन-वृक्तान्त में इसकी बड़े ही रोचक ढंग से व्याप्या की है। यहाँ केन्स ने मार्क्स एव उसके अनुयायियों के इस विचार का कि आधिक क्षेत्र में विकसित पूँजीवादी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विपमागता के आधार पर स्थायी रूप से पिछड़े राष्ट्री का ग्रोपण करते है, पूरी तरह से खंडन किया है। वास्तव में, केन्स अन्तर्राष्ट्रीय समागीकरण को विश्व-व्यापी समृद्धि एवं स्थायी विश्व-गाति का साधन मानता था। वह विश्व के सपन्न सदम्य-राष्ट्री की वचत की संभावनाओं को विपन्न राष्ट्री की विकास-सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप वनाने के लिए विश्व-वंक को एक प्रधान साधन समभता था। इस सम्बन्ध में बंक के ऋण की विस्तृत कार्यवाही नहीं, जिसमें समय-समय पर सुधार एव परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, विस्तृत पूर्विमर्मण एव विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्व-वंक का विचार ही भौतिक एव महत्वपूर्ण दोनो है। इस विचार का श्रेय केन्स की साहसिक कल्पना एव वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीयता को है। सामान्य रूप से विभिन्न

देखें, इनका 'वि लाइफ अरफ जान मेनाई केन्स' हरकार्ट, ब्रेस एव कम्पनी, न्यूयार्क, 1951 ।

^{2.} देखें, सितम्बर 1952 के 'सोशल रिसर्च' में ई० हेमन का 'माविसंदम एंड अंडर-डेबलप्ड कंट्रीज'।

राष्ट्रों के भविष्य के आचरण पर तथा विशिष्ट रूप से अल्प-विकसित राष्ट्रों के भावी आर्थिक विकास पर इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव की आशा की जाती है । $^{\rm L}$

जोसेफ ए० शुम्पीटर (1883-1950)

णुम्पीटर पहला आधुनिक वर्षणास्त्री था, जिसने आधिक विकास को आधिक विश्लेषण के एक विधिष्ट क्षेत्र का रूप दिया। ऐसा उसने 1911 ई० में जर्मन भाषा में प्रकाशित तस्कालीन बहुत कम प्रसारित पुस्तक दि थियरी आफ इकनामिक डेव-लपमेंट' में किया। २३ वर्षों के बाद इस पुस्तक के अंग्रेजी-संस्करण के प्रकाशन का भी बहुत ही कम प्रभाव पड़ा; नयोंकि उस समय मंदी एवं वड़े पैमाने पर वरोज़गारी जैसी गम्भीर अस्पकालीन समस्याओं में उलभे रहने के कारण विश्व को दीर्घकालीन समस्याओं की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने का अवसर नहीं था। केवल वर्तमान युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण एवं विकास, जो चक्रीय समस्याओं में हास के कारण ही सम्भव हुआ है, के समय में अर्थगास्त्रियों ने णुम्पीटर के आधिक विकास के सिद्धान्त की ओर नयं दृष्टिकोण से देखना अग्रम्भ किया है। किन्तु शुम्पीटर के सिद्धान्त के सैंद्धांतिक एवं संस्थागत अधिस्वरों ने इसके प्राविधिक महत्त्व को कम तथा इसकी व्यावहारिक प्रयोज्यता को सीमित बना दिया है।

शुप्पीटर के अनुसार साहसी (नयी रीति चलाने वाला), नवीन किया एवं साख की अस्थिर अन्तः क्रियाओं के परिणामस्वरूप पूँजीवाद का विकास भटके से होता है। अतः, अपने सफल निष्पत्तियों जैसे सामूहिक उत्पादन, सामूहिक शिक्षा एवं वृहत् व्यापार तथा इसके आवश्यक सहगामियों—जैसे राजकीय नियमन, बौद्विक रोप तथा श्रमिक संघवाद के परिणामस्वरूप यह निश्चय ही समाजवाद के किसी-न किसी रूप के समक्ष अपने को अपित कर देगा। यहाँ शुप्पीटर मानसं के पूँजीवाद के अवश्यंभावी विघटन की धारणा से सहमत है। यदाप शुप्पीटर इसके लिए पूँजीवाद की सफलता को उत्तरदायी मानते हैं, मानसं इसके लिए इसकी असफलता को उत्तरदायी ठहराते हैं। जो भी हो, ऐतिहासिक आधिक विकास के संस्थागत वास्तविक व्याख्यात्मक

देखें, यूनाइटेड नेशन्स का न्यूयार्क, 1951 में प्रकाशित भेयर्स फाँर दि इकानामिक डेयलपर्मेट आफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज'। साथ ही, इस पुस्तक का परिशिष्ट भी देखें।

^{2.} इस ह्रास के कुछ कारणों के लिए देखें, पूर्व उद्धृत 'दि व्यूजीनेस साईकिल इन दि पोस्ट बार बर्ल्ड'।

विशेषतः, जैसा कि उसके वाद पुस्तक 'कैषिटलिल्म, सोसलिम एवं डेमोक्रेसी' में विस्तृत किया गया है।

^{4.} मई, 1950 ई० के 'अमेरिकन इकॉनामिक रिच्यू' में शुम्पीटर का अन्तिम संदेश देखें।

परिवर्त्ती के रूप में साहसी, नवीन किया एवं साख के वर्णात्मक महत्त्व वो कम ही लोग अस्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि निजी उपक्रम एवं जोखिम उठाने का अभाव, नवीन किया में पटुता की अनुपस्थिति तथा वैकिंग की सुविधाओं एव पूँजी वाजार की आदिम अवस्था आज भी अल्प-विकमित बाजार सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्थाओं की सामान्य सस्थागत विशेषताएँ हैं।

विन्तु आज की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के यग में श्रम्पीटर द्वारा केवल निजी ज्यमकर्ता के रूप में नवीन क्रियाकारक की व्याख्या को निविवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विन्त जहां तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, इससे भी अधिक विवादास्पद उसकी नवीन किया-सम्बन्धी अत्यधिक आशावादी धारणा है। यदि नवीन किया उत्पादन की मुधरी हुई प्रविधि का रूप धारण करती है, तो इससे पूँजी के वर्तमान कोप में बिना किसी परिवर्त्त के ही अम की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो सकती है। श्रम की उत्पादन-क्षमता में इस प्रकार की वृद्धि वा पुँजी-विपन्न अर्थ-व्यवस्थाओं में निक्चय ही स्वागत होगा । किन्तू यदि पुँजी-विपन्न अर्थ-व्यवस्था की जनसंख्या मे तीन्न गति से वृद्धि हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में पूँजी के दिये हुए कोण की तुलना मे श्रम की कम आवश्यकता वाली प्रविधियों की अपनाने से वेरोजगारी की समस्या में भी युद्धि होगी। किन्तु, इसके दिपरीत यदि नवीन किया विस्तारित सयत्र एवं उपकरण का रूप धारण करती है, तो इसका लाभ यह होता है कि इससे उत्पादन की प्रविधि में बिना किसी आवश्यक परिवर्त्तन के ही श्रम की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होती है। किन्तु तब सभव है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था मे नये संयत्र एव उपकरण-सम्बन्धी नवीन क्रिया-निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में बचत नहीं हो। और पुन. चुँकि नदीन किया-निवेश लाभ की निजी प्रत्याशा तथा पुँजी प्रयोग की प्राविधिक स्थिति पर निर्मर करता है, एक अल्प-विक-सित अर्थ-व्यवस्था के लिए इस प्रकार का निवेश तीव आर्थिक विकास के लिए पूँजी-सचय का विश्वस्त साधन नहीं भी सिद्ध हो सकता है। बयोकि लाभ की विविधता एव प्रविधि की गत्यारमकना सदा इस प्रकार की नहीं होती, जो अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था मे वाछित मात्रा मे नवीन किया-निवेश को प्रोत्साहित करे 12

निजी साख के महत्त्व पर शुम्पीटर द्वारा दिया गया जोर पूँजीवाद के विकास में बैक-साख एवं निगम ऋण-इविवटी, जिल्ल-व्यवस्था के ऐतिहासिक महत्त्व को उचित रूप में प्रतिविम्बित करता है। फिर भी, यह केवल इस प्रकार के मौदिक साधनो

देखें, डब्लू० ए० नीवीस की एलेन एड अनवीन, लदन, 1955 द्वारा प्रकाशित प्रतक 'दि थियरी आफ इकानामिक प्रोय'।

देखे, ए० जोशिदा की 'शुम्पटेरियन सिस्टम एवं मोनोपली' तथा जून, 1957 के 'इकानामिक स्टडीज बवार्टली' में प्रकाशित के शिवयामा का 'मोनोपली एड इकानामिक डेबेलपमेट'।

(यानी उत्पादन में से उपभोग घटाने पर प्राप्त वास्तिवक वचत) के वास्तिवक आधार को दुर्बोध ही नहीं वनाता, वरन् राजकीय साख, घाटे की वित्त-व्यवस्था, वजट की वचतें तथा सरकार के अन्य राजकीपीय कार्यों को भी पृथक् कर देता है। साथ ही, यह कहना कि वैकिंग की सुविधाओं में विकास से औद्योगीकरण में सहायता मिलती है, स्वयं सिद्ध ही है। क्योंकि इसका तात्पर्य केवल संस्थापकों के इस विचार को दुहराना है कि मुद्रा एवं वैकिंग-सम्बन्धी संस्थाएँ वस्तु-विनिमय-व्यवस्था से विनिमय व्यवस्था के संकमण में शी झतापूर्वक पहुंचती हैं। वास्तव में, विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने में इस वात का सुभाव—िक किस प्रकार राजकीपीय एवं मौद्रिक नीति से निपज में वृद्धि की दर में वृद्धि होगी अथवा किस प्रकार एक विये हुए दर पर निपज में वृद्धि के स्थायित्व को प्रोत्साहित किया जा सकता है, अधिक लाभदायक होगा।

इसके वावजूद, आर्थिक विचारधारा के इतिहास में शुम्पीटर का नाम प्रविधि की गरयारमकता पर, दोनों सामान्य आर्थिक विकास के एकमात्र सर्वाधिक महत्व-पूर्ण कारण एवं विणिष्ट रूप से चकीय विकास की प्रमुख व्याख्या के रूप में अन्य अर्थ-शास्त्रियों की अपेक्षा अधिक जोर देने के कारण स्मरणीय होगा। संस्थानिक कारणों पर अधिक जोर देने का कारण, शुम्पीटर के आर्थिक विकास का सिद्धान्त, उसके अभिप्राय के विरुद्ध, उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को अधिक आकर्षक लगेगा, जो परम्परा से अलग होने के लिए उग्र रूप में तैयार हैं।

अध्याय 2

अरुप-विकसित अर्थ-व्यवस्था की संरचना

किसी भी आस्वरण-सम्बन्धी विदल्लेपण के लिए सर्वप्रथम सरचनात्मक विश्ले-पण अनिवार्य है। मभी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में सर्वनिष्ठ मीलिक समस्याओं का गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सरचनात्मक विश्रोपताओं तथा इसके निर्धारक तस्थों का विवेधन अनिवार्य है। किन्तु इम सम्बन्ध में हम केवल उन्ही विशेपताओं तथा निर्धारक तस्यों का वर्णन करेंगे, जो परिचालन की दृष्टि से अनि सार्थक एवं आधिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस पर्यवेक्षण-सम्बन्धी अध्याय में विचार-वस्तु को तीदण करने के लिए हम अत्य-विकसित एवं विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की विषयनाओं की तलना करने करेंगे।

अन्य आर्थिक विकास के सूचक

प्रति द्यक्ति न्यून बास्तविक आय

अल्प-विकमित अयं-व्यवस्या को चित्रित करने के लिए चाहे जितने भी अन्य सूचको की चर्चा की जाय, शायद एकमात्र मर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूचक प्रति-व्यक्ति न्यूम वास्तविक आय है। 'प्रति-व्यक्ति' विशेषक वाक्याश एक अन्यया अनादशीं सूचक में क्ल्याण का अश जोड़ देता है, क्योंकि इससे शीध ही यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था एक ऐसे ममुदाय का प्रतिनिधित्व भी करती है, जिसकी भौतिक समृद्धि प्रति-व्यक्ति उपभोग के रूप में सदियों से प्रगित्तित रही है। माथ ही यह इम बात की ओर भी सकेत करता है कि कोई अर्य-व्यवस्था अनिवायत केवल इसलिए अल्प-विकसित नहीं हो सकती कि उसकी प्रजनन की प्रवृत्ति उसकी उत्पादन-धमता से अधिक बलवती है, वरम् मम्भवत इसलिए भी कि उसकी उत्पादन-धमता प्रजनन की प्रवृत्ति को अपेक्षा अधिक कमजोर है। अत्प्त, 'प्रति-व्यक्ति' विशेषक अल्प-जनसर्या वाली अस्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के साथ-साथ जनाधिवय वाली अधिक सामान्य स्थिति को भी सभाल सकता है। वहाँ

^{1.} प्रीत व्यक्ति राष्ट्रीय आय को प्र=1/2 के रुप में परिमापित किया जाता है, जिसमे प्र औसत आय, Y, वास्तविक राष्ट्रीय आय एव P जनसंख्या का आकार है। अतएव प्रति-व्यक्ति राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की अपेक्षा आर्थिक प्रगति का अच्छा माप है। यह विभेद इमलिए महत्त्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति मे जविक जनसंख्या मे वृद्धि उपज मे वृद्धि से अधिक होनी है, जिसमे कि प्रति-व्यक्ति स्थिति पहले से भी खराब है, कोई आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है।

तक उपर्यु वत सूचक में सिन्निहित 'वास्तिविक राष्ट्रीय आय, 1 का प्रक्ष है, इससे निपज के भौतिक परिमाण एवं उसके मौद्रिक मूल्य के वीच जो अन्तर है, उसे जानने में सहायता मिलती है। उत्पादित एवं उपभुक्त भौतिक पदार्थों के रूप में उत्पादकता एवं कल्याण का वास्तिविक माप उत्पादन का भौतिक पिरमाण होता है, न कि उसका मौद्रिक मूल्य। साथ ही वास्तिविक आय की घारणा हमें मौद्रिक लाभदायकता को भौतिक उत्पादकता का प्रतिनिधि मान लेने की निकटदर्शी भूल से बचाती है। यह एक ऐसी भूल है, जिससे अनुमानतः उत्पादक साधनों का भारी अपनिरंगन हो सकता है, जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए संभवतः अहितकर है।

अपर्याप्त प्राकृतिक साधन

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का एक अन्य परिचालन-सम्बन्धी सूचक जनसंख्या के आकार के अनुरूप अपर्याप्त प्राकृतिक साधन है। यह अपुनरुपादनीय एवं क्षयशील भौतिक सम्पत्ति, विशेषतः प्रति संतुलन टेक्नोलॉर्जी की अनुपस्थिति में इतना अधिक महत्त्वपूर्ण एवं मानव कल्याणकारी जान पड़ता है कि संस्थापक अर्थशास्त्रियों ने भूमि को, पुनरुपादनीय पूँजी और श्रम के समकक्ष, उत्पादन के एक पृथक् साधन का रूप दिया था। इन संस्थापक अर्थशास्त्रियों में कुछ तीज गित से बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में सम्पूर्ण भूमि की लोचहीनता से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वे इस शोकपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्रमागत उत्पत्ति-हास-नियम की निरंतर क्रियाणीलता से जीवन-मान अवनत रहेगा। यद्यपि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विकसित अर्थ-व्यवस्थाएं विशालकाय उत्पादन की मितव्यियताओं से अत्यधिक लाभान्वित अवश्य हुई हैं, किन्तु टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाएँ, जिनकी जनसंख्या तीज्ञ गित से वढ़ रही है तथा जिनमें प्राकृतिक साधनों का अभाव है, अभी तक विभिन्न ढंग से क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास्-नियम के निर्मम परिचालन के प्रभाव में रहे हैं।

अपवादस्वरूप कुछ देशों को छोड़कर वास्तविक रूप में अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को जनाधिक्य की समस्या का सामना करना पड़ता है;

^{1.} वास्तविक राष्ट्रीय आय को Yr = Ym/P(t) के रूप में व्यक्त किया जाता है,

[√] जिसमें Ym मीद्रिक आय तथा t समय में P (t) औसत मूल्य (चुने हुए आधार-काल की तुलना में) हैं। दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए वास्तविक आय का आचरण ही महत्त्वपूर्ण है।

देखें, उब्लू० एस० एण्ड ई० एस० वायिटस्की, वर्ल्ड पापुलेशन एण्ड प्रोडक्शन, ट्वेन्टीयेथ सेन्च्री फंड, न्यूयार्क, 1953 ।

क्योकि इनमें मुख्य प्राकृतिक साधनों। (जैसे कृष्य-भूमि, कोयला, तेल तथा लोहे का भण्डार एवं वन) का प्रति-व्यक्ति औसत परिमाण इतना कम रहता है कि इनसे इनके टोस औद्योगीकरण एवं 'अपेक्षाधिक जनसंख्या' की समस्या के समाधान में कोई सहायता नहीं मिलतों। किन्तु इस सम्बन्ध में विषेष ध्यान देने योग्य वात यह है कि कोई देण प्रजुर मात्रा में प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी इन्हें विकसित करने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी तथा पूँजी के अभाव में साधन-विहीन देश की ही तरह निर्धंत होगा। फिर भी प्राकृतिक साधनों की प्रजुरता स्वय टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति की एक अनुकृततम शर्त है। इस प्रकार विचार करने से, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था से सम्भवतः जनाधिक्य बाले राष्ट्र का भी केवल इमलिए बोध हो मकता है कि आज की अल्प-विकसित, विशेषतः टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से पिछडी हुई, अर्थ-व्यवस्थाओं में प्राकृतिक साधनों का अभाव माल्यम की चेतावनी के उपदेशात्मक महत्य पर जोर देता है।

अपर्याप्त पूँजीगत साधन

स्थूल पूँजी की अपर्याप्तता अल्प-विकसित देशों की एक ऐसी प्रमुख विशेषता है कि कभी-कभी इन्हें केवल 'पूँजी-विपन्न' अयं-व्यवस्था की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, आधिक विकास में पूँजी का योगदान इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कुछ लेखक अन्य तथ्यों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। चूँकि किसी निश्चित समय में वर्तमान स्थूल पूँजी का कोप विगत बचत एव विनियोग का परिणाम होता है, अतएव यह कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत अल्प पूँजी के कोपवाली अल्प-विकसित अयं-व्यवस्था निम्न बचत एव निम्न विनियोग वाली स्थित के लिए निधिश्व करती है। इस निम्न बचत एव निम्न विनियोग वाली स्थित के लिए

2 उदाहरण के लिए देखें, आर० नक्सें की पुस्तक 'प्रोब्लेंक्स ऑफ कैपिटेल फारमेशन इन अंडरडेवलप्ड कॉन्टीब' ।

^{1.} किसी अर्थ-व्यवस्था में कृषि-योग्य भूमि के अतिरिक्त अन्य साधनों की जितनी ही अधिक प्रचुरता रहती है, वह उतना ही अधिक घरेलू निर्माण उद्योगों के विकास द्वारा खाद-पदार्थों के बदले अन्य वस्तुओं का निर्यात कर माल्यम के जनाधिवय की समस्या के समाधान के योग्य होता है। ग्रेट-ब्रिटेन पहले ऐसा ही करता था और मुख्य चीन आजकल ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा है। किन्तु, यदि किसी देश में बढ़ती हुई जनसख्या की तुमना में कृषि-योग्य भूमि एव अन्य प्राकृतिक साधन दोनों का अभाव है, उसके लिए माल्यस द्वारा विणत समस्या और भी गभीर हो जाती है। यदि प्राकृतिक साधनों का अभाव नहीं होता, तो जापान पिंचमी अर्थ-व्यवस्थाओं से सम्भवत. कम विकसित नहीं होता।

निम्न पारिवारिक आय, मितन्ययों मध्येम वर्ग की स्वल्पता, पूँजी-वाजार एवं वचत वाली अन्य संस्थाओं का दोपपूर्ण संगठन, सम्पन्न वर्ग द्वारा प्रदर्शन, उपभोग तथा वचत की आदत को प्रभावित करने वाले अन्य तथ्यों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य वात यह है कि पूँजी की अपर्याप्त पूर्ति के माप के रूप में अल्प वचत सभी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की एक सर्वेनिष्ठ समस्या है। किन्तु पूँजी की माँग (विनियोग के पूर्व) केवल अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की हो समस्या नहीं है।

यदि यह मान लिया जाय कि समाज में जितनी वचत होती है, ठीक उतनी ही रकम का विनियोग होता है, तो समाज की पूँजी का स्टाक वढ़ रहा है, स्थायी है अथवा हासमान है, इस आधार पर आर्थिक विकास के तीन प्रतिरूप वतलाये जा सकते हैं। इस प्रकार यदि समाज अपने गुद्ध उत्पादन से कम का उपभोग करता है, जिससे पूँजी के वर्तमान कोप अथवा शुद्ध विनियोग में वृद्धि हो रही हो तो इसे प्रमित्त अर्थ-व्यवस्था की संज्ञा दी जा सकती है। पुनः यदि समाज अपने शुद्ध उत्पादन का पूरा-पूरा उपभोग करता है, जिससे गुद्ध विनियोग शून्य के वरावर होता है, तो इसे स्थैतिक अर्थ-व्यवस्था कहा जा सकता है। अंततः, यदि समाज अपने शुद्ध उत्पादन से भी अधिक का उपभोग करता है जिससे शुद्ध विनियोग ऋषात्मक होता है, यानी प्रतिस्थापन के वगैर ही पूँजी के कोप में कमी आ रहीं हो तो इसे हास-मान अर्थ-व्यवस्था कहा जा सकता है। अतएव, यदि किसी देश के पास पूँजी का सतत-प्रवाही कोष अरुप मात्रा में हो तो इससे तीव्र आर्थिक विकास के विरुद्ध परिकल्पना विरचित होती है।

प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्थाः $(\mathrm{d}y/\mathrm{d}t)>0$ कारण कि $(\mathrm{d}k/\mathrm{d}t)>0$, (y>c,s=i>0)।

स्यैतिक अर्थ-ज्यवस्था : (dy/dt) = 0 कारण कि (dk/dt) = 0, (y=c), s=l=0)।

ह्रासमान अर्थ-ब्यवस्था : $(\mathrm{d}y/\mathrm{d}t)$ < o कारण कि $(\mathrm{d}k/\mathrm{d}t)$ < o, (y<c, s=1<0) ।

यहाँ पर y विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति, l: वास्तविक पूँजी, c उपभोग, s वचत, l विशुद्ध विनियोग तथा t समय है।

2. एस० कुजेन्ट्स के अनुसार वर्तमान समय में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में शुद्ध विनियोग की दर राष्ट्रीय उत्पत्ति के 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तथा विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में 10 से 15 प्रतिशत तक होती है। (देखें, मार्च, 1955 ई० के 'अमेरिकन इकानॉमिक रिट्यू' में इनका 'इकानॉमिक ग्रोथ एण्ड इनकम इन इक्पुलिटी।')

^{1.} इन प्रतिरूपों को प्रतीकात्मक रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

देक्नोलॉजी-सम्बन्धी पिछड़ापन

औसत उरपादन व्यय अथवा उत्पादन से सम्बद्ध श्रम या पूँजो के ऊँचे श्रनु-पात के रूप में मापने पर पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी की स्थिति में एक और भी परिचालन-मम्बन्धी सूचक अवलोक्ति हो मकता है। साधारणत टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अग्रवर्नी अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा टेक्नोलॉजी की दृष्टि से मद पड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं में उत्पादन की सपूर्ण शुद्ध लागत (यानी एक निश्चित माश्रा में उत्पादन के लिए पूँजी, श्रम एव अन्य साधनी का आगत) अधिक होती है। इसी वास्तविक अर्थ में उत्पादन के मोदिक व्यय में सम्मिलित अल्प-मोदिक मजदूरी के बावजूद, यड़े पैमाने पर उत्पादन की मितव्यिता के परिणामस्वरूप एक अग्रवर्ती अर्थ-व्यवस्था अल्प लागत क्षेत्र का प्रतिनिधिस्व करती है।

साथ ही टेन्नोलॉजी की दृष्टि से पिछडी हुई अर्थ-व्यवस्था में साधनी का मूल्य (मजदूरी, ब्याज इत्यादि) स्थायी दिया हुआ हीने पर, सम्भवत नियमित तथा औसत¹ रूप से उच्च श्रम-निपज अनुपात तथा उच्च पूँजी-निपज अनुपात पाये जाने है। इससे बहुधा श्रम एव पूँजी दोनों की अल्प-उत्पादकता का बौध होता है। टेवनोलॉजी-सम्बन्धी पिछडोपन अकुशल एव अप्रशिक्षित श्रमिको के रूप मे परिलक्षित होता है। अतएव, पुँजीगत साधनों के एक दिये हुए कोप के साथ तकनीक की दृष्टि से अपेक्षाकृत प्रशिक्षित श्रमिको की नुलना में निपत्र की प्रति डकाई पर अधिक श्रमिको की आवश्यकता पडती है। अत. टेवनोलॉजी की दुष्टि से पिछडापन के परिणामस्यरूप सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के श्रम-निपज अनुपात में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। टेक्नोलॉजी की पिछडी हुई स्थिति के परिणामस्वरूप ही एक निश्चित मात्रा में राष्ट्रीय निपज के उत्पादन में अधिक पूँजीगत साधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि अपर्याप्त तकनीकी ज्ञान के परिणामस्वरूप धम की उत्पादन क्षमता Y/N में पूँजी एव श्रम के अनुपान K/N की अपेक्षा कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो पूजी-निपज अनुपात में K/Y = (KN)/(YN) के माध्यम से वृद्धि होगी। ³ टेक्नोलॉजिकल पिछड्रापन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के पूँजी-निएज अनुपात को बढाने में कम-से-कम एक महत्त्वपूर्ण कारण है। इस प्रवृत्ति के प्रत्यावर्त्तन में लीचपूर्ण साधनो के मृत्य पर किम हद तक निर्भर किया जा सकता है, अभी तक बर्णनाधीन है।

सरसनात्मक अपूर्ण रोजनार

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की एक अन्य विशेषता संरचनात्मक अपूर्ण

विस्तृत विवेचन के लिए इस पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय देखें !

विवादास्पद अशो के लिए पाँचवें अध्याय के उपखड नीति 'प्राचल के रूप पूजी-निपण अनपात' देखें।

रोजगार है। इस प्रकार की वेरोजगारी समर्थ माँग के पर्याप्त रहने पर भी पूँजीगत साधनों के पूर्ण उपयोग के वावजूद इनकी अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ उपलब्ध श्रम (जनसंख्या में वृद्धि द्वारा णासित वर्तमान श्रम-संख्या), नियुक्त श्रम (श्रम-संख्या का वह भाग जो पूँजी के दिए हुए कोप पर, समर्थ मांग में परिवर्तन के अनुसार वास्तव में नियुक्त है) तथा अपेक्षित श्रम (श्रम का अधिकतम संभावी परिमाण जो समर्थ मांग के दिये हुए आकार के आधार पर वर्तमान उपकरणों के पूर्णरूपेण उपयोग करने पर रोजगार में लगाया जा सकता है और जो पूँजीगत साधनों एवं पूँजी की उत्पादन-क्षमता में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनशील है) में अन्तर करना लाभदायक होगा। अल्प-विकसित अर्थ-ज्यवस्थाओं में नियमित तथा औसत रूप, से अपेक्षित श्रम की अपेक्षा उपलब्ध श्रम का आधिक्य रहता है और इन दोनों का अन्तर संरचनात्मक अपूर्ण रोजगार का माप है।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में संरचनात्मक अपूर्ण रोजगार की विद्यमानता मुख्यतः बढ़ती हुई श्रम-संख्या की तुलना में पूँजी के दीर्घकालिक अभाव का परिणाम है। इसके विपरीत, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर वेरोजगारी मुख्यतः दी हुई जनसंख्या एवं पूँजी के कोप दोनों की तुलना में समर्थ माँग में चकीय कमी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। सरसरी तीर पर निम्नलिखित उदाहरण लाभदायक हो सकता है। जैसा कि पहले प्रासंगिक ढंग से इसे परिभाषित किया गया है: मान लें कि N=उपलब्ध श्रम, Ne=नियुक्त श्रम एवं Nr=अपेक्षित श्रम हैं। अब मोटे तौर पर वेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण सम्भव है- (क) किसी देश में सम्पूर्ण वेरोजगारी=N-Ne; (ख) किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में संरच-नात्मक अपूर्ण रोजगार=N-Nr; तथा (ग) किसी विकसित अर्थ-व्यवस्था में चकीय . वेरोजगारी = Nr—Ne । तो भी जैसा कि आगे के एक अध्याय में वर्णन किया गया है, एक वास्तविक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में एक ही समय सम्भवतः दोनों प्रकार की वेरोजगारी पाई जा सकती है। अपेक्षित श्रम की तुलना में उपलब्ध श्रम के आधिक्य का तात्पर्ययह है कि पूँजी का वर्तमान कोप, पूर्ण रूप से प्रयुक्त होने पर भी सम्पूर्ण उपलब्ध श्रम को उत्पादक रोजगार में लगाने के लिए अपर्याप्त है। दूसरी ओर नियुनत श्रम (Ne) की तुलना अपेक्षित श्रम (Nr) के आधिनय का तात्पर्य यह है कि उपलब्ध श्रम का वास्तविक नियुक्त अंश पूंजी के वर्तमान कोप के पूर्ण रूप से प्रयुक्त होने पर (जबकि समर्थ माँग पर्याप्त है) जितने नियुक्त श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, उससे कम है। इन विभिन्न प्रकार की वेरोजगारियों के विस्तुत एवं गत्यात्मक विश्लेषण को अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की दुहरी वेरोज-गारी के अध्ययन (छठे अध्याय) तक के लिए स्थगित करना पहेगा।

भ्राय की अत्यधिक असमानता

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का दूसरा परिचालन-सम्बन्धी चिह्न अत्यधिक

मात्रा में आय की असमानता है। इसे लॉरेन्ज दक के अर्थ में समता की पूर्ण रेखा से विचलन के रूप में मापा जा सकता है। एक प्रारुपिक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए लॉरेन्ज वक को एक प्रारुपिक विकसित अर्थ-व्यवस्था के वक की तुलना में 45° की रेखा के बहुत दूर पृथक् रहने की आणा की जाती है। इससे यह स्पट्ट होता है कि विकसित देशों की तुलना में अल्पविकसित देशों में न्यूनतम आय बाली 10 प्रतिणत जनसंख्या की आय कुल आय के 10 प्रतिणत से बहुत कम होती है। यह इस सामान्य विचार कि अधिकाश अरण-विकसित देशों में मम्पन्तता एवं विपन्तता के बीच बहुत विस्तृत खाई पाई जाती है, से बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जिससे इनमें मध्यम वर्ग वस्तृत पाया ही नहीं जाता। निषचय ही अपवादस्वरूप कुछ हालतों में राजनीतिक सिद्धान्त अथवा मानवतावादी दर्शन के परिणामस्वरूप आय की अत्यधिक असमानता को रहने नहीं दिया जाता है। किन्तु इन अपवादों से इस मौलिक तथ्य कि विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा समग्र रूप से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं तथा किसी अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा समग्र रूप से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का प्रक्रिय की परिपक्तता की अपेक्षा औद्योगिकरण की प्रक्रिय की स्थिति में आय की असमानता अधिक पाई जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके दो सामान्य कारणों का यहा उल्लेख किया जा सकता है।

प्रयमतः, औद्योगीकरण की स्थिति में अल्प-विकसित अर्थ-अ्यवस्थाएँ, अतिच्छापूर्वक ही सही, पूँजी-सग्रह की गति की तीथ बनाने के लिए उच्च मात्रा में आय की
विपमता को बनाये रखने के प्रयत्न आर्थिक दवाव के अतर्गत रहती हैं। निर्धंत
व्यक्तियों की अपेक्षा धनवानों की सीमात बचत की प्रवृत्ति साधारणतया अधिक होती
है। अतएव, जिस समाज में औसत पारिवारिक आय से बहुत उच्च या बहुत निम्त
आय बाले परिवारों का अनुपात जितना ही अधिक होगा, उसकी सीमात बचत की
प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और इसलिए पूंजी की पूर्ति भी अधिक होगी।
अब आय में अत्यधिक असमानता आर्थिक विकास में वास्तव में सहायक होती है या
नहीं यह दूसरी बात है। द्वितीय, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में वास्तविक आय
का स्तर तथा इसमें वृद्धि की दर इतनी निम्न होती है कि इन प्रगतिशील करारीपण,
सामिजिक बीमा, श्रीमक सघवाद, सामूहिक शिक्षा, बड़े पैमाने पर उत्पादन, एकाधिकार-विरोधी अधिनयम और व्यावसायिक गतिशीलना जैसी समकारी शकित्यों को

कुछ पूर्वकालिक तथा वर्तमान अनुभवाधित आंकडो के लिए एस० कुज्नेट्स की पूर्व उद्धृत पुस्तक 'इकानामिक ग्रोथ एण्ड इनकम इन इक्यूलिटो' देखे ।

^{2.} यह दशन उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में नहीं पाया जाता, जिनमें स्वय सरकार वजत करने वाले मुख्य अभिकरण के रूप में कार्य करती है तथा उन अर्थ-व्यवस्थाओं में जो मुक्त रूप में तथा जो सुगमतापूर्वक विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकती हैं, कम मात्रा में पाया जाता है।

बड़े एवं वृद्धिशील पैमाने पर विकसित करने के लिए आवश्यक आर्थिक आधार का अभाव रहता है। क्योंकि जब तक स्वयं राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि नहीं की जाएगी, तव तक किसी विशेष आय वर्ग के हिस्से को केवल दूसरे वर्ग की आय को कम करके ही बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार समकारी शक्तियों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए स्थान रह जाता है।

बाह्य ऋणग्रस्तता

विदेशी व्यापार सम्बन्धोंवाली विवृत व्यवस्था समभी जाने वाली अहप-विक-सित अर्थ-व्यवस्था की अंतिम विशेषता उसकी दीर्घकालीन ऋणी की स्थिति है। किसी भी देश की निरन्तर वाह्य ऋणग्रस्तता मूलतः उस देश की प्रवल आयात-सम्बन्धी अशवश्यकताओं की तुलना में दुवंल निर्यात-क्षमता को परिलक्षित करती है। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की दीर्घकालीन ऋण की स्थिति की व्याख्या निम्नांकित रूप में की जा सकती है -B=P+M-E। जिसमें B शुद्ध विदेशी उधार, P पूँजीगत खाते में शुद्ध विदेशी भुगतान, M वास्तविक आयात तथा E वास्तविक निर्यात हैं। यह समीकरण यह वतलाता है कि आयात में वृद्धि अथवा निर्यात में कमी के परिणाम स्वरूप शुद्ध विदेशी उधार में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे यह भी स्पष्ट है कि शुद्ध विदेशी भुगतान में वृद्धि होने से और भी उधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी, जब तक कि इस प्रकार की वृद्धि निर्यात में समवृद्धि अथवा आयात में समहास के द्धारा विस्थित न हो जाय। इस प्रकार विचार करने पर यह कोई संयोग की वात नहीं जान पड़ती कि इस समय की अधिकांश विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को अपने औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तथाकथित ऋणी की स्थिति से गुजरना पड़ा हो। इस वृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका भी प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक एक ऋणी राष्ट्र था।

यदि भूत में कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था दीर्घकालिक ऋणी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी, तो क्या ऐसा कोई कारण है, जिससे कि भविष्य में भी वह ऐसे राष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करती रहे। प्रयोग के तौर पर इसके कई उत्तर दिये जा सकते हैं। एक वात विल्कुल स्पष्ट है कि अधिकांग अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उन्तत अर्थ-व्यवस्थाओं से इतनी पिछड़ी होती है कि उन्हें विश्व-वाजार में प्रतियोगिता के चलते क्षति उठानी पड़ती है। फलतः वे अपने को आयात-आधिवय के लिए सुग्राही बना लेती हैं, जिससे उन्हें विदेशों से निरन्तर उधार लेना पड़ता है। इसका दूसरा उत्तर यह है कि आजकल की अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएं वाह्य भुगतान की अल्पकालीन समस्या की अपेक्षा विदेशों आधार के दीर्घ-कालीन आशय अथवा अपने आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अधिक चितित रहती हैं और स्वर्ण के विकय अथवा विदेशी अनुदान के द्वारा निर्यात से अधिक आयात का वित्त-प्रवंधन अधिक-से-अधिक अल्पकाल में ही सम्भव है। दीर्घकाल में अधिकांग अल्प-

विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए यह सम्भव नहीं है। अतनः आग यह मर्वत्र स्वीकार किया जाता है कि अल्प-विकसित देशों में आर्थिक विकास को अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के मुक्त प्रवाह के सयोग पर नहीं छोड़कर उन्हें पूर्नीनर्माण तथा विकास-सम्बन्धी विश्वे वैक एवं अन्य संस्थाओं, जिनका उद्देश्य उदार शतों एवं तकनीकी आधार पर दीर्ध-कालीन विकास-सम्बन्धी ऋण देना है, ढारा आयोजित तरीके से सहायता देनी चाहिए ! इस प्रकार के आयोजित बहुराष्ट्रीय ऋण के लेन-देन का लाभ यह है कि इससे पूँजी-सम्पन्न राष्ट्रों को साज्ञाज्यवादों के विश्वेष नाम से सम्बोधित हुए बनैर विदेशी ऋण देने का प्रोत्साहन मिलता है तथा पूँजी-विषन्न राष्ट्रों का परस्परागत राजनीतिक बंधनों के भय से मुक्त होकर तथा अत्यधिक राष्ट्रीय मितव्यियता की आवश्यकता के वगैर ही विदेशों से उद्यार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

उपर्युवत रूपरेखा होरा एक प्रारूपिक अस्प-विवसित अर्थ-व्यवस्था एव प्रारू-पिक विकसित अर्थ-व्यवस्था में विभेद करने के लिए कुछ लाभदायक अभिलक्षणों का पता लग जाता है, यद्यपि कि इनमें से कुछ वास्तविक रूप में अविकसित अर्थ-व्यवस्थाएं दोनों की बीच की सीमारेखा पर अवस्थित होती है।

विकास के सरचनात्मक निर्धारक तत्व

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की मापनीय अभिव्यक्तियों को देख लेने के पत्रचात् अब हम इन अभिव्यक्तियों के अध्र.स्य कारणारमक तत्वों का एक आम ढाचा तैयार कर सकते हैं। इसका एक मात्र उद्देश्य किसी भी आधुनिक समाज में आर्थिक विकास के प्रतिरूप तथा गति को प्रभावित करने वाले कुछ तकनीको कारणों की सामान्य प्रकृति एव महत्व के सम्बन्ध में प्रारम्भिक पर्यवेक्षण करता है। जिन आधारभूत निर्धारक तत्वों की यहा पर व्याख्या की जायेगी, वे विकसित तथा अल्प-विकसित दोनो प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं में, यद्यपि स्पष्टतः अधिक था कम बल के साथ, लागू होते है।

श्रम-संख्या

एक 'सबृत' व्यवस्था समभी जाने वाली किसी भी अयं-व्यवस्था की वास्तविक आय मूलतः श्रम-सख्या, पूंजी के कोप तथा टैक्नोलॉजिकल प्रगति के तक-नीकी सम्बन्ध पर निर्भर करती है। पूंजी के कोप तथा टैक्नोलॉजिक की स्थिति की दिया हुआ मानकर हम आर्थिक विकास में श्रम के महत्व पर अपना ध्यान दे सकते है। इसे मोदाहरण स्पष्ट करने के लिए मान लिया जाय कि Y=राष्ट्रीय निपज, N=श्रम सख्या और H=श्रम की औसत उत्पादकता है। तो हमें निम्नाकित सुल्याक प्राप्त होने हैं —

- (1) राष्ट्रीय निपज : Y=H.N
- (2) श्रम-संख्या : N = Y/H
- (3) श्रम की उत्पादन-क्षमता : H=Y/N

यहां Y पूर्ण रोजगार से संभाव्य निपज, N पूर्ण नियुक्ति रहने पर श्रम की संख्या तथा H टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित कुल निपज एवं कुल श्रम का अनुपात है।

उपयुं कत तुल्यांकों से स्पष्ट है कि यदि स्थिर श्रम की उत्पादन-क्षमता की तुलना में नियुक्त श्रम-संख्या में वृद्धि हो अथवा यदि स्थिर श्रम-संख्या की तुलना में श्रम की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो, तो राष्ट्रीय निपज में वृद्धि हो सकती है। यदि श्रम एवं निपज का अनुपात प्राविधिक दृष्टि से निश्चित हो, तो हमें श्रम-संख्या में वृद्धि के साथ-साथ निपज में वृद्धि का सहजतम उदाहरण मिलता है। किन्तु श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का लाने वालों की संख्या में वृद्धि कर जटिल स्थिति उत्पन्न कर देती है। क्योंकि यदि सम्पूर्ण जनसंख्या (केवल श्रमिकों संख्या ही नहीं) में सम्पूर्ण निपज से तीव गित से वृद्धि होती है, तो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के चलते कुल निपज में वृद्धि के परिणामस्वरूप भी प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय के रूप में आर्थिक प्रगित नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक प्रगित के लिए उपज में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता (H) में भी वृद्धि अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में अपुष्य वात यह है कि यदि संस्कृति द्वारा निर्धारित (जैसे काम एवं अवकाण के बीच चुनाव) कुल जनसंख्या का वह अंग, जो कार्य करने के लिए तत्पर तथा इच्छुक है, दिया हुआ है तो राष्ट्रीय निपज में वृद्धि की गित अन्य वातों के साथ-साथ नियुक्त श्रम की मात्रा एवं गृण, यानी उत्पादन-क्षमता पर निर्भर करती है।

वास्तविक पूंजी का कोष

आर्थिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व वास्तविक पूँजी की उप-लब्ध मात्रा है। वर्तमान संदर्भ में 'पूँजी' शब्द से उन मानव-कृत उत्पादन के भौतिक

^{1.} उदाहरण के लिए, मान लिया कि Y=40 मिलियन डालर (स्थिर मूल्य पर) N=40 मिलियन श्रमिक एवं प्रति वर्ष प्रति श्रम की इकाई कुल मनुष्य घंटे 2000 (प्रति वर्ष 50 सप्ताह और प्रति सत्ताह 40 घंटे की मान्यता पर)। तव $Y/N=40,000/40 \times 2,000=4/8=0.5/$ यदि प्रति सप्ताह औसत काम के घंटे 40 से अधिक थे तो प्रति मनुष्य घंटे (H) निपज 0.5 से भी कम होगा। साथ ही, वास्तविक वेरोजगारी N के मूल्य कमी ला देगी और इस प्रकार Y के मूल्य में भी जब तक कि H में वृद्धि द्वारा उसकी विस्थित नहीं हो जाती।

साधनो का बोध होता है, जो साधारणत. भौतिक उपभोग से णुद्ध उत्पादन के अधिक हो जाने के फलस्वरूप, यानी घनात्मक वास्तविक बचत एव निवंस निवेश के परिणामस्वरूप समुपस्थित होने है। राष्ट्रों के औद्योगीकरण में पूँजी-सचय का ऐति-हासिक दृष्टि से अपूर्वतया इतना निणंगात्मक स्थान रहा है कि इसने यदि इनकी सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को नही, तो कम-मे-कम इनकी उत्पादन-प्रणाली को 'पूँजी- / वादी' या 'चक्रदार' नाम से विख्यात कर दिया है। पूँजी के कोप-परिवर्तन के प्रभाव के पृथक्करण के लिए, श्रम की पूर्ति को स्थिर मान सेना सुविधाजनक होगा।

अब निम्नलिखित सम्बन्धों पर विचार करना सम्भव होता है .-

- (4) राष्ट्रीय निपज : Y==fK
- (5) पूँजी का कोप . K=Y/f
- (6) पुँजी की उत्पादिता f=Y/k

यहा पर K वास्तिविक पूँजी तथा f पूँजी औमत उत्पादिता है। (4) से (6) तक उपयुंक्त सम्बन्ध वास्तिविक पूँजी या पूँजी की उत्पादिता अथवा दोनों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निपज में वृद्धि की सैद्धान्तिक सम्भावना को स्पष्ट करते हैं। यदि पूँजी की उत्पादिता (f) को प्राविधिक रूप से दिया हुआ मान लिया जाय, तो निपज में वृद्धि का एक तरीका पूँजी के वास्तिविक कोप में वृद्धि है। अब स्वाभाविक प्रश्न यह होता है कि क्यो किमी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूँजी के कोप में 5 प्रतिशत की दर से तथा किमी बिकसित अर्थ-व्यवस्था में पूँजी के कोप में 5 प्रतिशत की दर से तथा किमी विकसित अर्थ-व्यवस्था में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होती है। इस प्रश्न का सर्वोत्तम तरीके से जवाब बचत की प्रवृत्ति, जो पूँजी की पूँत्ति का प्रतिनिधित्व करती है तथा विनियोग की प्रवृत्ति जो पूँजी की माँग एव पूर्ति के आम निर्धारक वत्व सर्वज्ञान है, किन्तु विशोपत अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में ऐच्छिक बचत की न्यूनता को सपूरित करने में बलात् बचत (उदाहरण के लिए बजट के आधिक्य, विनिधान की प्राथमिकता, मितव्यियता-नियतन, अनिवार्थ के लिए बजट के आधिक्य, विनिधान की प्राथमिकता, मितव्यियता-नियतन, अनिवार्थ

मुख लोग गुढ विनियोग की धारणा को विस्तृत बनाने के लिए इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य एव सफाई के कार्यक्रम द्वारा श्रमिको की उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि, निर- धरता को कम करने के लिए शिक्षा की सुविधाओं मे विस्तार तथा प्राविधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि पर व्यय को भी रखना उचित समभते हैं। उदा- हरण के लिए देखिए, ट्वंटियेथ सेनचुरी फड द्वारा 1955 ई० मे प्रकाशित एन० एस० वृत्तानन एवं एच० एस० एलिस की पुस्तक एप्रोचेज टूइकानामिक डवलप- मेट। किन्तु हम लोगो के अर्थ मे इस प्रकार के व्यय से प्रत्यक्ष रूप मे पूँजी- संचय नहीं होता।

वचत-पत्र-कार्यक्रम, अंतःप्रशासनीय उधार तथा विदेशी विनिमय नियंत्रण) के द्वारा तथा निजी निदेश को पूरित करने में सरकारी निदेश की संभावनाओं को स्वीकार करना चाहिए।

टेक्नोलॉजिकल अग्रवस्तिता

टेवनोलॉजी अंतिम आंतरिक निर्धारक तत्त्व है, जिसकी व्याख्या इस प्रारंभिक पर्यवेक्षण में की जायगी। व्यावहारिक अर्थपूर्ण ढंग से टेवनोलॉजी की व्याख्या करने के लिए इसकी अभिव्यक्ति श्रम-निपज अनुपात तथा पूँजी-निपज अनुपात जैसे कुछ प्राविधिक प्राचलों के रूप में सुविधाजनक होगी। इन दोनों गुणकों में से किसी में हास का तात्पर्य आर्थिक क्षेत्र में टेवनोलॉजिकल प्रगति होगा; क्योंकि श्रम-निपज अनुपात अथवा पूँजी-निपज अनुपात में हास से श्रम अथवा पूँजी की जीसत उत्पादकता में वृद्धि का बोध होता है। इसे (3) तथा (6) समीकरणों के पुनःसूत्रीकरण के द्वारा निम्नांकित प्रकार से दिखलाया जा सकता है:—

(7) (1/H) = (N/Y) (श्रम-निपज अनुपात)

(8) 1/f) = (K/Y) (पूंजी निपज अनुपात)

अन्य वातों के समान रहने पर, श्रम-निपज अनुपात में ह्रास (श्रम की उत्पादकता में वृद्धि) अथवा पूँजी-निपज अनुपात में ह्रास (पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि) के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय निपज में वृद्धि होती है। अब इस अवसर पर एक दिलचस्प प्रथन यह होता है कि किन शक्तियों के परिणामस्वरूप निम्नतर श्रम-निपज अनुपात तथा पूँजी-निपज अनुपात से श्रम एवं पूँजी की उच्चतर उत्पादकता का बोध होता है ? विशुद्ध टेक्नोलॉजिकल शब्दों में इस प्रश्न का जवाब देना अधिक आकर्षक जान पडता है, किन्तु मानवीय प्रयोजनों, वाजारगत दशाएँ, आयोजित कियाएँ तथा अन्य अन्योन्याश्रयी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस आकर्पण का संवरण अनिवार्य हो जाता है। तदनुसार, श्रम-निपज अनुपात में वीर्घकालिक ह्यास के लिए अत्यधिक श्रम-विभाजन, श्रम के बदले अन्य साधनों के प्रतिस्थापन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सुविधा, श्रम वचाने के साधनों का अधिकाधिक अंगीकरण मजदूरी की उच्च गति, जनसंख्या की मन्द वृद्धि आदि शनितयों के सम्मिश्रण की उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जहाँ तक पूँजी-निपज अनुपात में दीर्घकालिक हास को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजिकल तथा अन्य भवितयों का सम्बन्ध है, पूँजी बचाने वाले अन्वेपण तथा नवीन कियाएँ, पूँजी की अधिक टिकाऊपन वाली संरचना, ऊँची दीर्घकालीन व्याज की दर, अधिक पूँजी प्रधान से कम पूँजी प्रधान उद्योगों की ओर संरचनात्मक-स्थानान्तरण तथा अन्य उत्पादक साधनों के बदले पूंजी के प्रतिस्थापन की दीर्घकालीन लोच विशेष रूप से उल्लेखनीय है। टेक्नोलॉजिकल प्राचलों में ये दीर्घकालिक परिवर्तन या तो, जैसा कि मार्क्स और शुम्पीटर का विचार है, प्रधानतया स्वतत्र प्रकृति के हो सकते है, या जैसा कि परम्परागत विश्लेषण से स्पष्ट है, मुस्यतः अभिप्रेरित प्रकृति (बाजारगत दशाओ, जिनमे सापेक्ष साधनो के मूल्य भी सम्मिलित है) के हो सकते है।

बाह्य निर्धारक 💢 🗸

आतरिक विकास के दो आधारभूत मौलिक निर्धारक तत्त्व किसी राष्ट्र के निर्यात की क्षमता तथा पूँजी के आयात-सम्बन्धी उसकी योग्यता एव इच्छा हैं। इनसे पहला निर्धारक दीर्धकाल में निर्णायक होता है, क्योंकि लगातार आयात आधिवयाँ (यानी राष्ट्रीय निपज में गुढ़ योग) के भुगतान की योग्यता अततागत्वा किसी राष्ट्र की उस क्षमता पर निर्भर करती है, जिसके कारण वह प्रतियोगात्मक लाभदायक व्यय से दूसरे राष्ट्रो द्वारा अपेक्षित वस्तुओ एव सेंबाओ का उत्पादन एव निर्यात कर सकता है। दूसरा निर्धारक किसी राष्ट्र के औद्योगीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में, जबिक आवश्यक आयात के भुगतान के लिए उसकी निर्यात की क्षमता तकनीकी दृष्टि से सीमित होती है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।

भाधुनिक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार के परिवर्तियों का घरेलू आय एव घरेलू उत्पादकता पर विरोधात्मक प्रभाव पड़ता है। वयोकि निर्मात का घरेल आय पर स्फीतिक, किन्तु घरेलू उत्पादकता पर अवस्फीतिक प्रभाव पडता है जबकि आयात का घरेलु आय पर अवस्फीतिक तथा घरेलू उत्पा-दकता पर स्फीतिक प्रभाव पडता है। अतएव, विशोपत ऐसी स्थिति मे, जब हम स्फीति एवं असतुलन के बगैर स्थायी दिकास को प्राप्त करने एव बनाये रखने की सन्भावनाओं में अभिरुचि रखते हैं, तब हमें विदेशी व्यापार के दोनों, गुणक एव उत्पादकता प्रभाव, की आँच करना महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार की विस्तारपूर्वक जाँच आगे चलकर की जाएगी। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जहाँ तक अल्प-विन सित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, यदि अर्थ-व्यवस्था को बगैर निरन्तर मुद्रास्फीति एवं असंतुलन की हलचल के दीर्घकालिक विकास की ओर अग्रसर होना है, सी विदेशी व्यापार का गुणक-प्रभाव उसके उत्पादकता प्रभाव का अवश्य ही अतिक्रमण करेगा। आधुनिक विश्लेषण से हमे यह भी जात हुआ है कि पूर्ण रोजगार सम्बन्धी-सस्थापक मान्यता को अवश्य छोड़ देना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण रोजगार एवं अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सतुलन की प्रक्रिया को समभाने के लिए आय, न कि मूल्य-यत्र, का अध्ययन अनिवार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक परि-स्थितियों मे व्यापार की शर्तों एवं मूल्य लोच की परम्परावादी पूर्वधारणा की जगह थायात की सीमांत प्रवृत्ति, निर्यात-श्राय अनुपात, भाषात-श्राय अनुपात, निर्यात-प्रधान तथा आयात-प्रधान घरेलू उद्योगो की उत्पादकता तथा अन्य गैर-मृल्य-सम्बन्धी कारणो े अधिकाधिक विश्लेषण पर जोर दिया जाएगा।

विदेशी ऋण का, चाहे यह प्रतिकूल-भुगतान-संतुलन का परिणाम हो अथवा पूँजी के स्वतःप्रेरित आयात का, दीर्घकालिक महत्त्व इस वात में है कि ऋणी देण ऋण के रूप में प्राप्त रकम का उत्पादक तरीके से प्रयोग करें, जिससे कि उसकी घरेलू वास्तविक आय में उसके ऋण के वास्तविक दायित्व से अधिक वृद्धि हो। राष्ट्र अपने आयात के आधिक्य को इस प्रकार पूरा कर सकते हैं या नहीं, यह केवल उनके आयात की प्रवृत्ति पर नहीं, वरन् अन्य राष्ट्रों के विदेशों को उधार देने की इच्छा पर निर्भर करता है। किन्तु ऋणी राष्ट्र इस प्रकार अपने उत्पादक साधनों को विकसित करने में सफल हो जाते हैं, तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के इतिहास से स्पष्ट है, वे अंततः घाटेवाला एवं ऋणी राष्ट्र नहीं रहकर आधिक्य वाला एवं ऋणवाता राष्ट्र वन जाएँगे। जहाँ तक अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले राष्ट्रों का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह से वे ऋणवाता एवं उधार देने वाले राष्ट्रों के रूप में नहीं, वरन् ऋणी एवं उधार लेने वाले राष्ट्र के रूप में ही लाभान्वित होंगे।

दूसरी ओर विदेशी उधारदान का दीर्घकालीन महत्त्व विदेशी अर्जक परिसंपत्ति के व्याह बनाने की सम्भावना में है, जिससे इनके शुद्ध अर्जक से अंततः आयात-आधिक्य की प्रिष्ति की जा सके। इस सम्भावना को एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था के ऋणदाता की स्थिति L=E-M+R के रूप में व्यक्त करके स्पष्ट किया जा सकता है। इसके L मुद्ध विदेशी उधारदान, R पूँजी खाते में मुद्ध विदेशी प्राप्तियाँ और E तथा M पहले की ही तरह कमणः वास्तविक निर्यात तथा आयात हैं। यह समीकरण यह वतलाता है कि यदि शुद्ध विदेशी प्राप्तियाँ बहुत कम हैं, जैसा कि विदेशी उधारदान की प्रारंभिक स्थिति में संभवतः होता है, तो विदेशी उधारदानों में वृद्धि के लिए निर्यात-आधिक्य की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मौलिक रास्ता नहीं है। यदि विदेशी उधारदान में इस प्रकार वृद्धि हो जाती है, तो ऋणदाता राप्ट्र, आगे या पीछे, पूँजी-खाते में विदेशों से अधिक रकम अर्जन करेगा (यानी R में वृद्धि होगी)। पुन: जैसा कि उपर्युक्त समीकरण से स्पप्ट है, यदि पूँजीगत खाते में गुद्ध विदेशी प्राप्तियाँ विदेशों में प्रचलित उधारदान से अधिक है, यानी R 7 L हैं, तो आयात निर्यात से अधिक हो सकता है, यानी M 7 E । इस सम्बन्ध में यह कल्पना करना कोई कठिन काम नहीं है कि यदि ग्रेट निटेन प्रथम युद्ध के पूर्व तक विश्व का महान् ऋणदाता राष्ट्र नहीं होता, तो उसके औद्योगिक विकास का स्वरूप सम्भवतः कुछ दूसरा ही होता । यदि ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्र, जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध के परि-ू णामस्वरूप अपनी विदेशी सम्पूर्ण अथवा अधिकांश अर्जक सम्पत्ति को स्रो दिया है, इस प्रकार की विदेशी सम्पत्ति को पुन: संचित करना चाहते हैं, तो उनके लिए लगातार निर्यात-आधिवय प्राप्त करना एवं उसे बनाये रखना तथा व्यापाराधिक्य के वरावर अथवा कम रकम विदेशों में उधार देना अधिकाधिक मात्रा में आवश्यक होगा। इसके परिणामस्वरूप प्रचितित उधारदान के अतिरिक्त पूँजीयत खाते मे जी विदेशी प्रास्तियाँ होगी, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आयात-आधिक्य की पूरा करने में प्रयोग किया जा जर सकता है।

इस रपरेखा के बाद, अब हम लोग अधिक उचित रीति से, गम्भीरतापूर्वक एवं ब्यवहृत रूप में अधिक महत्त्वपूर्ण तरीके से आर्थिक विकास की प्रकृति एव प्रक्रिया का विश्लेषण करें।

अध्याय ३

विकास की सामाजिक अंष्ठतम गति

विकास-सम्बन्धी कार्यकम तैयार करने के लिए, सर्वप्रथम निर्देश के किसी केन्द्रीय मानक, यानी निर्देश के सामान्य आधार के रूप में आर्थिक विकास के किसी आदर्श अभिसूचक की आवश्यकता होती है। अतएव, इस अध्याय में विकास की सामाजिक श्रेण्ठतम गित की धारणा एवं निर्धारण की गवेपणा की जायगी। विकास की दर के इस लक्ष्य को एक वार स्पण्ट रूप से परिभाषित और निश्चित कर लेने के बाद इसे केवल परिष्कृत एवं कार्यान्वित करना ही रह जाता है। इस अध्याय में विकास की सामाजिक श्रेण्ठतम गित की व्याख्या स्पण्टतः निम्नलिखित संदर्भ में की जायगी—(क) जीवन-मान एवं जनसंख्या की वृद्धि में सम्बन्ध, तथा (ख) बढ़ती हुई जनसंख्या की आर्थिक आवश्यकताओं एवं विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था की टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी सम्भावनाओं के वावजूद प्रगत्ति की आदर्श गित को प्राप्त करने तथा वनाये रखने के लिए आवश्यक पूँजी-संचय की गित।

जनसंख्या की बृद्धि एवं जीवन-मान

किसी भी अर्थ-व्यवस्था में जनसंख्या एक ही साथ उपयोगिता-संतुष्टि का अंतिम विषय तथा उपयोगिता-निर्माण की एक मौलिक शर्त है। जनसंख्या की यह दुहरी विशेषता उपभोक्ता एवं उत्पादक के रूप में आर्थिक मनुष्य के दुहरे कार्य में निहित है। उपभोग करने वाली जनता के रूप में जनसंख्या उच्चतम जीवन-मान की आकांक्षा रखती है। कार्यकारी शक्ति के रूप में जनसंख्या इच्छित उच्च जीवन-मान को प्राप्त करने के लिए उसका आर्थिक आधार प्रस्तुत करती है। अत्रप्त, उपभोक्ता के कल्याण एवं श्रम की उत्पादकता दोनों के दृष्टिकोण से जनसंख्या की वृद्धि एवं जीवन-मान के सम्बन्ध का विश्लेषण अनिवार्य है।

नियोजनीय जनसंख्या

पहले इस वृहत् प्रक्रन, िक क्यों समय एवं स्थान के साथ-साथ (क) जनसंख्या की वृद्धि की दर, तथा (ख) दी हुई कुल जनसंख्या एवं नियोजनीय जनसंख्या के अनुपात में अंतर पाया जाता है, के कारणों की व्याख्या से प्रारंभ किया जाए। जनसंख्या के आकार में 'प्राकृतिक वृद्धि' (आप्रवास और उद्ययनास को छोड़कर) जनम-दर के मृत्यु-दर से अधिक होने पर निर्भर करती है। ये उपर्युक्त दरें स्वयं आर्थिक तथा

गैर-आधिक कारणों के सम्मिथण से प्रभावित होती है। जन्म-दर को प्रभावित करते वाल तस्त्रों में जनसंख्या-विशेषज्ञ साधारणतः निम्नलिखित का उल्लेख करते हैं विवाह की औसत आयु, प्रसूति-विद्या की स्थिति, सतित-निग्रह का ज्ञान एव प्रयोग, गृप्त तथा प्रकट गर्भपात, सरकार द्वारा पारिवारिक सहायता, पारिवारिक बहुजननता, प्रति-व्यक्ति वास्तिवक आय, पारिवारिक आय पर करो का बोभ एव वश्चों के लिए भविष्य में आधिक अवसर । जहाँ तक मृत्यु-दर का प्रश्न है, यह निम्नलिखित तस्त्रों से प्रभावित होती है—जनसख्या के घनत्र की मात्रा (स्वायत्त साधनों की तुलता में जनसप्ता), विकित्सा-विज्ञान एव जन स्वास्थ्य-विज्ञान की स्थिति, युद्धों की आवृत्ति (अतर्राष्ट्रीय तथा गृह-युद्ध), प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी, अकाल और स्वास्थ्य-वीमा की पद्धित ।

यद्यपि जनाकिकीय निर्धारक अनेक है, तथापि अर्थशास्त्र की दृष्टि से जन-संख्या मे वृद्धि की अर्थपूर्ण व्याख्या इस संग्ल मान्यता मे पाई जा सक्ती है कि जनसङ्या में वृद्धि की दर निम्नलिखित रूप लेती है —

$$\frac{\wedge P}{P} = B \left(\frac{P}{K} \right) - D \left(\frac{P}{C} \right), \tag{1}$$

जिसमे △P/P जनमच्या मे वृद्धि की दर है, B जन्म की दर, D मृत्यु की दर, K/P प्रति-व्यक्ति पूँजी का कोप, C/P प्रति-व्यक्ति उपभोग के साधन, B (P/K) प्रजनन की क्षमता जो इस मान्यता पर आधृत है कि जन्म-दर मे प्रति-व्यक्ति पूँजी के कीम के ठीक विपरीत परिवर्तन होता है। (पूँजीगत साधनो तथा पूँजीगत उत्पादो की माना जितनी ही अधिक होगी, उतना ही अधिक एक औसत परिवार का भुकाव 'वच्चे के वजाय एक नई मोटर' को पसद करने की ओर होगा) और D (P/C) जनसंख्या का यनस्व है, जो इस मान्यता पर आधृत है कि मृत्यु-दर मे प्रति-व्यक्ति उपभोग के माधनों के ठीक विपरीत परिवर्तन होता है।

अव इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि कुल जनसंख्या का एक निश्चित भाग क्यों मदा कार्य करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहता है ? इसका उत्तर विभिन्न सामाजिक एव आर्थिक कारको पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में निम्निलिखित कारकों का उल्लेख किया जा सकता है। समुदाय का श्रम एवं विश्राम के श्रीच चयन, पारिवारिक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएँ, सामाजिक स्तरण, सम्पत्ति-सम्बन्ध, वच्चो एवं स्त्रियों के श्रम पर वैद्यानिक प्रतिबंध, कार्य करने के लिए प्रोत्माहन, उत्तराधिकार, एवं मृत्यु-कर और जलवायु-सम्बन्धी स्थिति। इन्हीं कारकों के परिणामस्वरूप किसी एक अर्थ-व्यवस्था में श्रम-शक्ति कुल जनसंख्या का मामान्यतः आधी तो किसी दूसरी में एक-तिहाई हो सकती है। माधारणतः जो अर्थ-व्यवस्था जितनी ही अधिक श्रीशोगिकृत होती है, वहाँ की श्रम-शक्ति कुल जनसंख्या के अनुपात में उतनी ही कम

होती है। वयोंकि एक अत्यधिक औद्योगीकृत समाज एक कम आद्योगीकृत समाज की अपेक्षा एक बड़े अवकाश-प्राप्त वर्ग के सरण-पोपण में समर्थ होता है।

सरलता के लिए इन सभी अधःस्य प्रभावों को एक गुणक के रूप में लिया जाय जो श्रम एवं विश्राम के वीच समाज के चुनाव का मापन करता हो । इस प्रकार का गुणक नियोजनीय श्रम-शक्ति को कुल जनसंख्या से सम्वद्ध करता है । यदि समाज का श्रम एवं विश्राम के वीच चुनाव नियोजनीय श्रम-शक्ति (N) एवं कुल जनसंख्या (P) के वीच एक स्थायी अनुपात (α) निश्चित करता है, तो $N/P=\alpha=$ स्थायी होता है । इस सम्बन्ध से श्रम-संख्या की वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्ति होती है—

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{\alpha \Delta P}{N} = \frac{\alpha \Delta P}{\Delta P} = \frac{\Delta P}{P}$$
 (2)

समीकरण (2) के द्वारा निर्धारित श्रम-संख्या में वृद्धि की दर ही विकास की श्रेण्ठतम सामाजिक गति-रूपी भवन के निर्माण के विश्लेपणात्मक कार्य करती है। यदि जनसंख्या का आकार समीकरण (1) में वतलाये गये तरीके से निर्धारित होता हो, तथा समीकरण (2) के अनुसार श्रम-शक्ति एवं कुल जनसंख्या का अनुपात स्थायी हो, तो श्रम-संख्या के आकार में जनसंख्या में वृद्धि की दर के अनुसार ही वृद्धि होगी। जनसंख्या द्वारा आकांक्षित जीवन-मान नामक एक और विश्लेपणात्मक आधार है। अब इस दूसरे आधार की व्याख्या की जाय।

प्राप्य जीवन-स्तर

जीवन-स्तर साधारणतः प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय से मापा जाता है, किन्तु यहाँ इसकी व्याख्या एक सीमित अर्थ में की जा सकती है। चूँिक अन्तिम विग्रलेपण में, प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय श्रम की औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है, अतः जीवन-स्तर से प्रति-परिवार के 'कमासुत' की वास्तविक आय का बोध होता है। श्रम की उत्पादकता का यह दुहरा कार्य इस वात को दुहराने से कि श्रम की उत्पादकता ($\mathbf{H} = \mathbf{Y}/\mathbf{N}$) श्रम की औसत आय का भी प्रतिनिधित्व करती है, से सुगमतापूर्वक स्पष्ट हो जाता है। इन दोनों की वास्तविक अनुरूपता किसी मूर्त्त समाज की सांस्थानिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। इस सम्वन्ध में महत्त्वपूर्ण वात यह है कि प्रत्येक स्थान तथा समय में श्रम की औसत उत्पादकता 'कमासुत' की उच्च अथवा निम्न जीवन-स्तर की चरम तकनीकी औचित्य को निर्धारित करती है।

व्यवहारत:, उच्च जीवन-स्तर की आकांक्षा का तात्पर्य, उत्पादन के तरीकों में इस प्रकार की उन्नित की आकांक्षा करना है, जिससे श्रम की प्रति इकाई निपज, यानी श्रम की औसत उत्पादकता में वृद्धि हो। टैक्नोलॉजी की दृष्टि से एक पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था, मूलत:, अपने प्राचौगिक पिछड़ेपन को दूर कर ही यथार्थ रूप में उच्च जीवन-स्तर की आकांक्षा कर सकती है। मान लिया कि इस प्रकार की कोई

अर्थ-व्यवस्था अपनी प्राद्यौगिक प्रगति के द्वारा, थम की औसत उत्पत्ति में निम्न-लिखित दर से वृद्धि कर सकती है—

$$\frac{\Delta \mathbf{H}}{\mathbf{H}} = \mathbf{h} \tag{3}$$

जिसमे H पूर्ण नियुक्त श्रम एव निपज के अनुपात को स्पष्ट करता है। तव h > 0 का तात्पर्य बदता हुआ जीवन-स्तर, $h \ge 0$ का घटता हुआ जीवन-स्तर तथा h=0 ना स्थायी जीवन-स्तर से है। जीवन-स्तर के ये तीनों ढिंचे उत्पादन मे वृद्धि की दर एव जनसंख्या में वृद्धि की दर एव जनसंख्या में वृद्धि की दर में अन्तर पर निर्भर करते है। इस प्रकार, प्राप्य जीवन-स्तर जनसंख्या एव उत्पादकता पर निर्भर करता है। अब हुम लोग 'विकास की सामाजिक श्रेष्टनम गिन' की संकल्पना को सुलभाने की स्थिति में है।

सामाजिक श्रोटितम गति की संकल्पना

पूर्ववर्त्ती विश्वरण को ध्यान में रखते हुए वास्तियक आय में यृद्धि की दर को, जिसे सामाजिक दृष्टि से श्रेट्तम समभा जाता है, एक वढती हुई जनसंख्या की पूर्ण रोजगार एवं वढते हुए जीवन-स्तर की आत्मिनिष्ठ इच्छा की प्रतिविभिवत करने के बावजूद, कोकेनन (Cockaigne) के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि वर्तमान सदर्भ में, विकास की सामाजिक श्रेट्ट्तम गति वढ़िमान श्रम-संख्या की पूर्ण रोजगारी एवं श्रम की उत्पादकता की वढती हुई प्रवृत्ति के अनुरूप निपज में वृद्धि की अधिकतम गति का निर्देश करती है। इस प्रकार की अधिकतम विकास की प्राप्ति एवं इसे बनाये रखना पूँजी-सचय के समान दर की विद्यमानता पर निर्भर करता है। इसके परिणामस्वरूप श्रम की पूर्ण रोजगारी की आकाक्षा एवं पूँजी के बचत की आकाक्षा में एक प्रकार के सम्भावित संघर्ष का आभास होता है। इस प्रकार के आगय के सम्बन्ध से आगे चलकर व्याख्या की जायगी। इस बीच, प्रथम सन्तिकट मान के रूप में "हम लोग विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम दर को नियोज्य श्रम-

Y
$$(1+y)=H (1+h) N (1+n)$$

Y + yY= $(H+hH) (N+n N)$
= $HN+HnN+hHnN+hHnN$
y= $(nHN/Y)+(hHN/Y)+(hnNH/Y)$

^{1.} मान निया कि Y=HN, जिसमे Y शुद्ध राष्ट्रीय निपन, H श्रम की श्रीसत उत्पादकता एवं N श्रम की सहया है। इससे यह स्पष्ट होना है कि \triangle Y=H \triangle N+N \triangle H । पुन y= \triangle Y/Y, h= \triangle H/H तथा n= \triangle N/N मानने पर निम्नलिखित प्राप्त होता है .—

H संख्या में वृद्धि की दर एवं श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के योग के रूप में मान सकते हैं :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta N}{\Delta N} + \frac{\Delta H}{H} \tag{4}$$

जिसमें $\triangle Y/Y$ निपज में वृद्धि की अधिकतम दर है, जो उपर्युक्त वर्णित जनसंख्या में वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप है। समीकरण (4) से यह स्पष्ट होता है कि प्रति इकाई निपज के नियुक्त श्रम की मात्रा को कम करने के लिए श्रम की उत्पादकता ($\triangle H/H$) की दर के ऊँची होने तथा उत्पादक रोजगार में खप जाने योग्य श्रम-संख्या($\triangle N/N$) में वृद्धि की दर के ऊँची होने पर प्राप्य अधिकतम लक्ष्य की दर भी ऊँची होगी।

 $Gm = \triangle Y/Y, n = \triangle N/N$ तथा $h = \triangle H/H$ मानकर समीकरण (4) में अंतर्गस्त परिमाणों की सोदाहरण व्याख्या निम्नांकित प्रकार से की जा सकती है :

यदि n=0.01, h=0.04, तो Gm=0.05

(विकसित अर्थ व्यवस्था)

यदि n=0.015, h=0.02, तो Gm=0.035

(मध्यवर्ती अर्थ-व्यवस्था)

यदि n=0.02, h=0.005, तो Gm=0.025

(अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था)

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कोई अर्थ-व्यवस्था श्रम की उत्पा-दकता में वृद्धि की दर (h) को अधिकाधिक वनाकर तथा श्रम-संख्या में वृद्धि की दर (n) को न्यूनतम बनाकर वास्तविक रूप में विकास की ऊँची दर को लक्ष्य के रूप में अपना सकती है। किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए इसका आगय यह है कि यदि इसकी श्रम-संख्या दो प्रतिभत की दर से वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या की वृद्धि के अनुरूप, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तरह 5 प्रतिभत की वृद्धि की ऊँची दर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय श्रम की उत्पादकता में के प्रतिभत की जगह तीन प्रतिभात की वृद्धि है। इससे हम उत्पादन एवं जनसंख्या के सम्बन्ध पर पहुंचते हैं, जिसका अन्तर जीवन-स्तर को निर्धारित करता है।

उत्पादन बनाम जनसंख्या

समीकरण (4) से यह महत्त्वपूर्ण आशय स्पष्ट होता है कि प्रति 'कमासुत' के जीवन-स्तर Standard of living per "bread-winner") में दीर्घकालिक सुधार के

इसमें से अंतिम पद h n को उपेक्षित लघु प्राप्ति समभक्तर छोड़ने पर y = n + h होता है, जो हम लोगों के विकास की सामाजिक श्रेब्ठतम गति की धारणा y = Gm का प्रतिनिधित्व करता है।

निए श्रम-सख्या में वृद्धि की दर से नियंत्र में अधिक वृद्धि अनिवार्य है। यह आशय निम्निलिखित परिवर्तित समीकरण से स्पष्ट हो जाता है:

$$\frac{\Delta H}{H} = \frac{\Delta Y}{Y} - \frac{\Delta N}{N}, \tag{5}$$

जिसमें जैसा कि पहले बतलाया गया है, △H/H गत्यात्मक परिस्थिति में जीवन-स्तर का माप है। समीकरण (5) को जीवन-स्तर की तीनों प्रवृत्तियों के रूप में निम्नाकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है.

यदि Gm—n 'O, तो h O (बढता हुआ जीवन-स्तर) यदि Gm—n = O, तो h = O (स्वायी जीवन-स्तर) यदि Gm—n O, तो h O (गिरता हुआ जीवन-स्तर)

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि जीवन-स्तर (प्रति परिवार पोपण करने बाले) में दीर्घकालिक सुधार निएज में युद्धि की दर (Gm) को बढ़ाकर या जनसंस्या की वृद्धि की दर (n) को कम करके या दोनों के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही ये जनसंख्या की बृद्धि एवं उत्पादन से वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ कटिन प्रश्नों को भी प्रस्तुत करने है जो दीर्घवालिक जीवन-स्तर को निर्धारित करते हैं।

उदाहरण के लिए. यदि कोई अर्थ व्यवस्था ht+1> (Gm-n) के रूप में कालगत विषमता की तरह, चालू निपज एवं जनसंद्या की प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित जीवनस्तर की अपेक्षा अधिक ऊचे जीवन-स्तर की आवाक्षा करती है, तो इसे जनसंद्या की वृद्धि की दर को कम करने तथा उत्पादन में वृद्धि वी दर को बढ़ाने के बीच चुनाव की व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ना है। वहान सहसमें में हमें

यो ही विदव-जनसस्या-सम्मेलन (इटली, अगस्त, 1954) में सम्भवत आणावादी एवं निराणावादी विचार धाराओं के बीच ध्रुवात विरोध था। निराणावादी विचारधारा के लीग यह भयानक आणका व्यक्त करते थे कि न्यूकलीप विज्ञान की महान आणाओं के वावजूद विद्यं की जनसंख्या में कदाचित इसके साधनों से अधिक वृद्धि होगी। इसके विपरीत आणावादी विचारधारा के लीग केवत यह तक देने थे कि यदि आपके जूने आपको तम कर रहे है, तो छोटे जूनों के उपयुक्त बनाने के लिए अपने अगूठें को काटने के मूर्वतापूर्ण उपाय के बावजूद, अपने बड़ें पैरों के लिए अदे अगूठें को काटने के मूर्वतापूर्ण उपाय के बावजूद, अपने बड़ें पैरों के लिए अंडे जूने ही बयो न खरीदे जाए ? [देखे, जापान, मार्च, 1955 ई० के रोरन जैकू (Riron Keizaigalau) (इकॉनामिक स्टडिज क्वाटलीं) में प्रकाशित एम० टार्ची एवं के० अकमासु का ए रिपोर्ट ऑन दि बर्डें पापुलेशन कानफेंस।] निराणावादी विचारधारा के लिए देखें, मई, 1955 ई० के रिक्यू ऑफ इकानामिकस एवं स्टेटिक्स में एचं० एचं० विखाई का 'सम नोट्स ऑन पोपुलेशन एवं लिखिंग लेबुल्स'।

जनाधिक्य की समस्या के निदान के सम्बन्ध में माल्यस एवं मानसे के बीच संस्थापक विवाद की वात याद आती है। केन्स ने भी इस मतभेद की ओर संकेत किया था। माल्यस-मार्क्स-विवाद के सम्बन्ध में केन्स की पूर्व उद्धृत टिप्पणी की ध्यान में रखते हुए अधिक अनुभूतिपूर्ण तरीका यह जान पड़ता है कि जनसंख्या की समस्या पर, विशेषतः जीवन-स्तर के संकुचित अर्थ में, दो ओर से आक्रमण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसके लिए अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि पर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए तथा जनसंख्या की वृद्धि की दर को नियंत्रित करने के लिए दीर्षकालीन प्रयास करना चाहिए।

हैरोड के विकास की प्राकृतिक दर

अव यहां हैरोड के विकास की प्राकृतिक दर की तुलना विकास की सामाजिक श्रेंक्टतम गित से लाभदायक जान पड़ती है। हैरोड ने अपनी प्राकृतिक दर की परिभाषा इस प्रकार से वी है: "प्राकृतिक दर प्रगित की वह दर है, जिसे जनसंख्या की वृद्धि एवं टेक्नोलॉजिकल प्रगित सम्भव बनाती है तथा जो निपज की उस रेखा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके प्रत्येक बिन्दु पर सभी प्रकार के उत्पादकों की यह संतोप होता है कि वे श्रम एवं विश्वाम के बीच उचित संतुलन स्थापित कर रहे हैं।" इसके अतिरिक्त, वह अपने प्राकृतिक दर की धारणा से अनैच्छिक वेरोजगारी को अलग कर देते हैं जिससे प्राकृतिक दर से बढ़ने वाली अर्थ-व्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार की स्थित रहती है। अंततः, हैरोड यह सुभाव देते हैं कि दीर्घकाल में विकास की कोई भी दर प्राकृतिक दर से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे 'अधिकत साध्य' विकास की दर की संजा दी है। उ

हरोड ने एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था का विचार किया है जिसमें विकास की प्राइन-तिक दर (यानी जनसंख्या की वृद्धि एवं टेक्नोलॉजिकल प्रयति के अनुरूप दर) में

^{1.} केन्स एसेज इन वायग्राफी, पु॰ 107-8।

^{2.} डायनिमक इकानामिक्स, पृष्ठ 87

^{3.} देखें इनकी "दी रेट आफ इंटरेस्ट" एवं अन्य, पृष्ठ 160। डब्लू० फेलनर इस महत्व को विल्कुल भूल जाते हैं, जब वे इस वात की णिकायत करते हैं कि हैरोड के अर्थ में विकास की प्राकृतिक दर कोई निष्चित परिमाण नहीं हैं; क्योंकि विकास की कोई इस प्रकार की अनन्य दर नहीं है, जिसे प्राकृतिक कारण सम्भव बनाते हों। (देखें फेलनर का मैकमिलन, न्यूयार्क, 1951 ई० में प्रकाणित मनी, ट्रेड एण्ड इकानामिक ग्रोथ में 'दि कैंपिटल आउट-पुट रेशियो इन डायन-मिक इकानामिकस'। तथापि, फेलनर की आपत्ति हैरोड के प्राकृतिक दर की अस्पष्ट प्रकृति से है। यदि हैरोड ने अपने विकास के प्राकृतिक दर का निर्धारण स्पष्टत: अधिक निश्चित प्राकृतिक कारणों के सम्बन्ध में किया होता, तो इसकी अधिकांश अस्पष्ट प्रकृति दुर हो गई होती।

विकास की प्रमाणित दर से कम होने की प्रवृति पाई जाती है। विकास की प्रमाणित दर वह दर है, जो वचाने वालो की इच्छा एवं विनियोवताओं के लाभ के परियोजन के अनुहर होती है और, तब वे इसके लिए निदान प्रस्तावित करते हैं। दूसरे खब्वों में वे एक ऐसी विकासत अर्थ-व्यवस्था का वर्णन करते हैं, जिसमें पूँजी-संग्रह जनसंख्या में वृद्धि की अपेक्षा अधिक बढता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हैरोड के प्राकृतिक दर की धारणा विकासत पूँजीवादी की व्यवस्था की दीर्घकालिक अस्थरता (विशेषत अधोमुखी) के कारणों के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। "श्रीमंत्री रॉबिन्सन ने प्राकृतिक दर के प्रयोग को इस आधार पर चुनौनी दी है कि हैरोड हारा अवेब्छित स्थिति के ठीक विपरीत अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है"।"

प्रमोग के प्रश्न के अतिरिक्त भी हैरोड के प्राकृतिक दर की धारणा स्वयं कई कारणों से सित्य्धारमक है। प्रथमत उनके अनुसार यह अजत जनसच्या की यृद्धि पर निर्भर करती है जबकि श्रम एव विश्राम के बीच समुदाय के चुनाव की ओर उनका सकेत सम्पूर्ण जनसच्या के बदले श्रमस्त्या वा सुभाव देता है। इस विद्यति में भी हैरोड को श्रम-सच्या में वृद्धि वा निर्धारण ऊपर दिये गये समीकरण (2) के श्राधार पर करना पडता। दूसरा, हैरोड तकनीकी सुधारों की प्रकृति एव प्रभाव, जिन पर उसकी प्राकृतिक दर अगत निर्भर करती है, को श्रनिदिष्ट ही छोड देते हैं। श्रम वचाने वाले आविष्कारों को मनमाने ढण से पूँजी वचाने वाले तकनीकी के समानायंक रूप में परिभाषित कर, हैरोड एक स्थायी श्रम-निपज अनुपात एव एक स्थायी पूँजी-निपज अनुपात का अनुष्यान करते हुए जान पडते हैं। इस प्रकार वे कहते हैं कि "भेरी धारणा यह नहीं है कि आविष्कार पूर्व परिभाषित अर्थ में प्रधानतः श्रम बचाने वाले होते हैं।" अकन्तु, केवल उन्ही आविष्कारों को, जो पूँजी

शिक्ष प्रकार, श्रीभती रॉबिन्सन स्पटल एक पूँजी-विपन्न विश्व को ध्यान में रखते हुए हैरोड के एक-पक्षीय प्रयोग की आलीचना करती है। इनके अनुसार "कोई भी समुदाय, जिसकी एकमात्र समस्या यह है कि उसके पास आवश्यकता के लिए सभी प्रकार से पर्याप्त पूँजी है, को वास्तव में अधिक चिन्ता नहीं करनी पडती। अतएव, हमें भी इनकी कठिनाइयों को याद कर कप्ट नहीं उठाना चाहिए।" (देखें इनकी 'दी रेट ऑफ इन्टरेस्ट, एव अन्य, पूष्ठ 161)। फिर भी श्रीमती रॉबिन्सन हैरोड के प्राकृतिक दर की धारणा से असहमत नहीं होकर केवल इसके प्रयोग से असहमत है।

^{2.} डायनामिक इकानामिक्स, पुच्छ 26-7 ।

पूर्व उद्धृत, पृष्ठ 28 ।

प्रयोग करने वाले होते हैं, श्रम वचाने वाला समफता एक निर्यंक पुनरित है। 1 इसका कारण यह है कि हैरोड के श्रम वचाने वाले आविष्कारों की परिभाषा की आशाय के ठीक विपरीत, निपज की प्रति-इकाई अधिक पूँजी के प्रयोग के वगैर भी निपज की प्रति-इकाई श्रम में कमी हो सकती है, या दूसरे शब्दों में, प्रति-इकाई श्रम के निपज में वृद्धि हो सकती है। इस विरोधी विचार का कारण यह है कि श्रम वचाने वाली तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप निपज में सदा वृद्धि होती है और इस प्रकार श्रपने हर (y) में वृद्धि के द्वारा यह पूँजी-निपज अनुपात (K/Y) को घटा देता है। इस प्रकार हमें केवल पूँजी प्रयोग करने वाले तकनीक से ही श्रम-वचाने वाले तकनीक को उपस्थित नहीं करना चाहिए।

फिर भी, यदि पूँजी-निपज अनुपात में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बाव-जूद श्रम-निपज अनुपात को तकनीक की दृष्टि से स्थायी माना जाय, जिससे कि N/Y = B = Fस्थर हो, तो निपज में श्रम-संख्या में वृद्धि की दर से ही वृद्धि होनी चाहिए यानी

$$G_{n} = \frac{\triangle Y}{Y} = \frac{\triangle N/B}{N/B} = \frac{\triangle N}{N} = n.$$
 (6)

इस प्रकार समीकरण (6) द्वारा दिया गया Gn बढ़ती हुई श्रम-संख्या को पूर्णतया नियुक्त रखने के लिए आवश्यक हैरोड के विकास की प्राकृतिक दर की धारणा के विरुक्त सन्निकट जान पड़ता है।

किन्तु यदि Gn हैरोड के प्राकृतिक दर के सिन्तकट है तो यह हमारे अर्थ में 'सामाजिक श्रें ज्वतम दर' से कम है। क्योंकि, यद्यपि हैरोड की प्राकृतिक दर पूर्ण रोजगार की गारंटी प्रदान करती है, तथापि यह बढ़ते हुए दीर्घंकालिक जीवन-स्तर (प्रति परिवार पोषण करने वाले के) को स्वीकार नहीं करती। जीवन-स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सुस्पष्ट परिवर्त्ती के निपेध का प्रधान कारण हैरोड की स्थायी श्रम-निपज अनुपात की मान्यता है। किन्तु यदि श्रम-निपज में दीर्घंकाल में Ht=Ho(1+h)t, के अनुसार कमी होती है (यानी यदि श्रम की औसत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है) तो अन्यया-अवश्यंभावी तकनीक मूलक वैरोजगारी को दूर करने तथा जीवन-स्तर में दीर्घंकालिक सुधार के लिए समीकरण (4) के अनुसार किपज में Gm की दर में वृद्धि अनिवार्ध है। तकनीकी प्रगति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाली श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की दर (h) की प्रस्तावना से हैरोड की प्राकृतिक दर हमारे सामाजिक श्रों जितन गित को दर के समरूप हो जाती है। इससे

इस आलोचना के सम्बन्ध में देखें सन् 1954 ई० के ओसाका युनिवर्सिटी इन्स्टी-च्यूट ऑफ सोशल एण्ड इकानामिक रिसर्च के 'स्टिङ्ज इन ग्रोथ इकानामिक्स' (वाई० टाकता द्वारा संपादित) में वाई० टाकता का 'ए रिपलीकशन आन ग्रोथ रेट्स।'

Gn == Gm के हो जाता है। अस्पष्ट रूप में व्यक्त किए जाते के वावजूद हैरोड के विकास की प्राकृतिक दर की धारणा जनमख्या एव तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के सम्बन्ध में अन्तदृष्टि प्रदान करने तथा उसके प्रामाणिक दर के साथ-माथ, वृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था के दीर्धकालिक अस्थायित्व के सम्बन्ध में प्रकाण डालने के लिए महत्वपूर्ण है।

अपेक्षित पूँजी-सचय

यद्यपि विकास की सामाजिक थेप्टनम दर हमे जनसम्या के पूर्णंतर रोजगार एव अच्छे जीवन की आकाक्षाओं के अनुरूप प्रगति की दिशा को वतलाती है, फिर भी यह स्वय इस बात को स्पष्ट नहीं करती कि इस प्रकार की प्रगति बास्तव में प्राप्त की जा सकती है तथा इसे लगातार बनाये रखा जा सकता है अथवा नहीं । अब इस स्थान पर अपेक्षित पूँजी सचय के सम्बन्ध में विचार करना अनिवार्य है । यदि समीकरण (4) हरा व्यक्त विकास की सामाजिक थेप्टनम दर समाजशास्त्रीय एव तकनीकी ढंग से दी हुई हो, तो पूँजी सचय की अपेक्षित दर को निर्धारित करना समय एवं आवश्यक है । यह आवश्यक इसलिए है कि बढ़ती हुई थम-सख्या को सिंग्जत करने तथा वृद्धिमान जीवन-स्तर को प्राप्त करने के लिए पूँजी के बढ़ते हुए कोप की आवश्यकता होती है । यह सम्भव इसलिए है कि अपेक्षित (मानी हुई) वास्तविक पूँजी की मात्रा का निपज से कुछ निश्चित सम्बन्ध होता है । यदि सामाजिक थेप्टनम विकास के लिए आवश्यक पूँजी-सचय की दर निर्धारित हो जाती है, तो अगला तार्किक प्रथन यह हो सकता है कि क्या इस दर तथा वांछित उपभोग के सभावित त्याग पर जनसंख्या सचत की पूर्ति करने के लिए योग्य एव इच्छुक है अथवा नहीं ।

अपेक्षित निवेश-अनुपात

सामाजिक श्रेष्ठतम विकास के लिए आवश्यक पूँजी मे वृद्धि की दर को निर्धारित करने के लिए पहेले पूँजी-निपज के अनुपात को स्पष्ट करना आवश्यक है। वास्तविक पूँजी के लिए K तथा निपज के लिए Y मानने पर एक निश्चित मात्रा में निपज के उत्पादन के लिए अपेक्षित वास्तविक पूँजी की मात्रा को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है K-by, जिसमें b पूँजी-निपज अनुपात है, जिसमे

अपने "डायनिमक इकानामिक्स" (पृ० 87) में हैरोड़ इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का उनका अपना उत्तर यह है कि निपज में पृद्धि की प्राकृतिक दर के अनुरूप विनियोग की दर बचाने वालों की इच्छाओं के अनुरूप हो भी सकती है अथवा नहीं भी। अतएव, वे GnCr=अथवा в के लिखते है जिसमें Gn प्राकृतिक दर, Cr अपेक्षित पूँजी-निपज अनुपात तथा ड बचत अनुपात हैं।

तकनोकी प्रगति एवं/अथवा सापेक्ष साधन मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिवर्तन होता है। उपर्युक्त सम्बन्ध से यह स्पष्ट होता है कि यदि सामाजिक श्रेष्ठतम निपज में ΔY से वृद्धि होती है तो पूँजी में भी निश्चय ही $\Delta K = b\Delta Y + Y\Delta b$ ्मात्रा के वरावर वृद्धि होगी। इसमें $Y\Delta b$ निपज के किसी भी स्तर और इस लिए अपेक्षित अतिरिक्त वास्तविक पूँजी की मात्रा पर परिवर्तनीय पूँजी-निपज अनुपात के सम्भावित प्रभाव को व्यक्त करता है। विकल्पतः हम यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक श्रेष्ठतम निपज $\Delta Y = \Delta K/b + Y\Delta b/b$ मात्रा तक विस्तार-क्षम्य है। अत्यव यदि किसी अर्थ-व्यवस्था को Gm की दर से, यानी सामाजिक श्रेष्ठतम दर से वदना है, तो पूँजी में भी निश्चित रूप से Gm की दर से ही वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि K = bY से तथा सरलता के लिए $Y\Delta b$ पद को छोड़ देने से निम्नलिखित प्राप्त होता है—

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{b\Delta K}{K} = \frac{b\Delta Y}{bY} = \frac{\Delta Y}{Y} = Gm, \tag{7}$$

जिसमें $\triangle K/K$ पूँजी में वृद्धि की अपेक्षित दर है, जो बचतकारों की अभि-वृद्धि से सम्बद्ध नहीं भी हो सकती है।

समीकरण (7) के द्वारा दिये गये पूँजी में वृद्धि की अपेक्षित दर को सुपरिचित बचत एवं विनियोग सिद्धान्त के अनुरूप बनाने के लिए △K/K=Y मानकर उपर्युक्त दर को अपेक्षित विनियोग अनुपात के रूप में सुगमता-पूर्वक निम्न लिखित प्रकार से दिखलाया जा सकता है—

$$\frac{I^{r}}{V} = \frac{\triangle K}{V} = \frac{YK}{V} = Yb = Gmb, \tag{8}$$

जिसमें $1^r/\gamma$ अपेक्षित विनियोग अनुपात को व्यक्त करता है। यदि अपेक्षित विनियोग अनुपात समीकरण (8) के द्वारा दिया गया हो, तो जनसंख्या को निश्चय ही वास्तविक आय की इसी दर से वचत करनी चाहिये, यानी —

$$S^r = \frac{1^r}{V} = Gmb, \tag{9}$$

जिसमें s' अपेक्षित वचत-अनुपात को ब्यक्त करता है। s' को सामाजिक श्रेण्ठतम विकास के लिए आवश्यक वास्तविक पूँजी की पूर्ति का मापक मानकर समीकरण (7) से (9) के परिचालन-सम्बन्धी महत्व को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

यदि Gm=0.05, b=3, तो s^r=0.15 (विकसित अर्थ-व्यवस्था) यदि Gm=0.035, b=3.5, तो s^r=0.1225 (मध्यवर्त्ती अर्थ-व्यवस्था) यदि Gm=0.025, b=4, तो s^r=0.10

अरूप-विकसित अर्थ-स्थवस्था

उपपूंक्त मॉडली में सामाजिक घेंप्टतम विकास की दर का अलग-अलग मूल्य, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, जनसंख्या एव उत्पादकता में वृद्धि की दर मे विभिन्नता की मान्यता के परिणामस्वरूप है। जहाँ तक पूँजी-निपज अनुपात के मूल्य मे विभिन्नता का सम्बन्ध है, ये इस मान्यता पर आधृत हैं कि आर्थिक विकास की स्थिति जितनी ही उच्चतर होती है, निपज की प्रति-इकाई के लिए अपेक्षित पूँजी की मात्रा उतनी ही कम होती है, या बस्तुत यों कहा जा सकता है कि पूँजी की शीसत उत्पादकता उतनी ही अधिक होती है। इन मान्यताओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को विकास की सामाजिक भेष्टतम पति प्राप्त करने तथा धनाए रखने के लिए स्थायी तौर पर अपनो शुद्ध राष्ट्रीय निपज का 10 प्रतिशत वचाना पडेगा। इसी प्रकार एक विकसित अर्थ-व्यवस्था को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत वचाना पडेगा। इसी प्रकार एक विकसित अर्थ-व्यवस्था को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत वचाना पडेगा। अब स्वासाविक प्रकार यह है कि क्या प्रत्येक प्रकार की अर्थ-व्यवस्था वास्तव में अपेक्षित दर से बचाती है अथवा नहीं। इस प्रकार का उत्तर हम लोग, विश्वेषत एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में हेंग।

अपेक्षित बनाम बास्तविक बचत अनुपात

यदि अधिकाण आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाएँ बास्तव मे अपनी शुद्ध राष्ट्रीय निपज का 3 से 5 प्रतिशत तक बचा सके ती, जैसा कि प्राप्य आंकड़ी से विदित होता है इनके लिए समीकरण (9) मे दी हुई शतों को पूरा करना यथायंतः वडा ही कठित हो जायगा। मान ले कि किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था मे श्रम-संख्या में वृद्धि की दर 2 प्रतिगत तथा थम की उत्पादकता में वृद्धि की दर 🖢 प्रतिगत है। इससे उस अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य यथार्थ, निपज में 23 प्रतिशत सामाजिक श्रेष्ठतम विकास की दर की प्राप्त करना तथा बनाये रखना हो सकता है, जैसा कि उपर्युक्त Gm=0 025 के उदाहरण में दिया गया है। तब समीकरण (9) के अनुसार अपेक्षित वचरा-अनुपात 10 प्रतिशत है। किन्तु पदि सम्बद्ध अल्प-विकसित अर्थ-ज्यवस्था की संस्थानिक एव मनोवैज्ञानिक प्रथि इस प्रकार की है कि यह केवल 5 प्रतिशत ही बास्तविक वचत कर सकती है, तो वहाँ वचत में (s'-s) Y के वराबर कमी होगी। इस मे उ वास्तविक बचत अनुपात को व्यक्त करता है। जब तक बचत मे यह कमी किसी भी प्रकार पूरी नहीं की जाती, तब तक अस्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था पूँजी के अभाव में, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं एवं उत्पादकता के अनुरूप अपनी निपज में 21 प्रतिशत वृद्धि की दर को दीर्घकाल मे बनाये रखने को कौन कहे. प्राप्त करने मे भी समर्थ नहीं हो सकती।

अपेक्षित श्रेच्ठतम विकास की तुलना में पूँची के अभाव की समस्या से

पीड़ित अल्प-िकसित अर्थ-व्यवस्था के समक्ष दो विकल्प हैं—या तो n अथवा और h में अधोमुखी समयोजन द्वारा अपेक्षित निवेश के अनुपात में कभी या संस्थानिक एवं मनौवैज्ञानिक ग्रंथ में उचित परिवर्तन के द्वारा वास्तविक वचत-अनुपात में वृद्धि । इसके अतिरिक्त संभावनाएँ भी हैं । प्रथमतः, एक विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध वाली विकृत अर्थ-व्यवस्था में पूँजी के आयात द्वारा अपेक्षित एवं वास्तविक वचत अनुपात के अन्तर को समाप्त करने की सैद्धांतिक संभावना सदा रहती है । द्वितीय, वचत-कर्ताओं की अभिवृत्ति का विचार किए वगैर, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था उद्योगों के संगठन में सुधार-जैसे साधनों की अत्यधिक गतिशीचता, उपकरों के अत्यधिक मानकीकरण, निपज की अत्यधिक एकष्णता, एवं साधनों की अत्यधिक स्थाना-पन्नता के द्वारा पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि (पूँजी की पूर्ति की विपक्षता में) कर सकती है ।

. पूर्वीवत विश्लेपण से विकास की सामाजिक श्रेब्ठतम गति को प्राप्त करने तथा बनाये रखने की तकनीकी संभावनाओं एवं कठिनाइयों के सम्बन्ध में ज्ञान होता है। चूँकि, जनसंख्या तकनीक एवं पूँजी सभी अपने-अपने विकास के स्वतंत्र नियमों का अनुकरण करते हैं, इसलिए यह मानने का कोई भी कारण नहीं है कि विकास की सामाजिक श्रेब्ठतम दर एवं अन्य विकास-दरें, संयोग से अथवा प्रयास के अति-रिक्त, सदा समान होती हैं। ऐसा होने पर इस बात की प्रवल सम्भावना रहती है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी के अभाव में श्रम की उत्पादन-क्षमता बेकार हो जाती है तथा जीवन स्तर मन्द पड़ जाता है।

वचत की पूर्त्ति से पृथक् पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता के विस्तारपूर्वक विवरण के लिए देखें, मेरी पुस्तक "इण्ड्रोडक्शन दू केन्सीयन डायनिवस" एलेन एण्ड अनिवन, लंदन एवं कोलिन्विया यूनिविसिटी प्रस, न्यूयार्क 1956 ई०, पृ० 209 ।

अध्याय 4

पूंजी-संचय एवं उत्पादन-सामर्थ्यं

किसी भी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-सचय ओद्योगीकरण की कुँजी है; क्योंकि पूँजी ही उत्पादन का एकमात्र ऐसा साधन है, जिसमे अनिश्चित प्रसारणीयता का गुण विद्यमान है। पूँजी का अनन्य गुण ही, औद्योगीकरण के लिए भूमि एव ध्रम की अपेक्षा, मुख्य रूप से पूँजी के प्रसार पर निर्मार करने का मूल प्रयोजन है। साथ ही, कोई भी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था पूँजी के सचय का विचार अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए, न कि समर्थ माँग उत्पन्त करने के लिए करती है। विशेषरूप से हम लोग निपज के विकास की सामाजिक श्रेष्टितम दर को वास्तविक रूप में प्राप्त करने एव बनाये रखने के सम्बन्ध में पूँजी-सचय एवं उत्पादन समता के तकनीकी सम्बन्ध पर विचार करेंगे। विचारणीय वस्तु को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए हम लोग हैरोड-डोमर माँडल, जिससे उत्पादन-सामर्थ एवं समर्थ माँग की परस्पर किया निहित है तथा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के पूँकी-संचय के सिद्धान्त का भी आलोचनात्मक तरीके से अवलोकन करेंगे।

क्षमता-निर्माण की प्रक्रिया

किसी भी अर्थ-श्यवस्था की सम्भावित उत्पादन-क्षमता टैक्नोलॉजी की दी हुई सीमाओं के अन्तर्गत, वहाँ पर उपलब्ध सभी उत्पादक साधनों के पूर्ण उपयोग से प्राप्त सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की सम्पूर्ण पूर्ति में निहित होती है। टेक्नोलॉजी में प्राप्त तथा साधनों की खोज से यह बढ़ सकती है, किन्तु इन प्रभावों को पूँजी अथवा श्रम की उत्पादकता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साथ हो, यदि श्रम को दिया हुआ मान लिया जाय, तो उत्पादन-क्षमता पर पूँजी की मात्रा एव गूण के अनन्य फलन के रूप में विचार किया जा सकता है। ऐसा इस मान्यता पर किया जाता है कि श्रम का अभाव प्राप्त उत्पादक पूँजी के पूर्ण उपयोग में कोई बड़ी बाधा उपस्थित नहीं करता है। तब उत्पादन-क्षमता में वृद्धि (क) निवेश के श्रनुपात एवं (ख) निवेश की उत्पादकता के तकनीकी सम्बन्ध पर निर्मर करेगी। अब हमें देखना है कि उत्पादन-क्षमता में वृद्धि इन दोनों के बीच यथावंत. वयों और किस प्रकार निश्चत होती है।

पूजी एवं क्षमता की वृद्धि

यदि समर्थं माँग का दिया हुआ स्तर इतना ऊँचा हो, जिससे कि वर्तमान वास्तिविक पूँजी के पूर्ण प्रयोग को न्यायोचित करार दिया जा सके, तो शुद्ध निवेश (1), यानी वास्तिविक पूँजी में वृद्धि $(1=\triangle K)$ का तात्पर्य निश्चित रूप से उत्पादन-सामर्थ्य में वृद्धि होगी:

$$\triangle Y' = \sigma \triangle K = \sigma I, \tag{1}$$

जिसमें Y' उत्पादन क्षमता, K वास्तविक पूँजी एवं α प्रचलित टेश्नोलॉजी की दर पर निवेश की उत्पादकता है।

निपज की बनाबट एवं उद्योग का संगठन दिया हुआ रहने पर, शुद्ध निवेश एवं सामर्थ्य में निम्नांकित प्रकार का सम्बन्ध होता है:

$$\frac{1}{\mathbf{Y}'} = \delta \tag{2}$$

जिसमें 8 निवंश-अनुपात जिसका, मूल्य एक अर्थ-व्यवस्था से दूसरी अर्थ-व्यवस्था में तथा आर्थिक विकास के एक स्तर से दूसरे स्तर में अलग-अलग होता है। समीकरण (2) में व्यक्त निवंश-अनुपात—वचत-अनुपात जो वचत की पूर्त्त का प्रतिनिधित्व करता है, के ठीक विपरीत पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस अन्तर का महत्व थोड़ी देर बाद स्पष्ट किया जायगा।

समीकरण (1) तथा (2) से हमें उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्त होती है:

$$\frac{\Delta Y'}{Y} = \sigma \frac{1}{Y'} = \sigma \delta = GK, \tag{3}$$

जिसमें GK उस दर को वतलाता है, जिसमें गुद्ध निवेश के द्वारा यदि विनियोग -सम्बन्धी वस्तुओं के उद्योगों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग किया जाय, तो उत्पा-दन-क्षमता का प्रसार किया जा सकता है। समीकरण (3) से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दर में निवेश-अनुपात (8) तथा निवेश की क्षमता ० में वृद्धि के ठीक समान अनुपात में परिवर्तित होने की क्षमता है। यहाँ पर निवेश-अनु-पात पूँजी के परिमाण तथा निवेश की उत्पादकता-पूँजी के गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। समीकरण (3) से यह भी प्रकट होता है कि पूँजी एवं निपज दोनों में समान दर से एवं घातीय ढंग से निम्नलिखित प्रकार से वृद्धि होती है:

$$Y'(t) = Y'oec\delta t,$$
 (4)

$$K(t) = Koeg\delta t$$
 (5)

समीकरण (3) के परिचालन-सम्बन्धी महत्व को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:

यदि $\delta = 0.05$, $\sigma = 0.2$, तो Gk = 0.01 (अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था) यदि $\delta = 0.08$, $\sigma = 0.25$, तो Gk = 0.02 (मध्यतर्ती अर्थ-व्यवस्था) यदि $\delta = 0.12$, $\sigma = 0.5$, तो Gk = 0.06 (विकसित अर्थ-व्यवस्था)

लिये गये पूँजी-निषज अनुपात के घ्युत्कम से लगाया गया है। (अल्प-विकसित अर्थ-घ्यवस्था के लिए K/Y=5, मध्यवर्ती अर्थ-घ्यवस्था के लिए K/Y=4 तथा विकसित अर्थ-घ्यवस्था के लिए K/Y=2 की मान्यता पर $\frac{1}{5}=0.2$, $\frac{1}{4}=0.25$ तथा $\frac{1}{2}=0.5$)। δ के मूल्य का अनुमान इन विभिन्न प्रकार की अर्थ-घ्यवस्थाओं के बचत-अनुपात के यथासभय अनुष्प भी लगाया जाता है। उपयुंक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-घ्यवस्था की उत्पादन-क्षमता अधिक विकसित अर्थ-घ्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है। इसका कारण δ , जो पूँजी के परिमाण को व्यक्त करता है, के साथ-ही-साथ σ , जो पूँजी के गुण को घ्यक्त करता है, की न्यूनता है। अत अब हम उन ठीस कारणों की जाच करनी है, जिनके परिणामस्थरूप एक अल्प-विकसित अर्थ-घ्यवस्था मे निरन्तर निम्न-निवेश अनुपात तथा निवेश की निम्न उत्पादकता पाई जाती है।

यहाँ व के मुख्य का अनुपात तीनो प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए मान

निम्त निवेश-अनुपात

सस्थापक अर्थकाहित्रयों ने यह मान स्विया या कि निपज की रचना इतनी समजातीय होती है तथा उद्योग का संगठन इतना समायोजित होता है कि जो कुछ भी उपभोग में नहीं आता, यानी बचा लिया जाता है, उसका उपयोग सदा पूँजीगत वस्तुओं में बिना किसी किटनाई के किया जाता है। इस सरल मान्यता के आधार पर यह तर्क करना न्याय-संगत जान पड़ता है कि यदि कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था अधिक मितव्ययी होने का प्रयास करे, तो वह पूँजी एवं क्षमता में विकास की गति को तीव्रतर बना सकती है। किन्तु तब हम इस असगत कि कुछ अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में बचत की पर्याप्त उच्च औसत प्रवृत्ति के आवजूद इनमें पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में कमी होती है, को समभने में किकर्तव्य-विमूढ हो जाते है। वास्तव में, बात यह नहीं है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ

इतनी अमितव्यापी होती हैं कि ये वास्तविक आय के रूप में कुछ बचा ही नहीं पातीं, वरन् यह कि कुछ तकनीकी कठिनाइयों के चलते, जिन्हें संस्थापक अर्थ-शास्त्रियों ने अपनी मितव्ययिता के द्वारा प्रगति वाले तर्क में मान्यता के रूप में स्वीकार किया था, बचत की इच्छा के वावजूद उत्पादक उपकरणों में न तो ये विनियोग करती हैं और न कर ही सकती हैं।

उपर्युक्त असंगति के कारणों की व्याख्या के लिए संस्थापक मान्यताओं को समाप्त कर वास्तविक विश्व में निपल की विषमजातीय रचना तथा उद्योग की विपमायोजित संगठन को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य है। एक बार ऐसा मान लेने पर, यह स्पष्ट हो जायगा कि वास्तविक आय के रूप में जो कुछ भी बचाया जाता है, वह सम्पूर्ण पूँजीगत माल के लिए उपयुक्त नहीं होता । दूसरे शब्दों में गैर-जपभोग का आवश्यक रूप से यह आशय नहीं है कि इससे जस प्रकार के मानवीय एवं भौतिक साधनों की उपलिब्ध होती है, जिसका प्रयोग शान्त रूप से सुगमता-पूर्वक पूँजीगत मालों के उत्पादन के लिए किया जा सकता हो । अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में इसका आशय यह है कि यदि वास्तविक आय के रूप में अधिक वचत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमर कसकर भी प्रयास किया जाय, तो भी उप-भोक्ता उद्योगों द्वारा मुक्त श्रम, उपकरणों तथा कच्चे पदार्थों की विशिष्टता के परि-णामस्वरूप अधिक पुँजीगत मालों का उत्पादन सम्भव नहीं हो सकता। निपज की रचना जितनी ही विपमजातीय होती है, उत्पादक साधनों की यह विशिष्टता उतनी ही अधिक होती है ; क्योंकि जब तक उपभोक्ता एवं टिकाऊ वस्तुएँ भीतिक रूप में अलगाने योग्य होती हैं, (जैसे गेहूं एवं मशीन, अगर ये वस्तु सूची के रूप में अलगाने योग्य नहीं है), इनके उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन का साधन ऐसी विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं, जो साधारणतः पारस्परिक रूपांतरण की अवज्ञा करती है। इस प्रकार निपन की विपमांगीय रचना, जो एक आधुनिक आर्थिक समाज की प्रधान विशेपता है, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निवेश अनुपात के वास्तविक वचत-अनुपात से कम होने की असंगत किया की एक मौलिक व्याख्या है। उद्योग का विपमायोजित संगठन इसका एक दूसरा मीलिक कारण है। अब पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में इस बाद वाली अडचन पर विचार किया जाय ।

एक अल्प-विकसित अर्थं-व्यवस्था के औद्योगिक संगठन में निम्नलिखित हठ-धामिताएँ एवं कठिनाइयाँ पाई जाती हैं: प्रथमतः, उपभोक्ता वस्तुओं तथा प्रैजीगत वस्तुओं अथवा कृषि एवं उद्योग के बीच उत्पादक साधनों की सापेक्षिक अगतिशीलता पाई जाती है। साधनों की इस अगतिशीलता के लिए अप्रभावपूर्ण श्रम-विनिमय व्यवस्थाएँ, परिवहन एवं संचार की अकुशन सुविधाएँ और असंगठित पूँजी-बाजार आदि कारण उत्तरदायी हैं। द्वितीय, इस प्रकार की अर्थं-व्यवस्था में बहुत सारे छोटे पैमाने के पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग होते हैं, जिनमें अप्रचलित और प्रायः

आदिमकालीन समझ एव उपकरणों का अयोग किया जाता है। जनाधिक्य में परि-पूर्ण अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सस्ते श्रम की उपलब्धि सुप्रवाही संयत्री एवं उपकरणों के संस्थापन को हतोत्साहित करती है, यद्यपि इन की संस्थापना का व्यय आतरिक अथवा बाह्य साधनो से जुटाया जा मकता है। तृतीय, तीत्र घिमावट एव अप्रचलन के परिणामस्वरूप पूँजी की अगरिमित बरवादी होती है। अल्प-विव-सित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी का टिकाऊपन साधारणत. इस प्रकार का होता है कि इनमें विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में ऊंची दर से पुन स्थापन-व्यय की आव-श्यकता पडती है। इसका कारण यह है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं मे सयत्र एव उपकरण साधारणतया इतने पुराने और धिमे हुए सामानो से बने हुए होते है कि कुल नये विनियोग का अधिकाश पुन स्थापन पर ही खर्च किया जाता है, जिससे पूँजी के कोप से सुद्ध वृद्धि के लिए यहुत कम अथवा कुछ भी बोप नहीं रह जाता। अल्प-विकसित अर्थ-ज्यवस्थाओं मे गृहगुद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ, बडे-बडे अग्निकाट तथा सग्रह की अपर्याप्त सुविधाओं के परिणाम अत्यधिक पूँची की वरवादी एव क्षति के कारण भी विसाई की औसत दर (भीतिक अर्थ मे) अधिक ऊँची होती है। इन्ही कारणों से पूँजीगत माल के उत्पादन की अमता बचत की पूर्ति से कम हो सकती है, यानी S∠s इससे दूसरे प्रकार से यो कहा जा सकता है कि S∠s असमानता पंजीगत मालो की पूर्ति की अपेक्षा मांग के आधिवय को बतलाती है क्योंकि sy पूँजीयत माल की माँग, (1-s) ү' उपभोवता वस्तुओं की माँग, Sү' पूँजीयत माल की पूर्ति तथा (I-S)γ' उपभोक्ता वस्तुम्रो की पूर्ति को बतलाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि $(8-\delta)\gamma' = (1-\delta)\gamma' - (1-\delta)\gamma'$ के। यह इस बात को सूचित करता है कि विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध वाली विकृत अर्थ-व्यवस्था पूँजीगत मालों में कमी को उपभोक्ता वस्तओं की आतरिक पूर्ति के आधिक्य (1-S) y'-(1—S)γ' 7 ० के बदले में इनके आयात के द्वारा पूरा किया जा सकता है। विदेशी व्यापार के अभाव में ठ=S बनाने के लिए निपज की बनावट और या उद्योगकी सरचना को समायोजित करना होगा। किन्तुनिपज की बनावट और उद्योग की सरचना की अति अनुकूल मान्यता के आधार पर भी यदि ठ≕ 8 के होता है, तो निवेश की निम्न उत्पादकता के परिणामस्वरूप पूँजी की वृद्धि की दर श्रीप्ठतम विकास के उद्देश्य से बहुत ही कम होगी। अब ऐसी परिस्थिति में हमे अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निवेश की न्यन उत्पादकता पर विचार करना चाहिए।

निवेश की न्यून उत्पादकता

मोटे तौर पर, मन्द पूँजी-सग्रह एव तकनीकी प्रगति निवेश की उच्च उत्पा-

दक साधनों की तकनीकी प्रगति की प्रोत्साहित नहीं करता है। वास्तव में, यह कुछ व्यंग्यात्मक प्रतीत होता है कि एक अल्प-विकसित ग्रर्थ-व्यवस्था के लिए प्रेजी के गुण में सुधार करना अनिवार्य होता है, किन्तु पूँजी की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि नहीं होने के कारण यह ऐसा शीधतापूर्वक नहीं कर सकती, जबकि किसी विकसित ग्रर्थ-व्यवस्था के लिए ऐसा आवश्यक नहीं होने पर भी पूँजी की मात्रा में सुगमता-पूर्वक वृद्धि के कारण अपनी पूँजी के गुण में तेजी से सुधार कर सकती है। विश्व के सम्पूर्ण अल्प-विकसित हिस्से में उत्पादन के चकदार तरीके का अपर्याप्त प्रसारण उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक एवं उत्तम पूँजी की विद्यमानता के विरुद्ध एक प्रवल मान्यता है। हस्त-प्रचलित औजारों पर निर्भर करने वाली अर्थ-व्यवस्था एवं संचालित उपकरणों पर निर्भर करने वाली अर्थ-व्यवस्था (जैसे पैरों से चलने वाली द्विचकीय गाड़ी बनाम टुक्टर) के बीच उत्पादन-क्षमता के अन्तर की कल्पना करना कठिन कार्य नहीं है। चकीयता का स्तर जितना ही ऊँचा होता है, उत्पादन के अन्य साधनों के साथ प्रयुक्त पूँजीगत साधनों की प्रकृति उतनी ही अधिक स्वनालित होने की होती है। अपर्याप्त चक्रीयता स्वयं उच्च ब्याज संरचना अथवा उपभोग के निर्वाह-स्तर का परिणाम हो सकता है। ये दोनों, मार्शल के प्रचलित शब्दों में, प्रतीक्षा के द्वारा पूँजी के अधिकाधिक प्रयोग को निरुत्साहित करते हैं। अतएव तकनीकी पिछड़ापन एवं मन्द पूँजी-संग्रह अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में निवेश की उत्पादकता को न्यून बनाने वाले मौलिक कारण हैं।

डोमर ने कुछ अधिक विशिष्ट कारणों का सुफाव दिया है जिनमें से कुछ अल्प-विकसित अर्थ-ब्यवस्थाओं में लागू होते हैं। वे नये संयंत्रों को लगाये गये प्रति डालर की उत्पादन-क्षमता (इनके संकैतन के अनुसार) से निवेश के संभावित सामाजिक औसत क्षमता के न्यून होने के लिए श्रम की कमी को एकमात्र सर्वाधिक प्रधान कारण मानते हैं। डोमर र्थ स्पष्टतः एक ऐसी विकसित अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं जहाँ जनसंख्या की वृद्धि धीमी अथवा स्थायी है, जिससे कि निपज के सम्बन्ध में श्रम की पूर्ति इतनी लोचदार नहीं होती है कि श्रम के प्रभाव में पुराने संयंत्रों के उत्पादन में और कमी करनी पड़ती है और इस प्रकार यह नये संयंत्रों के उत्पादन में बृद्धि को खिसका देता है। किन्तु एक श्रव्य-विकसित अर्थ-व्यवस्था, जो स्वभावतः वेकार श्रमिकों से परिपूर्ण होती है, के संवर्भ में हम उसके सर्वाधिक प्रधान कारण को सबसे कम महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं। डोमर के अन्य कारणों— जैसे वह स्थिति जिसमें नये संयंत्र प्रभावोत्पादक माँग के अभाव में पूर्ण क्षमता भर उत्पादन नहीं कर सकते और अन्तिम स्थिति जिसमें जहाँ पर वाजार के लिये नये

कुछ अधिक मार्मिक टिप्पणी के लिए जे० रॉबिन्सन के रेट आफ इन्टरेस्ट, एवं अन्य में नोट्स आन दि इकानामिक्स आफ टेकनिकल प्रोग्रेस देखें।

^{2.} इ० डी० डोमर का पूर्व उद्धृत "इक्सपैन्सन"।

सयतो की प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप पुराने संयंत्र अपना उत्पादन कम कर देते है, कुछ अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थायों में सागू होते हुए पाये जाते हैं। किन्तु इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं को विशेषरूप से निजी उपक्रम के आधार पर विकसित करने वाली अर्थ-व्यवस्थाओं के लिप के व्यवन करना अनिवार्य है क्योंकि उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में जो बृहत एव वृद्धिशील सार्थजनिक निवेश को गुण्य के रूप में सँधारण करती हैं, प्रभावीत्यादक माँग के अभाव के कारण नये समन्नों के पूर्ण क्षमता से कम बिन्हु पर कार्य करने की सभावना बहुत ही कम पाई जाती है।

इस बात को मानने हुए कि सपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए निवेश की उत्पा-दकता (उनका कुल ०) पुराने समंथो की निषज पर नय समयों के प्रतिकूल प्रभाव से घट जाती है, तो जहां तक अल्प-विकसित वर्ष-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, स्वय नयं समयों में विनियोग किये गयं प्रति डॉलर की उत्पादन-क्षमता (उनका अलग-अलग 8) के व्यावहारिक महत्व को कम करना भूल होगी। वयोकि, किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में लिए, पिरामिष्ठ के प्रकार के नये समयों के निर्माण, जाहे अल्पकाल में इनका आय-प्रभाव जो भी हो, का परित्याग औद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए निर्णायक महत्व की बात है। बास्तव में, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रक्षित रूप में निम्न उत्पादन-क्षमता के कारणों की, स्वय नये समयों की प्रकृति एवं मेद के विशेष उल्लेख के वगर, पूर्णरूप से व्याख्या नहीं की जा सक्ती और निवेश अनुपात (३) जितना ही छोटा होगा, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को उत्त संयशे एसं उपकरणों, जो दीर्घकाल में उत्पादन-क्षमता (यानी वः △प्र/1 में अत-निहित बनावट को) में प्रसार करने हैं, के चुनाव में उतनी ही अधिक माव-धानी से काम लेना पटेगा।

पूँजी एव उत्पादकता की आवश्यकता

किसी अर्थ-स्यवस्था के वाछित विकास अयवा स्थायित्व से सम्बद्ध किये वगैर, पूंजी के सम्रह अथवा सम्मह का कोई अर्थ नहीं होता। हैरोड एवं डोमर ने विकसित पूँजीवादी व्यवस्था के सदम में पूँजी-असम्रह एवं दीर्घकालिक स्थायित्व के सम्बन्ध पर उचित हम से जोर दिया है। किन्तु जहा तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, पूँजी-संग्रह एवं निपज को सामाजिक व्येष्टतम वृद्धि के सम्बन्ध पर जोर देना चाहिए। निम्नाकित विश्लेषण के लिए, जैसा कि सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में होता है, हम लोग एक ऐसी स्थित की सकल्पना करेंगे, जिसमें पूँजी को यृद्धि की दर निपज की सामाजिक व्येष्टतम वृद्धि से कम है, यानी Gk ∠ Gm।

GK = Gm बनाने के लिए, निवेश-अनुपात (α) को बढाना या निवेश की उत्पादकता (σ) को बढाना या दोनों को बढाना आवश्यक है। Gk = Gm तथा $Gk = \alpha\sigma$ से $\alpha' = Gm/\sigma$ एवं $\alpha' = Gm/\sigma$ के रूप मे श्रीष्ठतम निवेश-अनुपात एवं

निवेश की श्रेष्ठतम उत्पादकता प्राप्त होती है। इन वाद वाले रूपों के परिचालन-सम्बन्धी महत्व को निम्नांकित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है:

> यदि Gm = 0.05, σ= 0.2, तो α' = 0.25 (श्रेष्ठतम निवेश-अनुपात) यदि Gm = 0.05, α = 0.1, तो α = 0.50 (श्रेष्ठतम उत्पादकता-अनुपात)

इस प्रकार विकास-दर का अधिकतम लक्ष्य 5 प्रतिशत तथा वास्तविक निवेश-उत्पादकता अनुपात के 2 प्रतिशत दिया हुआ होने पर, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को अपने निवेश-अनुपात को 25 प्रतिशत के श्रेष्ठतम अंक तक वढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार विकास की अधिकतम दर के समान रहने तथा वास्तविक निवेश अनुपात के 10 प्रतिशत दिया हुआ होने पर, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को अपने निवेश-अनुपात को 50 प्रतिशत के श्रेष्ठतम अंक तक वढ़ाना होगा, क्योंकि Gk = Gm की विषमता इस वात का सूचक है कि वास्तविक निवेश-अनुपात एवं निवेश-उत्पादकता अनुपात अपेक्षित सामाजिक श्रेष्ठतम विकास से कम है। इसके अतिरिक्त (ठ) अथवा व में वृद्धि का यर्थायवादी प्रयत्न वड़े (ठ) अथवा व के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियों, जिनकी व्याख्या हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, को भी ध्यान में रखेगा।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्प निकलता है कि सामाजिक श्रेष्टतम दर की वृद्धि के लिए एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी पड़ती हैं:

$$Gk = \sigma' \alpha' = Gm = n + h,$$
 (6)

क्योंकि $\operatorname{Gk} \angle \operatorname{Gm}$ से स्पष्ट होता हैं कि पूँजी के अभाव के परिणामस्वरूप संरचनात्मक अपूर्ण रोजगार के बगैर बढ़ते हुए जीवन-स्तर के आधार पर प्रगति के आदर्श मार्ग को प्राप्त करने एवं उसे यथावत बनाये रखने के लिए अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूँजी में वृद्धि की दर बहुत ही कम है।

हैरोड-डोमर मॉडल पर टिप्पणी

हैरोड एवं डोमर¹ के विकास-सम्बन्धी मॉडल विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किये गये हैं और इसलिए इनकी आलोचना मुख्यतः इन्हीं

हैरोड, डायनामिक इकानामिक्स; डोमर का पूर्व उद्घृत 'इक्सपैन्शन एण्ड' इम्प्लायमेंट'।

अर्थ-व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से की गई है। किन्तु हम तोग इनके मॉडल का मूल्याकन अल्प-विकित्त अर्थ-व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट रूप से जानने के लिए करेंगे कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए कौनमी चीज प्रासिंगक है और कौनसी नहीं है।

हैरोड को प्रमाणित दर

अपनी प्राकृतिक दर, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, के अतिरिक्त हैरोड के निर्देश का एक और मापदण्ड विकास की 'प्रमाणित' दर है। इसे ये इस प्रकार परिभाषित करते है: "विकास की प्रमाणित दर प्रगति की वह व्यापक दर है, जो कार्योग्वित करने पर उद्यमकर्ताओं को इस मानसिक स्थिति में छोडती हैं कि वे समान प्रगति को आगे बढाने के लिए तैयार होते हैं।" हैरोड की प्रमाणित दर (Gw) की यथार्थ प्रवृत्ति को देखने के लिए निम्नलिखित रूपों में इसे जानना शनिवाय है:

$$\frac{S}{Y_W} = s =$$
हिश्वर (1')

$$\frac{\triangle K}{\triangle Yw}$$
=Cr = स्थिर (2')

$$\triangle K = 1 = Cr \triangle Yw = sYw, \qquad (3')$$

$$G_W = \frac{\triangle Y_W}{Y_W} = \frac{s}{Cr}, G_W Cr = s.$$
 (4')

जो इस बात की ओर सकेत करता है कि

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{sYw}{K} = \frac{(s/Cr)K}{K} = \frac{s}{Cr}$$
 (5')

यहाँ पर Yw पूँजी ने पूर्ण उपयोग से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय निपज का प्रमाणित स्तर, K पूर्ण उपयोग की स्थिति में शुद्ध पूँजी का कीप, शुद्ध निवेश, अ औसत विषत अनुपात और Cr पूँजी-निपज अनुपात का संतुक्षन मूल्य (औसत == कल्पित सीमात) या हैरोड के शब्दों में 'अपेक्षित पूँजी गुणक' है।

^{1.} फिर भी श्रीमती जै॰ रॉविन्सन एवं आर० आइनर की आलोचनाओं में अल्पितिकासित अर्थ-ध्यवस्थाओं के लिए बहुत सी शिक्षाप्रद चीजें है। (देखें जै॰ रॉबिन्सन का पूर्व उद्घृत मि॰ हैरोड्स डायनिमत्स एवं 'दि रेट आफ इन्टरेस्ट, इद्स'; आइनार का भावें 1952 के अमेरिकन इकानामिक रिध्यू में प्रकाशित 'अडर इम्प्लायमेंट-इक्वोलिवियम रेट्स ऑफ ग्रीथ'।) डायनामिक इकॉनामिकस, एट 82 ।

उपर्युंक्त पद्धित से यह स्पष्ट होता है कि उद्यमकत्ता जतना विनियोग करते हैं, जितना समाज आय की पूर्ण-क्षमता के स्तर पर बचाने को तैयार होता है और यदि निपज में उसी दर से वृद्धि होती है, जिस दर से इस खुद्ध निवेश के परिणाम स्वरूप वास्तिवक पूँजी में वृद्धि उसे होने देती है, तो सम्विन्धित अर्थ-व्यवस्था अपनी वास्तिवक पूँजी का सदा पूर्ण उपयोग करती रहेगी और Gw की अपरिवर्त्ती दर से प्रगति करती रहेगी। जैसा कि समीकरण (5') में अंतभू त है, बचाने वालों की इच्छा के अनुरूप पूँजी में वृद्धि की अपेक्षित दर भी मालूम होती है। समीकरण (4') से यह स्पष्ट होता है कि हैरोड की प्रमाणित दर उत्पादन-क्षमता के उस संतुजित मूल्य की ओर संकेत करती है, जो बचत की पूर्ण क्षमता के प्रयोग के लिए पर्याप्त निवेश को प्रेरित करने के उद्देश्य से आवश्यक है, यानी जो अन्यथा अवश्यंभावी बेकार अथवा अतिरिक्त क्षमता के परिणामस्वरूप ऋणात्मक शुद्ध निवेश को घटित होने से रोकती है। अब हम लोग Gw की दर से उन्नित करने वाली अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी हैरोड के मॉडल का मूल्यांकन, विशेषत: अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के वृष्टिकोण से करेंगे।

1. 'प्रमाणित' दर हैरोड द्वारा दिया गया इस मीलिक प्रश्न का उत्तर है कि विकसित पूँजीवादी व्यवस्था के स्थायी विकास को बनाये रखने के लिए कौन-कौन-सी आवण्यक शर्तें हैं। मानर्स (एवं वाद में शुम्पीटर) ने भी इस प्रण्न को उठाया था तथा इसका उत्तर नैराण्यपूर्ण ढंग से दिया गया था। केन्स ने भी इसे पुनरु-जीबित किया था तथा इसका उत्तर आशावादी तरीके से देने का प्रयास किया था। केन्स की ही तरह हैरोड भी एक ऐसे विश्व की संकल्पना करता है, जिसमें बचाने . की प्रवृति निवेश की अभिप्रेरणा से अधिक होती है और इसलिए जिसमें चक्रीय अवस्फीति एवं दीर्घकालिक गतिरोध की निरन्तर प्रवृति पाई जाती है। किन्तू केन्स के विपरीत हैरोड निम्नलिखित वातों पर जोर देता है (क) उत्पादन क्षमता के प्रभावोत्पादक माँग से अधिक हो जाने का खतरा, (ख) प्रेरित निवेश का प्रवल कार्य और विश्रेषतः (ग) प्रगतिशील संतुलन की अगतिशीलता । यहां याद रखने योग्य वात यह है कि केन्स का तात्पर्य एक दी हुई उत्पादन-क्षमता की तुलना में प्रभावो-त्पादक माँग की अपर्याप्तता से था, जिसकी उत्पत्ति अपर्याप्त स्वतः प्रेरित निवेश की तुलना में वचत की उच्च सीमांत प्रवृत्ति (गुणक के माध्यम) से होती है। साथ ही, वचत एवं विनियोग की समानता से सम्बन्ध केन्स की संतुलन आय केवल स्यैतिक ही नहीं वरन स्थिर भी है, जब कि हैरोड का संतुलन इस अर्थ में गत्यात्मक एवं अस्थिर दोनों हैं कि परिवर्त्त न की सकारात्मक अचल दर होते हुए भी, अव्यवस्थित हो जाने पर, इसमें स्वयं पूर्व अवस्था में पहुंचने की क्षमता नहीं होती।

इन विभिन्नताओं के वावजूद हैरोड के 'प्रमाणित' दर की धारणा केन्स के प्रभावोत्पादक माँग के सिद्धान्त पर पूर्णरूप से आवृत है। वास्तव में, इसे केन्स के

अपर्याप्त प्रभावीत्पादक माँग एव अनैच्छिक सामूहिक वेरोजगार के सदर्भ के वगैर समभा भी नही जा सकता। इस प्रकार हैरोड चकीय अवस्कीति की सभावना की परिकरपना करते है, जो प्रभावोत्पादक माँग की 'जाच एव तृटि' का प्रतिनिधित्व करने वाली विकास की दर (C) के अपेक्षित उत्पादन-क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमाणित दर से निम्न होने के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार, वे दीर्घकालिक गितरोध की सभावना की भी परिकरपना करते है, जो 'प्रमाणित' दर के जनसच्या एव तकनीकी की वास्तविक प्रवृत्तियों के अनुरूप अधिकतम उत्पादन-क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वाभाविक दर (Gn) से अधिक होने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्त होती है। सक्षेप में, हैरोड की 'प्रमाणित' दर औद्योगिकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए पथ्यदर्शक नहीं होकर चक्रीय-विरोधी एव गतिरोध-विरोधी नीतियों की प्रकट करने के लिए विश्लेपण का अस्त्र है।

2 हैरोड की प्रमाणित दर, आवश्यक रूप से श्रम के पूर्ण रोजगार की प्रतिभूति (गारटी) न प्रदान कर, पूँजी के पूर्ण उपयोग की प्रतिभूति प्रदान करती है। यदि बचत अनुपात एव पूँजी-निपज-अनुपात स्वेच्छाचारितापूर्वक पूर्ण रोजगार सम्बन्धी आय से सम्बद्ध हो जाते है, तो भी जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रमाणित दर का तात्पर्य अपर्याप्त प्रभावोत्पादक मांग के परिणामस्वरूप केन्स की वेरोजगारी की ममस्या से है। ठीक इसके विपरीत, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में जिस प्रकार की वेरोजगारी पाई जाती है, उसका निराकरण केवल प्रभावोत्पादक मांग मे वृद्धि के द्वारा उस विन्दु तक नहीं किया जा सकता है, जहाँ उपलब्ध पूँजी के पूर्ण उपयोग का औचित्य दीख पड़ता है। कोई भी दूसरा निष्कर्प हैरोड के इस मौतिक विचार से कि 'केन्सीय रूप मे यह (प्रमाणित दर) बढती हुई अनैच्छिक वेरोजगारी की समावना की सकल्पना करता है, से असगत होगा। विश्व ही, जैसा कि कुछ लेखको ने प्रयास किया है, दैरोड (और डोमर के प्रतिरूप) की 'प्रमाणित' दर पूर्ण रोजगार एव पूर्ण क्षमता दोनो पर ध्यान रखने के लिए अलग उत्पादन-फनन (जिसमे धम

देखें, डायनिमक इॉकनामिक्स पृ० 91, साथ ही रजसं यूनियसिटी प्रेम द्वारा 1955 मे प्रकाशित (आर० ए० सोली द्वारा सपादित) इकानामिक्स एण्ड दि पब्लिक इन्टरेस्ट मे मेरा निवध ग्रोय थियरी एण्ड दि प्रोब्लेम्स आफ इकॉनामिक स्टेबिलाइजेशन'।

हैरोड इस प्रकार की दर को 'विशिष्ट' प्रमाणित दर कहता है। (देखें, उनकी पूर्व उद्धृत पुस्तक 'एन एसे इन डॉयनिमक थियरो')।

^{3.} डॉयनामिक इकॉनामिक्स, पु० 87 ।

⁴ जदाहरण के लिए देखें, नवम्बर, 1953 ई० मे क्वाटलीं जरनल ऑफ इकॉना-मिक्स मे एव० पिलवीन का 'फुल केपेसिटी वर्सेंज फुल इम्पलायमेंट ग्रोथ'।

एवं प्रावासिक अंतर्निहित हों) की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है। नयों कि, प्रमाणित दर के सहयोग से हैरोड की 'प्राकृतिक' दर ही इसे कर सकती है, यानी जब Gw = Gn = G। यहां घ्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि Gw की दर से पूर्ण नियुक्त पूंजी की वृद्धि भी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की संरचनात्मक वेरोज़गारी को, जो बढ़ती हुई उत्पादकता के साथ जनसंख्या की वृद्धि से पूँजी-संग्रह के पीछ पड़ जाने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है, दूर नहीं कर सकती। स्वत:-प्रेरित निवेश का वहिष्करण हैरोड की 'प्रमाणित' दर की धारणा को अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विश्लेपणात्मक ढंग से अपर्याप्त बना देती है। हैरोड स्वत:-प्रेरित निवेश का वहिष्करण शायद वााजरगत अर्थ-व्यवस्था के अस्थायित्व को प्रदिशित करने के लिए करते हैं। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में आय के उच्चावयन पर आधृत लाभ की प्रत्याशा पर निवेश में मनमाने ढंग से विस्तार तथा संक्चन किया जाता है। इसीलिए, श्रीमती जान रॉविन्सन ने स्वीकारात्मक ढंग से कहा है कि श्री हैरोड का मुख्य विपय यह है कि प्रमाणित दर को विशद अवैध-नीतिमय दशाओं में सामान्य रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दसरी और जे० आर० हिक्स का यह विचार है कि 'प्रमाणित' दर से बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था के लिए हैरोड के मॉडल में अत्यधिक अस्थायित्व है। अतएव, इनकी राय में स्थायित्व प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में स्वतः प्रेरित निवेश का प्रयोग आवश्यक है।

3. जो भी हो, सम्बन्ध बात यह है कि हैरोड (और हिक्स भी) स्वतः प्रेरित निवेश को, बचत के केवल उस भाग को, जिसका केवल प्रेरित निवेश अवशोषण नहीं

^{1.} देखें, इनकी दि रेट आफ इन्टरेस्ट, एटसेट्रा, पृथ्ठ 160, n-1 यह चर्चा उन्होंने हैरोड के आशय के सम्बन्ध में टी०सी० शेलिंग के भ्रम के विरुद्ध हैरोड को बचाने के सिलसिले में की थी। (देखें दिसम्बर, 1947 के 'अमेरिकन इकानामिक रिच्यू' में शेलिंग का 'कैपिटल ग्रोथ एण्ड इक्यूलिब्रियम'।) किन्तु हैरोड द्वारा अस्था-यित्व की स्थिति, जो आवश्यक एवं पर्याप्त दोनों है, के स्पण्टीकरण से यह अंतिम भ्रम शायद दूर हो गया होता।

^{2.} दे ब साइकिल, पृ० 60 । यह देखना किठन हो जाता है कि हिक्स की तरह के आत्म-समापन के सिद्धान्त पर आधृत स्वतः प्रेरित निवेश इतना समरूप कैसे हो सकता है कि स्थायित्व प्रदान करने वाले तत्व की तरह कार्य कर सकता है अथवा पूंजी के वड़े एवं वृद्धिशील स्टॉक के अस्थायित्व प्रदान करने के प्रभाव के कारण समरूप रह सकता है, जब तक कि हिक्स का स्वतःप्रेरित विवश स्टॉक से बाहर वाले प्रकार का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता हो । हिक्स के व्यापार चक्र-सम्बन्धी विश्लेपण के इस अन्तिम अस्पष्ट विचार के सम्बन्ध में 1952-53 के खंड XX (1) संख्या 52 के 'रिव्यू आफ इकानामिक्स स्टिडज' में एच० रोज का निवंध 'डिमान्ड सप्लाई एंड प्राइस लेबुल इन मैको डायनिमक्स'।

करता हो, समतोलन करने के लिए माँग का एक साधन मानता है। स्वतः प्रेरित निवेश के सम्बन्ध में यह विचार हैरोड के सुधरे हुए निम्नाकित समीकरण में अंतभू त है: GC=5-k, जिसमें G वास्तिक विकास की वर है, C भूल एवं सुधार पर आधृत पूँजी-निपज-अनुपात, इ वास्तिक आय-स्तर एवं बचत का अनुपात तथा k आय के अस के रूप में व्यक्त स्वत प्रेरित निवेश है। हैरोड अपने प्रमाणित बचत निवेश समीकरण GwCr=5 में स्पष्ट परिवर्तों के रूप में स्वतःप्रेरित निवेश को अलग कर देता है, क्योंकि अशतः वह त्वरक-सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से कार्य-क्षेत्र प्रवान करना चाहता है और अशतः इसलिए कि वह केवल उसी प्रकार के स्वतः-प्रेरित निवेश को ध्यान में रखता है, जो पूर्ति में वृद्धि किये बगैर ही माँग में वृद्धि करते हैं (उदाहरण के लिए शस्त्रीकरण) । उसके अनुसार दीर्घकान में K अवश्य अदृश्य हो जायेगा क्योंकि दीर्घकाल में सम्पूर्ण पूँजीगत व्यय जिस कार्य में प्रयोग किया जाता है उसके लिए न्यायोचित ठहराया जाता है।

4 हैरोड ने उस प्रकार के स्वत प्रेरित निवेश को. जिसे केन्स अधिकाधिक भावश्यक समभने थे, स्वेच्छापूर्वक स्पष्ट कर दिया है। यह है सार्वजनिक निवेश, जो दीर्घकालिक विचारों को ध्यान में रखते हुए पूँजी की सीमात क्षमता को पता लगाने मे राज्य की उत्कृष्ट क्षमता तथा सामान्य सामाजिक लाभो पर आधृत है। आज की अल्प-विकसित मिथित अर्थ-च्यवस्थाओं के विकास में इस प्रकार का निवेश बहुत अधिक व्यावहारिक महत्त्व का है। वास्तव मे, यह निश्चय ही कठिन जान पड़ता है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ, जिनके पास निजी उपक्रम एवं निधि दोनों का अभाव रहता है, किस प्रकार दीर्घकालीन विचारी एवं सामान्य सामाजिक लोगो पर आध्त पर्याप्त सार्वेजनिक निवेश, चाहे वह रूढ अर्थ मे आत्म-समापन बाला हो अथवा नहीं, के बगैर अपनी उत्पादन-क्षमता एवं साधनी की विकसित कर सकता है। साय हो, इस प्रकार की कल्पना उचित जान पडती है कि विकास-जागहक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ अपने स्वतःप्रेरित निवेशः, विशेषतः सार्वजनिक प्रकृति के निवेश का क्षमता-मुलक प्रकृति के दीर्घकालिक कार्यक्रम (जैसे राजपथ, बन्दरगाह, पुल, रेलवे, बाँध एवं प्राकृतिक साधनों के सरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनको उप-योग) मे लगायेंगी। यद्यपि हैरोड के शस्त्रीकरण की तरह के स्वत.प्रेरित निवंश समाप्त हो सकते है, तथापि इस प्रकार के स्वतः प्रेरित निवेश दीर्घकाल में निश्चय ही समाप्त नहीं हो सकते । यदि स्वत प्रीरित निवेश को आत्म-समापन एवं क्षमता-मूलक बनाया जा सके (अमेरिका की T. V. A. की तरह), तो कोई कारण नहीं कि

I. देखें डायनामिक इकाँनासिक्स पृ० 79, जिसमे वह युद्ध के सम्बन्ध में चर्चा करता

^{2.} तर्नव।

^{-3.} जनरल थियरी, पृ • 164।

इसे पूर्ण क्षमता निपज की वृद्धि की दर में, हम लोगों के Gk की तरह सम्मिलित नहीं किया जाय। इस प्रकार हैरोड का 'अपेक्षित पूँजी गुणक' (Cr) प्रेरित निवेश को केवल निपज से सम्बद्ध करता है, अतएव इसका अयोग्य स्टॉक उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले स्वतःप्रेरित निवेश के साथ सम्बन्ध किसी भी उत्पादकता को स्पष्ट नहीं कर सकता । निम्न वचत-अनुपात (s), जो अति अनुकूल मान्यता पर भी पूँजीगत वस्तुओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि पूँजी-निपज अनुपात के (1/Cr) को निजी अथवा सार्वजनिक स्वतः प्रेरित उत्पादक निवेश को सम्मिलित कर ऊँचा रखा जाय।

डोमर की पूर्ण रोजगार-दर

अव हम डोमर के विकास-मॉडल पर विचार करेंगे। उसकी शुद्ध निवेश में वृद्धि की पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी दर की धारणा के विस्तारीकरण द्वारा हम निम्नांकित प्रकार से प्रारम्भ करेंगे:---

$$Y^d = \frac{1}{\alpha}$$
, (1°)
(प्रभावोत्पादक माँग का स्तर)
 $Y^s = \sigma K$, (2″)
(उत्पादक क्षमता का स्तर)
 $Y^d = Y^s$ अथवा $\frac{1}{\alpha} = \sigma K$, (2″)

$$Y^s = \sigma K$$
, (2") (2")

$$Y^d = Y^s$$
 अथवा $\frac{1}{\alpha} = cK$, (3") (संतुलन की स्थित)

$$\Delta \mathbf{Y}^{a} = \frac{\Delta \mathbf{I}}{\alpha}$$
(भाँग की वृद्धि)

$$\triangle Y^s = \sigma \triangle K = \sigma I$$
, (क्षमता की वृद्धि) (5")

$$\triangle Y^d = \triangle Y^s$$
 अथवा $\frac{\triangle I}{\alpha} = \sigma I$, (6") (संतुलन की स्थिति)

$$Y = \frac{\triangle I}{I} = ασ$$
 (7") (frid in all q दि दर)

जो इस वात की ओर संकेत किया करता है कि

$$\frac{\Delta Y^d}{Y^d} = \frac{\Delta I/\alpha}{Y^d} = \frac{\Delta I/\alpha}{I/\alpha} = \frac{\Delta I}{I} = a\sigma$$
(8")

महाँ पर Y शुद्ध राष्ट्रीय आय का स्तरक अथवा पूर्ण रोजगार पर प्रभावोध्यादक माँग को दिखलाता है, को Y' उत्पादन-क्षमता का स्तर या पूर्ण रोजगार पर पूर्ति, I शुद्ध निवेश, K वास्तविक पूँजी, △ वचाने की सीमात प्रवृत्ति और ० पूँजी अथवा शुद्ध निवेश की उत्पादकता है।

इस पद्धति से हमे यह जात होता है कि स्थायी व एवं स्थायी व के दिया हुआ होने पर, यदि बुद्धि अर्थे-व्यवस्था में (4") द्वारा दिये गये मौग पक्ष एवं (5") द्वारा दिये गये पूर्ति पक्ष में इस प्रकार संतुलन स्थापित करना है कि (6") द्वारा विणित पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहे, सो शुद्ध निवेश में r (शुद्ध निवेश में वृद्धि की अपेक्षित दर) अथवा ०० की दर से वृद्धि करनी पडेगी। समीकरण (8°) की तरह इससे यह भी सकेत मिलता है कि आय अथवा मांग मे 🕫 की दर से अवश्य वृद्धि होनी चाहिए। सक्षेप में, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए अर्थ-स्थवस्था की सभीकरण (3") द्वारा वर्णित शतों को अवश्य ही पूरा करना पड़ेगा। डोगर द्वारा जोर दिये गये "निवेश की दुहरी प्रकृति" को ध्यान मे रखना महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि, केन्स ने गुणक सिद्धान्त की तरह △I/I का भाज्य, समीकरण (4") के भाष्यम से अतिरिक्त मांग का सुजन करता है, किन्तु डोमर की मृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था के मॉडल की तरह इसका भाजक समीकरण (5") के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता का सजन करता है। समीकरण (1") में परिवर्ती केवल माँग के एक स्तर का सुजन कर सकता है जबकि समीकरण (5") में यही। परिवर्त्ती, उचित समय में पूँजी में यृद्धि (ΔK) का सूजन कर सकता है। यदि बढती हुई पूँजी के स्टॉक बाली वृद्धि अर्थ-व्यवस्था लगातार पूर्ण-जोजगार को बनाये रखना चाहती है तो उसे वास्ति विक पूँजी में इस वृद्धि (ΔK) के परिणामस्वरूप उत्पादन-क्षमता में वृद्धि $(\Delta Y')$ को निवेश में वृद्धि (ΔI) के परिणामस्यरूप प्रभावोत्सादक माँग में समान वृद्धि $(\triangle Y^d)$ के द्वारा बरावर करना होगा। अब हम लोग डोमर के मॉडल का मुल्यांकन विशेष रूप से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से करेंगे।

1. होमर ने जिस स्थिति पर विचार किया था, वह सारतः वही है, जिस पर हैरोड ने भी विचार किया था। उच्च बचत-अनुपास (α) एव निवेश की उच्च उत्पादकता जो प्राय शुद्ध रूप से हैरोड के पूँजी निपज अनुपात का अध्योन्य है, उस स्थिति की प्रमुख विशेषताएँ है। इस प्रकार यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमे सिद्धांततः एव औसल रूप से प्रभावोत्पादक भाग मे उत्पादन-समला से कम-से-कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है यानी $\mathbf{X}^d \angle \mathbf{Y}^s$ । स्थायी तौर पर $\mathbf{Y}^d = \mathbf{Y}^s$ के लिए, डोमर का

वैकल्पिक आलोचनाओं के लिए देखें आर॰ आइसनर का पूर्व उद्भृत, दिसम्बर, 1947 के अमेरिकन इकाँनामिक रिच्यू में 'कैपिटल इक्सपेन्यन एड इक्यूलिब्रियम', नाई॰ टाकता द्वारा सपादित स्टब्जिइन ग्रोथ-इकानामी।

कहना है कि आय एवं क्षमता दोनों में एक समान दर से वृद्धि होनी चाहिए, यानी $\triangle Y^a = \triangle Y^s$ । सार रूप में यह वही विश्व है, जिसे केन्स ने 'प्रचुरता में निर्धनता' नामक विशेषता से विभूषित किया था। यह उस प्रकार का विश्व है जिस में प्रभावोत्पादक माँग की अपर्याप्तता का अनुभव होता है। वै न्योंकि उच्च वचत-अनुपात अपर्याप्त माँग के चलते वास्तविक निर्धनता का सूचक है, जविक निवेश की उच्च उत्पादकता पर्याप्त क्षमता के परिणामस्वरूप संभाव्य विपुलता का निर्देशक है। डोमर संस्थानिक एवं आनुभविक आधार पर उच्च α एवं उच्च σ की दृढ़ता को तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं और तव α एवं σ के प्रचलित मृत्यों के साथ शुद्ध निवेश की वृद्धि की दर ($\triangle I/I$) में तकनीकी अथवा राजकोपीय समायोजन का प्रस्ताव करते हैं। किन्तु अरूप-विकसित अर्थ-च्यवस्था में निम्न वच्त अनुपत एवं निवेश की निम्न उत्पादकता की समस्या पाई जाती हैं, जिससे यह अवस्फीति के प्रवृत्ति के लिए खुली रहती है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था के संभवतः अपने संस्थानिक एवं मनीवैज्ञानिक ग्रंथी को इस प्रकार से समायोजित करना पड़ता है, जिससे कि $\triangle I/I$ एवं α $C\alpha = r/\alpha$, जिससे $r = \triangle I/I$) के दिये हुये मूल्यों पर वचत-अनुपात में वृद्धि की जाय अथवा $\triangle I/I$ एवं α ($\sigma = r/\alpha$) के दिया हुआ रहने पर निवेश की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उत्पादक के तरीकों में सुधार किये जायँ।

2. डोमर इस वात की संभावना पर विचार नहीं करते कि शुद्ध निवेश की वृद्धि की दर, जिसे ये पूर्ण रोजगार की एक आवश्यक शर्त मानते हैं, स्वयं दीर्घकाल में इस प्रकार के स्थायी प्रभावों को उत्पन्न कर सकती है, जिससे कि संतुलन की अपेक्षित स्थिति $y^d = y^s$ एवं $\triangle y^d = \triangle y^s$ दीर्घकाल तक नहीं बनाई रखी जा सकती है। एक उन्नत अर्थ-व्यवस्था में नवीन किया के द्वारा निवेश-गुण्य (△I) को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास, जिसे डोमर अधिक अधिमान देते थे, गुद्ध निवेश की उत्पा-दकता (८) को बढ़ा सकता है। किन्तु जब तक 'नवीन किया-निवेश' मुख्यतः आय-उत्पादक प्रकृति का नहीं होता, तब तक साथ-ही-साथ क्षमता में वृद्धि किये वगैर यह आय में वृद्धि के अपेक्षित उद्देश्य को विफल बना देता है। इस प्रकार का आत्मघाती परिणाम एक जबरदस्त दीर्घकालीन संभावना है, क्योंकि नवीन किया निवेश के नये अवसरों को प्रस्तुत करने और इस प्रकार नवीन किया-संबंधी निवेश में वृद्धि (ΔI) के साथ-साथ, अतिरिक्त निपज को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक शुद्ध निवेश की रकम को घटा देता है। जहां तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, उपर्यु वत आत्मघाती परिणाम ठीक उलटा हो जाता है; क्योंकि स्फीतिजनक माँग को कम करने के लिए नवीन किया-निवेश में कभी के साथ-साथ निवेश की उत्पादकता में आत्मघाती कमी एवं इसीलिए उत्पादन-क्षमता में कमी हो सकती है।

जेनरल थियरी पृ० 30 । किन्तु, डोमर का विश्व केन्स की तुलना में अधिक कष्टकारक है; क्योंकि पहली पूँजी के वृद्धिशील स्टाकवाली गतिशील व्यवस्था है ।

इसके अधिक यदि नवीन किया-निवेश मे वृद्धि के प्रमत्नो के उपपरिणाम के रूप मे निवंश की उत्पादकता वढ जाती है, तो समुदाय की मितव्ययिता सम्भवतः वढ़ जाएगी। इससे वक्त-अनुपात मे वृद्धि तथा आय मे कभी होगी। यह भी एक प्रयत दीर्पकालीन सम्भावना है, क्योंकि निवेश की उत्पादकता एव वक्त अनुपात मे एक ही दिशा मे परिवर्तन होता है। अतएव, यह कोई आकस्मिक नहीं कि σ एव σ दोनों उत्पत अर्थ-व्यवस्थाओं मे उच्च तथा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निम्म रहते हैं। अतएव, निवेश की उत्पादकता एव वच्त अनुपात (σ α) Δ I/1 की वर से वढते हुए शुद्ध निवेश की उत्पादकता एव वच्त अनुपात (σ α) Δ I/1 की वर से वढते हुए शुद्ध निवेश की दीर्थवालीन गित से इस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं कि डोमर के सतुलन की स्थित $Y^d=^dY$ एव Δ $Y^d=\Delta \gamma^d$ डोमर द्वारा अपेक्षित कारणों से ही उलट सकते हैं।

3 अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से डीमर के माँडल के विरुद्ध शायद सर्वाधिक गम्भीर आलोचना यह है कि उसकी निवेश की वृद्धि की अपेक्षा दर 'सरचनात्मक वेरोक्रगारी' की समस्या के समाधान में असफल रहे जाती है। डोमर की 'अपेक्षित' वृद्धि की दर, केवल प्रभावीत्पादक मांग की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न 'केन्सीय वेरोजगारी' की समस्या या दूसरे शब्दों में, पूँजी के अपूर्ण प्रयोग का ही समाधान करती है, जबिक हैरोड 'अनैच्छिक बेरोजगारी' की मान्यता से प्रारम्भ करता है और तब gw=gn शर्तों की पूर्ति के द्वारा पूर्ण रोजगार सतुलन को प्राप्त करने की सभावनाओ पर विचार करता है, डोमर पूर्ण रोजगार की स्थिति (Y^d=Y') की मान्यता से आरम्भ करता है और तब द उँकी दर से आय एवं निवेश के विस्तार के द्वारा इस स्थिति को बनाये रखने की सम्भावना पर विचार करता है। हैरोड के gw से अधिक डोमर का y दोनो पूर्ण क्षमता एव पूर्ण रोजगार की प्रतिभूति (गार्रटी) नहीं दे सकता है। क्योंकि, अधिकाश अल्प-विकसित देशों की तरह यदि श्रम-सख्या मे पूँजी-सग्रह से अधिक बृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो पूर्ण रोजगार के साय प्रारम्भ करने वाली अर्थ-व्यवस्था को प्रजीगत उपकरणों के अभाव में आगे अथवा पीछे गैर-केन्सीय घेरोजगारी की अनुभूति होगी। ऐसा तभी होगा, जबकि यह नहीं मान लिया जाय कि उत्पादन के श्रम-गहन जपाय श्रम की उत्पादकता में किसी प्रकार की कमी लायें वर्षर इसे टाल नहीं देते अथवा यह नहीं मान लिया जाय कि श्रम की प्रारंभिक अधिकता वास्तविक मजदूरी की दर में इस प्रकार की कटौती करती है, जिससे कि पूँजी-संप्रह अत्यधिक लाभदायक हो जाय । यह एक खुला प्रश्न है कि क्या श्रम-गहन तकतीको का प्रयोग, बचपि कि ये गैर-केन्सीयन वेरोजगार को कम करने में सहायक होते हैं, तथापि ये बड़े पैमाने की उत्पादन की भितव्ययिताओं के माध्यम से, जिसमे श्रम की तुलना में पूँजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, उत्पादकता में पूँजि के बीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्वि में बाधक हो सकता है ? यह भी एक खुला प्रमन है कि क्या अधिक विकसित श्रम-सध के अभाव में किसी भी अल्प-दिकसित अर्थ-व्यवस्था में श्रम वास्तविक मजदूरी की दर में संतुलनकारी कटौती को सहर्प स्वीकार कर सकता है ? इस प्रकार शुद्ध-निवेश में ०० की दर में वृद्धि यद्यपि यह अनुपयुक्त क्षमता को जत्पन्न होने से रोकती है, वढ़ती हुई श्रम-संख्या को खपाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तीन्न नहीं भी हो सकती है। अपने ० को जनसंख्या की वृद्धि एवं प्राविधिक प्रगति के अंतर्गत करने के वजाय, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की गैर-केन्सीयन वेरोजगारी तथा विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की केन्सीयन वेरोजगारी दोनों के विश्वेषण के लिए हैरोड की 'प्राकृतिक' दर की तरह डोमर को विकास की किसी अतिरिक्त दर को काम में लाना होगा। इस प्रकार, हैरोड के विकास की 'वारंटेड' दर की तरह डोमर के विकास की संतुलन दर पूँजी के पूर्ण नियोजन की प्रतिभृति (गारंटी) प्रदान करती है और जब तक श्रम-संख्या की वृद्धि की दर के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मान्यता नहीं की जाती, तब तक यह आवश्यक रूप से श्रम के पूर्ण नियोजन की प्रतिभृति (गारंटी) नहीं प्रदान करता।

4. अंततः, तकनीक के सम्बन्ध में डोमर की अभिमित में बहुत-ती अपेक्षित वातों की कमी रह जाती है। समर्थ माँग की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में चितन-रत रहने के कारण, डोमर तकनीकी प्रगित को मुख्यतः निवेश के अवसर का अध्या मानता है। जहां तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, तकनीकी प्रगित की आकांक्षा, इस वात को ध्यान में रखे वगैर कि इससे समर्थ माँग में वृद्धि होती है अथवा नहीं, इसके उत्पादकता-प्रभाव (σ) के लिए की जाती है। इस सम्बन्ध में यह वतलाना अनिवार्य है कि केन्स, जैसा कि डोमर मान लेता है, पूँजी के उत्पादक गुणों पर अधिक जोर नहीं देता है। इसके लिए डोमर केन्स को ही उत्तरवायी ठहराता है। ये अवकाश के काटा के रूप में तकनीकी प्रगित के विये केन्स इतने अधिक उत्सुक थे कि वे इसके सहगामी 'तकनीकी वरोजगारी' को 'कुसमंजन की अस्थायी स्थिति' समफ्तर टाल देने के पक्ष में थे। अवकाश के रूप्टा के रूप में तकनीकी प्रगित के सम्बन्ध में केन्स की यह सुखद स्थिति, डोमर की तकनीकी से सम्बन्ध-निवेश की अत्यधिक ऊँवी संभावित उत्पादकता (σ) के प्रति चेतावनी-सम्बन्धी स्थिति के विल्कुल विपरीत है। अतएव, जहां तक पूँजी के तकनीक की दृष्टि से सुधार-योग्य गुण (डोमर का उच्च σ) का सम्बन्ध है, केन्स द्वारा इस पर अधिक जोर देना उचित जान पड़ता है।

और न तो केन्स ने, जैसा कि डोमर मानते हैं, दीर्घकाल से पूँजी के वहते हुए परिमाण के सम्बन्ध में कोई गंभीर चिन्ता ही व्यक्त की है। ठीक इसके विपरीत केन्स ने पूँजी के परिमाण [में उस हद तक वृद्धि संभव एवं वांछित बतलायी है, जहां पूँजी की 'सीमांत क्षमता शून्य हो जाती' है। अतएव, यहाँ पूँजीवाद का लगान

^{1.} डोमर-पूर्व उद्धृत, पृ० 53।

^{2.} केन्स का पूर्व उद्घृत 'इकाँनामिक पोसिविलिटिज फाँर आवर ग्राम्ड चिल्ड्रेन'।

उपजीवी पक्ष समाप्त ही जाता है। पूंजी की घटती हुई सीमात-क्षमता के लिए केन्स की गम्भीर चिन्ता, जिसकी चर्चा डोमर ने की है, केवल आतरिक परिस्थितियों में ही होती है, जहां पूँजी के सचय को अवध-नीति पर छोड़ दिया जाता है और जहां द्रव्य एवं ऋण पर दिये गये व्याज की दर, संस्थानिक एवं सनोवैज्ञानिक कारणों से, पूँजी की घटती हुई सीमात क्षमता से सुगमतापूर्वक समायीजित करने के लिए घटने में असमर्थ सिद्ध होती है। अतएव, एक उचित तरीके से सचालित समाज की तरह, यदि पूँजी की मात्रा एवं व्याज की दर पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाय, तो पूँजी-सचय के बजाय तकनीक, अभिवृत्ति, जनसंख्या एवं संस्थाओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रगति की आधा करना केन्स सम्भव समभता था। किन्तु स्पष्ट है कि इस बात की बिना जाने डोमर केन्स के निष्कर्ष से करीव-करीव सहमत् हो जाता है, जबकि वह तकनीकी प्रगति की अभिवृद्धि (ज में वृद्धि) की वाछनीयता को इस गर्त पर प्रजापित करता है कि वैयवितक नवीन किया-निवेश जिस अतिरिक्त बचत का प्रयोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग अन्य तरीको से (जैसे सरकार के द्वारा) किया जाता है।

राबिन्सन के मॉडल पर टिप्पणी

जान राबिन्सन के पूँजी-सचय के सिद्धाव का सार उनके इस केन्द्रीय प्रस्ताव में निहित है: 'यदि उद्यमकर्ताओं को लाभ नहीं होता, सो वे पूँजी-सग्रह नहीं कर सकते और यदि वे पूँजी-संग्रह नहीं करते, तो उन्हें लाभ नहीं होता।' आधिक विकास की मौलिक प्रकृति का विश्लेषण वह पूँजीवादी नियमों के अनुसार करना चाहती हैं। इस उद्देश्य से वे केवल पूँजी एवं ध्यम को उत्पादन का साधन मानते हुए एवं सम्पूर्ण उत्पत्ति को उद्यमकर्ताओं एवं ध्यमिकों के बीच वितरण करते हुए एक संवृत अबंध अर्थ-व्यवस्था के शाब्दिक माँडल का निर्माण करती हैं। पहले हम लोग वे राबिन्सन के आधारभूत माँडल का विवेचन करेंगे और ठव हैरोड डोमर माँडल के साथ इसके सम्बन्ध एवं केन्सोत्तर विकास-सम्बन्धी अर्थशास्त्र में इसके स्थान को, विभोध हए में अहप-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के वृद्धिकोण से, स्पष्ट करेंगे।

आगं-आगे आने वाले विश्लेषण को सहज बनाने के लिए, उचित मान्यताओ के आधार पर रॉविंग्सन के सग्रह के सिद्धान्त को निर्दिष्ट आकार देना लाभदायक

^{1. &#}x27;जेनरल घियरी' पु॰ 221, पु॰ 376।

^{2.} पूर्व उद्धृत पृ० 220-1।

देखें, इनकी पुस्तक 'दि एक्मुसेयन ऑफ कंपिटल', इरविन, होम उड, 1956 (विशेषत: द्वितीय खंड, भाग 1 एव II)

⁴ पर्व उद्धत, ए० 76।

जान पड़ता है। उसके मूल मॉडल में निम्नॉकित सरल मान्यताएं अंतर्निहित हैं: (क) श्रिमिक मजदूरी के रूप में प्राप्त अपनी सम्पूर्ण आय को उपभोग पर व्यय करते हैं, जबिक लाभ प्राप्त करने वाले लाभ से प्राप्त अपनी संपूर्ण आय को बचाते एवं विनियोग करते हैं और (ख) एक दी हुई निपज को उत्पन्न करने में पूंजी एवं श्रम एक निश्चित अनुपात में लगाये गये हैं। आगे चलकर वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, वे अपनी दूसरी मान्यता को कुछ शिथिल कर देती हैं। उनका सम्पूर्ण विवेचन घटनोत्तर रूप में संचालित होता है, किन्तु हम लोग इसकी व्याख्या आर्थिक सिद्धान्त के घटना-पूर्व रूप में भी कर सकते हैं।

वितरण समीकरण जो जे० राविन्सन के विकास-सिद्धांत का केन्द्रीय-बिन्दु है, जो निम्नाँकित प्रकार से दिखलाया जा सकता है :

$$p\gamma = wN + \pi pK$$
, (1"')

जिसमें γ शुद्ध राष्ट्रीय निपज, N रोजगार-प्राप्त श्रम का परिमाण, I. उपर्युक्त पूँजीगत उपकरणों का भीसत मूल्य, v मजदूरी की मौद्रिक दर और π वास्तविक पूँजी के वर्तमान स्टाक के सामान्य प्रयोग के लिए आवश्यक कुल लाभ की दर (सूद की दर को सिम्मिलित करते हुए) हैं। समीकरण (1''') के दोनों पक्षों को औसत मूल्य-सूचनांक p से विभाजित करने पर हमें वास्तविक अर्थ में निम्नलिखित वितरण समीकरण प्राप्त होता है:

$$\gamma = \frac{w}{p} N + \pi K, \qquad (2''')$$

जिससे हम लोग लाभ की दर π प्राप्त कर सकते हैं। $\gamma/N=P$ एवं K/N=0 रखते हुए लाभ की दर को बताने के लिए समीकरण $(2^{n'})$ का निम्नांकित रूप में पुनिंवन्यास किया जा सकता है:

$$\pi = \frac{\gamma - \frac{w}{p}N}{K} = \frac{\frac{\gamma}{N} - \frac{w}{p}}{\frac{K}{N}} = \frac{P - \frac{w}{p}}{0}$$
(3"')

जिससे यह स्पष्ट होता है कि लाभ की दर श्रम की उत्पादकता (P), वास्तविक मजदूरी की दर (w/p) एवं पूँजी-श्रम अनुपात (θ) तकनीकी सम्बन्ध पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, लाभ की दर को पूँजी के गुद्ध प्रतिफल की दर (P-w/p) के साथ प्रत्यक्ष रीति से तथा पूँजी की तीव्रता के गुणक (θ) के साथ प्रतिलोमतः परिवर्त्तित होने के योग्य है।

यह मान लिया जाता है कि उद्यमकर्त्ता लाभ को अधिकतम बनाने की निम्नाँकित दशा की पूर्ति करते हैं:

$$d\frac{\left(\frac{0}{b-\frac{b}{b}}\right)}{\frac{0}{b}} = 0 (4")$$

उत्पादन फलन के रहने धर।

$$\gamma \Rightarrow F(N, K),$$
 χ_{V} $(5''')$

जिस K/N को स्थिर मान लिया जाता है (थोड़े समय के लिए) और जहाँ Y को K एव N से सन्निकटतम सजातीयता का सम्बन्ध मान लिया जाता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल के रूप में आगे चलकर हम लोग इस उत्पादन फलन की परिवर्तनीयना पर विचार करेगे। समीकरण (5") वितरण-ममीकरण 1") का उत्पादन-प्रतिहप है। व्ययपक्ष की ओर से,सत्नम की स्थिति भे, गुढ वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक उपभोग ब्यम ((') एव शुद्ध वास्तविक निवेश (I) के बरावर अवस्य होगा : Y = C + I; S = I, $C \cap A$

$$Y = C + I; S = I, \quad C^{*}$$
 (6"')

जो यास्तव में केन्म का प्रचलित आय-ध्यय अथवा यचत-निवेश-समीकरण है। यहाँ उपभोग (C) एव बचन (S) राष्ट्रीय आग से लिये गये है, अनएय इन्हे रॉबिन्सन की मान्यताओं से संगत रूप में इस प्रकार में परिवर्तित करहा युद्धिवार्य है:

$$C = Cn = \frac{\nu}{p} N, \qquad (7'')$$

एव

$$S = Sk = \pi K, \tag{8"}$$

यहाँ Cn मजदूरी के रूप मे प्राप्त आय में से उपभोग रुपय है और Slc लाभ के रूप में प्राप्त आय में से बचत है। जहाँ तक गुद्ध निवेश की सम्बन्ध है। इसे केवल बास्त-विक पूँजी में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है :

$$1 = \triangle K \qquad (9")$$

समीकरण (S'') एव (D'') को ध्यान में रखते हुए हम लोग समीकरण (G'') के द्वारा व्यक्त निवेश-सम्बन्ध निम्नाकित प्रकार से पुनं लिख सबने हैं.

$$\Delta K = \pi K, \qquad (10")$$

जिसमें तथा समीकरण (3") को ध्यान भे रखने हुए हम लोगों को पूँजी में वृद्धि की निम्नलिखित देर प्राप्त होती है

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{\pi K}{K} = \pi = \frac{p - \frac{w}{p}}{\varphi} \tag{11"}$$

समीकरण (11") द्वारा दी गयी पूँजी में वृद्धि की दर वह दर है, जिसे जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उद्यमकर्ता पूँजीवादी खेल के नियमी का अनुकरण कर प्राप्त करते हैं। समीकरण (11'') यह वतलाता है यदि पूँजी का शुद्ध प्रतिफल (P-w/P) श्रम-निपज अनुपात से अधिक अनुपात में वढ़ता है, तो पूँजी में वृद्धि की दर वृद्धि-क्षम्य होगी। रिकाडों के शब्दों में, इसका तात्पर्य यह है कि जब तकनीकी स्थिति पूर्ववत् रहती है (हम लोगों के उदाहरण में P एवं θ स्थिर रहते हैं) तो वास्तविक मजदूरी की दर हास से पूँजी का संचय प्रवल तथा वास्तविक मजदूरी की दर हास से पूँजी का संचय प्रवल तथा वास्तविक मजदूरी की दर हास से पूँजी का संचय प्रवल तथा वास्तविक मजदूरी की दर हास से पूँजी का संचय प्रवल तथा वास्तविक मजदूरी की दर में वृद्धि से कमजोर होता है। अतः, ऐसा जान पड़ता है कि जॉन राविन्सन मे हम लोगों को केन्स के माध्यम से, पुनः डेविड रिकाडों के आर्थिक-विकास के सिद्धान्त पर वापस ला दिया है। इस सम्बन्ध में आगे हम कुछ कहेंगे।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राबिन्सनीयन विचारधारा में पूँजी में वृद्धि की दर उन बातों पर निर्भर करती है, जो लाभ की दर (π) का निर्धारण करती है। यहाँ 'अन्य बातों' से शायद वास्तविक मजदूरी की दर (w/p) श्रम की उत्पादकता (P) तथा पूँजी-श्रम अनुपात (θ) के तकनीकी सम्बन्ध का बोध होता है।

अव जॉन रॉविन्सन के श्रम के पूर्ण रोजगार एवं पूँजी के पूर्ण उपयोग के स्वर्णयुगीय संतुलन की धारणा पर विचार किया जाए। इस संतुलन के लिए आव- श्रम एक आधारभूत शर्त को इस प्रकार से देख सकते हैं। पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण प्रयोग की स्थिति में $\mathbb{K}/N = 0$ को स्थायी मानते हुए पूर्ण नियुक्त श्रम की मात्रा में वृद्धि $\Delta N = \Delta K / 0$ के द्वारा दी जा सकती है। इस अति सम्बन्ध से हमें पूर्ण नियुक्त श्रम में वृद्धि की दर प्राप्त होती है:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{\Delta K/\theta}{N} = \frac{\Delta K/\theta}{K/0} = \frac{\Delta K}{K}, \quad (12'')$$

जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण नियुक्त श्रम में पूँजी में वृद्धि की दर के समान ही वृद्धि होती है। साथ ही, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब पूँजी-श्रम-अनुपात (0) स्थायी रहता है, तब पूँजी में भी इतनी तेजी से वृद्धि होनी चाहिए, जितनी . तेजी से श्रम की संख्या में वृद्धि होती है। निपज के सम्बन्ध में श्रम की पूर्ति के पूर्ण-तथा लोचदार होने पर, समीकरण (12") पूँजी एवं श्रम दोनों की पूर्ण नियुक्ति के स्वर्णयुगीय संतुलन को स्पष्ट करता है।

तव जॉन रॉविन्सन यह प्रथन उठाती हैं कि यदि किसी कारणवण अर्थ-व्यवस्था इस स्वर्णयुगीय संतुलन से विचलित हो जाय, तो इसे ठीक करने के लिए क्या इसके पास कोई संतुलनकारी यंत्र उपलब्ध है ? मान लिया कि अर्थ-व्यवस्था ने विपम मार्ग ग्रहण कर लिया है तथा इसक ; विपमता निम्नाँकित प्रकार से स्पष्ट होती है :

$$\frac{\Delta K}{N} = \frac{\Delta N}{K}$$

यानी अधिकाश अल्पविकसिन अर्थ-ध्यवस्थाओ की तरह श्रम संध्या पूँजी-संचय से अधिक तीन्न गति से बढ रही है। ऐसी स्थिति में अर्थ-व्यवस्था पुन. स्वर्ण-यगीय सत्तलन की स्थिति मे आ सकती हैं अथवा नहीं, यह जॉन रॉबिन्सन के अनु-सार लाभ-मजदूरी सम्बन्ध के आकरण पर निर्भर करता है। उपर्युक्त विपमता में अर्ताहत, प्रगतिशील पूर्ण रोजगारी सन्तिहित थम के आधिवय द्वारा सतुलनकारी यंत्र के निर्माण से दूर हो जा सकती है। किन्तु, यह एक बहुत बड़ी 'यदि' है; वयोकि साम-मजदूरी-सम्बन्ध सनुलनकारी तरीके का आचरण रख सकता है अयवा नहीं भी। वास्तव में, यह बाजार की परिस्थितियों (प्रगतियोगात्मक एव एकाधिकारी), मजदूरी के जीवन निर्वाह दर की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, एवं स्वतन्त्र तकनीकी समा-वनाओ पर निर्भर करता है। तकनीक की दी हुई स्थिति मे, श्रम के उपर्युवन आधिवय से शीझ अथवा बाद में नकद मजदूरी की दर (॥) में कमी होती है। यदि सामान्य मृह्य (p) स्थायी रहे, जैसा कि एकाधिकार-प्रधान अर्थ-व्यवस्था में होता है, तो नवद मजदूरी की दर में इस कभी से बास्तिविक मजदूरी की दर (w/p) में भी कभी होगी। इस प्रकार यदि बास्तिविक मजदूरी की दर खट जाय, तो जैसा कि समीकरण तब (11''') से स्पष्ट है, पूँजी की वृद्धि की दर में लाभ की दर पर वास्तिविक मजदूरी में कभी के बढ़ते हुए प्रभाव के माध्यम से वृद्धि ही सक्ती है। सम्भव है कि पूँजी में वृद्धि की दर बढ कर श्रम सक्ष्मा में वृद्धि की स्थायी दर के बरावर हो जाय, जिससे कि $\triangle K/K = \triangle N/N$ हो जाय। दूसरी ओर, मजदूरी के जीवन-निर्शह स्तर के अतराक्षेप अथवा सामान्य मूक्ष्य मे नकद मजदूरी के अनुपात मे ही कमी के कारण बास्तविक मजदूरी की दर में ह्नास हो जाय (जैसा कि दीर्घकाल में प्रतियो गारमक बाजार में होता है) तो सन्निहित श्रम का आधिक्य संतुलनकारी यत्र का तिर्माण नहीं कर सकता तथा प्रगतिशील अपूर्ण रोजगारी दूर नहीं हो सकती। यह अतिम सम्भावना हैरोड की अनिश्चित अस्थिरता की धारणा से मिलती-जुलती हैं। हैरोड की यह धारणा तकनीकी गुणाको की स्थिरता एवं साधनों की सापेक्ष मूल्य-गतियों की मान्यता पर आधत है।

इसका ठीक विलोग पूँजी-सचय के धम-सस्या से अधिक तेजी के साथ बढ़ेन की स्थिति, जैसा कि अधिकाश विकसित देशों में सत्य होता है। फिर भी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के स्वणंपुगीय सतुलन के पथ पर लौटने की सम्भावना अधिक है। इसके कारण जे० शुम्पीटर के आर्थिक विकास के सिद्धान्त के पाठकों (जॉन रॉबिन्सन को सिम्मिलित करते हुए) के लिए बिल्कुल स्पष्ट हैं। क्योंकि, यद्यपि वास्तविक मजदूरी को दर अनम्य भी, फिर भी धम की उत्पादकता (p) अधवा पूँची धम अनुपात (0) में परिवर्तन इस प्रकार हो सकता है, जिससे लाभ की दर में वृद्धि हो और जिसके परिणामस्वरूप की में वृद्धि की दर में भी सतुलनकारी तरीके से वृद्धि (अथवा कभी) हो। समी- करण (11"") से यह स्पष्ट है। यहीं जॉन रॉबिन्सन अपने आधारभूत मॉडल से भी आगे चली जाती हैं, तथा रिकार्डों की अपेक्षा शुम्पीटर से अधिक समीप हो जाती हैं। यहीं हमें समीकरण (5") द्वारा अभिन्यक्त उत्पादन-फलन पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। यदि श्रम की उत्पादकता (Y/N = p) में उसी q जी-श्रम-अनुपात (K/N=0) के लिए वृद्धि हो जाय अथवा यदि पहले के उसी मुल्य के लिए बाद के अनुपात में कमी हो जाय, तो सम्पूर्ण उत्पादन-फलन ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा । तकनीकी गुणांकों में उन परिवर्तनों को बाजारगत परिस्थितियों से स्वतंत्र समभना शुम्पीटर की भावना के अनुरूप है। इसी भावना से जॉन रॉविन्सन भी तकनीकी परिवर्तनों पर विचार करती हैं। समीकरण (11") यह बतलाता है कि किसी स्थायी पुँजी-श्रम अनुपात $(\theta = \theta)$ के लिए यदि श्रम की उत्पादकता (P) में वास्तविक मजदूरी की दर की अपेक्षा अधिक तेजी में वृद्धि होती है, तो पूँजी की वृद्धि की दर में भी वृद्धि होगी। साथ ही, यदि पूँजी-श्रम अनुपात (0) में W/p एवं p, में सहगामी परिवर्तनों के वगैर कमी हो जाय तो भी पुँजीं में वृद्धि की दर में और अधिक वृद्धि हो सकती है। पूँजी की गहनता के गुणांक में कमी के साथ-साथ दी हुई वास्तविक मजदूरी की दर की त्रतना में श्रम की उत्पादकता में अधिक कमी होने पर कठिनाई उपस्थित हो सकती है। इसका संभा-वित परिणाम यह होगा कि पूँजी में वृद्धि की दर में वृद्धि के बजाय कमी होगी, उत्पादन की कम पूँजी वाली अथवा चक्रदार तरीके का प्रतिनिधित्व करती है, जो श्रन्यथा श्रम की उत्पादकता तथा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कर सकती है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि समान अनुपात ही इस प्रकार देखने से, समीकरण (11") के सम्बन्ध में वर्णित 'रिकार्डों का प्रभाव', परिवर्त्ती टेक्नोलॉजिकल प्राचलों से युक्त अधिक सामान्य स्थिति की एक विशिष्ट स्थिति है।

हैरोड तथा डोमर के साथ जॉन रॉविन्सन के मॉडल को निम्नांकित प्रकार से देखा जा सकता है : समीकरण (2''') को ध्यान में रखकर तथा पुनर्व्यवस्थित करते हुए, समीकरण (3''') को पुनः इस प्रकार से लिखा जा सकता है :

$$\pi = \frac{Y - \frac{W}{p}N}{K} = \frac{Y}{K} \left(\frac{Y - \frac{W}{p}N}{Y} \right), \quad (13''')$$

जो यह वतलाता है कि लाभ की दर के पूँजी की उत्पादकता $(\gamma/K=\sigma)$ के अनुपातिक होने के लिए राष्ट्रीय आय $[\gamma-(W/p)N]/\gamma$ में लाभ के हिस्से के गुणा होता है। चूँकि $S=\pi K$ और $[\gamma-(w/p)N]/\gamma=\pi K/\gamma=S/\gamma=S$ और चूँकि $b=I/\sigma$, अतएव

$$\frac{\Delta K}{K} = \pi = \sigma S, l/c$$
 (डोमर) अथवा $= \frac{s}{b}$ (हैरोड) । (14"')

इस प्रकार जॉन रॉबिन्सन का मॉडल सारतः हैरोड तथा डोमर के मॉडलो के ही समान है। फिर भी, इनमे महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि जॉन रॉबिन्सन पूंजी-संजय को स्पट्त लाभ-मजदूरी सम्बन्ध (रू एव w/p) तथा श्रम की उत्पादकता (p) पर आश्रित मानती है। इस तरह, ये अपने सिद्धान्त को वास्तिवक बाजारगत अर्थ-व्यवस्था के विलक्ष समीप ला देती है। इसके विपरीत, मुख्यतः केन्स के तरीके से, हैरोड तथा डोमर पूंजी-सचय को वचत-अनुवात (अथवा इसके श्युत्कम) पर आधृत मानते हैं जो पूंजोबाद अथवा समाजवादी सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में लागू होता है। साथ हो, यह महत्त्वहीन नहीं है कि जान रॉबिन्सन पूंजी सचय के प्रकार पर मुख्यत धम के दृष्टिकोण से तथा हैरोड एव डोमर पूंजी के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। इम प्रकार जब जॉन रॉबिन्सन पूंजीवाद खेल के नियमों के द्वारा पूंजी-संचय की चर्चा करती है, तो उनके कथन का यही तास्पर्य जान पड़ता है कि पूंजी के मूल्य (प्राय. मुद्ध हप से आय की दर) एव धम की उत्पादकता की तुलना में श्रम के मूल्य में (अस्तिवक मजदूरी की दर) में कमी के अर्थ व्यवस्था हो सकता है कि एक अल्प-विकसित नहीं कर सकता। यह उसके कहने का तरीका हो सकता है कि एक अल्प-विकसित नहीं होगा। इनके लिए स्वतत्र निवेदा (जिममे सुम्पीटर की तरह के नवीन कियात्मक निवेश भी शामिल होगे) को प्रोत्माहित करने के उद्वेश्य से वित्तीय एव मीदिक नीतियों से युक्त केन्म की मिश्रन राजकीय एव निजी अर्थव्यवस्था के तकनीक वो अपनाना अधिक उचिन होगा।

केन्सोलर विवास अर्थशास्त्र मे बाँन राँबिन्सन की प्रधान देन यह जान पड़ती हैं कि उन्होंने सस्थापक मूल्य एवं वितरण मिद्धान्त तथा केन्स के आधुनिक बचत एवं निवेश-सिद्धान्त को एक सलग्न प्रणालों में समाकलित कर दिया है। किन्तु, जहाँ तक नीति के प्रयोग का सम्बन्ध है, यह उनका प्रधान दोप भी जान पड़ता है। व्योकि, हैरोड एवं डोमर के माँडलों की भाँति विन्तीय एवं मौद्रिक नीति प्राचलों को प्रस्तुत करने के लिए जाँन राँविन्सन का माँडल तब तक सुधार के योग्य नहीं है, जब तक कि ध्रम की उत्पादकता, मजदूरी की दर, लाभ की दर तथा पूँजी-श्रम अनुपात को पूर्णंतमा आयोजित अर्थं-व्यवस्था की तरह व्यावहारिक नीति का उन्देश्य नहीं समभा आय। साधनों के सापेक्ष मूल्य के प्राच्वीय कार्य के द्वारा आय के पुर्नीवतरण (लाभ एवं मजदूरी के बीच) को लाने तथा इस प्रकार पूँजी-सचय को जनसंख्या की बृद्धि से ममायोजित होने देने के बजाय, कोई भी व्यक्ति वित्तीय नीतियों के द्वारा आय के पुर्नीवतरण अथवा जनसंख्या मे वृद्धि को पूँजी मे दी हुई वृद्धि के साथ समायोजित करना अधिक पसन्द कर सकता है। फिर भी, जाँन राँविन्सन का सिद्धान्त विगुढ़ पूँजीवादी खेल के नियमों के अनुसार पूँजी-सचय की मौतिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में पूँजीवादी खेल के नियमों के अनुसार पूँजी-सचय की मौतिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में

हमारी जानकारी को और तीन्न बनाता है। अंततीगत्वा, जॉन रॉबिन्सन के संतुलन-कारी यंत्र के गुणकारी होने अथवा नहीं होने की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि इनका विकास-सम्बन्धी मॉडल, यद्यपि स्थायी संतुलन का साधन प्रस्तुत करने योग्य है, तथापि इस सारभूत रूप में, हैरोड एवं डोमर की अवैध नीति वाली अर्थ-व्यवस्था के मॉडलों की तरह ही अस्थायित्व है।

अध्याय ५

आर्थिक विकास में टेक्नोलॉजिकल भूमिका

आर्थिक प्रगति के लिए पूँजी-सचय के ठीक बाद टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति कारणात्मक महत्त्व की है। आदमसमय ने राष्ट्रों को सम्पत्ति मे अभिवृद्धि के आधार के रूप में विशेषकता पर जोर दिया था। मार्क्स ने टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति को पंजीवादी विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं तत्त्व माना था। बाम वर्क (Bohm-Bawerk) ने उत्पादन के चलदार तरीको को औद्योगीकरण के समरूप बतलाया था। शुस्पीटर ने ऐतिहासिक विकास की सम्पूर्ण प्रतिक्रिया की व्याख्या मुख्यतः नवीन किया के रूप में की थी। केन्स ने अविध्य में एक ऐसी अर्द्ध-स्थायी स्थिति की भविष्यवाणी की थी, जिसमे परिवर्तन तथा प्रगति केवल तकनीक, रुचि, जनसंख्या एव संस्थाओं में परिवर्तन के ही परिणामस्वरूप होगे। इन सभी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक एव सामाजिक विकास में टेक्नोलॉजी-सवधी प्रगति के कारणात्मक महत्त्व पर अतर्दिष्ट की विभिन्न मात्रा के साथ जोर दिया था। हैरोड और डोमर से प्रारम्भ करने पर हम देखते है कि आधिक विकास से महत्त्व का साकेतिक स्थानान्तरण टेक्नोलॉजिकल भूमिका के अधिक व्यावहारिक उपचार की ओर हो गया है। फिर भी, ये लोग देवनोलॉजी-सम्बन्धी स्थायी प्रचालन, जो विभिन्न नमय एव स्थानो के विकास-सम्बन्धी कार्यकम तैयार करने के लिये विश्लेषणात्मक दृष्टि से असुविधाजनक होते हैं, को आधार मानकर, 'तटस्य टेवनीलॉबी-सम्बन्धी अप्रवर्तिता' की अभिधारणा करते हैं। जॉन रॉबिन्सन ने अपने उत्तेजक, 'नोटम आफ दि इकनामिक्स आफ टेकनिकल प्रोगेस' मे विकास-विश्नेषण के टेक्नोलॉडी-सन्बन्धी अधिक लखीले प्राचलत को बत-लाया है: क्योंकि विभिन्न अनुपातों को रखने के आशय पर भी विचार करना अधिक शिक्षाप्रद होगा । तथापि ये तथा आधिक विकास के अन्य लेखकगण मुख्यतः टैक्ती-लॉजी के माँग-पक्ष के साथ अभिकृति रखते है और उसकी उत्पादकता-पक्ष के साथ

देखिए, इनकी 'दि रेट ऑफ इन्टरेस्ट, एट्सेट्रा' पु॰ 63 ।

इनका सम्बन्ध-मात्र प्रसंगवण रहता है। पेसा इसलिए है कि ये टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं की विकास-सम्बन्धी समस्याओं से सम्बद्ध न होकर विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की स्थायित्व की समस्या में पहले से व्यवस हैं।

वर्तमान अध्याय का उद्देश्य अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं पर गैर-तटस्थ टैक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रभावों का विश्लेषण तथा साथ ही, अंतर्गत टैक्नोलॉजी-सम्बन्धी नम्य प्राचलों पर इसके विभिन्न प्रभावों को स्पष्ट करना है।

श्रम की उत्पादकता पर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रभाव

सर्वप्रथम शुद्ध राष्ट्रीय निपज पर श्रम बचाने एवं श्रम प्रयोग करने के तकनीक के प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा। इन्हें अपनाये जाने के विशेष कारणों पर वाद में विचार किया जायगा। इसके लिए हम ग़ैर-श्रम उत्पादक साधनों, मजदूरी दर-सहित साधनों के सापेक्ष मूल्य एवं जनसंख्या की वृद्धि तथा समर्थ माँग की दशाओं को दिया हुआ मान लेंगे। इन मान्यताओं के आधार पर निपज को श्रम की मात्रा एवं उत्पादकता का एक अद्वितीय कार्य (फंक्शन) माना जा सकता है। इनमें से श्रम की उत्पादकता टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी परिवर्तनों को परिलक्षित करती है।

मूल सम्बन्ध

उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर, निपज में निम्नलिखित के वरावर वृद्धि होगी :

$$\triangle Y = p \triangle N \tag{1}$$

जिसमें १ पूर्ण रोजगार से निस्सरित संभाव्य निपज है, N पूर्ण रोजगार की स्थिति में श्रम की मात्रा तथा p टेक्नोलॉजी की प्रचलित स्थिति के द्वारा निर्धारित श्रम की औसत एवं सीमांत उत्पादकता है। यह वही श्रम की उत्पादकता है, जिसे दिखलाया जाएगा कि यह श्रम बचाने तथा श्रम के प्रयोग करने सम्बन्धी तकनीकों की अनुक्रिया अनुरूप कालान्तर में बदलती रहती है। यहां केवल इतना ही कहना

माँग-सम्बन्धी पहलू से पूर्वप्राह्मता के आवर्षा उदाहरण के लिए देखें — जे० हुसेनवरी (J. Ducsenberry) का मई, 1956 ई० में "अमेरिकन इकाना-मिक रिक्यु" में "इनोवेशन एंड प्रोथ"। इस प्रकार की पूर्व-प्राह्मता की आलोचना के लिए एच० आर० वोवेन का दिसम्बर, 1954 के "अमेरिकन इकॉनामिक रिक्यु" में प्रकाशित "टेक्नोलॉजिकल चेन्ज एंड एप्रीगेट डिमांड" देखें। दूसरी ओर, जापानी अर्थशास्त्रियों की टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी व्याख्या, जैसे वाई० ताकटा द्वारा संपादित "स्टडीज इन ग्रोथ इकानामिक्स" में अल्प-विक-सित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए वहुत सी शिक्षाप्रद वार्ते मिलती हैं।

पर्याप्त है कि, नियमत तथा औसत रूप में, टेक्नोलोंजी की दृष्टि से विकसित अर्थ-ध्यवस्था में p उच्च तथा टेक्नोलोंजी की दृष्टि से पिछड़ी हुई अर्थ-ध्यवस्था में p निम्न होती है।

अव पूर्ण नियुक्त श्रम-संख्या में वृद्धि एवं पूर्ण रोजगार-निषज के अनुपात को ν के समरूप करने पर निम्माकित निष्कर्ण प्राप्त होता है '

समीकरण (2) में दिया गया अनुपात जनसङ्या की वृद्धि को बतलाता है तथा जनसङ्या की वृद्धि के साथ ही इसकी गति में भी परिवर्तन होता है। यह प्रकल्पना की जा सकती है कि जनाधिवय वाली अर्थ-व्यवस्था में y बड़ा तथा कम आबादी वाली अर्थ-व्यवस्था में y छोटा होता है।

(1) और (2) से हमे पूर्णरोजगार-निपज मे वृद्धि की निम्निलिखित दर प्राप्त होती है.

$$\frac{\triangle Y}{Y} = p_{Y},\tag{3}$$

जो यह स्पष्ट करता है कि पूर्ण रोजगार निपज में pv की दर से वृद्धि होती है। और pv की दर टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रयति और जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर करती है।

चूँकि, श्रम की उत्पादकता श्रम-निपज अनुपात का उलटा भी है, p=1/a (जहाँ $a=N/Y=\triangle N/\triangle Y$), हम लोग पूर्ण-रोजगार मे वृद्धि की दर को नैकल्पिक रूप मे निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं:—

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{I}{a} \quad v = \frac{v}{a},\tag{4}$$

जो अब यह दिखलाता है कि जब अतिरिक्त श्रम-सख्या एव पूर्ण रोजगार-निपज का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, तो पूर्ण रोजगार-निपज की वृद्धि की दर में श्रम-निपज अनुपात (a) मे परिवर्तन के ठीक विपरीत परिवर्तन होता है।

टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी परिवर्तनो के प्रभावो को पृथक् करने के लिए हम लोग यह मान लेते हैं कि पूर्ण निधुक्त श्रम की सदया एवं निपज का अनुपात कालान्तर में स्थायी रहता है, यानी समय का अपरिवर्ती फलन होता है:

$$v = vt = \overline{v}. \tag{5}$$

तो भी जैसा कि हम लोग देखेंगे, टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी परिवर्तनी की प्रचलित प्रकृति एवं दिशा के प्रत्युत्तर में धम-नियज अनुयात परिवर्तनाश्रित होता है।

श्रम-बचाने के तकनीकों का प्रभाव

साधनों का सापेक्ष मूल्य दिया हुआ रहने पर, हम लोग उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में श्रम बचाने अयवा श्रम लगाने वाली टेक्नोलॉजी के प्रयोग को स्वतन्त्र रूप से दिया हुआ, यानी उन्हें वाजारगत परिस्थितियों से स्वतंत्र मान सकते हैं। फिर भी हम लोग आगे चलकर श्रम-वचाने अथवा श्रम-उपयोग करने वाले तकनीकों को अपनाने के आर्थिक एवं टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी कारणों की खोज करेंगे। श्रम-वचाने वाले तकनीक की प्रकृति को इस प्रकार से देखा जा सकता है: यदि श्रम-निपज अनुपात श्रम-पूँजी अनुपात एवं निपज-पूँजी अनुपात का परिणाम है, यानी $N/\gamma = (N/K)/(\gamma/K)$, और यदि पूँजी की उत्पादकता (γ/K) को स्थायी माना जाय, तो दी हुई पूँजी की तुलना में श्रम की मात्रा में कोई कमी से (निम्न N/K) श्रम-निपज अनुपात में कमी (निम्न N/γ) होगी। अतएव, एक दिये हुए उत्पादन फलन में प्रति इकाई पूँजी के श्रम की मात्रा के घटाने के लिए सभी अन्वेपण एवं नदीन किया को श्रम वचाने का साधन समक्षा जा सकता है।

यह मानते हुए कि N/K एवं इसके परिणामस्वरूप N/γ में अपरिवर्त्ती ह्रास को रोकने के लिए कोई वाद्या-जनक अथवा खिसकाने वाली शक्ति नहीं, हम लोग कालान्तर में श्रम-निपज अनुपात (a=N/Y) को ga की स्थायी दर से घटने दे सकते हैं:

$$a = at = \frac{ao}{(I+ga)t'} \tag{6}$$

जिसमें at समय के फलन के रूप में गत्यात्मक श्रम-निपज अनुपात है, ao उस अनुपात का प्रारम्भिक मूल्य है श्रीर ga उस अनुपात के ह्रास की स्थायी दर है। समीकरण (6) में निम्नलिखित अनुत्रम अंतर्निहित है:

$$ao = e,$$

 $a_1 = ao/(I+ga) = e/(I+ga),$
 $a_2 = a_1/(I+ga) = e/(I+ga)^2,$
 $a_3 = a_2/(I+ga) = e(I+ga)^3,$

इत्यादि, इत्यादि ।

(5) एवं (6) को ध्यान में रखते हुए एवं $\triangle \gamma / \gamma$ को Gn से निर्दिण्ट करते हुए समीकरण (4) को पुन: सूत्र के रूप में निम्नांकित प्रकार से वर्णन किया जा सकता है:

$$Gn = \frac{\overline{v}}{ao/(1+ga)t_i} \tag{7}$$

जो यह बतलाता है कि कालान्तर में जैसे-जैसे थम-निपज अनुपात घटता है, वंसे-वंसे पूर्ण रोजगार-निपज की वृद्धि की दर विषरीततः घढने में सक्षम होती है! दूसरे घट्दों में, अतिरिक्त ध्रम एवं निपज का स्थायी अनुपात $(u=\bar{v})$ दिये रहने पर श्रम की बढ़ती हुई उत्पादकता (pt=w/I/at) के प्रभावस्वरूप Gn, में वृद्धि होती है!

श्रम-उपयोग के तकनीको का प्रभाव

दूसरी ओर, मान नें कि श्रम-उपयोग करने वाले तकनीको को इस प्रकार अपनाया जाता है कि कालान्तर में श्रम-निपज अनुपात में ga की स्थायी दर से धासीय सम्बन्ध के अनुसार वृद्धि होती है '

$$a = at = ao (1+ga)^t, (8)$$

जिसमें ga अब थम-निपज अनुपात में बृद्धि की स्थायी दर को स्पष्ट करता है। समीकरण (8) पृथक् गतियों को बतलाता है जो निम्नाकित प्रकार से परिभा-पित किये जाते है:

$$ao = e$$
;
 $a_1 = ao$ (I+ga) = e (I+ga),
 $a_2 = a_1$ (I+ga) = e (I+ga)²,
 $a_3 = a_2$ (I+ga) = e (I+ga)³,

इत्यादि, इत्यादि ।

(5) एव (8) को ध्यान में रखते हुए समीकरण (4) को पुन. इस प्रकार से लिखा जा सकता है

$$Gn = \frac{v}{ao (1+ga)t}, \qquad (9)$$

जो यह बतलाता है कि स्थायी v के दिये रहते पर कालान्तर में श्रम-निपज अनुपात में जैसे-जैसे वृद्धि होती है, वैसे-वैसे पूर्ण रोजगार निपज की अविध की दर विपरीतत: घटने में सक्षम है। दूसरे प्रकार से इसे यो कहा जा सकता है कि जब अतिरिक्त श्रम एवं निपज का अनुपात स्थायी रहता है, तो घटती हुई उत्पादकता के परिणामस्यरूप Gn में ह्नास होता है।

नीति प्राचल के रूप में श्रम-निपज अनुपात

यदि हम क्षोग उस गौरव-पूर्ण स्थिति को अपनाते हैं, जिसे टी० हैबलो ने एक स्थान पर अपनाया है कि टेक्नीलॉजी-सम्बन्धी प्राचल वस्तुतः रासायितक सूत्रो तथा यात्रिको के नियम की अपेक्षा मानवीय पुसद तथा आचरण से अधिक सम्बद्ध है

^{1.} देखें, इनकी पुस्तक 'ए स्टडी इन दि थियरी आफ इकानामिक इवोल्यूशन' पू॰ 49।

तो श्रम-निपज को आयोजित हेर-फेर किया जा सकने वाला नीति-प्राचल समफता अधिक लाभदायक है। अब प्रश्न यह है कि श्रम-निपज अनुपात या निपज-श्रम अनुपात को एक ऐसा दिया हुआ तकनी की आधार जिससे अन्य सभी का अनुकूलन किया जा सके, मानने के वर्तमान श्रम-निपज अनुपात को Gn तथा v के किसी स्वीकृत मान के ही अनुकूल क्यों न किया जाय ? इस प्रश्न का आश्रय यह सुफाव देना होगा कि तकनी की प्राचलों को नीति-गत विषय की तरह समफा जा सकता है। चूँकि केवल संयोग के अतिरिक्त वास्तविक श्रम-निपज अनुपात (a') को सदा आपे- क्षित या संतुलित (a) के समान होने के पक्ष में कोई परिकल्पना नहीं है, अतएव यथासंभव a' = a के वरावर रखना आवश्यक एवं वांछनीय हो जाता है। तीसरे समीकरण से Gn एवं v के स्वीकृत स्तर के अनुरूप श्रम-निपज अनुपात का अपेक्षित मान मिलता—

$$a = \frac{v}{Gn}, \qquad P = \frac{Gn}{v} \tag{10}$$

यहाँ पर a एवं p कमशाः आपेक्षितः श्रम-निपज अनुपात एवं श्रम की उत्पादकता हैं। समीकरण (10) से यह स्पष्ट है कि श्रम-निपज अनुपात को पूर्ण रोजगार निपज तथा अतिरिक्त श्रम एवं निपज के एक दिये हुए आधार के अनुपात के किसी प्रकार के अनुकूलन के लिए तकनीकी परिवर्तनों की प्रकृति एवं दिशा में निश्चित रूप से विचार पूर्वक परिवर्तन करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह $a' \neq a$ की विपमता पर विचार करता है।

मान लिया कि औद्योगीकरण की और उन्मुख अर्थ-व्यवस्था की भाँति दिये हुए v की तुलना में एक ऊँचे Gn को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो समीकरण (10) के अनुसार अपेक्षित श्रम-निपज अनुपात में ह्रास अवश्य होगा। इस का आश्रम यह है कि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम वचाने वाले उपायों का प्रयोग करना चाहिए। यदि तकनीक की प्रचलित स्थिति के परिणामस्वरूप वास्तव में वृहत् श्रम-निपज अनुपात (a') प्राप्त होता है, तो Gn में उपर्युवत परिवर्तन से तकनीक में इस प्रकार की उन्नित की आवश्यकता होती है, जिससे वास्तविक श्रम-निपज अनुपात कम होकर अपेक्षित अंक (a) के स्तर तक हो जाय। यह अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की एक विशेष स्थिति हो सकती है। फिर भी, अन्य दिये हुए आधार v में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम वचाने वाले तकनीकों की जाह श्रम-प्रयोग करने वाले तकनीकों की आवश्यकता की संभावना का अनुभोदन किये वगैर श्रम वचाने वाले उपायों के उपयोग की सिफारिश नहीं की जा सकती। अब मान लिया कि एक जनाधिक्य वाली अर्थ-व्यवस्था की मांति, एक दिये हुए gn की तुलना में उच्च v स्वीकार्य समभा जाता है। तब इसके परिणामस्वरूप समीकरण

(10) के अनुसार, अपेक्षित धम-निपज अनुपात v मे उपयुंक्त परिवर्तन के पूर्व की अपेक्षा अधिक है। इस सम्बन्ध में नीति का आश्रम यह है कि जब तक निपज में वृद्धि की निम्न दर को स्वीकार नहीं किया जाता है, श्रम प्रयोग करने वाले तकनीकों को प्रोत्साहित करना चाहिये। किन्तु तब श्रम प्रयोग करने वाले तकनीकों को अपनाने से श्रम की उत्पादन-क्षमता में कभी आ जाती है। अतएव, एक-जनाधिक्य वाली अर्थ-ज्यवस्था में, तील तकनीकी प्रगति की प्रक्रिया में श्रम की उत्पादन सा को बढ़ाने की इच्छा तथा गभीर वेरोजगारी को टालने की इच्छा में सभावित संघर्ष पाया जाता है। तो भी, यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि श्रम-निपज अनुपात को सदा एक दिया हुआ आधार मानने के बजाय, इसे किसी भी तकनीक की दृष्टि से नम्य अर्थ-अयवस्था में विचारपूर्ण परिवर्तन के योग्य सभावित नीति प्राचल समभना चाहिए। यह हमें श्रम बचाने तथा श्रम को प्रयोग करने वाले तकनीक को अपनाने के लिए प्रभावित करने वाले कितप्य कारणों के सर्वेक्षण की ओर ले जाता है।

थम बचाने एवं थम का प्रयोग करने वाले तकनीकों पर प्रभाव

थम-निपज अनुपात मे परिवर्तन की गरित, यानी ga जिसे हम लोग स्वतम हप से दिया हुआ मान लेते हैं, का ठीक-ठीक निर्धारण कठिन है। फिर भी, थम बचाने तथा थम का प्रयोग करने वाल तकनीको के चयन के प्रमुख कारणों की निम्नितियित रप-रेखा के द्वारा ga के निर्णायकों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

किसी बाजारगत अर्थ-व्यवस्या द्वारा श्रम बचाने के उपायों को अपनाने का सर्वाधिक स्पष्ट कारण यह है कि इनके परिणामस्वरूप श्रम की प्रति-इकाई उत्पादन

शापान का एक अयंशास्त्री इस वात की व्याख्या इस प्रकार करता है: वस्तुत उत्पादकता में वृद्धि का ताब उत्पादन की प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक अतिरिक्त जनसङ्या को खपाने की आवश्यकता से कम-से-कम अस्थायी तौर पर अवमंदित हो जाएगा। जहाँ तक नियुक्त साधनी के अनुपात का सम्बन्ध है, यथिप आधुनिक तकनीक को पूर्णत लोचदार नही माना जा सकता, फिर भी जापान में शायद श्रम की उत्पादकता की जगह श्रम-गहन उपायों को अपनाने के कुछ उदाहरण फिर सकते हैं। (देखें, एवं किडमुरा कोजफर प्रोजेक्यक ऑफ दि जैपकीय इकानामी—'ए किटिकल इमैं सुयदान, काइक्लोस, IX (2), 1956 किन्तु, जेसा कि जॉन रॉबिन्मन ने बतलाया है 'यदि वस्तुओं तथा पूँनीगत मालों की समयं माँग प्रति-व्यक्ति निपज में वृद्धि के अनुसार घीरे-धीरे बढती है, तो श्रम-बचाने वाली नवीन कियाओं को अपनान से तकनीक-मूलक बेरीजगारी नहीं होती।

लागत में साधारणतया कमी होती है। अतएव, अन्य बातों के यथावत रहने पर, ओसत मजदूरी की दर जितनी ही उच्च होगी, श्रम बचाने के उपायों को पता लगाने तथा अपनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। संयुक्तराष्ट्र का 'स्वचालन' की ओर भुकाव इसका अच्छा उदाहरण है, किन्तु वहाँ पर श्रम-संगठनों का 'उच्च मजदूरी-आन्दोलन' ही इसका एकमात्र प्रेरक कारण नहीं है। किन्तु, वहां एक अवाजारगत अर्थ-व्यवस्था में सम्भवतः श्रम की प्रति-इकाई वास्तविक आय में वृद्धि अथवा मानवीय नित्यक्रम (वास्तविक लागत) में कमी की सम्भावना पर अधिक जोर दिया जाता है। श्रम बचाने के उपायों को अपनाने का दूसरा संभावित कारण श्रम विनिमय की प्रभावयुक्त व्यवस्था के अभाव में वर्तमान श्रम की अत्यधिक अगृतिशीलता हो सकता है। इस प्रकार की वड़ी एवं वृद्धिशील जनसंख्यावाली अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा भी श्रम वचाने वाले तकनीकों की प्रगति को प्रोत्साहित करने के कारणों की व्याख्या मुख्यतः इस आधार पर की जा सकती है कि संभावित प्राप्य श्रम-शक्ति सदा उचित समय एवं स्थान में नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहती। श्रम-बचाने वाले उपायों को अपनाने का एक दूसरा संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पूर्ण रोजगार की तेजी अल्प रोजगार की मंदी से वढ जाती है, जिससे श्रम बचाने वाले अन्वेपणों एवं नवीन कियाओं को अपनाना, विशेपतः जनसंख्या में मंद वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम की पर्याप्त मात्रा में बेलोचदार पूर्ति वाली अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य एवं लाभदायक हो जाता है। विवृत अर्थ-व्यवस्थाओं में श्रम बचाने वाले तकनीकों के प्रयोग का एक संभावित कारण इनका श्रम बचानेवाले उपायों के अत्यधिक जानकार अर्थ-व्ववस्थाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार के तकनीक को अपनाना उसे आयात करने तथा तकनीक की द्िट से विकसित देशों की नकल करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अतएव, एक विवृत अर्थ-व्यवस्था में श्रम बचाने के उपायों को अपनाने की दिशा तीव्र गति से बढ़ सकती है। 'मेजी रेस्टोरेशन' के बाद का जापान इसका एक अच्छा ऐतिहासिक उदाहरण है। साधारणतया, श्रम बचाने वाले उपायों से अस्थायी वेरोजगारी (इस सम्बन्ध में तकनीक मुलक वेरोजगारी) के रूप में अल्पकालीन हानि की तुलना में अत्यधिक उत्पादकता के रूप में इससे दीर्घकालीन लाभ के सम्बन्ध में जितनी ही अधिक जानकारी होगी, श्रम बचाने वाले आधारों पर नवीन क्रियाकरण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक तीन्न होगी।

जहाँ तक श्रम वचाने वाले उपायों के संभावित कारणों का सम्बन्ध है, इन्हें पता लगाना प्रवीणता के इस युग में और भी किठन कार्य है। श्रम वचाने वाले तकनीक को अपनाने की क्लासिक स्थिति का निर्माण तकनीक-मूलक वेरोजगारी के सर्वज्ञात भय से किया जाता है। किन्तु रोजगार के लिए श्रम-प्रयोग करने वाले तकनीकों को स्थायी रूप से अपनाने का सुभाव बहुत कम लोग देंगे; क्योंकि उत्पादन-क्षमता का परित्याग किये वगैर वेरोजगारी को दूर करने के वैकल्पिक उपाय एवं साधन (यानी

अल्पनाल में समर्थ मॉम में बृद्धि एवं दीर्घनाल में वास्तविक पूँजी के सचय के द्वारा) उपलब्ध हैं। इसका एक प्रवल कारण यह जान पडता है कि उत्पादक, विशेषत: जनाधिवय बाली अर्थ-स्थवस्थाओं में, ऐसा सोचते हैं कि उत्पादन के श्रम बचाने वाले तक्तीको मे उपलक्षित थम की निम्न उत्पादन-क्षमता की क्षति-पूर्ति मृख्यतः निम्न श्रम-ध्यय के द्वारा हो जायगी । इसी विश्वास पर नार्य करते हुए उत्पादक श्रम-बचाने वाले तकनीको की तलना में थम-प्रयोग करने वाले तकनीको को अधिकाधिक मात्रा मं अपना सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप सम्प्रणे अर्थ-व्यवस्था के लिए श्रम-निपज अनपान में वृद्धि हो जाती है। इसका एक दूसरा कारण यह भी दिया जा सकता है कि साहसियों के बीच तीव प्रतियोगिता के अभाव में वे निम्न तकनीकी मौप्यता वाले उपकरणो को अपनाकर भी सतुष्ट हो जाते है। किन्तु, यह उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के साथ लाग नहीं होता जिन्हें भीषण विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पडता है और इस प्रतियोगिता का सामना करने तथा विकास के कार्यों के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय प्राप्त करने के उद्देश्य से थम बचाने वाले तकनीको की नहीं अपनाकर श्रम-प्रयोग करने वाले तकनीकों को अपनाने का एक प्रधान कारण उच्च तकनीकी वाले सप्रवाही उपकरणो को लगाने के लिए कीप (अतनः शास्त्रविक बचत) का सामान्य अभाव जान पडता है। साख (यानी मौद्रिक पूँजी) के कार्य (फनशन) के रूप मे शुम्पीटर का नवीन त्रिया का सिद्धान्त यहाँ प्रासिंगक जान पडता है । सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्रम-प्रयोग-सम्बन्धी तकनीकी प्रगति सर्वत्र थम की बढती हुई उत्पादकता की प्रभावशाली प्रवृत्ति की सीमा निर्धारित करती है।

क्षमता-वृद्धि पर देवनीलॉजी-सम्वन्धी प्रभाव

विकल्पतः श्रम को दिया हुआ मानकर, हम लोग क्षमता-निपज की युद्धि पर टेक्नोलॉजी-मम्बन्धी आघानो की जाँच-पदताल करें। इसके लिए पूँजो की पूर्ति के ब्याज की लोच को शून्य के बराबर मान लेना सुविधाजनक होगा, किन्तु पूँजी-निपज अनुपात के स्थायित्व की सामान्य कल्पना का परित्याग अनिवार्य है। इसके बदले में हम ग्रैर-तटस्थ टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति के सूचक के रूप में लोचपूर्ण पूँजी-निपज अनुपात के आधार पर कार्य करने का प्रस्ताव रखते है। औपचारिक विक्लपण के बाद, इस विभिन्न परिस्थितियों में पूँजी-निपज अनुपात को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।

मूल सम्बन्ध

श्रम की उत्पादकता की ही तरह, हम पूर्ण-क्षमता-निपज में वृद्धि की दर के "गधारभूत निर्धारण के विश्लेषण से प्रारम्भ करते हैं। वास्तविक पूँजी में वृद्धि के

परिणामस्वरूप निपज में पूर्ववर्णित मान्यताओं के अनुसार निम्नांकित के वरावर परिमाण में वृद्धि होती है।

$$\triangle Y' = \sigma \triangle K, \tag{1'}$$

जिसमें γ' पूर्ण-क्षमता से प्राप्त सम्भावित शुद्ध राष्ट्रीय निपज, या केवल पूर्ण क्षमता निपज है, K पूर्ण नियुवित की स्थिति में वास्तविक पूँजी की मात्रा, और δ सम्विध्यत पूँजी की औसत एवं सीमांत उत्पादकता (सीमान्त उत्पादकता की स्थिति में यह शुद्ध निवेश की औसत उत्पादकता को सूचित करता है; क्योंकि $\Delta K = I$) हैं। पूनः, हम यह मानते हैं कि शुद्ध निवेश एवं उपज में एक निश्चित सम्बन्ध है:

V K 1

$$\delta = \frac{\Delta K}{Y} = \frac{I}{Y'},\tag{2'}$$

जिसमें 8 वहती हुई पूँजी एवं निपज का अनुपात अथवा जैसा कि पहले कहा गया था 'पूंजीगत वस्तुओं को उत्पन्न करने की क्षमता' है। जैसा कि पहले अध्याय में वॉणत किया गया था, अति अनुकूल मान्यता के आधार पर 8 = 5 (जहाँ पर 5 वचत का अनुपात है) होता है। इसी प्रकार की मान्यता के आधार पर हैरोड के मॉडल 5 स्पष्ट परिवर्त्ती के रूप में दीख पड़ता है। निवेश अनुपात (8) के लिए स्थायी रहना कोई आवश्यक नहीं है, किन्तु यह साधारणतया अर्थ-व्यवस्थाओं में उच्च तथा अल्प-विकसित में निम्म होता है।

(1') एवं (2') समीकरणों से पूर्ण-क्षमता निपज में वृद्धि की दर प्राप्त होती है:

$$\frac{\Delta Y'}{K'} = \sigma \delta \tag{3'}$$

जो यह बतलाता है कि पूर्ण क्षमता निपज में वृद्धि की दर पूँजी की उत्पा-दकता (σ) \times निवेश-अनुपात (δ) के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है।

चूँकि पूँजी की उत्पादकता पूँजी-निपज अनुपात के विपरीत है, $\sigma = I/b = K/Y = \triangle K/\triangle Y$, समीकरण (3') को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है :

$$\frac{\Delta y'}{y'} = \frac{I}{b} \delta = \frac{\delta}{b} \,, \tag{4'}$$

जो यह वतलाता है कि δ के स्थायी दिया हुआ होने पर, पूर्ण-क्षमता निपज में वृद्धि की दर में पूँजी-निपज अनुपात (b) के ठीक विपरीत अनुपात में परिवर्तन होता है।

स्पष्ट रूप में टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी आघात को उपस्थित करने के लिए हम लोग विशोप रूप से यह मानते हैं कि निवेश अनुपात अचर रूप से समय का फलन है :

 $\delta \doteq \delta_l = \bar{\delta}$ (5')

इतना तो आवृत्ति-सम्बन्ध, किन्तु तैयारी अभी करनी है। अब उत्पादन क्षमता पर पूँजी बनाने तथा पूँजी उपयोग करने वाले तकनीकों के सभावित प्रभाव का विक्लेपण किया जाएगा।

पूँजी बचाने के तकनीको का प्रभाव

मान लिया कि पूँजी बचाने के तकनीक प्रयोग मे है। यदि इस प्रकार के तकनीकों को go की स्थायी दर पर अपनाया जाता है, तो पूँजी-निपज अनुपात मे धातीय ह्यास होगा

$$b = b_i = \frac{bo}{(I + g_b)^{i'}} \tag{6'}$$

जिसमें b_t गत्थात्मक पूँजी-निपज अनुपात, bo इस अनुपात का प्रारम्भिक मान तथा g_b इस अनुपात में ह्नास की दरें हैं। समीकरण (6') वस्तुत. पूँजी की बृदिशील उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि $a_t = I/b^t$ है। यह निम्नाक्ति अधोगामी गतियों को सुचित करता है

$$b_0 = 0,$$

$$b_1 = b_0/(I + g_0) = c/(I + g_0),$$

$$b_2 = b_1/(I + g_0) = c/(I + g_0)^2,$$

$$b_3 = b_2/(I + g_0) = c/(I + g_0)^3,$$

इत्यादि, इत्यादि ।

समीकरण (5') एव (6') को (4') मे प्रतिस्थापित करने तथा $\Delta\gamma'/\gamma'$ को G_k से निर्दिण्ट करते हुए निम्नाकित प्राप्त होता है :—

$$G_k = \frac{\widehat{\delta}}{b_0/(I+gb)_i}, \tag{7'}$$

जो यह बतलाता है कि निवेश-अनुपात (g) के स्थायी रहने पर, पूर्ण-क्षमता निपज-अनुपात में वृद्धि की दर पूँजी-निपज अनुपात में दिये हुए समय में कमी के टीक विपरीत अनुपात में बढ़ती है।

पूँजी-उपयोग के तकनीको का प्रशाव

अब हम इसकी विषरीत स्थिति की व्याख्या करेगे जहाँ मुख्य प्रवृत्ति उत्पादन के पूँजी-उपयोग वाले तकवीको को अपनाने की होती है। इसके कारणो को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि पूँजी निपज अनुपात में gb की स्थायी दर से वृद्धि होती है, तो हमें उस अनुपात के चक्रवृद्धि व्याज की वृद्धि प्राप्त होती है:

$$b = b_t = b_0 (I + g_b)^t,$$
 (8')

जिस में g_b , इस वार, पूँजी-निपज अनुपात की वृद्धि की स्थायी दर को वतलाता है। पहले की ही तरह समीकरण (S') को प्रविधत किया जा सकता है:

$$b_0 = c,$$

 $b_1 = b_0 (I + g_b) = c (I + g_b),$
 $b_2 = b_1 (I + g_b) = c (I + g_b)^2,$
 $b_3 = b_2 (I + g_b) = c (I + g_b)^3,$

इत्यादि, इत्यादि ।

(5') एवं (8') समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, समीकरण (4') को परिवर्तित रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है:

$$G_k = \frac{\delta}{b_0 \left(I + g_b\right)^{\epsilon}},\tag{9'}$$

यह समीकरण यह वतलाता है कि यदि निवेश अनुपात स्थायी रहे, तो पूर्ण-क्षमता निपज में वृद्धि की दर में बढ़ते हुए पूँजी-निपज अनुपात के ठीक विपरीत ह्रास होता है। दूसरे शब्दों में, पूँजी की ह्रासमान उत्पादकता से G_k में दीर्घकालिक कमी उत्पन्न होती है।

नीति-प्राचल के रूप: पूँजी-निपज अनुपात

श्रम-निपज अनुपात ही की तरह, पुनः संभावित नीति प्राचल के रूप में पूँजी-निपज अनुपात पर विचार करना भी लाभदायक होगा। समीकरण (3') से G_k एवं δ के दिये हुए मान के अनुरूप अपेक्षित पूँजी-निपज अनुपात प्राप्त होता है:

$$b = \frac{\delta}{G_k}, \sigma = \frac{G_k}{\delta}, \tag{10'}$$

जिसमें b एवं a कमशः अपेक्षित पूँजी-निपज अनुपात एवं पूँजी की उत्पादकता हैं । चूँिक अवंध नीति के अंतर्गत पूँजी-निपज अनुपात के वास्तविक मूल्य (b') के इसके अपेक्षित अथवा संतुजित मूल्य (b) से विचलित होने की सम्भावना रहती है, अतएव G_b एवं b का कोई दिया हुआ स्वीकार्य मूल्य होने पर, b'=b करने के उद्देश्य से, टेकनोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति की प्रकृति एवं दिशा को प्रभावित करना सार्वजितक नीति के लिए आवश्यक हो जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि एक दिये α की तुलना में उच्च G_k आवश्यक एवं वांछनीय होता है, तो समीकरण (10') के अनुसार अपेक्षित पूँजी-निपज अनुपात में अवश्य ह्वास होगा। यदि देवनोलॉजी की प्रचलित स्थित उच्च वास्तविक पूँजी-निपज अनुपात को स्थापित करने वाली है, सो उपयुंकत उदाहरण में उच्च G_k को इच्छित वस्तु के रूप में स्वीकार करने के लिए बतंमान पूँजी-निपज अनुपात को G_k एवं α के स्वीकार्य मूह्य, यानी α अनुपात के सतुलन सूह्य के समस्य जान-वूभकर करना होगा। फिर पूँजी-निपज अनुपात में कमी, यद्यपि समता-निपज में विकास की ऊँची दर को सूचित करती है, तो भी इसमें कुछ प्रत्ययात्मक एव व्यावहारिक कठिनाइयाँ अन्तग्रंस्त है।

उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) के एक अध्ययन में यह सुमान दिया गया है कि एक जनसंख्या में वृद्धि की उच्च दर एवं निम्म बंधत दर वाली अल्प-विकसित अर्थ-ज्यवस्था के लिए अपने निवेश-कार्यंक्रम में भारी उद्योगों, जैमें पूँजी-गहन योजनाओं की तुतना में कृषि जैसी घोष्ट्र फल देने वालों योजनाओं को प्रधानता देना अधिक उत्तम होगा। विक्रिं इसे केवल दृढतापूर्वंक यह क्हकर दाल सकता है कि भारी उद्योगों का कोई आधारभूत विकल्प नहीं है, जैसा एन० कालडोर ने किया था, किन्तु फिर भी गडवडी रह ही जाती है जो सिद्धातत होस नीति के लिए हानिकारक होती है। इस शोध-फल देने वाली योजनाओं को गायद इसलिए शेष्ट समभा जाता है कि ये शोधाता के दृष्टिकोण से स्वतः ही अपेक्षा-कृत निम्म पूँजी-निपज अनुपात देती है। विश्चय ही यह प्रस्ताय पूँजी-विपन्न, जना-धिक्य वाले एव अल्पविकसित देशों के लिए आकर्षक जान पडता है, किन्तु किसी भी प्रकार यह उतना स्पष्ट नहीं होता कि शीध फल देने वाली एव थम-प्रधान योजनाओं की ओर निवेश कार्यंक्रम को लगाने का परिणाम निम्म पूँजी-निपज अनुपात होता है। हम अपने सदेह को निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते है।

यू० एत० इकानॉमिक बुलेटिन फॉर एशिया एड दि फॉर ईस्ट, नवम्बर, 1955, विशेषतः 'त्रोब्लेम्स एंड टेकिनिक्स ऑफ इकॉनॉमिक डेबलपमेट प्लानिंग एड प्रोग्रॉमिंग बिंद स्पेशल रेफरेंस टुइ० सी० ए० एफ० ई० कीन्टीज'।

² दिसम्बर, 1956 ई॰ मे न्यूयाकं मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमिक एसोशियेशन की एक बैठक में, 'इकानामिक डेवलपमेंट इन इंडिया बिद स्पेशल रंफरेंस टू सेकंड फाइव ईयर 'लान' नामक भाषण में।

यू॰ एन॰ पूर्व उद्घृत ।

मान लिया कि K वास्तिवक पूँजी, N नियुक्त करने योग्य श्रम, γ निपज, K/N पूँजी-श्रम अनुपात, K/γ पूँजी-निपज अनुपात, एवं γ/N श्रम की उत्पादकता हैं। पुनः मान लिया कि K/N पूँजी-जिय अनुपात, एवं γ/N श्रम की उत्पादकता हैं। पुनः मान लिया कि K/N पूँजी-श्रवान' उद्योग अथवा योजना एवं निम्न K/N को 'श्रम प्रधान' उद्योग अथवा योजना से सम्बद्ध किया जा सकता है। यह प्रस्ताव कि एक निम्न-'पूँजी-गहन' योजना का परिणाम निम्न पूँजी-निपज अनुपात होता है, केवल तभी सत्य होगा जविक श्रम की उत्पादकता को पूँजी की तीव्रता से स्वतन्त्र मान लिया जाए। किन्तु, इस अन्तिम मान्यता की स्वीकृति संदेहात्मक जान पड़ती है; क्योंकि अवलोकन एवं अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि श्रम की उत्पादकता में औद्योगीकरण में 'पूँजी-गहन' को मात्रा के अनुसार अधिक या कम परिवर्तन होता है। इसे हम लोग पूँजी-निपज अनुपात एवं अन्य टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्राचलों के निम्न सम्बन्ध के संदर्भ में स्पष्ट कर सकते हैं:

 $\frac{K}{\gamma} = \frac{K/N}{\gamma/N} \tag{11'}$

जो यह वतलाता है कि पूँजी-निपज अनुपात पूँजी-श्रम अनुपात का प्रत्यक्ष तथा श्रम की उत्पादकता का परोक्ष तरीके से अनुरूप है। समीकरण (11') से यह स्पष्ट है कि यदि $(K/N)/(\gamma/N)$ अनुपात के भाजक को इसके भाज्य में ह्रास से अप्रमान्वित मान लिया जाय, तो पूँजी-निपज अनुपात को श्रम-प्रधान उपायों या नवीन किया से समतुल्य समभा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि श्रम की उत्पादन क्षमता (γ/N) में पूँजी की तीव्रता के गुणक (K/N) से कम अनुपात में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप उच्च पूँजी-निपज अनुपात प्राप्त हो सकेगा। अतएव, इस बात की सैद्धान्तिक सम्भावना है कि 'पूँजी-प्रधान' औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप, न कि वावजूद, पूँजी-निपज अनुपात हो सर प्रकार विख्लेषण अनुपात कि वावजूद, पूँजी-निपज अनुपात हो सर प्रकार विख्लेषण अनुपात

 इस सम्भावना को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित संख्या-सचक उदाहरण पर विचार करना लाभदायक जान पडता है:—

अपनाये गए तकनीक का प्रकार	(1) चकदार की स्थिति	(2) श्रम की उत्पादकता	(3) पूँजी-निपज अनुपात	(4) बचत अनु- पात	(5) विकास-दर
	(K N)	(γ/N)	(K/Y)	(S/Y)	(△ Y/Y)
प्रारम्भिक	50/100	10/100	5	0.05	0.01
पूँजी-प्रधान	100/100	25/100	4	0.05	0.0125
श्रेम-प्रधान	25/100	4/100	6.25	0.05	0.008

^{(3) = (1)/(2); (5) = (4)/(3)}

मे ह्यास होगा ।' इस प्रकार विश्लेषण एवं नीति, दोनों की दृष्टि से पूँजी-श्रम-अनुपात (K|N) एवं श्रम की उत्पादकता (γ/N) को केवल परतन्त्र परिवर्ती (K|Y) के सम्बन्ध में स्वतन्त्र परिवर्ती ही नही, वरन् एक दूसरे के सम्बन्ध में अन्योग्याश्रित परिवर्ती समभना महत्त्वपूर्ण है।

यह उदाहरण इस सम्भावना को स्पष्ट करता है कि न्यून पूँजी अनुपात वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था भी पूँजी-प्रधान तकनीक को अपना कर अथवा पूँजी-प्रधान औद्योगीकरण को प्रोत्साहित कर (द्वितीय पिंत की तरह) उच्च विकास दर ($\Delta \gamma/\gamma$) प्राप्त कर सकती है।

पाठक जपर्युक्त जदाहरण, जो 8 मार्च, 1957 ई० के 'इकॉनामिक बीकली' (भारत) मे प्रकाशित हमारे 'टेक्नीक्स फाँर मैक्सिमम श्रोथ एण्ड एम्प्लायमेट' के एक अश के रूप में छपा था, के प्रति श्रीमती जोन राँविन्सन तथा श्री ए० के० सेन एवं एस० साची की प्रतिक्रिया में दिलचस्पी ले सकते हैं। अन्य स्थानों में श्रीमती राँविन्सन की प्रतिक्रिया तकनीक के जुनाव के सम्बन्ध में बाद-विवाद की सचात-प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। साथ ही, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त उदाहरण से श्रीमती राँबिन्सन तथा अन्य कहाँ सहमत तथा बहाँ असहमत होते है।

'इकॉनिमिक बीकली' (अप्रैल 27, 1957) के अपनी टिप्पणी मे श्रीमती जीन रॉबिन्सन कहती है। 'वे (श्री के॰ के॰ कुरीहारा) तीन तकनीक दिखलाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 100 व्यक्ति नियुक्त किये जाते है। इनमें सर्वाधिक पूँजी-गहन तकनीक निवेश की 100 इकाई (अधिक स्पष्ट रूप से, पूँजी) से निपज की 25 इकाई उत्पन्न करता है। दूसरे निपज की 10 इकाई के लिए 50 इकाई निवेश नाहता है। इनमें से पहला तकनीक (हम लोगों के सख्या-मूलक उदाहरण में दूसरी पित प्रत्येक दृष्टिकोण से अन्य दो से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार का तक, उदाहरण के लिए अम्बर चरखा के विश्व प्रयोग किया जा सकता है, जिसका एक सूत कातने वाले, कारखाने की तुलना में दोनों प्रति व्यक्ति तथा प्रति इकाई निवेश से कम उत्पा-दन होता है, किन्तु इसका दो प्रकार के करघों के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पडता। इनमें से पहले प्रकार का करघा कम यन्त्रीकृत होने के कारण प्रतिव्यक्ति कम, किन्तु निवेश की प्रति इकाई अधिक एव दूसरा अधिक यत्रीकृत होने के नारण निवेश की प्रति इकाई अधिक, किन्तु प्रति-व्यक्ति कम उत्पादन करता है।'

श्री ए॰ कें॰ सेन अपने 'मंन, मशीन एण्ड प्रोथ' (30 मार्च, 1957 के , 'इकॉनामिक बीकली' मे) में कहते है, 'प्रो॰ कुरिहारा का यह प्रस्ताव बिल्कुल -पूंजी बचाने एवं पूंजी प्रयोग करने वाले तकनीकों पर प्रभाव

पूँजी-निपज अनुपात (g_b) में परिवर्तन की दर को प्रभावित करने वाली प्रवृतियों का चित्रण करना कठिन होते हुए भी संभव है। किन्तू, यहाँ पर आगे हम लोग

ठीक है कि पूँजी की गहनता के अल्पीकरण से पूँजी-निपज अनुपात अल्प नहीं होता । यदि (γ/N) में (K/N) के अनुपात से अधिक वृद्धि हो, तो सम्भव है कि उच्च पूँजी-श्रम अनुपात से निम्न पूँजी-निपज अनुपात की प्राप्ति हो । यह वास्तव में तथ्य का प्रश्न है तथा (K/N) एवं (K/Y) के वीच सम्यन्ध का दो में से एक तरफ़ सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रो० कृरिहारा श्रम की उत्पादकता (γ/N) को पूँजी की गहनता (K/N) से स्वतन्त्र मानने की कल्पना करते हुए वचत-अनुपात (S/γ) को इससे स्वतन्त्र मानते हैं (तीनों स्थिति में 0.05)। किन्तु, वचत-अनुपात निश्चय ही मजदूरी के विल तथा निपज के अनुपात पर निर्भर करता है, जो स्वयं श्रम की उत्पादकता (Y/N) पर आश्रित है।'

एस० साची अपने "प्रो० कुरिहारा ऑन चायस आफ टेकनीक्स" (इकॉना-मिक चीकली, मार्च, 1957 में) में कहते हैं, "जैसा कि अन्य लोगों ने इसके पूर्व किया है"; प्रो० कुरिहारा दृढ़ता से इस सिद्धान्त (कि अम की प्रचुरता के परिणाम-स्वरूप अल्प-विकसित देशों को अम-प्रधान उद्योगों का विकास करना चाहिए) का खण्डन करते हैं, जैसा कि अन्य कई व्यक्तियों ने पहले किया है। ऐसी स्थिति में (उपर्युक्त संख्या-मूलक उदाहरण के संदर्भ में) चुनाव का कोई प्रभन ही नहीं रह जाता। यदि पूँजी-प्रधान निवेश की पद्धित को नहीं चुना जाय, तो यह केवल अज्ञानता-मात्र होगी। किन्तु, जब एक प्रकार की निवेश-पद्धति, दूसरी की तुलना में, प्रारम्भ में विकास की निम्न दर तथा बाद में उच्च दर प्रदान करती है. तभी चुनाव की वास्तविक समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में किस पद्धति को चुना जाय, यह आर्थिक विश्लेषण के बजाय राज-नीतिक विचारों पर निर्मर करता है।

सैद्धान्तिक स्तर पर देखें — डब्लू० फेलनर का पूर्व उद्धृत "दि कैपीटल आउटपुट रेशियो इन डायनिमक इकॉनामिक्स" जे० रॉविन्सन का पूर्व उद्धृत 'नोट्स आंत दि इकॉनामिक्स ऑफ टेकनिकल प्रोग्रेस'; वाई० टाकटा का पूर्व उद्धृत; एस० सुरु का अग्रैल 1956 ई० के इकॉनामिक रिब्यू में प्रकाशित "ए नोट ऑन कैपिटल आउटपुट रेशियोज"। आनुभविक आधार पर देखें — जून 1953 के "हारवर्ड इकॉनामिक रिसर्च प्रोजेक्ट", ऍस्टिमेट्स ऑफ दि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इन्डस्ट्रीज, 1947; डी० कीमर का कैपिटल एंड आउटपुट ट्रेंड्स इन मैनुफैक्चरिंग इन्डस्ट्रीज 1880-1948 (नेश्वनल बुरो आफ इकॉनामिक रिसर्च का 41वां कदाब्तिक पेपर, 1947), एम० शिनोरा का अक्टूबर, 1956 के इकॉनामिक रिस्मू में प्रकाशित 'दि डिफरेंस आफ कैपिटल आउटपुट रेशियोज एंमाँग

वेवल उन प्रभावो का वर्णन करेंगे, जो पूँजी प्रयोग करने वाले तकनीकों को अपनाना अवदा उत्माहित करना अनिवार्य वनाते हैं और इस प्रकार पूँजी-निपज अनुपात को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत वाले प्रभावो को पाठकों के अनुमान के लिए छोड़ दिया जाएगा। ययोकि, यहाँ हम लोग मुख्यत इस बात से सम्बद्ध हैं कि स्यायी निवेश अथवा वचत अनुपात के दिये हुए रहने पर आधिक विकास वो सीमित करने वाले वारण के रूप में हमें उच्च पूँजी-निपज अनुपात को समास्त करने के लिए क्या करना चाहिए।

आगे की ध्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में अनावश्यक उच्च पूँजी-निपज अनुपात का एक मीलिक कारण पूँजी-गहनता की निम्त मात्रा है, जो दिये हुए अम की तुलना में पूँजी से प्राप्त निपज को अधिक अनुपात में घटा देता है। दूसरे शब्दों में, श्रम की तुलना में पूँजी की मितव्यियता (कम चन्नदार) के प्रयत्नो के परिणामस्वरूप एक दी हुई निपज को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पूँजी की मात्रा में विरोध मासी तरीके से वृद्धि होती है। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, यह विरोधाभास इस सम्भावना का परिणाम है कि धम की प्रति इकाई पूँजी (K/N) में ह्वास पूँजी-निपज अनुपात (K/γ) की घटाने के बजाय बढा सकता है, यदि, जैसा कि समीकरण (11') से स्पष्ट है, श्रम की प्रति इकाई पूजी मे यह हास थम की उत्पादकता में अनुपात से अधिक कभी उत्पन्त करता है। जोन राँबिन्सन इसके लिए एक इसरा कारण बतलाती हैं जो इस प्रकार है: "जहाँ साहसी एक दूसरे में पूँजीणत माल परीदते हैं, मजदूरी-दर की तुलना में पूँजीगत बस्तुओं के मूल्य में कमी से पूँजी-प्रयोग के तकनीकों को अपनाने में प्रोत्साहन मिलता है।" यह उन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विशेष महस्य का होता है, जो मुख्यतः आयात किए गए उपकरणोतया कच्चे पदार्थी पर निर्भर करती हैं तथा जिनमे वडे समाकलित उद्योगों का अभाव रहता है, जिनके लिए साधनों के मुल्य से बहुत कम अन्तर होता है, और पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अनुकृत ह्याम होगा। ऐसा केवल इसलिये नहीं कि पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादकों एवं निर्यातकों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से इनके मूल्य में कमी होगी, वरन् इसलिए भी कि जनसरुया में आतरिक वृद्धि मजदूरी की श्रीसत दर पर अधोमुखी दवाव डासती है । यही परम्परागत विश्लेषण प्राप्तांगक हो जाता है । पूँजी-श्रम अनु-पात की आधित परिवर्ती के रूप में निम्न तरीके पर विचार ह

इन्डस्ट्रीज'; बाई॰ ओक्जेकी का मार्च, 1957 के 'इकानॉमिक स्टडीज स्वाटलींज' में 'ऑन दि कैपिटल को-एफिशियन्ट इन अडर-डेवलप्ड कस्ट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू दि केसेज आफ इण्डिया एड जायान'।

देखें उननी पुस्तक दि रेट ऑफ इंटरेस्ट, एटसेट्रा, पृष्ठ 52-3।

$$\frac{K}{N} = f\left(\frac{P_k}{P_m}\right),\tag{12'}$$

जिसमें P_k पूँजी का औसत मूल्य (कुछ परिभाषा के आधार पर) और P_n श्रम का औसत मूल्य (मौद्रिक मजदूरी की दर) हैं। तब श्रम के रूप पूँजी में प्रतिस्थापन की लोच को निम्नलिखित सामान्य रूप में व्यक्त किया जा सकता है:

$$e = \frac{P_k/P_n}{K/N} \cdot \frac{d(K/N)}{d(P_kP_n)} = \frac{d(K/N)}{d(P_kP_n)} / \frac{K/N}{kP/P_n} \rightleftharpoons 1, \tag{13'}$$

इसमें e लोच गुणक को सूचित करता है, जो इस सुविधा की मात्रा को मापता है, जिससे साधनों के सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन के प्रतिवचन में श्रम के बदले पूँजी का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। यदि श्रम की उत्पादकता को स्थिर मान लिया जाय, तो समीकरण (11') के योग से समीकरण (12') एवं (13') यह सूचित करते हैं कि e=1 स्थायी पूँजी-निपज अनुपात तथा e>1 वर्णनाधीन उच्च पूँजी-निपज अनुपात तथा e<1 निम्न पूंजी-निपज अनुपात के लिए उत्तरदायी हैं। जहाँ तक स्वयं साधनों के मूल्य में परिवर्तन का सम्बन्ध है, ये पूँजी एवं श्रम के सापेक्ष अभाव, पूँजी एवं श्रम के सापेक्ष अभाव, पूँजी एवं श्रम वाजार के संगठन, संगठित पूँजी एवं श्रम की भित्तयों की तुलनात्मक सौदा-भित्त तथा संभवत: उत्पादक साधनों के बीच दी हुई राष्ट्रीय आय के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक नीति पर निर्भर करता है।

अल्प-विकसित अर्थ-त्र्यवस्थाओं में साधारणतया उच्च पूँजी-निपज अनुपात का एक अन्य संभावित कारण औद्योगीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में टिकाळ विकास पूँजी—जैसे इस्पात, विजली, जहाज-निर्माण तथा अन्य पूँजी-उपयोग-सम्बन्धी कार्यों की संरचनात्मक आवश्यकता है। इसका परिणाम यह होता है कि नयी अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी-उपयोग की तकनीकी प्रगति की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा अंगतः इसलिए होता है कि ये अर्थ-व्यवस्थाएँ अभी तक परिपक्व स्थिति तक नहीं पहुँच पाई हैं, जहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध (प्रवन्ध एवं व्यवस्था-सम्बन्धी) एवं अन्य पूँजी बचाने वाली प्रगति तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है। साथ ही, कृषि-क्षेत्र में व्यापक उन्नति के लिए भी, जैसा कि तीव्र गति से उन्नति करने वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, स्पण्टतया प्रति इकाई कृषि-निपज के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-निपज अनुपात की प्रवृत्ति के इतना उच्च होने का एक अन्य प्रधान कारण व्याज की उच्च दर है। यह कुछ विरोधाभासी जान पड़ सकता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान से यह जात होता है कि उच्च व्याज की दर

उत्पादन की प्रक्रिया में पूँजी के प्रयोग को हतोत्साहित करता है और इस प्रकार पूँजी-निपज अनुपात को कम करने का प्रयास करता है। किन्तु पूनविचार करने पर यह दिखावटी विरोधाभास समाप्त हो जाएगा। ब्याज की उच्च दर में श्रम की तुलना मे पूँजी के प्रयोग को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है (निम्न K/N); क्योंकि यह वर्तमान परिस्थिति के पुँजीगत मुल्य को नयी परिसपत्ति के सम्भावित पूर्ति मुल्य की तुलना में कम कर देती है और इस प्रकार पहले की अपेक्षा बाद वाली परिसपत्ति को अधिक मृत्यवान एव कम आकर्षक बना देती है। केन्स की प्रचलित शब्दावली मे, इसरा अर्थ यह है कि पूँजी की सीमात क्षमता (शुद्ध लाभ की दर) बाजार की ब्याज दर से निम्न है जिससे यह स्टॉक, ऋण-पत्र एव अन्य वर्तमान परिसपति मे वित्तीय निवेश की तुलना में टिकाऊ उपकरणों में वास्तविक निवेश की हतौत्साहित करता है। मुद्य बात यह है कि यदि ब्याज की प्रचलित उक्च दर से उत्पादन का चकदार तरीका हतीत्साहित होता है (थानी K/N निम्न होता है) तो पूँजी की तुलना में निपज में सभवत अधिक अनुपात में ह्याम होगा, जिससे समीकरण (11') के अनुसार पूँजी-निपज अनुपात वढ जाएगा। इस प्रकार ब्याज की निरन्तर ऊँची दर की सभावना मे कम पूँजी-प्रधान (या अधिक श्रम-प्रधान) तकनीकी को प्रोत्साहित करने तथा मजदूरी एवं शुद्ध लाभ की थी हुई स्थायी दर होने पर निपज पर बाद बाले घटते हुए दबाद के कारण उच्च पंजी-निपज अनुपात के निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है।

अतत एक अस्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था मे निपज की बताबट तथा नये उद्योगों के आकार एव स्थित का भी उच्च पूँजी-निपज अनुपात पर कुछ प्रभाव पडता है। उदाहरण के लिए, यदि हस्त-निमित वस्तुओं की तुलना मे यत्र-निमित वस्तुओं को अधिक पसद किया जाता है, तो निपज मे बनाबट मे इस प्रकार परिवर्तन होगा, जिससे प्रति इकाई निपज से अधिक पूँजी को आवश्यकता पडेगी। साथ ही, यदि नये सयत्र तथा उद्यमो के आकार में वृद्धि होती है, किन्तु ये कच्चे पदार्थों के साधनों (जो अधिक काशत विदेशों मे पाये जाते है) से बहुत दूर स्थित हो, तो अतिरिक्त वास्तविक निपज की तुलना में पूँजीयत लायत में वृद्धि होगी, जिसके साथ सपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पँजी-निपज अनुपात में बद्धि होगी।

अध्याय 6

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में दोहरी बेरोजगारी

केन्स के रोजगार के सामान्य सिद्धान्त में व्यापकता का यथाव है; क्यों कि यह उस प्रकार की वेरोजगारी पर विचार नहीं करता, जो पूर्ण प्रयोग के वाद भी वास्त-विक पूँजी के अभाव के कारण वर्तमान रहती है, यानी जो पूँजी के वर्तमान कोप के पूर्ण प्रयोग के लिए समर्थ माँग की पर्याप्तता के वाद भी पाई जाती है। उसका रोजगार का सिद्धान्त अल्पकालीन स्थिति में लागू होता है, जिसमें पूँजी-संचय, जनसंख्या की वृद्धि, तकनीकी प्रगति तथा पूर्ति की अन्य आधारभूत शत दी हुई मान ली जातीं हैं और इसलिए उस रोजगार की मात्रा अनन्य रूप से समर्थ माँग के स्तर द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार, केन्स का सिद्धान्त केवल समर्थ माँग को स्थायी वनाने अथवा वढ़ाने के उद्देश्य से पिरामिड-निर्माण की तरह अनुत्पादक रोजगार की नीति को युवितसंगत ठहराने में प्रयुक्त होने का खतरा मोल लेता है।

इसी केन्सीय पृष्ठभूमि में हैरोड रोजगार के स्थायित्व पर विचार करने में उत्पादकता के दीर्घकालीन महत्त्व पर जोर देते हैं। इनके अनुसार 'सतत विकास की दर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वातों पर ध्यान दिये वग्रैर अल्पकाल में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना अदूरदर्शिता है। 'में केन्स के रोजगार के अल्पकालीन सिद्धान्त तथा मार्क्स के रोजगार के दीर्घकालीन सिद्धान्त के बीच लुप्त कड़ी प्रदान करने का श्रेय हैरोड को दिया जाता है। क्योंकि, जैसा कि जोन रॉविन्सन का कहना है कि अयद्यपि कि उनका यह विल्कुल विचार नहीं है, तथापि हैरोड हमें मार्क्स के श्रम की आरक्षित सेना की ओर ले जाते हैं, जो पूँजी-संचय की दर की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि एवं कमी के अनुसार बढ़ती अथवा घटती है। इस अन्तिम प्रकार को इन्होंने 'केन्सीय वेरोजगारी' के विपरीत "मार्किस्यन वेरोजगारी' का नाम दिया है। जोन रॉविन्सन ने

आर० एफ० हैरोड, डायनिमक इकॉनामिक्स, पु० 74 ।

^{2.} जे॰ रॉबिन्सन, मि॰ हैरोड्स डायनामिक्स, पूर्व उद्धृत।

^{3.} पूर्व उद्भुत।

यह भी सुभाव दिया है कि "माविसयन वैरोजगारी उस प्रकार की वैरोजगारी है, जो पूरव के पिछड़े हुए एव जनाधिनयवाले देशों तथा युद्ध-विनष्ट अर्थ-व्यवस्थाओं मे जहाँ केवल काम करने के लिए साधनों एवं सामानों के अभाव में वेरोजगारी पाई जाती है, वर्तमान रहती है।"1

इस प्रकार केन्स का रोजगार सिद्धान्त, विचलन का वह केन्द्रीय विन्दु प्रदान करता है, जहाँ से रिकाडों के स्वत पूर्ण रोजगार (व्य' ल से के नियम) विश्व की आलोचना की जा सकती है तथा माल्यस एव माक्स के जनाधिक्य वाले विश्व और धर्म की आरक्षित सेना की धारणा पर विचार किया जा सकता है। साथ ही, केन्स के वेरोज-

देखें 'कलेक्टेड इकॉनामिक पेपसं' में इनका निबन्ध 'मावर्स एन्ड केन्स' पूर 133-145।

केत्स के रोजगार के सिद्धान्त को विकासोन्सुत एव उन्नत्वशीय अर्थ-व्यवस्था के लिए लागू करने के प्रयास के लिए देखें, हैरोड का 'डायनिवन इकॉनामिक्स'; डोमर का पूर्व उद्धृत 'एक्सफेश्यान एव एम्पलायमेन्ट'; जीन रॉक्सिन का 'द रेट ऑफ इन्टरेस्ट एटसेस्ट्रा', विशेषत. तृतीय अध्याय 'दि जेनरलाइजेशन ऑफ द जेनरल विवरी', एम० वालेकी का राईनहर्ट, न्यूयार्क 1954 का 'विवरी ऑफ इकॉनामिक डायना-मिक्स', विशेषत छठा भाग, बी० हिगीन्स का जून 1950 के 'इकॉनामिक जरनल मे 'द विवरी ऑफ इक्तीजिय अन्डर इम्पलायमेन्ट; आर० आइनर का पूर्व उद्धृत 'अन्डर इम्पलायमेन्ट रेट्स ऑफ श्रोथ', डी० हैम्बर्य का अगस्त 1952 ई० के 'क्वाटरली जरनल ऑफ इकॉनामिक्स' में 'फुल कैपेमिटी वर्सेंज फुल एम्पलायमेन्ट ग्रोथ'; एच० पितवीन का 'फुल कैपेसिटी वर्सेंज फुल एम्प्लायमेन्ट ग्रोथ'; एच० पितवीन का 'फुल कैपेसिटी वर्सेंज फुल एम्प्लायमेन्ट ग्रोथ' एच० पितवीन का 'फुल कैपेसिटी वर्सेंज फुल एम्प्लायमेन्ट ग्रोथ' एच० पितवीन का 'फुल कैपेसिटी वर्सेंज फुल एम्प्लायमेन्ट ग्रोथ' 'उसी स्थान मे नवम्बर 1953 ई० (हैरोड एव डोमर की टिप्पणी के साथ)।

^{3.} अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से सम्बद्ध निम्नलिखित है—जोन रॉबिंग्सन का अवट्वर, 1955 का इकॉनामिक रिट्यू (जापान) में प्रवाशित 'ए थिवरी ऑफ लौग-रन डेयलपमेन्ट' तथा 23 जून, 1956 ई० के इकॉनामिक घोकली (भारत) में प्रकाशित 'द वायस ऑफ टेकनीक'; आर० नक्मे, प्रोडलम्स ऑफ फेंपिटल फ्रॉरमेशन इन अन्डरडेवलप्ड इकॉनामिकझ; ए० एन्ड डी आई० एम० नवारेटे का 1953 के न० 3 इन्टरनेशनल इकॉनामिक पेपसे में 'अन्डर एम्पलायमेन्ट इन अन्डरडेवलप्ड इकॉनामिकस; स्टडीज इन पृोच इकॉनामिकस (वाई० ताकता द्वारा सम्पादित) से एम० मीरिथिमा का 'फूल एम्पलामेन्ट पॉतिमी इन ए प्रोइंग इकॉनामी' तथा एस० फूजीता का 'प्रोच थियरी एन्ड सुपरपन्अस पापुलेशन'; 4 अगरत, 1956 के इकॉनामिक वीकली में डि० घोष ना 'टेकनीक ऑफ प्रोडकगन

गार के सिद्धान्त को अल्प-चिकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए विल्कुल अप्रयोज्य कहकर टाल देना गलत होगा। ऐसा केवल इसलिए नहीं होगा कि अल्पकाल मिलकर केन्स के उस दीर्घकाल का सर्जन करते हैं, जिसमें 'हम सभी मर जाते हैं', वरन् मृलतः इसलिए कि मुख्य रूप से निजी व्यवसाय पर संचालित अल्प-चिकसत अर्थ-व्यवस्थाएँ समर्थ माँग की चक्रीय अभाव की सम्भावनाओं से मृक्त नहीं हो सकतीं दीर्घकालीन गैर-केन्सीयन वेरोजगारी के साथ-साथ अल्पकालीन केन्सीयन वेरोजगारी की उप-स्थिति से अल्प-चिकसित अर्थ-व्यवस्था की पूर्ण रोजगार सम्बन्धी नीति वहुत ही जिल्ल हो जाती है; क्योंकि पहले को दूर करने के लिए अल्पकालीन उपाय आवश्यक रूप से वादवाले दीर्घकालीन उपायों को दूर करने के लिए अलुक्प नहीं होते।

वर्तमान अध्याय का सम्बन्ध व्यापकतया अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में विरोजगारी की दुहरी प्रकृति से हैं । इसका सम्बन्ध अधिक विशिष्ट रूप से (क) केन्सीयन वेरोजगारी की चक्रीय वृद्धि तथा (ख) ग़ैर-केन्सीयन वेरोजगारी की व्यिष्ट से हैं । दोनों हालतों में पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार के लिए प्राचलीय कार्यक्रम पर भी विचार किया जायगा । छिपी हुई वेरोजगारी के सम्बन्ध में भी पण्च-लेख के रूप में कुछ टिप्पणी की जाएगी ।

केन्सीयन वेरोजगारी की चक्रीय वृद्धि

पूँजीवादी प्रकृतिवाली अल्प-विकसित अर्थं-ज्यवस्था अपने विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम की अल्पकालीन परिधि (उदाहरण के लिए पाँच वर्ष) के अन्तर्गत केन्स द्वारा वर्णित चकीय वेरोजगारी का अनुभव करती है। क्योंकि, इसकी समर्थ माँग यचिप यह दीर्घकाल में उत्पादन-क्षमता से बढ़ जाती है, तथापि अल्पकाल में उत्पादन-क्षमता से कम पड़ सकती है। इस प्रकार की सम्भावना ऐसी अल्प-विकसित अर्थ-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में, जिनकी निर्यात-सम्बन्धी आय तथा निजी निवेश-परिमाणात्मक रूप में इनकी कुल समर्थ माँग का प्रधान साधन होते हैं—विशेप रूप से पाई जाती है। केन्स के वेरोजगारी-सम्बन्धी विश्लेपण की संबद्धता एवं अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में केन्स की पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी नीति की विशेपताओं को स्पष्ट करने के लिए हम पहले बड़ी संख्या में अनैच्छिक वेरोजगारी में चकीय वृद्धि के वर्णन से प्रारम्भ करेंगे।

श्थम की पूर्ति

यदि जनसंख्या, तकनीक एवं साधनों के मूल्यों को दिया हुआ मान लिया जाय,

एन्ड एम्पलायमेन्ट इत एन अन्डरहेवत्न्इ इकॉनामी; अगस्त, 25, 1956 के उसी में ए० के० दास गुप्ता का 'डिसगाइज्ड अनइम्प्लायमेन्ट एन्ड इकॉनामिक डेवलपमेन्ट, के० के० कुरीहारा का पूर्व उद्धृत 'ग्रोथ एनेलेसिस् एन्ड द प्रोव्लम ऑफ कैंपिटल एकुमुलेशन इत अन्डरडेवलप्ड कन्ट्रीज'।

तो इस प्रकार की मान्यता सम्भव होगी कि सदा इतनी मात्रा में श्रम वर्तमान रहता है, जिससे कि पूँजी के वर्तमान कीय को पूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में, हम यह मानते हैं कि श्रम की पूर्ति में उसी दर से वृद्धि होती है, जिस दर से पूँजी के वर्तमान कोय को पूर्ण रूप से एवं सत्त प्रयोग के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग सरचनात्मक वेरोजगारी की प्रकृति एवं उद्भव का अध्ययन प्रारम्भ करेंगे, तो यह मान्यता समाप्त हो जायगी। यथार्येता के लिए हम मानते हैं कि निम्नलिखित शत सदा पूरी होती हैं—

$$N = Nr, \ \triangle N = \triangle Nr, \tag{1}$$

जिनमें N उपलब्ध थम की मात्रा है, जो जनसब्या की वृद्धि के द्वारा शासित होती है तथा Nr पूंजी के वर्तमान कीप को पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए अपेक्षित थम की मात्रा है। (1) द्वारा दी गई शतें यदि पूरी हो जाये, तो वे इस वात का विश्वास दिलाती है कि श्रम का अभाव पूंजी के पूर्ण प्रयोग में कभी रकावट नहीं उत्पन्न कर सकता। वे इस वात की ओर भी सकेत करती हैं कि यदि पूंजी का वर्तमान कीप पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं होता है, यानी यदि वेकार अथवा अधिक क्षमता वर्तमान है, तो यह समर्थ माँग की अपर्याप्तता के कारण है। इस प्रकार यदि मान लिया जाय कि श्रम की पूर्ति अपने की श्रम की किसी भी माँग के अनुरूप वना लेती है, तो केम्सीयन वेरोजगारी की उपस्थित की श्राह्म माँग की परिस्थितियों के सन्दर्भ में की जा सकती है। यहां अपेक्षित श्रम की माँग एव वास्तविक श्रम की माँग में स्पष्ट रूप से अन्तर करना अनिवार्य है। इतमें पहले प्रकार की साँग पर पहले विचार कर लिया जाय।

अपेक्षित श्रम की मांग

यदि समर्थ माँग (सम्पूर्ण निपज के लिए) को इतना अधिक मान लिया जाय, जो पूँजी के वर्तमान कोय के पूर्ण प्रयोग को आवश्यक बना देती है, तो उस पूर्ण प्रयोग के लिए आवश्यक श्रम की मात्रा निम्नाकित रूप से दी जाती है:

$$Nr = \beta K$$
, (2)

जिसमें Κ पूर्ण प्रयोग के बाद वास्तविक पूजी की मात्रा है तथा β टेक्नोलॉर्जी की वर्तमान स्थिति द्वारा दी हुई श्रम की गहनता का गुणाक (पूर्ववर्णित पूजी-श्रम अनुपात का व्युक्तम) है। समीकरण (2) पूजी के वर्तमान कोप के पूर्ण प्रयोग से उपलब्ध रोजगार की अधिकतम सभाव्य मात्रा को बतलाता है।

हम जानते हैं कि पूंजी एवं निपज निम्न रूप से सम्बद्ध है :

$$K=bY', (3)$$

जिसमे Y' पूर्ण क्षमता-निपज तथा b औसत तथा सीमान्त पूँजी निपज

अनुपात हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि मुद्ध निवेश (1) अतिरिक्त पूंजी ($\triangle K$) के वरावर है और साम्य की स्थिति में बचत के बरावर होता है, यानी

$$I = \triangle K = sY', \tag{4}$$

जिसमें ऽ पूर्ण क्षमता निपज पर वचत की औसत क्षमता है।

(3) एवं (4) से पूर्ण नियुक्त पूँजी में वृद्धि प्राप्त होती है:

$$\triangle K = \frac{s}{b}K,\tag{5}$$

. जिससे पूर्ण नियुक्त पूँजी में वृद्धि की दर प्राप्त होती है (यानी, इस समीकरण के दोनों पक्षों को K से भाग देने पर)

$$\frac{\triangle K}{K} = \frac{s}{b},\tag{6}$$

समीकरण (2) एवं (6) को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपेक्षित, श्रम में वृद्धि की दर को निम्नांकित प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं:

$$\frac{\triangle Nr}{Nr} = \frac{\beta \triangle K}{Nr} = \frac{\beta \triangle K}{\beta K} = \frac{\triangle K}{K} = \frac{s}{b}$$
 (7)

जो यह वतलाता है कि अपेक्षित श्रम की मात्रा में पूर्ण नियुक्त पूँजी में वृद्धि की दर के वरावर दर, यानी s/b की दर से वृद्धि हो सकती है। यदि s/b स्थायी है, तो समीकरण (7) पूर्ण क्षमता वृद्धि के अनुरूप प्रगतिशील पूर्ण रोजगार के एक स्थायी क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु, वास्तविक रोजगार पूर्ण रोजगार के इस स्थायी कम पर होगा या नहीं, यह श्रम की पूर्ति की लोच, जिसे हम लोग वर्तमान समय में अनन्त मानते हैं, पर निर्भर नहीं करके, समर्थ माँग, जिसे हम लोग दिया हुआ मानते हैं, के आचरण पर निर्भर करती है। अव यहाँ पर हमें वास्तविक श्रम की माँग के निर्धारण को देखना चाहिए।

वास्तविक श्रम की मांग

श्रम को सज्जित करने के लिए वास्तविक पूँजी के कोप के दिया हुआ होने पर, वास्तविक नियुक्त श्रम की मात्रा समर्थ माँग का फलन है, यानी—

$$Ne = \varepsilon Y^{\circ},$$
 (8)

जिसमें Ne वास्तिविक राष्ट्रीय आय या समर्थ माँग की अनुिकया में माँगी जाने वाली वास्तिविक श्रम की मात्रा है, Yo वास्तिविक राष्ट्रीय आय या समर्थ माँग के स्तर तथा ह समर्थ माँग की तुलना में नियुक्त श्रम का टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया अनु-पात है।

केन्स के गुणक सिद्धान्त से हम लोग यह जानने है कि समर्थ मांग निम्नाकित मात्रा से परिवर्तित हो सकता है:

$$\triangle Y^{\circ} \frac{I}{s'} \triangle I, \tag{9}$$

जिसमे $\triangle I$ वास्तिथिक शब्दों में अपूर्वानुमेय निजी निवेश एवं पूर्वविणित विदेशी होंग की सिमितित करते हुए स्यतन्त्र निवेश गुणक तथा s' यचत की सीमात प्रवृत्ति है। यहाँ पर I/s' गुणक है। घ्यान दैने योग्य यात यह है कि यहा बचत की सीमान प्रवृत्ति (s') समीकरण (4)-(7) में पाई जाने वाली बचत की औसत प्रवृत्ति (s) की तरह स्थायी नहीं है।

यदि हम लोग अतिरिक्त निवेश को निश्चित रूप से समर्थ माँग से सम्बद्ध भानते हैं, तो हमें निम्नाकित प्राप्त हो सकता हैं—

$$v = \frac{\triangle I}{Y^2},\tag{10}$$

जिसमें भ समर्थ माँग एवं चृद्धिशील निवेश का अनुपात है और उतना ही अस्थायी हो सकता है जितना कि स्वतन्त्र निवेश को प्रभावित करने वाले तत्त्व परिवर्तनीय हैं (सार्वजनिक निवेश को छोडकर)।

समीकरण (9) एव (10) से समर्थ माँग में वृद्धि की निम्नांकित दर प्राप्त होती है:

$$\frac{\triangle Y^{\circ}}{Y^{\circ}} = \frac{I}{s'} v = \frac{v}{s'}. \tag{11}$$

जो दर चन्नीयतः उतना ही परिवर्तनीय है, जितना कि उसके निर्धारक (s', v) अस्यायी है।

समीकरण (9) एव (11) को ध्यान में रखते हुए वास्तविक थर्म में वृद्धि की दर को निम्नाकित तरीके से लिखा जा सकता है:

$$\frac{\triangle Ne}{Ne} = \frac{\epsilon \triangle Y^{\circ}}{Ne} = \frac{\epsilon \triangle Y^{\circ}}{\epsilon Y^{\circ}} = \frac{\triangle Y^{\circ}}{Y^{\circ}} = \frac{\nu}{s'}, \tag{12}$$

को यह बतताता है कि माँगी हुई बास्तिविक श्रम की माँग v/s' की दर से बढ़ सकती है, सानी यदि बास्तिविक श्रम एवं समर्थ माँग का अनुपात (६) स्थायी हो, तो यह • माँग में यदि की दर से ही बढ़ेगी।

केन्सीयन बेरोजगारी की वृद्धि

पूर्ववर्ती विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि केन्स के अर्थ में पूर्ण रोज़गार को वनाये रखने के लिए आवश्यक शर्ते निम्नांकित के द्वारा व्यक्त की जाती हैं—

$$\frac{\triangle K}{K} = \frac{\triangle Y^{\circ}}{Y^{\circ}}, \quad \frac{s}{d} = \frac{v}{s'}, \tag{13}$$

किन्तु यदि निजी निवेश अथवा निर्यात से प्राप्त आय (१ के द्वारा व्यवत) में अस्थायी ह्रास के कारण पूँजी का आधिवय, अथवा समर्थ माँग की कमी उत्पन्न हो जाती है, तो अपेक्षित श्रम एवं माँग जाने वाले वास्तविक श्रम में असंगति उत्पन्न होगी। क्यों- कि, जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, चक्रीय वेरोजगारी की माप पूँजी की वर्तमान कीप के पूर्ण प्रयोग से प्राप्त पूर्ण रोजगार एवं वास्तविक रोजगार, जिसे समर्थ मांग का वर्तमान स्तर सम्भव बनाता है। से होती है, अतएव, वर्तमान गतिशील सन्दर्भ में केन्सीयन वेरोजगारी को निम्नांकित रूप में व्यवत किया जा सकता है:

$$\frac{\triangle U^c}{U^c} = \frac{\triangle Nr}{Nr} - \frac{\triangle N^c}{N^c} = \frac{s}{b} - \frac{v}{s'}, \tag{14}$$

जिसमें $\frac{\triangle U_0}{U_0}$ माँग (सम्पूर्ण निपज के लिए) में वृद्धि की दर से पूँजी की वृद्धि की दर में आधिक्य के परिणामस्वरूप केन्सीयन वेरोजगारी में वृद्धि की दर है और जिसमें सिरनामा c संलग्न वेरोजगारी की समस्याकी चक्रीय प्रकृति को व्यक्त करता है। समीकरण (14) के द्वारा व्यक्त केन्सीयन वेरोजगारी की वृद्धि पूर्ण क्षमता की वृद्धि के अनुरूप प्रगतिशील पूर्ण रोजगार की स्थिर रेखा से चक्रीय विचलन (निम्नगामी) की मात्रा को मापता है। यह विकसित अथवा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूंजीवाद के चक्रीय विकास को स्पष्ट करता है। फिर भी, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में, जो समीकरण (13) में दिये हुए सन्तुलन की शर्तों की पूर्ति का प्रयास करती है, ऐसे तरीकों, जो संरचनात्मक वेरोजगारी की अधिक गम्भीर एवं मौलिक समस्या के समाधान के दीर्घ-कालीन उद्देश्यों को समाप्त कर दें, को नहीं अपनाये जाने के लिए कटोर दवाब पड़ता है। इस अपवाद को ध्यान में रखकर अब हम लोग मध्यम एवं दीर्घकालीन पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार के लिए परिचालन-सम्बन्धी सम्भावनाओं की संक्षेप में खोज करें।

केन्सीयन वेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राचलीय संक्रिया

वचत की, सीमान्त क्षमता (s') को, पूर्व निश्चित वचत की आदतों को व्यक्त करने वाले स्थायी प्राचल मानते हुए केन्स ने स्थतन्त्र निवेश (v द्वारा व्यक्त) को परि-वर्ती नीति-प्राचल माना है। किन्तु, वर्तमान सन्दर्भ में नीति के कुशल प्रयोग के क्षेत्र के विस्तार के लिए हम v एवं s' दोनों को परिवर्ती नीति-प्राचल मानेंगे। साथ ही,

केन्सीयन वेरोजगारी से पीडित अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए उपलब्ध वैकल्पिक मार्ग को देखने के लिए v एव s' को अलग-अलग करना अनिवार्य है।

अतिरिक्त स्वतन्त्र निवेश एव समर्थ माँग के अनुपात को हम लोग निम्नावित प्रकार से अनग-अलग कर सकते हैं—

$$v = \frac{\Delta I_v + \Delta I_o + \Delta E}{Y^\circ} = \frac{\Delta I_v}{Y^\circ} + \frac{\Delta I_s}{Y^\circ} + \frac{\Delta E}{Y^\circ} = v_o + v_s + v_s, \quad (15)$$

जिसमे I_{σ} अन्तरिक निजी निवेश, I_{σ} सरकारी निवेश, E निर्यात-सम्बन्धी आय, तथा v_{σ} , v_{σ} एव v_{σ} कमशा: $\triangle I_{\sigma}/\gamma^{\circ}$, $\triangle I_{\sigma}/\gamma^{\circ}$, तथा $\triangle E/\gamma^{\circ}$ को सूचित करते है। समी-करण (15) तीन निवेश नीति-प्राचन प्रदान करता है, जिससे हम लोग गुणक की प्रक्रिया के लीवर पक्ष की निया का संचातन कर सकते है।

इस प्रकार, वचत की सीमान्त प्रवृत्ति को भी निम्न प्रकार से पृथक् किया जा सकता है:

$$s' = \frac{\Delta S_p + \Delta S_o + \Delta M}{\Delta Y^o} = \frac{\Delta S_o}{\Delta Y^o} + \frac{\Delta S_s}{\Delta Y^o} + \frac{\Delta M}{\Delta Y^o} = s'_o + s'_o + m_s \tag{16}$$

जिसमें So निजी बंचत, So राजकीय बंचत (यानी बंजट का आधिक्य), M जामात-सम्बन्धी व्यय, s'o निजी बंचत की सीमान्त क्षमता, s'o राजकीय बंचत की मीमान्त क्षमता एवं M आयात की सीमान्त क्षमता है। समीकरण (16) गुणक प्रक्रिया के क्षरण-पक्ष की किया-संचालन के लिए तीन बंचत-प्रांचल देता है।

(15) एव (16) को ध्यान में रखते हुए समीकरण (11) को निम्नाकित प्रकार से पुन. निखा जा सकता है—

$$\frac{\Delta Y^{\circ}}{Y^{\circ}} = \frac{v}{s'} = \frac{v_{s} + v_{s} + v_{s}}{s'_{s} + s'_{s} + m} \tag{17}$$

कैन्सीयन वेरोजगारी को दूर करने लिए यह दीवंकालीन आवश्यकता कि s/b की स्थामी दर पर पूँजी की वृद्धि को मध्यम एव दीवंकालीन उपायों के द्वारा निर्विष्ण छोड़ देना चाहिए, यहा सम्भावित प्राजलीय प्रतिया पर कुछ प्रतिबन्ध लगा देती हैं! सर्वप्रथम तो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए वचत की सीमान्त क्षमता (5') को केवल स्थायी तौर पर गुणक को बढ़ाने के लिए घटाया नहीं जा सकता; क्योंकि ड' में कमी से ड आतमधाती हास हो सकता है और इसीलिए पूर्ण नियुक्त पूजी में वृद्धि की दर में भी कमी हो सकती है। इसका तात्ययं यह है कि ड' के अवयवों को इस प्रकार जोड़-मोड़ करना चाहिए, जिससे सम्पूर्ण ड' स्थिर रहे तथा वास्तविक भार लीवर-पक्ष

पर पड़े। यदि s' को स्थिर रहना है, तो निजी वचत की सीमान्त-क्षमता (s's), राजकीय बचत की सीमान्त क्षमता (s's) एवं आयात की सीमान्त क्षमता (m) प्रत्येक को दूसरे में वृद्धि की मात्रा के बरावर से कम करना होगा। अव s' के विभिन्न अवयवों में किसको कम किया जाय, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका निर्णय दीर्घकालीन उत्पादन-क्षमता में न्युनतम क्षति को घ्यान में रखते हुए करना पड़ेगा।

जहाँ तक लीवर-पक्ष का सम्बन्ध हैं, उपयुंक्त आवश्यकता का तात्पर्य यह है कि ν के किसी भी अवयव की उत्पादकता एवं इसके आय-उत्पादक प्रभाव को निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा । अतएव, समर्थ माँग एवं अतिरिक्त निवेश के कुल अनुपात में ν_p , ν_p एवं ν_e के उत्पादकता-प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इनमें एक साथ वृद्धि के द्वारा वृद्धि की जा सकती है । दूसरे शब्दों में, पिरामिड-निर्माण के प्रकार के निवेश को प्रत्येक परिस्थित में अवश्य ही टालना होगा । अन्यथा गृद्ध निवेश की उत्पादकता में कभी के परिणामस्त्रक्ष्म पूंजी-निपज अनुपात (b) में वृद्धि होगी, जिससे पूंजी की वृद्धि को अविकल रखने का दीर्घकालीन उद्देश्य विफल हो जायगा । किन्तु, व्यावहारिक नीति के रूप में ν_e प्राचल सुगमतापूर्वक आन्तरिक नीति-निर्घारण में सहायक नहीं होता; क्योंकि यह प्रधानतः विदेशों की आयात की क्षमता पर निर्भर करता है । ν_p एवं ν_e को दिया जानेवाले सापेक्षभार का निर्धारण b के दीर्घकालीन के प्रतिरूप (यानी इसके व्युत्कम σ) एवं जिस हद्द तक अवन्ध नीति को काम योग्य समक्षा जाता है, सन्दर्भ में किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में केन्सीयन वेरोजगारी को समाप्त करना अधिक कठिन है। इसका कारण यह है कि विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पहले से ही पूँजी की वृद्धि की उच्च दर होती है, जिसके परिणामस्वरूप यह अपनी वचत की सीमान्त क्षमता को कम कर सकती है, अथवा अनुत्पादक, किन्तु रोजगार वढ़ानेवाली योजनाओं में निवेश की क्षमता को बढ़ा सकती है। फिर भी उपर्युवत पृथक्करण सम्बन्धी विश्लेषण, उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के वीर्धकालीन उद्देश्य में किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये वगैर, मध्यम एवं दीर्घकाल में केन्सीयन वेरोजगारी को दूर करने की सम्भावनाओं को वतलाता है।

ग्रीर-केन्सीय बेरोजगारी की दीर्घकालिक वृद्धि

समर्थ माँग के चकीय कुव्यवहार के परिणामस्वरूप केन्सीयन वेरोजगारी से वहुत अधिक गम्भीर ग्रैर-केन्सीय तरीके की वेरोजगारी है, जो एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था को अल्प-विकासित एवं जनाधिक्यवाली संरचना में निहित है। यह मुख्यत: अनुत्पादक पेशों के रूप में व्यक्त होती है तथा इसे 'छिपी हुई वेरोजगारी' कहा जाता है। यह उसी प्रकार की वेरोजगारी है, जिसे हैरोड के विकास की स्वाभाविक एवं प्रामाणित दरों की सिन्निध लक्षित करती है तथा जिसे जोन रॉविन्सन

ने 'माबिसंयन वेरोजगारी' की सज्ञा दी है। किन्तु, किर भी, हम लोग इसे 'गैर-केल्सीयन वेरोजगारी' अथवा 'सरचनात्मक वेरोजगारी' कहना अधिक सुबोध सममते है। क्योंकि, मानसं की 'आरक्षित धम-सेना' सम्भव है कि हैरोड एव जोन रॉबिन्सन द्वारा स्वया वॉजत समान मौलिक परिवर्तियों का परिणाम हो, किर भी यह ऐतिहासिक तथ्य कि लाभ की दर की तुलना में मजदूरी की दर पर अत्यधिक श्रम-संख्या का घटता हुआ दबाव पूजी के तीव संवयन को प्रोत्साहित करता है, की आलकारिक अभिव्यक्ति जान पडती है। इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि मानसं 'आरक्षित धम-सेना' को पूजीवादी विकास की आवश्यक गर्ज मानता था, यदि वह सिनहित श्रम के 'शोपण' पर रोप प्रकट करता था। इसके विपरीत हमारी मौलिक स्थिति यह है कि उत्पादक मानव शक्ति की प्रत्यक्ष वरवादी तथा भारी उद्योगों के बदले सीमान्त कृषि, कृटीर-उद्योग एवं द्विपी हुई वेरोजगारी के अन्य धक्ताहों को अपत्यक्ष प्रोत्सहन के परिणामस्वरूप गैर-केल्सीयक तरीके की वेरोजगारी के औद्योगीकरण के मार्ग में एक आधारभूत स्कावट है।

इस सामान्य पृष्ठभूमि के साथ, अब हम अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में गैर-केन्सीय वैरोजगारी की प्रकृति एव उद्भव की आँच करेंगे। हम उपलब्ध श्रम की पूर्ति, जिसे पिछले खड में हमने दिया हुआ मान लिया था, के विश्लेषण से प्रारम्भ करेंगे।

^{1.} देखें, इनका पूर्व उड़त 'मानसं एवं केन्स'।

^{2.} इस मान्यता पर कि लाभ-सम्बन्धी आय से बचाने की सीमात प्रवृत्ति धनारमक तथा मजदूरी-सम्बन्धी आय से बचाने की सीमान्त-प्रवृत्ति धून्य या ऋणारमक है। माक्सं की 'आरक्षित ध्रम-सेना' के औपचारिक माँडल के रूप में स्पष्ट अधवा अस्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन के लिए देखे. एस्॰ सुरु, 'एसेज ऑन माक्सियन इकॉनामिक्स' (साईस कींसिल ऑफ जापान इकॉनामिक सीरिज (नं० 8) टोकियो, 1956; एन॰ शिनोहरा, जुलाई, 1954 के 'इकॉनामिक सिर्ध्य' मे 'इकॉनामिक प्रोग्नेस एन्ड प्राइस स्ट्रवचर'। अनीपचारिक अवलोकन के लिए देखें, नॉफ, न्यू॰ या॰ 1948 मे प्रकाशित 'दि न्यू इकॉनामिक्स' (एस॰ ई॰ हैरिस द्वारा सम्पादित में पी० स्वीजी का 'केन्स, द इकॉनामिस्ट', विशेष रूप से पू॰ राजा सम्पादित में पी० स्वीजी का 'केन्स, द इकॉनामिस्ट', विशेष रूप से पू॰ राकनोकी दोष का सक्षण मानते है, जबिक मार्क्स इसे एक अपरिहार्य साधन समभने है, जिसके द्वारा पूँजीवादी धम-याजार पर अपना नियन्त्रण कायम करते हैं।' दूमरी ओर जोन रॉबिन्सन इसलिए मार्क्स की आलोजना करती है कि उसने घचाने के सम्बन्ध में निर्णय एव निवेश के सम्बन्ध में निर्णय के राजा एवं अस्पादना, जिस पर केन्स ने जोर दिया है, की उपेक्ष की है। (देखें इनका पूर्व उद्धृत 'मार्क्स एव केन्स'।)

श्रम की पूर्ति

साधनों के सापेक्ष मूल्य एवं समाज का कार्य तथा विश्वाम के बीच चुनाव के दिया हुआ होने पर, श्रम की पूर्ति में निम्नांकित मात्रा से वृद्धि होते हुए माना जा सकता है:

$$\triangle N = \alpha \triangle P, \tag{18}$$

जिसमें N पहले की तरह पूर्ति की गई श्रम की मात्रा, P सम्पूर्ण जनसंख्या का आकार तथा «समाज के कार्य तथा विश्राम के अधिमान पर आधारित कार्य की औसत एवं सीमांत प्रवृत्ति हैं।

इसके वाद हम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उपलब्ध श्रम के बीच एक निश्चित सम्बन्ध की उपस्थिति मान सकते हैं, यानी—

$$\lambda = \frac{\triangle P}{N},\tag{19}$$

जिसमें प्रे को जन्म एवं मृत्यु की प्रचलित दरों तथा सम्भवतः उत्प्रवास की नीति द्वारा स्वतंत्र रूप से पूर्व-निर्धारित माना जा सकता है। बाद में, वर्णित कारणों के चलते यह माना जा सकता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में उच्च प्रे होता है।

समीकरण (18) एवं (19) से हमें श्रम की संख्या में वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्त होती है:

$$\frac{\triangle N}{N} = \alpha \lambda, \tag{20}$$

जो सरचनात्मक अल्प-बेरोजगारी की समस्या के पूर्ति-पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। समीकरण (20) यह बतलाता है कि उपलब्ध श्रम में वृद्धि की दर कार्य की क्षमता (α) में अतिरिक्त जनसंख्या एवं उपलब्ध श्रम के अनुपात (λ) के अनुक्रमानुपाती है। दूसरे शब्दों में, एक वृद्धिशील अर्थ-ब्यवस्था में श्रम की पूर्ति सांस्कृतिक रूप से दिये गए प्राचल (α) एवं जनांकिकीय रूप से दिये गये प्राचल (λ) का फलन है।

पूर्ति-पक्ष में मौलिक किठनाई यह है कि अधिकांश अरुप-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में उपलब्ध श्रम की वृद्धि की दर $(\Delta N/N)$ बहुत ऊँची होती है। इसके दो कारण हैं; प्रथमतः, इनकी कुछ जनसंख्या के एक बहुत वड़े भाग को कार्य करने के लिए इच्छुक रहने (उच्च α) के अतिरिक्त कोई दूसरा मौलिक विकल्प नहीं होता और द्वितीयतः, इनकी जनाँकिकीय संरचना साधारणतया इस प्रकार की होती है जो बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उपलब्ध थम का उच्च अनुपात (उच्च λ) प्रदान करती जनांकिकीय संरचना साधारणतया इस प्रकार की होती है जो बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उपलब्ध थम का उच्च अनुपात (उच्च λ) प्रदान करती जन सम्भित्त थम में वृद्धि की यह आनुषंगिक उच्च दर संरचनात्मक वेरोज्ञ एगी अथवा नहीं, यह अभियाचित श्रम की वृद्धि की प्रचलित दर पर हिंपून: एक वार हम लोग माँगपक्ष को देखें।

श्रम की माँग

जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, श्रम की माँग के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो आधारमूत कठिनाइयों का अनुभव होता है: (क) पूर्ण नियुक्त पूँजी की मद वृद्धि, तथा (ख) औद्योगीकरण की प्रक्रिया प्रति-इकाई निपज के माँगे जाने वाले श्रम की मात्रा पर टेक्तोलॉजिकल प्रगति का घटता हुआ प्रभाग।

यदि बदती हुई श्रम-णिवत को पूर्ण एव उत्पादक तरीके से रीजगार प्रदान करना है, तो पूँजी मे भी उपलब्ध श्रम में वृद्धि की दर से वृद्धि होनी चाहिए। किन्तु, सभी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी में वृद्धि की दर निम्न होती है। ऐसा केवल इनके निम्न वचत अनुपात (s') के कारण ही नहीं, चरन् इसलिए भी होता है कि पूर्वबिणित कारणों से इनकी पूँजी-निपज का अनुपात (b) उच्च होता है। तदनुसार, जैसा कि समीकरण (7) से स्पष्ट होता है, अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर भी विम्न होती चाहिए। पूँजी में वृद्धि की निम्न दर स्वयं अपने आप में एक वडा अशुभ नक्षण है, किन्तु अपेक्षित श्रम की तीव वृद्धि पर एक दूसरा दवाव भी है। अब इम यह देखें कि ऐसा किस प्रकार से होता है।

समीकरण (7) यह नक्षित करता है कि उत्पादन-क्षमता में भी निश्चित हम से उसी दर में वृद्धि होने चाहिए, जिस दर में अपेक्षित अम में वृद्धि हो रही है। क्योंकि, अपेक्षित अम एवं क्षमता-निपण के दिये हुए स्थायी अनुपात $N_r/\gamma = a$, से उत्पादन-क्षमता में $\Delta \gamma' = \Delta_r N/a$ से बृद्धि होगी। अतएव हमें उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की निश्न दर प्राप्त होती है.

$$\frac{\Delta Y'}{Y'} = \frac{\Delta N_r/a}{Y'} = \frac{\Delta N_r/a}{rN/a} = \frac{\Delta N_r}{N_r} = \frac{s}{b}.$$
 (21)

जो यह बतलाता है कि उत्पादन-शमता एवं पूर्ण नियुक्त पूँजी में निश्चित रूप में s/b की दर से वृद्धि होगी।

किन्तु, यदि श्रम की उत्पादकता मे टेक्नोलॉजिकल प्रगति के प्रभाव के अन्दर वृद्धि होती है, तो जैमा कि पिछले अध्याय मे बतलाया गया है, श्रम-निपज अनुपात में समय के कमानुसार कमी होगी। ऐसा होने पर किसी भी समय अपेक्षित श्रम की मात्रा, यदि श्रम-निपज अनुपात में कमी नहीं होगी, तो जससे कम होगी, यानी —

$$N_r(t) = \frac{a^o}{(1+g_a)^i} Y'_0, \qquad (22)$$

जिसमे Y_0' , t पर क्षमता निपज का प्रारम्भिक मुल्य है तथा g_4 पूर्व की तरह श्रम-निपज अनुपात मे ह्वास की दर है।

^ ्. (21) एवं (22) को ध्यान में रखने से समीकरण (7) में तरीके से संबोधन करना अनिवार्य होता है:

$$\frac{\triangle N_r}{N_r} = \frac{I + \frac{s}{b}}{I + g_a} - I,\tag{23}$$

जो यह वतलाता है कि यदि पूंजी एवं निपज में s/b की दर से वृद्धि होती है, जविक श्रम-निपज अनुपात में g_a की दर से ह्रास हो रहा है, तो अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर $(I+\Delta N_rN/_r)$ वरावर होगी $(I+s/b)/(I+g_a)$ । इस प्रकार, समीकरण (23) दीर्यकालीन टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी को सूचित करता है जो तटस्थ टेक्नो-लॉजी की स्थिति में संरचनात्मक अल्प-रोजगारी की सहज अवस्था को जलभनपूर्ण बना देता है। यह पूर्ण रोजगार को साम्यावस्था की एक मौलिक आधारभूत शर्त को भी सूचित करता है। इसकी व्याख्या हाल ही में जाएगी।

ग़ैर-केन्सीयन वेरोजगारी की वृद्धि

यदि ऊपर वर्णित कारणों से उपलब्ध श्रम में वृद्धि की दर अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर से अधिक हो जाती है, तो निम्नांकित असमता प्राप्त होती है:

$$\frac{\triangle N}{N} = \frac{\triangle P}{P} > \frac{\triangle N_r}{N_r} = \frac{\triangle K}{K},$$

जिस असमता से सरचनात्मक अल्प-रोजगार में वृद्धि की निम्नांकित दर प्राप्त होती है:

$$\frac{\triangle U^{\bullet}}{U^{\bullet}} = \frac{\triangle N}{N} - \frac{\triangle N_{r}}{N_{r}} = \alpha \lambda - \frac{s}{b}, \qquad (24)$$

जहाँ $\triangle U^{\circ}/U^{\circ}$ सैर-केन्सीय वेरोजगारी की दर है। इसमें अपर अंकित s सिन्तिहत वेरोजगारी की दीर्थकालीन प्रकृति को सूचित करता है। समीकरण (24) यह सूचित करता है कि संरचनात्मक अल्प-रोजगारी के पिरमाण में समय के कम से घातीय रूप में निम्न प्रकार से वृद्धि होगी:

$$U^{s}(t) = e(\alpha \lambda - s/b) U_{0}$$
 (25).

समीकरण (24) एवं (25) छिपी हुई वेरोजगारी की निरंतर विद्यमानता को सूचित करते हैं; क्योंकि पूँजीगत साधनों के अभाव में स्थायी रूप से वेरोजगार होने बाले लोगों में से अधिकांश बाद में जीवन-निर्वाह के लिए कृषि, हस्तिशिल्प मार्ग-विक्रय एवं घरेलू नौकरियों जैसे अनुत्पादक पेशों में लग जाते हैं। इन सभी पेशों में काम करने के लिए कम अथवा कोई भी पूँजीगत साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतएव, छिपी हुई वेरोजगारी संरचनात्मक अल्प-वेरोजगारी का वह विशिष्ट रूप है, जो केवल अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में ही नहीं, वरन् विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अविकसित क्षेत्रों (उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ दक्षिणी हिस्सों) में भी पाई जाती है।

अतएव, हम देखते हैं कि संरचनात्मक वेरोजगारी उस प्रकार की अल्प-विक्रित अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न एवं स्थिर रह मकती है, जिसमें, यदि पूंजी के वर्तमान कोप के पूर्ण प्रयोग की स्थिति में रखने के लिए समर्थ गाँग पर्याप्त मात्रा में उच्च हो तथा यदि देवनीलॉचिनल प्रगति तटस्थ हो, जिससे कि निपज को प्रति-इकाई आवश्यक थम की मात्रा में हास नहीं होता हो, तो भी जिसकी थम की पूर्ति में थम की मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए सरजनात्मक वेरोजगारी सामान्य रूप में आर्थिक विकास एवं विशिष्ट रूप में औदीगीकरण के लिए एक कर्ष है; वयोकि यह अनुत्यादक एयं अयोग्य उद्योग का गैर-चंशीय और गैर-संघर्षणात्मक वेरोजगारी के रूप में स्वायित्व प्रदान करती हैं।

गैर-केन्सीय प्रकार की सध्या बहुन वेरीजगारी को न्यून बनाने की क्यिन त्मक सभावनाओं की व्याख्या के पूर्व, दीर्घकाल में पूर्ण रोजवार के लिए आवश्यक निम्नाकित दो आधारभूत शर्तों को बतलाना लाभदायक होगा:

$$\frac{s}{b} = \alpha \lambda \tag{26}$$

जयिक टेक्नोलॉजी की तटस्थता की मान्यता पर श्रम की उत्पादकता स्थायी रहती है, तथा

$$\frac{s}{b} = \alpha \lambda + ga \tag{27}$$

जबिक समय के कम मे श्रम की उत्पादकता मे श्रम-निपज अनुपात मे कमी के लिए वृद्धि होती है। समीकरण (27) का दार्मा पक्ष $(I + \alpha \lambda)$ $(I + g \mu) - I$ के सिनकट है। यह वह दर है, जिस पर श्रम-निपज अनुपात में हास के परिणामस्वरूप उत्पन्न दीयंकालिक टेक्नोलॉजिकल वेरोजगारी की दूर करने के लिए पूँजी एवं समना में वृद्धि अनिवार्य है।

गर-केन्सीय बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राचल-किया

पूर्ववर्ती विवरण से यह स्पष्ट है कि गैर-केन्सीय तरीके की सामूहिक बैरोजगारी से पीडित अस्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को मुख्य रूप से पूँजी में वृद्धि की दर
(\(\triangle K / K \)) में वृद्धि करनी होगी या जनसक्या में वृद्धि की दर
(\(\triangle K / K \)) में वृद्धि करनी होगी या जनसक्या में वृद्धि की दर
(\(\triangle K / K \)) में कमी
करनी होगी या दोनों ही करने होगे। विशेषत्या सरचनात्मक अस्प-वेरोजगारी की
समाप्त करने के लिए, या निश्चयात्मक आधार पर, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार की
दीर्धकालिक रूप में बनाये रखने के लिए, पूँजी एवं जनसक्या की वृद्धि की दर को
निर्धारित करने वाले सरचनात्मक प्राचलों के साथ उचित कार्रवाई अनिवार्य है। अब
समीकरण (26) एवं (27) द्वारा दी गई साम्यावस्था की परिस्थितियों को ध्यान में
हिए प्राचल-कियाओं पर विचार किया जाय।

अपेक्षित श्रम में वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए, एक अल्प-विकसित अर्थ-न्यवस्था को बचत-अनुपात (s) में वृद्धि तथा पूँजी-निपज अनुपात (b) में कमी यानी $(\triangle P/P) > (\triangle K/K)$ की परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी । ऐसा करने से कहना आसान है, विशेपतः जब और जिस स्थिति में उपभोग का स्तर पहले से ही इतना निम्न है कि उ में कोई भी वृद्धि कठिन हो जाती है तथा टेक्नोलॉजी की स्थित इतनी पिछड़ी है कि b में कमी (अथवा पंजी की उत्पादकता में विद्ध) भी कठिन हो जाती है। यहाँ हम श्रम की पर्ण रोजगार की इच्छा एवं इसकी अधिक चाल-उपभोग की इच्छा के बीच एक प्रकार का द्वन्द्व पाते हैं। इस प्रकार का द्वन्द्व एक विकसित अर्थ-च्यवस्था में नहीं पाया जाता है, जिसमें अधिक वचत (अथवा निम्न उपभोग) ही केन्सीय वेरोजगारी का कारण होती है। अतएव, वचत-अन्पात को वडाकर अपेक्षित श्रम की नृद्धि की दर में वृद्धि करने से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में एक आधिक व्यवस्था, जो सामृहिक उपभीग की वेदी पर कुछ लोगों को अधिक वचाने की सुविधा देती हैं, उसके प्रति श्रमिकों में तिरस्कार की प्रवृत्ति उत्तेजित होती है। फिर भी, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था ड में उन उपायों के द्वारा, जो पहले से ही निम्न उपभोग में और अधिक त्याग को आवश्यक नहीं बनाते (उदाहरण के लिए, वित्तीय एवं विदेशी व्यापार-सम्बन्धी नीतियां, जिनका आगे चलकर पृथक् रूप से विवरण किया जाएगा), जिस हद्द तक वृद्धि करतीं हैं, उस हट तक वह लौकिक रोप को जाग्रत करने एवं राजनीतिक साम्य को उलटे, वगैर पुँजी की वृद्धि की दर में वृद्धि कर सकती है और इसलिए अपेक्षित श्रम में विद्व की दर में भी विद्व कर सकती है।

जहाँ तक पूँजी-निपज अनुपात (b) में कमी का प्रश्न है, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को पूँजी बचाने वाले टेक्नोलॉजिकल सुधारों को अपना कर तथा यन्त्रों एवं साधनों के वेकार प्रयोग को दूर कर पूँजी की समता में वृद्धि करनी होगी। आगे चलकर यह दिखलाया जायगा कि अधिक उत्पादक क्षेत्रों में पूँजी के पुनर्विभाजन से सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी निपज अनुपात में कमी हो सकती है। मँहगी मूद्रा-नीति के द्वारा पूँजी-निपज अनुपात में कमी के प्रयास को आशाहीन एव अनर्थक समभक्तर टाल देना चाहिए। क्योंकि, मँहगी मुद्रा-नीति के द्वारा पूँजी-निपज-अनुपात में जो भी कमी आती हैं, वह मजदूरी की मौद्रिक दर में सम्भावित वृद्धि (उदाहरण के लिए, अम-संघों के कार्यो द्वारा) अथवा पूँजीगत वस्तुओं के औसत मूल्य में सम्भावित हास (उदाहरण के लिए, वाजार की प्रतियोगिता से), यानी साधना-मूल्यों में परिवर्तन द्वारा उत्पादन के पूँजी प्रयोग वाले तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से विलकुल समान्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, मँहगी मुद्रा-नीति विकासात्मक निवेश-सम्बन्धी कियाओं को प्रोत्साहित करने के दोर्घकालीन उद्देश्य के अनुस्प नहीं है। पाठक टेक्नोलॉजी पर पिछले अध्याय में पूँजी-निपज अनुपात को कम करने के सम्बन्ध में अन्य सुभावों को देख सकते हैं।

दूसरी कियात्मक सभावना समीकरण (27) मे अम-निपज अनुपात मे कभी की दर (ga) को नम करने की है। इसका तात्वर्य यह है कि दीर्यकालिक देवनोलॉजि-कल बेराजगारी की सभावना से प्रस्त अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सरचनात्मक अल्प रोजगारी में उस वृद्धि को, जो αλ को, की दर पर पूजी-सचय के द्वारा उत्पादक रोजगार में नहीं खप सकती है, अन्य न्यूनतम बनाने के लिए श्रम बचाने वाले उपायो नाप्रतिरोध करमा होगा । यहाँ दो कठिनाइयाँ दृष्टियोचर होवी है । प्रयमतः तो जैसा कि पिछले अध्याय में देखा जा चुका है, थम बचाने वाले उपायों को अपनाने के प्रतिरोध से धम की उत्पादकता में इतनी कमी हो सकती है, जिससे कि $K/\gamma =$ $(K/N)/\gamma/N)$ के माध्यम से उच्च पूजी-निएज अनुपात आवश्यक हो जाय। वास्तव में, यह आत्मधाती है; क्योंकि वचत-अनुपात के दिया हुआ होने पर, b के उच्च होने पर पूँजी में इतनी वृद्धि हो सकती है, जितना कि इसके निम्ने होने पर। हितीयत, श्रम की उत्पादकता की वृद्धि की दर में अन्तर्निहित ह्नास पूर्व वर्णित विकास की सामाजिक श्रेष्ठतम दर की धारणा से असबद्ध है; क्योंकि दीर्वकालिक रूप मे बढते हुए जीवन-स्तर को प्राप्त करने के लिए श्रम की उत्पादकता में ह्याम नहीं, वरन् वृद्धि आवश्यक होती है। इन कठिमाइयों के सन्दर्भ में एक स्थायी धना-रमक go को दिया हुआ मानना ही सर्वाधिक उचित तरीका जान पडता है और तब पूजी में वृद्धि की दर को $(\alpha\lambda + ga)$ के अनुकूल बनाना चाहिए, जिससे श्रम की उत्पादकता के परित्याग तथा जीवन स्तर को निम्न बनाये वर्गर ही दोषंकानिक देवनोलॉजिकल वेरोजगारी को दर किया जा सकता है।

विकल्पत , एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था पूँजी में वृद्धि की दर को दिपा हुआ मानकर जनमध्या की वृद्धि की दर में कमी के द्वारा उपलब्ध अम में वृद्धि की दर को कम करने का प्रथास कर सकती है। इसे और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए यह कहा जा सकता है कि ($\triangle P/P$) > ($\triangle K/K$) की परिस्थितयों में, एक अल्प-विकमित अर्थ-व्यवस्था को दोनों व तथा λ में निश्चित रूप से कभी करनी चाहिए। कार्य करने की क्षमता (σ) में कभी इस बात का सकेंत करती है कि समाज को काम की जगह विश्राम की पसन्द करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि कुल जनसच्या का एक छोटा भाग ग्रदा कार्य करने के योग्य एवं तत्पर रहें। इसमें अनिवार्यत. साम्कृतिक वरण सन्निहित है, जो आधिक दृष्टि से अपेक्षित हो सकता है, अथवा नहीं भी। यदि ऐसे व्यक्तियों को, जो कि ध्यम-मेंना के नियमित सदस्य नहीं है अथवा नहीं होना चाहने हैं (उदाहरणतः; स्कूल जाने अथवा व्यक्तिश-प्राप्त उम्र के काम योजने वालो, सरुटमय उद्योगों में काम करने के लिए इच्छुक गृहिणियों एव माताएँ, विशेष रूप से विद्वान वैज्ञानिक एवं कलाकार, जिन्हें अपनी रोजी-रोटो के तिए बाम करना पड़ना है और विलक्षण धनी व्यक्ति, जो ित तरीके से अपनी जीविका प्राप्त करना चहने हैं। थम-बाजार से स्थायों हप

से अलग कर दिया जाय, तो अपेक्षित ध्रम या विकास की दर को वढ़ाने-सम्बन्धी दवाव में निश्चय ही बहुत कमी हो जाएगी। यदि श्रम की उत्पादिकता में स्थायी धनात्मक दर ga में वृद्धि हो रही है, तो एक अल्य-विकसित अर्थ-व्यवस्था एक बढ़े अवकाश-प्राप्त वर्ग का भरण-पोपण कर सकती है और इस प्रकार α के अन्यथा अधिक मूल्य को कम कर सकती है। वयोंकि, बढ़ती हुई उत्पादकता काम के कम घंटे तथा अधिक मजदरी आन्दोलन को सम्भव बनाती है।

अन्ततः एक अल्प-विकसित वर्षं-व्यवस्या संतित निग्रह तथा अन्य जनांकिकीय प्रयोगों के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उपलब्ध श्रम के अनुपात λ को कम करने का प्रयास कर सकती है। किन्तु, जैसा कि जनसंख्या-सम्बन्धी विशेषज्ञों द्वारा सदा इस वात की चेतावनी दी जाती है, इस सम्बन्ध में कुछ सांस्थानिक कठिनाइयों का निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा। λ को कम करने के प्रयास में उत्प्रवास का प्रोत्साहन भी, यदि यह सम्भव है, सिम्मिलत है। किन्तु, जैसा कि हावेल्मो का सुक्षाव है, यदि यह मान लिया जाय कि जन्म-दर जानकारी के सूचकांक से प्रतीपानुपाती दर में परिवर्तित होता है, तो जनसंख्या में वृद्धि को नियन्त्रित करने के नकारात्मक उपाय से, व्यापक अर्थ में, टेवनोलॉजिकल प्रयति को त्वरायित करने वाले घनात्मक प्रभाव की उत्पति हो सकती है। साय ही, जैसे-जैसे एक अरूप-विकसित अर्थ-व्यवस्था निविरोध रूप से उस विन्दु की योर अग्रसर होती है, जहाँ जनसंख्या की वृद्धि को संरचनात्मक वेरोजगारी में वृद्धि का कारण न समक्तर निवेश की माँग को प्रोत्साहित करने वाले साधन के रूप में समभा जाता है, वैसे-वैस वड़ी एवं वृद्धिशील जनसंख्या के पक्ष का तर्क कमजीर होने के वजाय दृढ़ होता जाता है।

उदाहरण के लिए, जापान यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, तथापि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की तरह इसमें जनाधिक्य की स्थित पाई जाती है। अतएव, यह अल्प-जनसंख्या वाली अर्थ-व्यवस्थाएं (जैसे, युद्धोत्तर काल में ब्राजील स्वीकार करने के लिए जितना तैयार रहती हैं, उतना उत्प्रवास को प्रोत्साहित करता है।

^{2.} हावेलमों: 'ए स्टडी इन दि थियरी आफ इकॉनािमक इबोल्यूगन' (पृष्ठ 43)। हावेलमों इस मान्यता को विस्तृत नहीं करता, किन्तु उसने इस अवलोकनीय तथ्य को अपने ध्यान में रखा था कि अग्निक्षित परिवारों की अपेक्षा शिक्षित परिवारों को संतित-निग्रह के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त है। तथािप, यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि इस सूचना एवं व्यवहार में एकरूपता है। उदाहरण के लिए जापान में साक्षरता का प्रतिशत अधिक होने पर भी वहाँ खिलाते तथा रोजी देने के लिए बड़ी एवं वृद्धिशील जनसंख्या है। फिर भी, अधिक जानकारी के पक्ष का तर्क ठीक ही रह जाता है, क्योंिक टेक्नोलॉजिकल प्रगति पूंजी में गुणात्मक सुधार के द्वारा पूंजी-निपज-अनुपात को कम करती है।

छिपी हुई बेरोजगारी पर अनुसेख*

रोजगारी पर अपनी विवेचना को समाप्त करने के पूर्व आर० नस्कें वी जनाधिययवाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में बचत सम्भाव्य के रूप में कम विकास वाली धेरोजगारी पर विचार करना लाभदायक जान पहला है। [‡] इस विचार के अनुसार, छिपी हुई बेरोजगारी की पूर्ण सामबन्दी उपभोग में कमी के वगैर शुद्ध-निवेश में विद्व कर सकती है। इसे तस्कें अवश्यमानी निकल्प के रूप में निवेश एवं उपभोग की सस्थापक धारणा तथा आवश्यक परिपुरक के रूप में केन्स के निवेश एवं उपभोग के विचार के बीच समभौता कराने के रूप में प्रस्तुत करते है। बयोकि, अतिरिक्त पूँजी के कोए के बगैर अतिरिक्त थम के बड़े कीप वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था सस्या-पको के पूर्णत नियुक्त साधनो, जिल्ला अधिकांश उपभोक्ता बस्तुओं के कम तथा पूँजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन पर लगाया जाना है तथा केन्स के निरयोगीय साधनो, जिनका प्रयोग दोनो पुँजीगत तथा उपमीक्ता बस्तुओं के उत्पादन की बढाने में किया जा सकता है, के बीच पाई जाती है। यह 'तटस्थ' स्थिति सुखदायक विचार है, किन्तु अधिक विचार-विमर्श करने पर यह भामक जान पड सकती है। यहाँ न्युनाधिक मात्रा मे प्रचलित व्यावहारिक आक्षेप को दुहराने के बजाय हम लोग निवेश एव उपभोग के सम्बन्ध में सस्यापक एवं केन्सीय विवारों के बीच नक्सें के इस समभीते के पक्ष में दिये जाने वासे विभिन्त तकों में सन्तिहित कछ कठिनाइयों को बतला सकते है।

^{*} यह लेखक के पूर्व-उद्धृत "टेकनीनस फॉर मैनिसमम ग्रोथ ऐंड एम्पलायमेट" का अग है।

^{1.} देलं नवमें ना 'प्रोब्लेम्स ऑफ केपिटल फॉरमेशन इन अन्डरहेबस्पड कन्ट्रीड !' साथ ही, देखे बुधानन एव एलिस का एप्रोचेज टुइकॉनामिक डबलपमेट 13 अवत्वर, 1956 के इकॉनामिक बीकली (इण्डिया) में क्यो एम० तिवासन का कॉमन सैन्स मेड डिफिनस्ट; ए० के० दास गुप्ता का पूर्व उद्भृत 'डिसगाइण्ड अन-एम्प-लायमेट एण्ड इकॉनामिक डेबलपमेट।

थे. मेरे सहयोगी प्रोफेसर रॉबर्ट अलेग्जेग्डर ने मेरा ध्यान सेटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर दृष्टिगोचर इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया कि वहां कृषि में छिपे हुए वेरोजगार औद्योगिक अनुशासन से इतने अनिभन्न हैं कि अब वे नारखानों में उत्पादक तरीके पर नियुक्त होते हैं, तब स्वभावत: अनुपस्थित हो जाते हैं। उन्होंने इस तथ्य का भी जिक्त किया कि लेटिन अमेरिका में छिपे हुए वेरोजगारों का एक बड़ा भाग सक्तर सेवाओं में रोजी पाता है। इससे यह स्पष्ट है कि किसी अल्प-विक्तित अर्थ-व्यवस्था में सभी छिपे हुए वेरोजगारों को उत्पादक-भित्र में नहीं लगाया जा सकता है।

इन तर्कों का सार निम्न प्रकार से हैं : मान लिया जाय कि सभी छिपे हए वेरोजगार उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में नियुक्त हैं (जिसे साधारणतया गुजारा कृपि कहते हैं) । चूँकि, परिभाषा के अनुसार छिपे हुए वेरोजगार व्यक्ति सीमान्त अथवा अनुत्पादक श्रम हैं, अतएव उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में से इन्हें हटा देने से उप-भोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अव छिपे हुए वेरोज़गार को पूँजीगत उद्योगों के क्षेत्र में ले जाया जाय तथा इस प्रकार के परिवर्तन की . च्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार नहीं किया जाय । चूँकि, मान्यता के अनु-सार, पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक है, अतएव इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में छिपे हुए वेरोजगारों को सम्मिलित करने से प्रैजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। अतएव, जब कभी छिपे हुए बेरोजगारों को पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण तरीके से लगाया जाता है, तब इसे 'बचत सम्भाव्य' समक्ता जाता है, जो शुद्ध निवेश (अथवा पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में उपर्युक्त विणित वृद्धि के परिणामस्वरूप पूँजी के वर्तमान कोप में वृद्धि) के रूप में फलित होता है। इस प्रकार, इस धारणा का सर्जन होता है कि छिपी हुई वेरोजगारी अंततः, औद्योगीकरण पर बोभ होने के बजाय छिपा हुआ वरदान है। किन्तु, निम्न-लिखित निवेचन इस वहकाने वाली धारणा को हटा सकता है।

जब उपभोक्ता-वस्तुओं के क्षेत्र से मुक्त होने वाले श्रम की विशिष्टताओं को ध्यान में रखा जाएगा तब स्थायी पूँजी की निपज में, जिसका औद्योगीकरण के लिए निर्णायक महत्त्व होता है, विशेष रूप से वृद्धि नहीं भी हो सकती है। यह मानते हुए कि छिपे हुए वेरोजगारों को ऐसी निवेश-सम्बन्धी योजनाओं में स्थानास्तरित किया जा सकता है, जिसमें विशेष दक्षता अथवा साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इस प्रकार की श्रम-प्रधान प्रकृति के निवेश की योजनाओं से औद्योगीकरण के लिए गींघ एवं पर्याप्त उपयोगी उचित मात्रा एवं गुण वाली स्थायी पूँजी प्राप्त होने की आशा किठनाई से की जा सकती है। ऐसी श्रम-प्रधान योजनाओं से अधिक-से-अधिक सीमित मात्रा में प्रारम्भिक पूँजी-निर्माण की आशा की जा सकती है (उदाहरण के लिए, कारखानों के स्थान के लिए महापक वाली भूमि की सफ़ाई, आधुनिक महापयों के निर्माण के लिए मिट्टी की सड़कों का निर्माण तथा यन्त्र-निर्मत उद्योगों के कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किये जाने वाले हस्तिशल्प)। किन्तु, आद्योगोंकरण को पर्याप्त मात्रा में गतिमान बनाने के लिए यन्त्र-निर्माण करने वाले यन्त्रों की अव-यमकता पड़ती है और छिपा हुआ वेरोजगार इस प्रकार के 'यन्त्र-निर्माण करने वाले यन्त्रों' का अप्रभावी प्रतिस्थापन है।

स्थायी उपभोग की मान्यता का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि उपभोग्य वस्तुओं के क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम की उत्पादकता शून्य से अधिक है, वरन् इसलिए कि पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में हस्तान्तरित होने से इसकी उपभोग-झमता में सम्भवत आय के प्रत्येक स्तर पर वृद्धि होती है। यह सम्भावता दो कारणों सं सत्य प्रतीयमान होती है। प्रथमतः, पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र से हस्तान्तरण के पूर्व छिपे हुए रोजगार उपभोग के इतने निम्न स्तर को अपनाने के लिए बाध्य होने हैं कि वे हस्तातरण के वाद निश्चय ही नई सुदृढ उपभोग की आदनों को अपनायेंगे। द्वितीयन, महरी क्षेत्र, जहां पूँजीयत वस्तुओं के उद्योग मुख्यतः केन्द्रित होने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों, जहां से छिपे हुए वेरोजगार आते हैं, की अपेक्षा स्पष्टतः उपभोग की सुदृढता क्षमना को बढाने वाले होते हैं। अनएव, यदि पीगू-सम्बन्धी प्रभाव को। अने ला छोड़कर, 'आदतसम्बन्धी प्रभाव' एव 'क्षि-सम्बन्धी प्रभाव' पर उचित ध्यान दिया जाय, तो पहले अनुस्पाफ किन्तु अब उत्यादक उपभोक्ताओं, यानी छिपे हुए बरोजगारों के नागरीकरण के परिणाम-स्वरूप सम्पूर्ण अर्य-व्यवस्था की उपभोग-क्षमता मे निश्चय ही वृद्धि होगी। ऐसी स्थित में जो साधन अन्यया पूँजीगत यस्तुओं की निपज को बढाने के लिए प्रयोग में आने वाली उपभोवता-सस्तुओं के क्षेत्र में उनके विनिधान के लिए दवाब बढेगा।

फिर भी, यदि, जैसा कि औद्योगीकरण की प्रक्रिया में सम्भावना रहती है. पूँजीगत वस्तुओं का क्षेत्र उत्पादन के श्रम बचाने वाले तकनीक को अपनाता है, तो निपज की प्रति इकाई अपेक्षित श्रम की मात्रा में सन्निहित कमी, इस क्षेत्र द्वारा छिपे हुए वेरोजगारो को पूर्णत तथा निरन्तर रूप मे लगाने की क्षमता को सीमित बना देती है। जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है, इस प्रकार की स्थिति में स्थायी उत्पादकता वाली श्रम-शक्ति को सण्जित करने के लिए बढती हुई उत्पा-इकता वाली श्रम-शक्ति की अपेक्षा पूँजी में अधिक दर से वृद्धि करनी होगी। इस प्रकार, छिपी हुई वेरोजगारी को 'बचत सभाव्य' गानते के सामान्य तक में सन्निहिन टेक्नोलॉजिकल सटस्यता की मौन भान्यता अमान्य एवं नि सहाय हो जाती है। यदि हम लोग, देवनीलाँजिकल प्रगति से उत्पन्न उपयु बत समस्याओं को छोड भी देते हैं, तो भी हम लोग जनसम्या की वृद्धि के पूँजी-सचय से अधिक हो जाने की मूलमूत समस्या से छुटकारा नही पा सकते। केवल यडी ही नही, यरन् बढती हुई जनसङ्या उपभीग को कम किये बगैर गुद्ध निवेश को बढाने की कठिनाई को घनीभूत कर देती है, क्योंकि इसका तात्पर्य खाने के लिए अधिक ब्यक्ति तथा नियुक्ति के लिए अधिक काम चाहने वाल, दोनो प्रकार के लोगों से होता है। वृद्धिणील जनसंख्या वाली अर्थ-व्यवस्था में उपभोग से अधिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति में ऐसी वृद्धि, जिसे छिपे हुए वेरीजगारी का पूर्ण उपयोग समव बनाता है, यदि सम्पूर्ण नहीं, तो अधिकाण जनसदया में यथार्थतः अनुत्पादक वृद्धि (उदाहरण के लिए, साधारणतया उत्पादकता उम्र, जैसे 15 वर्ष से कम आयु वालो की बढ़ती हुई सस्या) के द्वारा समान्त ही आएगी। साथ ही, जन-सध्या में वृद्धि के पूँजी-सचय से अधिक होने की प्रवृत्ति का तात्पर्य यह है कि छिपे वरोजगारों की सहायता से पूंजी के कोप में हुई वृद्धि से जितने लोगों को उत्पा-

दक तरीके से काम पर लगाया जा सकता है, उससे छिपी हुई वेरीजगारी की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है।

ये विचार पूँजी-संचय के साधन के रूप में छिपी हुई वेरोजगारी की परि-कल्पना की जपादेयता पर सन्देह प्रकट करते हैं। ये विचार एवं हम लोगों के औप-चारिक विवरण यह संकेत करते हैं कि ये पूँजी-संचय एवं आर्थिक विकास में सहायक होने के बजाय, छिपी हुई वेरोजगारी की क्षमता को बढ़ाने वाली प्रकृति की जगह जर्पन्न करने वाली अस्पष्ट योजनाओं को सहायता एवं आराम देकर, इनमें वाधा जरपन्न करते हैं।

अध्याय 7

आर्थिक विकास में पुनर्वितरणात्मक-भूमिका

विकासित अर्थ-व्यवस्था में आय के वितरण के सम्बन्ध में दीर्घकालीन विवेषन मुख्यत इस प्रश्न पर केन्द्रित है कि आर्थिक विकास का आय के दीर्घकालीन विवेषन पर क्या प्रभाव पड़ता है ? जहाँ तक अल्य-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यह प्रश्न गीण महत्त्व का हो जाता है, क्यों कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यह प्रश्न गीण महत्त्व का हो जाता है, क्यों कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं ऐसी स्थित में नहीं होती कि विकास की दिया हुआ मानकर आय के वितरण पर इसके सभावित प्रभावों पर विचार किया जाये अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से सम्बद्ध प्रश्न वस्तुतः यह जान पड़ता है: सास्थानिक, राजनीतिक एव नैतिक कारणों से आय के वितरण में कुछ परिवर्तनों के दिया हुआ रहने पर, निपज एव पूँजी की वृद्धि पर इस प्रकार के परिवर्तनों के क्या प्रभाव होगे ? वर्तमान अध्याय में अशतः इसी अन्तिम प्रश्न की व्याख्या की जायगी।

दूसरा प्रमुख प्रस्न, जिसका यहाँ विचार किया आयगा, आर्थिक विकास के सदर्भ में साधनों का पुनर्विनिधान है। क्योंकि, दीर्घकालिक विचार से दिये हुये साधनों का पुनर्विनिधान एवं दी हुई आय का उत्पादक तरीके से पुनर्वितरण ठीक उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि उत्पादक साधनों तथा राष्ट्रीय आय के आकार को घोष्ट्रतापूर्वक वढाना। चूँकि किसी अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर में वचत-अनुपात के आनुपातिक तथा पूजी-निपज अनुपात के प्रतिलोमी दर में परिवर्तन होने

^{1.} देखें सी० वलाकं, दि कन्डीशन ऑफ इकॉनामिक प्रोग्नेस; एस० कुजनेट्स 'इकॉ-नामिक प्रोथ एड इनकम इनइवेबिलटी', पूर्व उद्धृत; पोस्ट केन्सीयन इकॉनामिक में एम० क्रोनफनवेनर का 'समनेगलेक्टेड इम्प्लिकेशन्स ऑफ सेकुलर इन्पले-गन'। चूँकि हमने अन्तिम परिसंवाद में विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के सदर्भ में निवेश की मांग परपुनवितरण-प्रभाव का वर्णन किया था, अत्एव अब हम अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में पूर्ति एव पूँजी की क्षमता पर ध्यान 'रेगे।

की प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव हम लोग स्पष्टतः निम्नलिखित विषयों का वर्णन करेंगे: (क) बचत-अनुपात पर आय के पुनिवतरण का प्रभाव, तथा (ख) पूँजी-निपज अनुपात या इसके व्युत्क्रम पूँजी की उत्पादकता पर साधनों के पुनिविनिधान का प्रभाव।

तो भी, आय के पुनिवित्रण एवं साधनों के पुनिविनिधान की विशेष प्रिक्रयाएँ जिनमें एक अर्थ-व्यवस्था से दूसरी अर्थ-व्यवस्था में अन्तर पाया जाता है, वितरण के प्राचलों में विधे हुए परिवर्तन में अन्तिनिह्त होगी। तथापि, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश परिस्थितियों में आय का पुनिवित्रण एवं साधनों का पुनिविनिधान मूल्य की गति, प्राथमिकता विनिधान, वित्तीय नीति, एकाधिकार-विरोधी अधिनियम एवं सामूहिक सौदे के द्वारा किया जाता है।

वचत-अनुपात पर पुनर्वितरणका प्रभाव

संस्थापक अर्थशास्त्रियों से प्रारम्भ कर आज तक यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता रहा है कि आय (एवं सम्पत्ति) का वितरण राष्ट्रीय पूँजी के संचय की पृष्ठ-भूमि में प्रमुख एवं आग्रह-युक्त कारण के रूप में वर्तमान रहा है। किन्तु, आर्थिक प्रगति पर वितरण-सम्बन्धी प्रभाव की मात्रा प्रारम्भ से अब तक विवाद का विषय रही है। मैण्डेविले के 'सधुमिक्खयों की कल्पित कथा' से प्रारम्भ कर केन्स के 'मितव्यय के विरोधाभास' तक न्यून उपभोग के समर्थकों द्वारा विये गये तर्कों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है। जहाँ तक अल्पकाल में विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, केन्स ने इस बात को दिखलाकर कि पूर्ण रोजगार से निम्न विन्दु पर मितव्यय में वृद्धि से वास्तविक पूँजी में वृद्धि के बजाय कमी होती है, शुम्पी-टर के वाक्यां मों में, 'बूज्'आ तर्क के अन्तिम स्तम्भ को भी निस्सन्देह चकनाचूर कर

3. जे॰ शुम्पीटर, "जीन मेनर्ड केन्स 1883-1946" पूर्व उद्धृत ।

आगे के अध्यायों में कुछ पुनर्वितरणात्मक प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया जायगा।

^{2.} पूर्व-संस्थापक युग में वर्नार्ड मैण्डेविके (Bernard Mandoville) का यह तत्कालीन विधर्मी विचार था कि समृद्धि बचत से नहीं, वरन् व्यय करने से बढ़ती है। आदम स्मिथ ने गलत कहकर इस विचार का परित्याग कर दिया था, किन्तु केन्स ने इसे स्वीकारात्मक रूप में उद्धृत दिया है। (देखें केन्स की जेनरल थियरी, विशेषतः 'मरकेण्टिलज्म पर टिप्पणियाँ') आधिक विचारधारा के इतिहास में न्यून उपभोग के अन्य समर्थकों लौडरडेल, माल्यस, सिस्मोंडी, मार्क्स एवं स्वावन हैं।) देखें नोरटन, एन० वाई०, 1951 द्वारा प्रकाशित ए० एच० हैनसेन की विजिनेस साइकिट्स एण्ड नेशनल इन्कम, अध्याय 14; किन्तु, हैनसेन ने सिस्मोंडी एवं मार्क्स को छोड़ दिया है।)

दिया। जहाँ तक दीर्घकान में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि व्यय न करने की हामता के अनुभित न्यून न हो सकते योग्य दोप के विरुद्ध, केन्स का तक पूर्णत: प्रवल तथा मितव्यय के अनुभानित शृद्ध गुण के पक्ष में सस्थापक तक के प्रति विलकुत अग्राह्म है। निम्नांदित विवेचन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के विशेष सदर्भ में इस सस्थापक-भूत केन्सीय विवाद पर कुछ प्रकाश हानता है

आय की विषयता एवं बचत-अनुपात

मान निया कि दी हुई राष्ट्रीय आय (γ) मजदूरी-सम्बन्धी आप (γ_{ν}) तथा गैर-मजदूरी-सम्बन्धी आय (γ_{π}) में समाप्त हो जाती है, जिससे कि

$$Y = Y_w + Y_{\tau\tau}, \tag{1}$$

जिसमे कि Y_n मे बेनन (सफेंद कालर बाले मजदूरों का) तथा Y_n मे मुनाफा, लागाँग, लगान, ब्याज एवं स्वत्व-शुरूक सिम्मिलित हैं यद्यपि वास्तिविक विश्व मे कुछ अति-व्यापकता हो सकती है, फिर भी प्रत्येक परिवार अथवा व्यक्तिगत आय प्राप्त करने वाले की आय का प्रधान साधन ही इस बात का निर्धारण करता है कि वह किस वर्ग के अन्तर्गन आता है। इस प्रकार यदि किसी परिवार की आय मुख्यतः मजदूरी तथा अथतः लाभाँग (उदाहरण के लिए, इसके कुल स्टॉक पर) जो प्राप्त होती है, तो उसके परिवार को मजदूरी से प्राप्त आय वाले वर्ग के अग्तर्गत सममना चाहिए। इस प्रकार के विचार से सीमान्त साधनों से प्राप्त पारिवारिक आय एक-दूसरे को समान्त कर देती है, जिससे मुख्य माधन ही शुद्ध रूप मे रह जाता है।

^{1.} संस्थापक तर्क इस विश्वास पर आघृत है कि पूंजी का सचम बचाने की ध्यक्ति गत क्षमता की प्रवलता पर निर्भर करता है। इस पूंजी-सचय के एक बहुत बड़े भाग के लिए सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था 'धिनिको के उपभोग-स्थगन' पर निर्भर करती है। इस तर्क के साथ यह आशय भी जुड़ा हुआ है कि अर्थ की विपमता आर्थिक प्रगति की एक आवश्यक शर्त है। इसके विपरीत संद्वान्तिक प्रमाणों के अति-रिक्त, बचत को प्रोत्साहित करने मे आय की विपमता का क्षेत्र इस तथ्य से भी अत्यधिक कम हो जाता है कि अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ व्यवस्थाएँ अपनी विकासात्मक पूँजी के एक बहुत बड़े भाग के लिए सरकारी बचत पर निर्भर रहती है। 'अन्योन्याश्रित उपभोक्ता की प्राथमिकता' जो, जैंगा कि ऊपर मूल ग्रंथ मे बणित किया जायगा, पूँजी के विवाम की आवश्यक गर्त के रूप में आय की विपमता के व्यावहारिक महत्त्व को और भी कम कर देती है; इस पूर्व-विलयत गर्त में पूँजी-विकास के तथ्य को और भी वल मिलता है।

समीकरण (1) से निम्नांकित मजदूरी एवं गैर-मजदूरी प्राचल प्राप्त होता है :

$$\frac{Y_{v}}{Y} = \eta, \frac{Y_{\pi}}{Y} = \mathbf{I} - \eta, \tag{2}$$

जो सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार के सांस्थानिक कारणों द्वारा पूर्वनिष्चित होते हैं तथा जो साधनों के मूल्य एवं पुनिवितरण-सम्वन्धी नीति से संगोधित होते हैं। इस विवेचन के सन्दर्म में मजदूरी-वितरण अनुपात १ में किसी भी प्रकार की कमी को आय की विपमता में कमी के रूप में समभ्रा जायगा। आय की विपमता का यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि औसत राष्ट्रीय आय से कम आय प्राप्त करने वालों में मजदूरी तथा चेतन पर काम करने वालों की अत्यन्त प्रवल प्रधानता रहती है, जविक ग़ैर-मजदूरी पर काम कराने वालों की अत्यन्त प्रवल प्रधानता रहती है, जविक ग़ैर-मजदूरी पर काम कराने वालों की अत्यन्त प्रवल प्रधानता रहती है, जविक ग़ैर-मजदूरी पर काम कराने वालों की अत्यन्त प्रवल प्रधानता रहती है, जविक ग़ैर-मजदूरी पर काम कराने वालों की अत्यन्त प्रवल प्रधानता रहती है, जविक ग़ैर-मजदूरी पर काम कराने वाले औसत आय से अधिक आय वाले अत्य-व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में एक अतिरिक्त धारणा वनाई जा सकती है कि मध्यम वर्ग, जिसकी आय औसत आय से कुछ अधिक है, अपेक्षाकृत कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धनी एवं निर्धन के वीच आय की विपमता चरम-सीमा पर है। आय के वितरण की यह अत्यधिक विपमता, आधारभूत रूप में, आय-उत्पादन सम्पत्ति के अत्यधिक केन्द्रीकरण का सूचक है।

अब दी हुई राष्ट्रीय आय में से कुल बचत (S) भी दो भागों में विभक्त की जाती हैं—प्रथम वह, जो मजदूरी-सम्बन्धी आय (S_w) से तथा द्वितीय वह, जो ग़ैर-मजदूरी-सम्बन्धी (S^π) आय से प्राप्त होती है। जिससे

$$S\pi = S_w + S\pi, \tag{3}$$

जिस समीकरण का दाहिना पक्ष दीर्घकालीन प्रवृत्ति के पृथक् वचत-फलन के कृप में निर्दिष्ट किया जा सकता है (वचत की औसत एवं सीमान्त क्षमता को सूचित करते हुए):

$$S_w = s_w Y_w s_w \eta Y, \qquad (4)$$

और

$$S\pi = s\pi Y_{\pi} = s\pi (I - \eta) Y$$
, (5)

यहाँ s_w मजदूरी-सम्बन्धी तथा $s_{\mathcal{D}}$ ग़ीर-मजदूरी-सम्बन्धी आय में से बचत की औसत एवं सीमान्त प्रवृत्ति हैं। यह देखा जा सकता है कि $s_w\eta$ राष्ट्रीय आय में से वेतन-भौगी मजदूर-वर्ग के बचाने की औसत तथा सीमान्त समता का एवं $s_{\mathcal{D}}$ ($I-\eta$) राष्ट्रीय आय में से वेतन न पाने वाले मजदूर वर्ग के बचाने की औसत तथा सीमान्त समता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि व्यावहारिक है, यह मान लिया कि

मजदूर-वर्ग के बचाने की अपेसत एवं उसकी सीमान्त दामता वेतन न पाने वाले मजदूर-वर्ग की अपेक्षा कम है, याची $s_w < s_{T-1}$ यह वही अन्तर है, जो आप के पुनिवतरण को सार्थक बनाता है।

समीकरण (3) में (4) एवं (5) की प्रतिस्थापित कर एवं नये तम में रखने से युत्त बचत आय एवं नितरण के फनन के रूप में निम्नांकित प्रकार से प्राप्त होती है.

$$S = [s_w \eta + s_\pi (I - \eta)] Y, \tag{6}$$

जिसते हमें सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए बचत की औसत प्रवृत्ति (s) प्राप्त होती है :

$$-\frac{S}{Y} = s = e\eta + e\pi (I - \eta) \tag{7}$$

समीकरण (7) यह स्पष्ट करता है कि यदि मजदूरी-वितरण अनुपात १ स्यायी रूप से नीचे आ जाता है, तो $s_{\nu} < s_{\mu}$ होने पर राष्ट्रीय आय से से बचाने को औमत-क्षमता में वृद्धि होगी । किसी अर्थ-ज्यवस्था की विकास-दर के सम्बन्ध में समीकरण (7) के आशय को निम्नोकित प्रकार से दिखलाया जा सकता है:

$$\frac{\triangle}{y} = G = \frac{s_{\omega} \eta + s_{\pi} (I - \eta)}{b} \tag{8}$$

जिसमें GL निपज (अथवा पूजी) में बृद्धि की दर तथा (b) पहले की ही तरह पूजी-निपज अनुपात है। समीकरण (8) यह बतलाता है कि यदि पूँजी निपज अनुपात स्थायी रहे, तो आय की विषमता में बृद्धि (निम्न १ के रूप में व्यक्त) के परिणामस्वरूप निपज में बृद्धि की दर बढ़ने योग्य है। समीकरण (8) विपमता एवं धिनिकों के उपभोग-स्थाग के माध्यम से प्रमति की सस्थापक स्थिति की व्याख्या करता है। इस प्रकार, ऐसा जान पड़ता है कि आधिक प्रमति के अपिरहाय पूर्विकालित के रूप में आय की विपमता को मौन रूप में न्यायोचित करार करने में सस्थापक अर्थशास्त्री निर्दोष ये। फिर भी, प्रयुक्त विश्वेषण दो आधारमूत वातों में अपूर्ण है: प्रयमतः, यह बचत-अनुपात पर अन्योन्याधित उपभोक्ता के आवरण के सम्मावित विस्थित प्रभाव की उपेक्षा करता है तथा द्वितीयतः, यह पूँजी-निपज अनुपात पर साधनों के पुनिवतरण के सम्मावित निम्नगामी प्रभावों की अवहेलना करता है। साथ ही, मजदूरी कमाने वालों से लेकर गैर-मजदूरी कमाने वालों के बीच आय के पुनिवतरण, विजयतः वैसी अस्य-विकसित अर्थ-ज्यवस्थाओं पर भी जिन्होंने अवसर की समानता के प्रजातान्त्रक सिद्धान्त में अपने को समर्पित कर दिया है, सन्देह

प्रकट किया जा सकता है। ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयों को छोड़कर, हम उप-भोक्ताओं के अन्योन्याश्रित अधिमान के वर्तमान विवेचन को ध्यान में रखते हुए आय के पुर्नावतरण तथा बचत अनुपात के सम्बन्ध पर विचार करें।

आय का समीकरण एवं वचत-अनुपात

ड्युसेनवेरी ने परिहास के रूप में अथवा अन्यथा विषमता के माध्यम से प्रगति-सम्बन्धी चिर-प्रतिष्ठित विचार पर ऐसा सुफाव देते हुए कि उस समाज में, जो अमुक के बराबर होकर रहने की संस्थागत मनोवैज्ञानिक आदत के वश में है, 'विषमता में कमी से वचत की आंसत-प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है,' प्रश्नवाचक चिह्न लगाया है। संभव है कि इस प्रकार का प्रस्ताव 'न्यून उपभोग' के समर्थकों के इस विश्वास को, कि समर्थ माँग की अपर्योध्तता का शिकार बन जाने वाली एक विकसित अर्थं व्यवस्था में आय का समान वितरण उपभोक्ता की माँग में वृद्धि कर सकता है, हतोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया गया हो। फिर भी, जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, अधिक समानता एवं पूँजी में वृद्धि की संगतता में केन्सीय विश्वास को दृढ़ बनाने के कार्य पर ड्यूसेनवेरी के उपर्युक्त सुफाव का संभवतः अनिमतः प्रभाव पड़ता है।

निम्नांकित विवेचन के लिए हम लोग यह एक व्यापक मान्यता स्थिर करते हैं कि सम्बद्ध अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था विदेशी वस्तुओं के आयात पर जो अन्तर्रा-ष्ट्रीय महानुभावों के वरावर होकर रहने में सहायक सिद्ध होती है, प्रभावपूर्ण

श्री अनुरूप, एक भारतीय अर्थणास्त्री का कहना है कि आर्थिक सिद्धान्त (संस्थापक) से हमें यह पता चलता है कि अर्थ-अ्यवस्था में वचत को बढ़ाने का एक तरीका आय को निर्धन व्यक्तियों से लेकर धनिकों के बीच पुनर्वितरण करना है। किन्तु वर्तमान समय में एक प्रजातन्त्र देश में इस प्रकार की नीति राजनीतिक वृष्टि से कितना सम्भव तथा सामाजिक वृष्टि से वाँछनीय भी है, यह कहना कठिन है। (देखें, डी० भा 'फिसकल पाँलिसी एन्ड द इकॉनामिक डिवेम्लपमेन्ट ऑफ अन्डर-डिवेलप्ड कन्ट्रीज', इण्डियन जनरल ऑफ इकॉनामिकस, जलाई, 1956।

^{2.} देखें, जे० एस० ड्यूसेनवेरी, इनकम, सेविंग एण्ड दि थियरी आफ कन्ज्यूमर विहेचियर, कैम्ब्रिज, 1949, पृ० 44; साथ ही देखें एच० जी० जान्सतः 'दिं इफेक्ट्स आफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन आन एग्रीगेट कन्जम्पशन विथ इंटरडिपेन्डेंस आफ कन्ज्यूमर प्रेफरेन्सिज, इकानॉमिका मई, 1952। इन दोनों लेखकों का सम्बन्ध विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से है, न कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में आधिक विकास की समस्या के लिए आय के समीकरण के आशय से।

नियत्रण (उदाहरण के लिए, चयनारसक ण्ल्क दर एव अनेक विनिमय-दर के रूप मे) रखती है। दम प्रकार की मान्यता हमें आतिरिक आय के समीकरण (वौरेंज-वक के अर्थ मे) एव उपभोग (अथवा बचत) अनुपात के सम्बन्ध को पृथक् करने के लिए अनुप्रेरित करती है। अन्य सबद्ध मान्यनाओं का उल्लेख यथास्थान किया जाएगा।

मान लिया कि दी हुई राष्ट्रीय आय (γ) का एक अंश निम्न आय वाले परिवारो (γ_1) में. दूसरा अश मध्यम आय वाले परिवारो (γ_2) में तथा हैंप माग उच्च आय वाले परिवारो (γ_3) में समाप्त हो जाता है, जिससे:

$$Y = Y_1 + Y_2 + Y_3 \tag{9}$$

$$\frac{Y_1}{Y} = \mu, \quad \frac{Y_2}{Y} = \varepsilon, \quad \frac{Y_3}{Y} = I - \mu - \varepsilon \tag{10}$$

जिसके वितरण अनुपात है ।

पुन, हम कुल वास्तिविक उपभोग व्यय (C) का विभाजन भी इस तरह करते हैं एक अश निम्न आय वाले परिवारों (C_1) , दूसरा भाग मध्यम आय वाले परिवारों (C_2) तथा शेय भाग उच्च आय वाले परिवारों (C_3) में समाप्त हो जाता है, यानी

$$C = C_1 + C_2 + C_3, \tag{11}$$

यहाँ पुनिवितरण के अन्योग्याधित प्रभाव को देखने के लिए प्रत्येक वर्ग के परिवारों की उपभोग-सम्बन्धी आदतों को स्पष्ट करना अनिवार्य है। यह मान लिया जाएगा कि पहते एवं सीसरे वर्ग का उपभोग के बल उनके परिवार की अपनी-अपनी आय पर निर्मर करता है, जबिक द्वितीय वर्ग का उपभोग इनकी अपनी आय के अतिरिक्त अशत पहले एवं तीमरे वर्ग की आय पर निर्मर करता है। दूसरे शब्दों में, मध्यम वर्ग के परिवार को इस अर्थ में प्रति-स्पर्धात्मक माना जाता है कि उनका उपभोग स्पष्टतः अन्य दो वर्गों के परिवारों के उपभोग द्वारा प्रभावित होता है। प्रथम एवं तृतीय वर्गों के उपभोग में परिवर्गन का द्वितीय वर्ग के उपभोग पर किसी हद्द तक प्रभाव पहला है, जिसकी अभी व्याख्या करनी है।

^{1.} देयं, आर० नक्सं, प्रोक्तिस्स आफ कंपिटल फाँरमेशन इन अडर-डिवेलप्ड कन्द्रीच पृ० 577-0 अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से अन्तर्राष्ट्रीय धनवान महानुभाषों की 'रपण्ट उपस्थिति' से आतरिक बचत को बढाने की कठिनाइयों की विधेचना के प्रयासस्वरूप, मेनक्सें ने, ड्यूसेनवेरी के अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के प्रदर्शनात्मक प्रभाव का, जिसका आशय अतर्राष्ट्रीय समागीकरण एव विकसित तथा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के बीच उपभोग-स्तर की विस्तृत खाई को कम करने की इच्छा है—प्रयोग किया है।

अब समीकरण (11) के दाहिने पक्ष को तीन पृथक् उपभोग-फलन के रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है:

$$C_1 = a_1 Y_1 = a_1 \mu Y, \tag{12}$$

$$C_3 = a_3 Y_3 = c_3 (I - \mu_1^3 - \epsilon) Y,$$
 (13)

और

$$C_2 = \alpha C_1 + \beta C_3 = \left[\alpha a_1 \mu = \beta a_2 (I - \mu - \varepsilon)\right] Y, \tag{14}$$

यहाँ a_1 सम्पूर्ण निम्न आय वाले परिवारों की निम्न आय से उपभोग की औसत एवं सीमांत क्षमता है, a_3 सम्पूर्ण आय वाले परिवारों की ऊँची आय से उपभोग की औसत एवं सीमांत क्षमता है, α सम्पूर्ण भध्यम आय वाले परिवारों की निम्न आय वाले परिवारों के उपभोग की प्रतिस्पर्धा करने की एवं β मध्यम आय वाले वर्गों की ऊँची आय वाले वर्गों के उपभोग में प्रतिस्पर्धा करने की औसत तथा सीमांत क्षमता है। यहाँ आय एवं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के वीच प्रतिलोम सह-सम्बन्ध की सामान्य मान्यता के अनुसार $a_1 > a_3$ है। जहाँ तक प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, ऐसा मान लेना उचित जान पड़ता है कि मध्यम आय वाला वर्ग, निम्न आय वाले वर्ग की अपेक्षा ऊँची आय वाले वर्ग के उपभोग को अधिक महत्त्व प्रदान करता है, यानी $\beta > \alpha$ है। इसका आग्रय यह है कि मध्यम आय वाला वर्ग निम्न आय वाले वर्ग के उपभोग-परिवर्तन के परिणामस्वरूप अपने उपभोग में जो वृद्धि करता है, उससे अधिक मात्रा में वृद्धि वह ऊँची आय वाले वर्ग के उपभोग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप करता है।

समीकरण (12), (13) एवं (14) को मिलाने से समीकरण (11) अब इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है:

$$C = [a_1 \mu + \alpha a_1 \mu + \beta a_3 (I - \mu - \epsilon) - a_3) I - \mu - \epsilon)] Y,$$
 (15) जिससे हमें सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था (c), के उपमोग की औसत प्रवृत्ति प्राप्त होती है:

$$\frac{C}{Y} = c = a_1 \mu + \alpha a_1 \mu + \beta \mu_3 (1 - \mu - e) + a_3 (1 - \mu - e), \quad (16)$$

णो यह बतलाता है कि यदि आय का पुर्नावतरण तीसरे वर्ग से पहले वर्ग में किया जाता है (जी व को स्थायी रखकर उच्च μ एवं निम्न $I-\mu$ — के रूप में ध्यक्त होता है), तो इस प्रकार कें पुर्नावतरण से उत्पन्न आय-प्रमाव तथा अन्योन्याश्रित प्रभाव से उपभोग की औसत राष्ट्रीय-क्षमता (c) में कमी हो सकती है। स्पष्टतः समीकरण (16) यह सूचित करता है कि पुर्नावतरण का मध्यम आय वाले वर्ग पर इस प्रकार का अन्योन्याश्रित प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय में इसके उपभोग की औसत एवं सीमांत-क्षमता घट जाएगी, $\alpha a_1 \mu + \beta a_3 (I-\mu - \epsilon)$, उच्च आय वाले वर्ग पर इसका ऐसा आय-प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय में इसके उपभोग की औसत एवं

मीमात-क्षमता घट जायगी, $a_3(I-\mu-\epsilon)$ और निम्न आय वाले वर्ग की आय पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय में इसके उपभोग का औसत सोमात वंद जाएगा, $a_1\mu$ । इसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय उपभोग अनुपात (c) कम हो जाता है। अतएव, यदि निम्न आय वाले वर्ग की निम्न आय में से उपभोग की औसत एव सीमात क्षमता उच्च आय वाले वर्ग की उच्च आय की अपेक्षा अधिक है $(a_1>a_3)$ तो आय के समीकरण के परिणामस्वरूप कुल उपभोग में सिन्निहित वृद्धि $\beta<\sigma$ के विपरीत अन्योग्याधित प्रभाव के रहते हुए सूचक विस्थिति विलक्षल ह्यास हो जाता है।

भूंकि राष्ट्रीय यचत-अनुपात s=I-c के द्वारा दिया हुआ है, अतएव एक स्थायी पूंजी-निपज अनुपात (b) वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर के लिए समीकरण (16) का आग्रय निम्नानित रूप में देखा जा सकता है।

$$G_{\varepsilon} = \frac{I - \left[a_{1}\mu + \sigma a_{1}\mu + \beta a_{3}\left(I - \mu - \varepsilon\right) + a_{3}\left(I - \mu - \varepsilon\right)\right]}{b} \tag{17}$$

जो यह बतलाता है कि विकास की दर (G_k) मे तभी वृद्धि हो सकती है, जबिक सभीकरण (9) से (16) द्वारा विजित आय समीकरण के अन्नोन्याधित प्रभाव एव आय-प्रभाव की परस्पर किया के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय बचत अनुपात में वृद्धि होती है।

उपयुंक्त विवेचन यह बतलाता है कि आय की विषमता पर आधृत'धिनिकों के उपभोग-स्थगन' के सम्बन्ध में सस्थापक माग्यता उतनी ही अनिक्षायक है, जितना कि यह पथ-भ्रष्ट करने वाली है। यह इस बात को भी बतलाता है कि प्रबल समानता एवं कल्याण की भावना बाली अल्प-विकसित अर्थ-प्यवस्था को महत्त्वपूर्ण व्यक्तिपों के बराबर होकर रहने एवं उपभोक्ता के अन्योन्याधित अधिमान के सामाजिक मनी-वैज्ञानिक तत्त्व से सार-प्रहण द्वारा प्राप्त आधिक प्रगति की आय की अधिक समानता के साथ अनुमित असगति के सम्बन्ध में, इतना आधिकत नहीं होना चाहिए।

पूँजी-निपज अनुपात अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि साधनों के पुनर्विनिधान के परिणाम-

^{1.} वर्तमान विश्लेषण एस० कुजनेट्स के समयवाद वा यह कह कर कम-से-कम अंशतः समर्थन किया है: "साधारण उपमाओं में खतरा है, ऐसे तक देने में कि चूंकि पहले पश्चिमी यूरोप में आय के विषम वितरण से वचत का सचय हुआ और आधार भूत पूँजी-निर्माण को वित्तीय आधार प्राप्त हुआ, अतएव इसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए अल्प-विकमित अर्थ-व्यवस्थाओं में आय की वर्तमान विषमता को बनाये रखना अथवा वढाना आवश्यक है।"—देखें इनकी 'इकॉनामिक ग्रोप एण्ड इनकम इन इन-इनववेलिटी', पूर्व उद्धृत।

स्वरूप, चाहे यह किसी भी प्रकार से क्यों न हुआ हो, पूँजी-निपज अनुपात में कमी, अथवा दूसरे शब्दों में, पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि होगी अथवा नहीं । इस प्रकार विचार के पूर्व, यह मान लिया जाता है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अथवा उद्योगों के वीच आर्थिक साधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में घोर विषमता व्याप्त है तथा दी हुई अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादकता निहित है।

पूंजी का पुनर्विनिधान एवं उत्पादकता

मान लिया कि कोई अर्थ-व्यवस्था कृषि एवं उद्योग. दो क्षेत्रों में विभक्त है, तो पूर्ण प्रयुक्त रहने पर पूँजी के कुल वास्तविक कोप (K) को कृषि-संबंधी पूँजी (K_a) तथा औद्योगिक पूँजी (K_I) में विभक्त किया जा सकता है, जिससे कि

$$K = K_a + K_i \,, \tag{18}$$

जिसका वितरण अनुपात है---

$$\frac{K_a}{K} = \lambda_i \frac{K_i}{K} = I - \lambda. \tag{19}$$

मान लिया कि पूर्ण-क्षमता निपज (γ) के दो अंग कृषि-सम्बन्धी निपज (γ) तथा औद्योगिक निपज (γ) है, जिससे कि

$$Y = Y_a + Y_i \tag{20}$$

तव श्रम को दिया हुआ मानकर निपज को पूँजी एवं वितरण का फलन मानकर स्पष्ट किया जा सकता है:

$$Y_a = \sigma a K a = \sigma a \lambda K. \tag{21}$$

$$Y_i = \sigma_i K_i = \sigma_i (I - \lambda) K. \tag{22}$$

यहाँ इस आधार पर कि औद्योगिक क्षेत्र को कृषि-क्षेत्र की अपेक्षा श्रेष्ठतम टेक्नो-लॉजिकल जानकारी तथा नवाचार-सम्बन्धी पटुता प्राप्त है यह मान लिया जाता है कि औद्योगिक पूँजी (σ_i) की औसत एवं सीमांत क्षमता कृषि-पूँजी (σ_o) से उच्च है ।

प्रतिस्थापित एवं नये कम से रखने पर हमें संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूंजी की औसत उत्पादकता प्राप्त होती है।

$$\frac{Y}{K} = \sigma = \sigma_v \lambda + \sigma_i (I - \lambda), \tag{23}$$

जो यह बतलाता है कि $a_i > \sigma_v$ होने पर पूँजी-वितरण अनुपात में $(1-\lambda)$ वृद्धि के

परिणामस्वरूप सामान्य रूप से पूँजी की औसत क्षमता (०) मे वृद्धि हो सकती है। दूसरे शब्दों में, उच्च औसत एवं सीमात उत्पादकता वालें औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में वास्तविक पूँजी के पुनिविनिधान से सपूर्ण अर्थं-व्यवस्था के लिए पूँजी निपज अनुपात कम हो जाएमा। अर्थं-व्यवस्था को विकास-दर के लिए पूँजी-निपज अनुपात में इस प्रकार के विनिधान-प्रेरित परिवर्तन का आशय रूपान्तरित विकास समीकरण के रूप में देखा जा सकता है

$$Gk = \frac{s}{b} = s \frac{I}{b} = s\sigma = s \left[\sigma a\lambda + \sigma t \left(\mathbf{I} - \lambda\right)\right],$$
 (24)

जहाँ पहले की ही तरह s बचत-अनुपात तथा b पूँजी-निपज अनुपात है । समीकरण (24) यह स्पष्ट करता है कि यदि बचत-अनुपात स्थायी रहता है, तो भी जब तक oı > oa होगी, तब तक कृषि-क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र मे बास्तविक पूँजी-पुनर्विनिधान के परिणामस्वरूप निपज की वृद्धि की दर मे वृद्धि हो सनती है।

यही विश्लेपण एव तर्क उस अर्थ-स्यवस्था के साथ भी लागू होता है, जिसे विभिन्न उत्पादकता वाले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में विभवत किया जा सकता है। किन्तु, ऐसी स्थित में पूँजी के पुनिविनिधान में अधिक राजनीतिक एव दार्शनिक किठनाइयाँ होंगी। फिर भी, विभिन्न उत्पादकता वाले भारी तथा हस्के उद्योगों अथवा निर्यात-सम्बन्धी अथवा घरेलू उद्योगों के बीच पूँजी के पुनिविनिधान में कम ही किठनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समीकरण (18) से (21) तक विणत हमारे मांडल में, इस प्रकार अन्तर-उद्योग पुनिविनिधानों के अनुरूप बनाने के लिए आसानी से सगोधन किया जा सकता है।

श्रम का पुनर्विनिधान एवं उत्पादकता

पूँजी एव टेक्नोलॉजी को दिया हुआ मानकर, अब हम अर्थ-ब्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, श्रम के पुनविनिधान के सम्मानित प्रभावों पर भिन्न-भिन्न उत्पादकता वाले विभिन्न प्रकार के श्रम की उपस्थित की मान्यता के आधार पर, विचार करें। पुन हमें उत्पादन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूर्ण-नियुक्त श्रम-सब्या के पुनविनिधान के विशेष तकनीक से निष्कर्ष निकालेंगे।

एक दी हुई पूर्ण-निध्वत थम-सद्या (N) को अकुशल, श्रम (Nu) एव क्रुगल श्रम (Ns) मे अलग किया जाय, जिससे

$$N = Nu + Ns, \tag{25}$$

जिसवा वितरण अनुपात है।

$$\frac{Nu}{N} = r, \quad \frac{Ns}{N} = I - r \tag{26}$$

जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यहाँ मान्यता यह है कि श्रम-वितरण अनुपात r बहुत बड़ा है। इसका आशय यह है कि टेक्नोलॉजी के निम्न स्तर, विस्तृत तकनीकी शिक्षा के अभाव, गहन उपस्करों के अभाव एवं विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने (उदाहरण के लिए देशी विद्यार्थियों को विदेशी तकनीकी विद्याल्यों में भेजना) अथवा विदेशी विश्वेषकों की सेवाओं के अपेक्षाकृत उच्च व्यय के परिणामस्बरूप, कृत्रल श्रम पूँजी की ही तरह दुर्लभ है।

पुन: यह मान लो कि कुल निपज अकुशल श्रम के उत्पादन (Yu) तथा कुशल श्रम के उत्पादन (Ys) के बीच विभवत की जा सकती है,

जिससे.

$$Y = Yu + Ys, \tag{27}$$

जिसके दाहिने पक्ष को इस प्रकार से उल्लिखित किया जा सकता है:

$$Yu = pu Nu = purN, \tag{28}$$

$$Ys = psNs = ps (1-r) N \tag{29}$$

यहाँ pu एवं ps कमणः अकुगल एवं कुशल श्रम की उत्पादकता हैं (दोनों परिस्थितियों में स्थायी प्रतिफल के आधार पर औसत एवं सीमान्त उत्पादकता समान हैं)। यहाँ भी यह मान्यता है कि अकुगल श्रम की अपेक्षा कुशल श्रम की सीमान्त उत्पादकता ऊँची है, ps > ps, तथा अकुगल श्रम अपने को कुगल क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनान के योग्य हैं। इन मान्यताओं के आघार पर, Ys क्षेत्र में पूर्ण नियुक्त श्रम का पुनर्विनिधान सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए श्रम की औसत उत्पादकता में निम्न प्रकार से वृद्धि करेगा:

$$\frac{Y}{N} = p = pur + ps (I - r) \tag{30}$$

समीकरण (30), यद्यपि कृशल श्रम के वितरण अनुपात (1-r) में वृद्धि के द्वारा आसत उत्पादकता को वढ़ाने की सम्भावना को स्पष्ट करता है, फिर भी, अच्छे प्रशिक्षण, उन्नत अभिरुचि, अथवा उपाजित कृशलता के चलते अकुशल श्रम की क्षेत्रीय क्षमता (उच्च pu) में वृद्धि के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अर्थ-व्ययस्या के लिए श्रम की औसत उत्पादकता में वृद्धि की सम्भावनाओं को पृथक् नहीं करता।

समीकरण (30) को ध्यान में रखकर तथा Y/N को पूँजी-निपज अनुपात को प्रभावित करने वाली स्वतन्त्र इकाई के रूप में समभ कर हम बाद बाले अनुपात को संशोधित रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं:

$$\frac{K}{Y} = b = \frac{K/N}{Y/N} = \frac{K/N}{\rho u r + \rho s} (I - r)$$
 (31)

पूँजी-श्रम अनुपात को 0 के द्वारा निर्देशित करते हुए हम स्थायी वचत-

अनुपात (s) वाली अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर के लिए समीकरण (30) एव (31) के आशप को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं:

$$Gk = \frac{s}{0/[pur + ps(I - r)]}, \tag{32}$$

जो बचत अनुपात (5) एव पूंजी की गहनता के गुणक (0) के स्थायी रहने पर कुशल श्रम के वितरण अनुपात (I-r) मे वृद्धि के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विकास दर (GL) मे वृद्धि की सैद्धान्तिक सम्भावनाओं की व्यक्त करता है।

अतएव, ओद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण नियुक्ति की स्थिति में दी हुई श्रम-सदया के उन क्षेत्रों तथा उपयोगी में, जिनमें प्रमाण के रूप एवं पूँजी की उत्पादकता ऊँची हो, पूर्नीविन्धान की योजना सिम्मिलित कर तेनी चाहिए। इसी प्रमार का विश्लेषण विभिन्न उत्पादकता वाले प्राष्ट्रतिक साधनों (भूमि) के पुन-विनिधान के सामदायक प्रभाव के सम्बन्ध में भी विया जा सकता है। किन्तु, इनसे यह नहीं सममना चाहिए कि पूर्ण नियुक्त साधनों के पुनिविन्धान को निर्वाध मूल्य-यन्त्र की मरणी पर छोड दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि निर्वाधों नीति की स्थिति में आर्थिक साधनों के दीर्थकालीन तथा खतरनाक कार्यक्रम से हटा-कर भीच लाभ प्रदान करने वाले, किन्तु सदा उत्पादक नहीं, कार्यक्रम में लगाने की सम्भावना पाई जाती है। श्रम-शक्ति लाभवन्दी के लिए सार्वजनिक श्रम-नियोजनान्त्रयों के साथ-साथ योग्यता-प्राप्त, निपुण शिल्पियों तथा विश्रपक्तों के राष्ट्रीय रोस्टरों से उत्पादक पुनिविन्धान में बहुन अधिक मुविधा होगी। साथ ही, प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को विदेशी शिल्पियों तथा विश्रपत्रों के उत्प्रवासन को प्रोत्साहन देने वाली राष्ट्रीय नीति से भी बहुन अधिक सहायता प्राप्त होगी।

अध्याय 8

आर्थिक विकास में मौद्रिक भूमिका

विकास-सम्बन्धी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भौद्रिक विचारधारा की वर्तमान स्थिति चहुधा इस शिकायत में प्रतिविम्बित होती है कि अर्थशास्त्री एवं मौद्रिक अधिकारी अब भी उत्तम वैकिंग-सम्बन्धी सुविधा ग़ैर-राजनीतिक केन्द्रीय वैकिंग-सम्बन्धी नीति एवं लोचपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था की वांछनीयता के सम्बन्ध में विहित सामान्य वार्ता ही प्रस्तुत करते हैं। फिर भी, कम-से-कम दो आधुनिक अर्थशास्त्रियों—केन्स एवं शुम्पीटर ने दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व एवं विकास के सम्बन्ध में मौद्रिक मूमिका (कुछ अर्थ में) के कारणात्मक महत्त्व पर जोर दिया है। केन्स सार्वजनिक साख (यानी राजकीय प्रतिकारी उद्यार एवं व्यय तथा विश्व-वैंक के उधार देने की क्रियाएँ) को आन्तरिक स्थायी विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास दोनों की एक अग्रवश्यक शर्त मानता था। साथ ही, दीर्घकाल में प्रवल निवेश के सहायक प्रोत्साहक के रूप में वह सस्ती मुद्रानीति के पक्ष में था। दूसरी ओर, शुम्पीटर निजी साख को आर्थिक विकास का एक प्रमुख परिवर्ती तथा साहसोद्यम एवं नवीन किया का एक अपरिहार्य

^{1.} उदाहरण के लिए देखें सी० आर० ह्विटलेसी, रिलेशन ऑफ मनी टू इकॉनामिक ग्रोथ, अमेरिकन इकॉनामिक रिब्धू, मई, 1956। साथ ही, देखें जे० जी० कर्ले एवं ई० एस० शा, फाइनान्शियल एस्पेक्ट्स आफ इकॉनामिक डिवेलपमेन्ट', पूर्व उद्धृत, सितम्बर, 1955; आर० एफ० हैरोड की पुस्तक डायनेमिक इकॉनामिक (लेक्चर 5) में 'इज इन्टरेस्ट ओवसोलीट' ? जोन रोविन्सन के 'दि रेट ऑफ इन्टरेस्ट ऐटसेट्ग, में 'दि रेट ऑफ इन्टरेस्ट' (अध्याय 1 से 6); एस० पाल, 'सम एस्पेक्ट्स ऑफ मोनीटरी एन्ड फिसकल पॉलिसीस फॉर इकॉनामिक ग्रोथ इन अन्डर-डिवेलप्ड कन्ट्रीज' 'इन्डियन जनरल ऑफ इकॉनामिक्स, जुलाई, 1956। केवल अन्तिम लेखक का ही सम्बन्ध विशिष्ट रूप से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से है, यद्यपि इसका विश्लेपण मुख्यतः ऐतिहासिक और सांस्थानिक है।

सहायक समधना था। केन्स एव शुम्पीटर की हम मौद्रिक अन्तर्दृष्टियो को ध्यान में रखने हुए, इस अध्याय में आधिक विकास की विसीय भूमिका (जिस पर पृथक् रूप से अगले अध्याय में विचार किया जायमा) से भिन्न, मौद्रिक भूमिका की गवेपणा की जाएगी।

वर्तमान अध्याय में स्पष्ट रूप से निम्नाकित विषयों का विवेचन किया जायगा: (क) साख, ब्याज एव विकास के बीच फलनीय सम्बन्ध, तथा (ख) स्फीनि एव विकास-विषयक सम्बन्ध । विभेचन के उद्देश्य से हम यह सास्थानिक मान्यना स्थिर करेंगे कि सम्बद्ध अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था का एक केन्द्रीय बैके है, इसके अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक वैक है, जो केन्द्रीय वैक के नियन्त्रण (कानून अथवा रिवाद के अनुसार) में है, जिसका एक मौदिक अधिकारी है, जो जनहित में मुद्रा की उपलब्धि एवं मुत्र को निर्धारित अथवा प्रभावित करता है।

साख, ध्याज एवं विकास

यह दिखलाया जा मकता है कि निर्दिण्ट परिस्थितियों के अग्तगंत साख की उपलब्धि एवं ब्याज की दर निपज में वृद्धि की दर की प्रभावित कर सकती हैं। पहले हम ब्याज की दर को दिया हुआ मानकर साख एवं विकास के सम्बन्ध पर पृथक् रूप से विचार करेंगे।

'संवृत' मॉडल

सवृत व्यवस्था समभी जाने वाली अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय में वृद्धि पर मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के प्रभावों को विखलाने के लिए केन्स के तरजता-अधिमान सिद्धान्त में निम्न प्रकार का सशोधन लाभदायक होगा । प्रथमतः, हम पूर्ति की गई एवं धारण के लिए मांगी गई मुद्रा के कुल परिमाण के केवल उसी भाग पर विचार करेंगे, जो आग पर निभार करती है तथा जिसे केन्स 'लेन-देन' तथा 'एहतियाती' प्रवृत्तियों का परिणाम बतलाते हैं। इसे उस भाग से पृथक् किया जागगा, जो ब्याज की दर एवं सन्तिहत परिकल्पना वी प्रवृत्ति पर निभार करता है। यह मणी-

^{1.} केल्स मौद्रिक साम्य के रूप में लिखते है कि $M=M_1+M_2=L_1(Y)+(L_2Y)$ जिसमें M पूर्त की गई मुद्रा का परिमाण है, M_1 'तेन-देन' तथा 'एहिंतपाती उद्देश्य' में पूर्त की गई मुद्रा का परिमाण, M_2 'परिकल्पना उद्देश्य' से पूर्त की गई मुद्रा का परिमाण, $L_1(\gamma)$ लेन-देन तथा 'परिकल्पना के उद्देश्य' से मुद्रा की माँग का परिमाण है, जो भीद्रिक राष्ट्रीय आय पर निभर करता है तथा $L_2(Y)$ 'परिकल्पना के उद्देश्य' से माँगी गई मुद्रा का परिमाण है, जो ब्याज को दर पर निभर करता है। (देशों, जेनरल थियरी पृ० 199) यहाँ पर हमारा सम्बन्ध मुख्यत. M_1 एवं $L_1(Y)$ के प्रकारान्तर से है।

धन हमें केवल मुद्रा एवं वस्तुओं के बीच चयन (मुद्रा एवं प्रतिभृतियों को छोड़) के अध्ययन तथा मुद्रा एवं आय के बीच के प्रत्यक्ष सम्बन्ध (इनके बीच निवेण की माँग पर व्याज की दर में परिवर्तन के द्वारा परोक्ष सम्बन्ध को छोड़) के विश्लेषण में सहायक होता है। द्वितीयतः, उपभोक्ता वस्तुओं की उपेक्षा कर हम अपने आपको लेन-देन को पूँजीगत वस्तुओं तक सीमित रखेंगे। यह अधिक सामान्य स्थिति की विशिष्ट स्थिति (जैसा कि केन्स के सिद्धान्त में) है, तथा जिसमें व्यावसायिक एवं व्यवितगत लेन-देन दोनों सन्निहित हैं। यह दूसरा संशोधन हमें लेन-देन से सम्बद्ध मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन से उपभोग एवं वचत को अप्रभावित छोड़कर मुद्रा एवं निवेश के सम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता प्रदान करता है।

इस संशोधित मान्यताओं के आधार पर हम वचत-निवेश के साम्य की स्थिति को निम्नाँकित रूप में व्यक्त कर सकते हैं:

$$I = S + \triangle M_c - \triangle L_1, \tag{1}$$

जिसमें 1 शुद्ध निवेश है, S नचत है, $\triangle M_I$, लेन-देन की मुद्दा के परिमाण में वृद्धि है, जिसकी पूर्ति वैकिंग-व्यवस्था द्वारा की जाती है तथा $\triangle L_I$ व्यापारी-समुदाय द्वारा माँग की जाने वाली लेन-देन की मुद्रा के परिमाण में वृद्धि है।

समीकरण (I) में लेन-देन के लिए माँगी गई अतिरिक्त मुद्रा से अधिक लेन-देन के लिए अतिरिक्त मुद्रा की पूर्त्त, $\triangle M_1 - L_1$ की मात्रा के बरावर बचत से निवेश के अधिक होने, i > S, की सम्भावना को व्यक्त करता है। I एवं S के बीच विसंगति की यह सम्भावित स्थिति रावर्ट्सन के आज के निवेश-योग्य कोए की माँग के कल की आय में से आज की वचत से असंग्रह। वचानेवाले अपनी बचत से अधिक ऋण देते हैं) की मात्रा के बरावर अधिक होने की स्थिति के अनुरूप है। I

अव हम समीकरण (1) के परिवर्तियों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं:

$$I = b \triangle Y, \tag{2}$$

$$S=sY,$$
 (3)

$$\triangle Mi = mY, \tag{4}$$

$$\triangle Li = \lambda Y. \tag{5}$$

यहां Y शुद्ध राष्ट्रीय आय है, b पूँजी-निपज अनुपात, s वचत-अनुपात, m लेन-देन के लिए अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति तथा आय का अनुपात, और λ लेन-देन के लिए अतिरिक्त माँगीं गई मुद्रा एवं आय का अनुपात है। यहाँ m को मौद्रिक-नीति-प्राचल समक्ता जा सकता है, जिसे ज्यावसायिक समुदाय की परिवर्तनीय आवश्यकः

देखें, डी० एच० रॉवर्टसन, सेविंग एण्ड हेडिंग,' इकॉनामिक जनरल, सितम्बर, 1933 ।

ताओं के अनुरूप तथा व्यापक मीद्रिक उद्देश्यों के अनुसार विकित-व्यवस्था घटा बदा सकती है। जहाँ तक के का सम्बन्ध हैं, इसे किसी दिए हुए राष्ट्रीय व्यय-स्तर (Y के रूप मे व्यक्त) की ध्यान मे रखते हुए व्यावसायिक समुदाय की लेन-देन के लिए कितना अधिक अथवा कम मुदा-धारण करने की इच्छा का अतिनिधित्य करते हुए समक्षा जा सकती है।

(1) से (5) तक समीकरणों की ध्यान में रखते हुए, समीकरण (1) को इस प्रशास से पन लिखा जा सवता है

$$b \triangle Y = sY + mY - \lambda Y = (s + m - \lambda)Y, \tag{6}$$

जिससे मीडिक प्राचलों को अन्तर्गस्त करते हुए विकास को निस्नाकित दर प्राप्त होती है .

$$\frac{\Delta Y}{Y} = -\frac{s + m - \lambda}{b},\tag{7}$$

जो यह व्यक्त करता है कि यदि ७ एवं b को स्थायी रदा जाय तो $m-\lambda$ वृद्धि से विकास की दर में वृद्धि होगी नथा $m-\lambda$ के स्थायी रहने अयदा हास होने पर यह भी त्रमध स्थायी अयदा कम होगी।

निम्म 8 एवं उच्च b बालों अल्य विकसित अयं-व्यवस्था के लिए समीकरण (7) के नीति-सम्बन्धी आशय को समक्ष्मना कोई कठित नहीं है। वयोंकि समीकरण (7) के अनुसार दस प्रकार की अयं-व्यवस्था को लेन-देन के लिए सुद्रा-अनुपात की दी हुई माँग (λ) की नुलना में लेग-देन के लिए सुद्रा-अनुपात की पूर्ति (m) की यदाना होगा अथवा व्यावनायिक समुदाय को लेन-देन के लिए सुद्रा की दी हुई पूर्ति (m) की नुलना में लेन-देन के लिए सुद्रा की माँग (λ) को घटाने के लिए समस्या होगा। इस प्रकार, जैसा कि समीकरण (1) से प्रकट होता है, यदि एक विकासणील अर्थ-व्यवस्था की निवेश के लिए कोप की माँग सदा बचन एवं सव-निर्मित साख के द्वारा पूर्ण हो जाती है, तो इसने सौद्रिक परिमाण मीति के लिए दोन है।

'विवृत' माँडल

अब विदेशी आधिक सम्बन्ध वाली 'विवृत' व्यवस्था समभी जाने वाली अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था की ओर ध्यान देने से, आधिक विकास के लिए मुद्ध विदेशी
उधार के प्रावलीय महस्थ की व्यवन करना सम्भव है। इसके लिए हम सन्तृलित
व्यापार की सहज मान्यता करेंगे, जिससे राष्ट्रों के बीच पूँजी की गति को विगुद्धतः
-स्वत. प्रेरित अथवा गैर-श्रांतपूरक समभा जा सके। यह मान्यता हमें 'पुनर्भुगतान'
की जटिल गौण समस्या के पृथक्षरण में भी सहायता देती है; क्योंकि विदेशी निवेश
की आय एव मुगतान (समुद्ध-पार पूर्व-निवेश पर प्राप्त या दिया गया शुद्ध क्यांज
नाभाश आदि) बाह्य भुगतान सन्तृतन के चाल खाते में सम्मिनित होते हैं।

जहाँ तक उधार लेने वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, 'पुनर्भुं ग-तान' की यह पिछली समस्या विदेशी पूँजी की सहायता से उत्पादन क्षमता वड़ाने की प्रधान समस्या से गौण समभी जाती है। साथ ही, यह भी माना जा सकता है कि अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ स्वतन्त्र रूप से (यानी चालू व्यापार—संतु-लन का विचार किये वग्रैर) वह भी अन्तर्राष्ट्रीय वैंक से विशेषतः, पुनर्निमाण एवं विकासार्थ उधार लेती है।

साम्य की स्थिति में, एक अल्प-विकसित विवृत अर्थ-व्यवस्था का कुल निवेश इसकी कुल बचत के विशेष रूप से वरावर होता है।

$$I_h + L_f S_h = B_f, \tag{9}$$

णहाँ पर I_h शुद्ध घरेलू निवेश, L_I विदेशी उद्यार-दान, S_h घरेलू वचत तथा B_f विदेशी ऋण है। पहले की ही तरह, यहाँ पर भी सभी परिवर्तियों की बास्तविक रूप में दिखलाया गया है। समीकरण (9) का वार्यां पक्ष विवृत अर्थ-व्यवस्था के कुल 'निवेश' एवं दायाँ पक्ष इसकी कुल 'वचत' का प्रतिनिधित्य करता है। यह मान लेना अधिक उचित है कि स्पष्ट कारणों से अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं L_f शून्य, अथवा बहुत कम है; यद्यपि निर्यात आधिक्य वाली कुछ अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में, कम-से-कम समय के लिए अतिपूरक विदेशी उद्यार-दान (हम लोगों की मान्यता के अनुसार जिसे L_f सम्मिलित नहीं किया है) धनात्मक या अधिक भी हो सकता है।

समीकरण (9) से हमें निम्नांकित रूप में घरेलू निवेश प्राप्त होता है:

$$J_h = S_h + B_f - L_f, \tag{10}$$

जो यह वतलाता है कि विदेशी उधारदान से विदेशी ऋण के आधिक्य, B_f — L_f की मात्रा के वरावर से घरेलू निवेश घरेलू वत्तत $I_h > S_h$ से अधिक हो। सकता है।

पुन: हम समीकरण (10) के दोनों पक्षों को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं:

$$I_h = \frac{\triangle Y}{\sigma}. \tag{11}$$

$$S_h = sY_t \tag{12}$$

$$B_f = yY, \tag{13}$$

और

$$L_f = \delta Y, \tag{14}$$

यहाँ व पहले की ही तरह शुद्ध निवेश की औसत एवं सीमान्त उत्पादकता हैं, s घरेलू बचत का अनुपात है, y विदेशों से उद्यार लेने की औसत एवं सीमांत क्षमता

है, तथा 8 विदेशों से उद्यार देने की औमत एव सीमान क्षमता है। यह मान लेना उचित है, कि एक विवृत अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था से सामान्य रुप से निम्न ठ, निम्न ड उच्च भे एव निम्न & रहता है।

(11) से (14) तक के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समीकरण (10) को इस प्रकार से प्न. लिखा जा सकता है:

$$\frac{\triangle Y}{\sigma} = sY + yY - \delta Y = (s+y-\delta) Y, \qquad (15)$$

जिससे हमे अन्तर्राष्ट्रीय मीदिक प्राचल से युवत निपज मे वृद्धि की निम्ता-कित दर प्राप्त होती है:

$$\frac{\wedge Y}{Y} = \sigma (s + \gamma - \delta), \tag{16}$$

जहां पर y एव ह दोनो नीति में हेर-फेर की घर्ठ पर मौद्रिक प्राचल हैं। समी-करण (16), निरम्तर निम्न 5 एव निरन्तर निम्न 5 के रहने पर, एक अल्प-विकसित विद्वत अर्थ-व्यवस्था की दर पर निदेशों से उद्यार लेने की औसत क्षमता (y) में यूढि अथवा निदेशों को उद्यार देने की सीमात क्षमता (ठ) में ह्नास के परिणाम-स्वरूप यूढि की सैद्धान्तिक सम्भावनाओं को प्रस्तावित करता है।

(9) से (16) समीकरण द्वारा चित्रित 'विवृत' माङल 'कम विक्सित देशो' के साधनो एव उत्पादन-क्षमता को विकसित करने एव 'सर्वन जीवन-स्तर श्रम की दशाओं में मुधार के लिए' विश्व वैक के बढते हुए महत्वपूर्ण उधारवान-सम्बन्धी कियाओं पर केंन्स के आशावादी जोर को न्यायोचित ठहराता है। किन्तु, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि यदापि विश्व वैक से उधार लेना सामान्यतः आधिक दृष्टि से अधिक शाद्धित तथा राजनीतिक दृष्टि से कम अनुचित समभा जाता है, तयापि अल्पिवस्तिन अर्थ-व्यवस्थाओं की पूँजी-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूँति के लिए सम्भवतः निजी विदेशी निवेश. अन्तर-राज्य निवेश तथा विदेशी अनुदान की भी आवश्यकता पहेंगी।

पुनर्तिर्माण एव विकासार्थ विश्व वैक पर दितीय वायोग की प्रथम बैठक मे 3 जुलाई 1944 वाला इनका प्रारम्भिक विचार देखें।

शात कारणो से अल्प-विकासत अर्थ-व्यवस्था विदेशी पूँजी के इन अतिरिक्त माधनों पर कम-मे-कम विश्वास करती है। उदाहरण के लिए, एक लेखक ने निजी विदेशी निदेश के महत्त्व को इस आधार पर न्यूनतम बतलाया है कि 'लाभ की प्रवृत्ति,' 'जातीय एव राजनीतिक सम्बन्ध,' एव 'उद्यार देने वाल देशी की मौगो-लिक स्थिति' से अत्यधिक प्रभावित होता है। (देखें डी० भा, फिस्कल पाँलिसी ऐड दि इकानोमिक डिवेलमेट ऑफ अन्डर-डिवेल्प्ड कन्ट्रीज, पूर्व उद्धत) जै०

व्याज, पूँजी एवं विकास

बल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए व्याज की दर का दीर्घकालीन महत्त्व है, जो कि मीद्रिक नीति का एक अन्य मुख्य अस्त्र है—उसकी आधारभूत व्याख्या इन वातों पर निर्मर करती है (क) बाह्य वित्त की प्रधानता (पूर्व अवितरित लाभ के रूप में जमा की गई व्यावसायिक वचत को प्रयोग करने के बजाय वैक्तिंग व्यवस्था अथवा पूँजी वाजार से जधार लेना) और (ख) दीर्घ नियोजन क्षितिज वाले नये टिकाऊ संयंत्रों एवं उपकरणों की तीव्र आवश्यकता, भविष्य में जिनके प्रतिफल को मुदा के रूप में बट्टा किया जा सके। अब यह देखा जाय कि व्याज की दर किस प्रकार से चक्रदार निवेश-विपयक निर्णयों एवं इसके द्वारा आर्थिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं।

हम ब्याज की दर को निम्नाँकित रूप से दिया हुआ मानकर प्रारम्म करते

₹:

$$r = L(pY, \widetilde{M}), \tag{17}$$

जिसमें r मुद्रा एवं ऋण पर दिया गया व्याज है, L माँगी गई मुद्रा की मात्रा है, Y व्यास्तिविक आय, \overline{M} वैकिंग व्यवस्था द्वारा स्वतंत्र रूप से पूर्ति की गई मुद्रा की मात्रा और p निपज का असित मूल्य है (अतएव pY मौद्रिक राष्ट्रीय आय है)। समीकरण (17) वास्तव में केन्स का खास तरलता अधिमान फलन है।

समीकरण (17) द्वारा दी गई व्याज की दर शुद्ध लाभ की दर की गणना में निम्नांकित के माध्यम से प्रवेश करती है:

$$\pi = \frac{pY - wN}{qK} - \mathbf{r},\tag{18}$$

जिसमें Y शुद्ध राष्ट्रीय निपज है, N श्रम-निवेश है, K पूँजीवल, π शुद्ध लाभ की दर है, p राष्ट्रीय निपज की प्रति इकाई कीमत, wश्रम-निवेश की प्रति इकाई कीमत अथवा मौद्रिक मजदूरी की दर है, \mathbf{v} यूं \mathbf{q} पूंजी-निवेश की प्रति इकाई कीमत है, \mathbf{t} समीकरण (18) यह

धतलाता है कि मुद्रा एव ऋण पर दी गई ब्याज की दर जितनी ही निम्न होगी, लाभ की दर उतनी ही ऊँची होगी। यह मान लिया जाता है कि चेतनशील उत्पादक, निम्ना-कित उत्पन्ति-फलन की शर्त पर समीकरण (18) द्वारा दी गई शुद्ध लाभ की दर को अधिकतम बनाने है:

$$\frac{Y}{N} = f\left(\frac{K}{N}\right),\tag{19}$$

यहाँ पहले की ही तरह यह मान लिया जाना है कि चक्रदार की मात्रा को व्यक्त करने वाले पूँजी की गहनता के गुणक (K/N) में वृद्धि से श्रम की उत्पादकता (Y/N) में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। p=Y/N एवं 0 = K/N मानकर, हम इस मान्यता को निम्नाकित रूप में व्यक्त कर सकते हैं

$$\frac{dp}{d\theta} > 1,$$
 (20)

वर्तमान में ही हम जिस मान्यता को महस्वपूर्ण पायेंगे।

केन्स के पूँजी के सिद्धात के अनुरूप ही कुल लाभ की दर, यानी गुद्ध लाभ की मुद्ध जमा ब्याज की दर को, उचित बट्टे की दर के रूप मे विचार करना है, जो पूँजी के भवित्य के प्रतिफल के वर्तमान बट्टाकृत मृहय को उस पूँजी के निर्मित करने अथवा प्राप्त करने वाले वर्तमान ब्यय के बराबर बनाता है.

$$qK = \frac{pY - wN}{\pi + \epsilon},\tag{21}$$

जिसका दाहिना पक्ष नये पूँजीगत उपकरणो के, जैसा कि केन्स ने कहा था, प्रत्याशित प्राप्ति के वर्तमान बट्टाक्टत मूल्य का प्रतिनिधिस्य करता है सथा जिसका बायाँ पक्ष, जिसे उसने उस उपकरण का, 'प्रतिस्थापन व्यय' कहा था, का प्रतिनिधिस्य करता है। यदि हम् K को टिकाऊ मानने है और pY-wN के सन्दर्भ में q_k का अवकलन करते है, तो हम लोगो की बट्टा-दर n+r केन्स की 'पूँजी की सीमांत क्षमता' का सकेतक ही जाता है। इस बात की ध्यान मे रखना है कि हम लोगो की प्रत्याशित प्राप्ति अपेक्षित शुद्ध मौद्रिक आय (pY) घटाव अपेक्षित मौद्रिक मजदूरी (wN) का प्रतिफलन है, जबिक हम लोगो की बट्टा-दर मे दो तत्वो का समावेश है—शुद्ध लाभ की दर (n), जो जोखिम एवं अनिश्चिता की मात्रा को मापता है तथा व्याज की दर (r), जो सरलता अधिमान की मात्रा को मापता है।

समीकरण (21) से हमें पूँजी की आय (पूँजी-निवेश के व्यक्तिगत उपभोक्ता के दृष्टिकीण से व्यथ) प्राप्त होती है जो शुद्ध मौद्रिक राष्ट्रीय आय, घटाव मजदूरी-सम्बन्धी आय (श्रम-निवेश के व्यक्तिगत उपभोक्ता के दृष्टिकोण से व्यय) के वरा-वर होती है:

$$(\alpha + r) qk = pY - wN$$
 (22)

जिसके दोनों पक्षों को N से भाग देने तथा नये क्रम रखने से हमें निम्नां-कित प्राप्त होता है:

$$\frac{K}{N} = \theta = \frac{\frac{Y}{P_N} - w}{(\eta + r)q} = \frac{P_P - w}{(\eta + r)q}$$
 (23)

समीकरण (23) यह वतलाता है कि पूँजी की गहनता का गुणक 0 पूँजी की प्रति इकाई शुद्ध प्रत्याशित प्राप्ति Pp-w से प्रत्यक्ष-रूप में तथा पूँजी की प्रति इकाई व्यय (II+r)q से उलटी तरह से परिवर्तित होता है। यहाँ प्रासंगिक वात यह है कि यदि P, p, w एवं q स्थायी हों, तो व्याज की दर r में ह्रास के परिणामस्वरूप p में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि, सम्बद्ध प्रणाली में r ही एक ऐसा है, जिसे मौद्रिक अधिकारी प्रत्यक्ष-रूप से प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी, जैसा कि जोन रॉबिन्सन ने वतलाया है, उत्पादन की किसी प्रक्रिया में श्रम की प्रति इकाई प्रयुक्त पूँजी की मात्रा पर निम्न व्याज की दर का उत्तेजक प्रभाव भी निपज की प्रति इकाई मूल्य में ह्रास, श्रम की उत्पादकता में ह्रास या मजदूरी की दर में वृद्धि (समी p के अंशा के रूप में आते हैं) तथा शुद्ध लाभ की दर में वृद्धि π^1 या पूँजी-निवेश की प्रति इकाई कीमत p (दोनों p के साथ-साथ p के प्रत्येक रूप में आते हैं) से विस्थित हो सकता है। फिर भी, हमें इस सम्भावना को अवस्थ ही स्वीकार करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में स्वतन्त्र परिवर्तन विस्थित-मूलक प्रवृत्ति के हो सकते हैं।

20-वीं मान्यता को ध्यान में रखते हुए, स्थायी वचत-अनुपात (s) वाली अर्थ-ध्यवस्था के विकास की दर ($\Delta Y/Y$) के लिए 'सस्ती मुद्रा'-नीति के अनुकूल आशय को, यदि ह्य उपर्युंक्त विस्थिति परिवर्तनों से प्रितितोलित नहीं हो जाता है, पूँजी की गहनता के गुणक को पूँजी-निपज अनुपात से सम्बद्ध करते हुए, बतलाना सम्भव है:

$$\frac{K}{Y} = b = \frac{K/N}{Y/N} = \frac{pp - w/(\pi + r) q}{P}, \tag{24}$$

और इसलिए

$$\frac{\triangle Y}{Y} = \frac{s}{b} = \frac{s}{[pp - w/(\pi + r)q]/p}$$
(25)

देखें, इनकी पुस्तक 'िंद रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट्सेट्रा,' से विशेषतः पृ० 65 ।

^{2.} यह विशेष रूप से उन उत्पादकों के लिए सत्य है, जिन्हें दूसरों से पूंजीगत वस्तुओं का क्रय करना पड़ता है; क्योंकि श्रुद्ध लाभ की दर में वृद्धि से पूंजीगत वस्तुओं के क्रय-मूल्य (q) में मजदूरी की दर (w) की अपेक्षा वृद्धि हो जाती है, जिससे कि उत्पादकों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी के वदले श्रम के प्रतिस्थापन के लिए प्रेरणा मिलती है।

समीकरण (25) यह वतलाता है कि अन्य वातों के समान रहने पर निम्न क्याज की दर, पूँजी की गहनता के मुणक (चकदार) पर यदते हुए प्रभाव तथा श्रम की उत्पादकता पर इम बादवाल के प्रभाव के द्वारा श्रम-निपज अनुपात b को क्षम कर देगा और इसलिए जब बचत-अनुपात s म्यायी रहता है, तक विकास की दर ($\Delta Y/Y$) को ऐसे ही बढा देगा। ऐसे अन्य प्राचलीय परिवर्तनों तथा विम्यितमूलक प्रकृति वाले स्वतन्य देवनालाँजिकल परिवर्तनं, जिनका उत्लेख करार विया जा चुका है, को छोडकर, विकास कार्यभ्रम तैयार करने के अस्य के रूप में 'सस्ती मुद्रा'-नीति के लिए, विशेषत, इन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से जो स्थायी पूँजीगत उपकरणों के भविष्य से अपेक्षित लाभदायक जीवन के ऊगर लाम से परम वृद्धि के निद्धान्त का अनुकरण करती है, के छुछ क्षेत्र हैं, ऐसा जान पडता है।

स्फीति एव विकास*

तीसा में कुछ अर्थणाहित्रयों ने केन्स के पूर्ण रोजगार के मिद्वान्त को स्फीति-विरोधी कहकर इसका विरोध किया था। आज भी हम देखते हैं कि कुछ अर्थ-शास्त्री, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप में, स्फीति के भय ने विकास-सम्बन्धी नीति का विरोध करते हैं। 'स्फीति-जनक' विक्त के द्वारा पूर्ण रोजगार एवं आयिक विकास दोनों के विरोध से यह सन्देह होता है कि इसमें निहित आधिक तर्क-नियमनवादियों, समाजवादियों, साम्यवादियों, राष्ट्रवादियों, सरक्षणवादियों, नीकरशाही के समर्थनों तथा इन सभी के सम्बन्धियों पर एक हत्का, छिपा हुआ सैद्वातिक आत्रमण है। इन

ग्रैर-बाजारवाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में भी चन्नदार निवेश के सम्यन्ध में, निर्णय में, सभवत व्यय के ऊपर अपेक्षित प्रतिफल की अधिवाता को मापने के लिए कुछ बट्टा दरें सन्निहित रहती है।

^{*}यह परिच्छंद प्रारम्भ में 'ए नोट ऑन इन्प्लेशन एड डिवेलपमेंट' नामक शीर्पक के अन्तर्गत रिरॉन किर्जमकु (इक्तॉनामिक स्टडीज क्वाटर्ली), जापान, जून, ं 1957 में प्रकाशित हुआ था।

^{2.} यह उद्धरण एफं० मैधल्य के 'दि फाइनान्स फाँर डिवेल्पमेट इन पूअर कन्द्रीज : फाँरेन कैपिटल एव डोमेस्टिक इन्फ्लेलन' रिरॉन किजैयकु अप्रैल, 1956 से हैं। नियमनवादियों, ममाजवादियों एव अन्यां को स्फीति के समर्थको की श्रेणी में शामिल करने की वैधता पर आपत्ति उठाई जा सक्ती है। मैं स्वय केन्स के इस विचार से महमत होने की इच्छा करता हूँ कि सामूहिक वेरोजगारी (और अल्प-रोजगारी) के जातिकारी खतरे प्रजातत्रात्मक आस्थाओं के लिए स्फीनि के सहगामी नियत्रणों की अपेक्षा अपरिमित एप में अधिक हानिकारक हैं। जै०

वात का योड़ा भय है कि स्फीति-विरोधी अड़ंगा लगानेवाले अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को, आधिक विकास के ऊपर, मूल्य-स्थायित्व को प्राथमिकता देने के लिए, भुजावा देंगे। किन्तु, यहाँ निर्णायक सैद्धान्तिक प्रथन यह है कि क्या स्फीति के हारा विकास, जैसा कि अल्प-विकसित देशों के अर्थशास्त्री आशापूर्ण ढंग से दावा करते हैं, पूँजी-संचय में सहायक होता है, अथवा, जैसा कि विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अर्थ-शास्त्री भयपूर्ण तर्क देते हैं, इसके प्रतिकृत होता है। इस टिप्पणी का उद्देश्य इसी विवादास्पद प्रथन पर कुछ प्रकाश देना है।

सच्ची स्फीति के प्रमाण

प्रारम्भ में, जिसे केन्स ने विकसित अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्ध तथा अल्प-विक-सित अर्थ-व्यवस्था से सम्बद्ध 'सच्ची स्फीति' कहा है, के बीच विभेद करना महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि सर्व-नात है, बृद्धिशील समर्थ माँग की तुलना में पूर्ण रोजगार निपज की लोच का अभाव ही, केन्स के अर्थ में, सच्ची स्फीति के अभाव का कार्य करती है, यद्यपि केन्स ने पूर्ण रोजगार-स्तर के पूर्व ही असामान्य कठिनाइयों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कुछ स्फीति की सम्भावनाओं की चर्चा की है: फिर भी,

ए० शुम्पीटर ने भी अपनी मृत्यु के पूर्व अन्तिम व्याख्यान में नाटकीय ढंग से इस पर वहत अधिक जोर दिया था।

केत्स के कथन की तुलना कीलिए: 'अतएव जविक उपमोग की क्षमता एवं निवेश की प्रेरणा की एक-दूसरे के साथ समायोजित करने के कार्य में सिन्निहित सरकार के कार्यों में वृद्धि उन्नीसवीं शतान्दी के किसी लोक-प्रचारक अथवा अमेरिका के किसी समकालीन वित्तदाता को व्यिष्टिवाद का तीच्च अतिक्रमण जान पड़ेगा । किन्तु, ठीक इसके विपरीत, वर्तमान आर्थिक ढाँचे को सम्पूर्ण विनाश से वचाने तथा व्यक्तिगत प्रेरणा के सफल कार्यान्वयन की शर्त के रूप में एकमात्र व्यावहारिक साधन समफ कर में इसका समर्थन करता हूँ।' (जनरल वियरी, पृ० 380)। जि० ए० शूम्पीटर का कथन: 'चिरस्थायी स्फीति-जनक दवाव नौकरणाही द्वारा निजी कार्यक्रम की प्रथा पर अन्तिम रूप से विजय प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता है। इसके परिणामस्त्ररूप उत्पन्न संघर्ष एवं गत्यवरोध के लिए निजी उपक्रम को जत्तरदायी ठहराया जा सकता है तथा उन्हें और अधिक नियंत्रण एवं नियमन के पक्ष में तर्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। (देखें, इनका मरणोपरान्त प्रकाणित लेख 'दि मार्च इनटू सोगलिएम', अमेरिकन इकानामिक रिच्यू, मई, 1950।

 जैनरल थियरो, पृ ≥ 296-302, निम्नौकित पर विशेष रूप से ध्यान दें: 'यदि हम स्वयं उपकरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए अधिक मध्यान्तर की मान्यता करते है, तो अन्ततः पूर्ति की लोच निश्चय ही वहुत अधिक होगी। इस जहां तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, सच्ची स्फीति का उचित प्रमाण पूर्ण क्षमता निषज की लोच के अभाव मे पाया जाता है। क्योंकि, इन अर्थ-व्यवस्थाओं मे, धम का नहीं, वरन वास्तविक पूँजी का अभाव ही 'मौद्रिक' प्रसार की तलना में 'वास्तविक' प्रसार के गार्ग में अन्तिम कठिनाई है।

दीर्घकालिक विश्लेषण के रूप में (उदाहरण के लिए, पाँच वर्षों के कार्यक्रम सैयार करने की अल्पकालीन अवधि से अधिक) इसका तालप्य यह है कि इस बात का पता लगाना अनिवायं है कि क्या दीयंकालिक स्कीति के लिए जो तस्व उत्तरदायी हैं, वे ही मुख्य-स्थायित्व के भी तत्त्वो का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा नहीं। अधिक स्पष्ट होने के लिए, इस बात की जाँच करनी चाहिए कि क्या तथाकथित स्फीति-जनक विस्त से प्राप्त निवेश का दीर्घकाल में आय-उत्पन्त करने वाले प्रभाव की तुलना मे क्षमता-बढानेवाला प्रभाव अधिक होगा, अथवा नहीं। यहाँ पर डोमर के निवेश की दूहरी प्रकृति प्रासगिक है; क्योंकि वह इस सभावना की और सकेत करता है कि 🛆 1/1 की दर से विनियोग करनेवाली कोई अर्थ व्यवस्या, यद्यपि गुणक प्रभाव के माध्यम से मौद्रिक प्रसार का अनुभव करती है, फिर भी 'सिंगमा प्रभाव' के माध्यम से अधिक वास्तविक प्रसारका अनुभव कर सकती है। डोमर इसी सभावना से इस तथ्य को कि "शान्ति काल मे..... स्फीति इतनी विरल होती है " सम्बद्ध करता है। कई-एक कारणो से हम किसी अल्प-विक-सित अर्थ-व्यवस्था के लिए भी इस प्रकार की सभावना का परित्याग नहीं कर सकते। अब हम इसके कुछ स्वीकार कारणो की एक रूपरेक्षा तैयार करें कि क्यों निवेश मे वृद्धि की दी हुई दर उत्पादन-क्षमता मे इतना पर्याप्त विस्तार कर मकती है, जिसमें कि दीर्घकालिक स्फीति की अनिवार्यता को अल्प करने वाले तज्जनित स्फीति-मूलक प्रभावको यह निष्फल कर सके।

1. यदि कोई अस्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था, जो शुद्ध निवेश में △1/1 की दर से वृद्धि का आयोजन करती है, अपने निवेश कार्यक्रम की मुख्यतः टिकाऊ उत्पादक उपकरणों के निर्माण की ओर संयोजित करती है, तो दीर्घकाल मे यह 'सिमगा प्रभाव'

प्रकार दूर-दूर तक विस्तृत बेरोजगारी के अन्तर्गत उत्पन्न समर्थ माँग मे साधारण परिवर्तन से मूल्य-स्तर में बहुत कम वृद्धि होकर मुख्यतः रोजगार मे वृद्धि होती है, जबिक इसमें बड़ा परिवर्तन, जो अप्रत्याशित होने के कारण कुछ अस्थायी कठिनाइमो को उत्पन्न करता है, बाद की अपेक्षा पहले रोजगार के बदले मुख्यो में ही वृद्धि उत्पन्न करता है। पूर्व-उद्धृत पृ० 300-301)। इ०डी० डोमर, ''एवसपैनशन एण्ड एम्पलायमेंट'' अमेरिकन इकॉनामिक रिष्यू.

मार्च, 1947।

को पूर्ण अवसर प्रदान करेगी और इसलिए सिन्तिहत, 'गुणक प्रभाव' को,यि पूर्ण रूप से नहीं, तो कुछ मात्रा में निष्फल बना देगी। व्यवहार में इसका यह अर्थ हो सकता है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था पिरामिड-निर्माण अथवा अस्त्रीकरण की तरह की निवेश की योजनाओं में जान-बूक्तर विनियोग नहीं करती है। ये योजनाएँ उत्पादत-समता में वृद्धि के वगैर ही माँग का सर्जन करती है। यहाँ पर हमारा संवच्य निर्पक्ष शुद्ध निवेश की तुलना में शुद्ध निवेश में कुछ वृद्धि (Δ 1) के अवयव गुण्यों की उत्पादकता से है। अतएव, एक मिश्रित विवृत अर्थ-व्यवस्था में Δ 1/1 का Δ 1p/1p, Δ 1g/1g और Δ F/F में अलग-अलग करना पड़ेगा। यहाँ 1P शुद्ध निजी निवेश को वतलाता है, 1g शुद्ध राजकीय निवेश को वतलाता हैं और F शुद्ध विदेशी संतुलन को बतलाता है। यदि कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था दीर्घकालिक स्फीति के भय का अल्पोकरण चाहती है, तो उसे शुद्ध निवेश में वृद्धि की दर के उन विशेष अवयवों पर अधिक जोर देना होगा, जिसकी उत्पादकता की संभावना सर्वाधिक हो। यह मान लिया जा सकता है कि शुद्ध निवेश में वृद्धि की राजकीय दर (Δ 1g/1g) को इस संबंध में जान-बूक्तर अत्यंत तत्परता के साथ चुना जा सकता है।

2. चूँकि पूँजी-संचय एवं तकनीकी प्रगति दोनों सहगामी होते हैं, अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि शुद्ध निवेश में वृद्धि की दर (\triangle 1/1) जितनी ही ऊँची होगी, मुद्ध निवेश के किसी भी स्तर के लिए, निवेश की उत्पादकता में वृद्धि (डोमर की अंकन-पद्धति में σ) की संभावना उतनी ही अधिक होगी । यदि ऐसा है, तो σ 1 की दर से बढ़ती हुई उत्पादन-क्षमता अनुमानक Δ 1 α दर से बढ़ती हुई समर्थ माँग से अधिक हो सकती है (जहाँ डोमर की अंकन-पढ़ित में उ बचत की सीमांत क्षमता को व्यक्त करता है)। इसी आशय का जोन रॉविन्सन का यह सुफाव है कि जितना ही अधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उद्योग के यंत्र-निर्माण करनेवाले क्षेत्र में उत्पादन के तरीकों में सुधार के अवसर उतने ही अधिक होते हैं। जैसा कि जोन रॉविन्सन का संकेत है पूँजी के गुण में सुधार पूँजी की मात्रा का परिणाम हो सकता है। यदि यह सत्य है, तो तकनीकी प्राचलों व के मूल्य में वृद्धि का एक तरीका पूँजी की मात्रा में वृद्धि है, या वर्तमान संदर्भ में उचित मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों के द्वारा riangle 1/1 में वृद्धि करना है । विचार करने की यही पद्धति ही हायेल्मो के विचार के पीछे कार्य करती हुई जान पड़ती है :..... "साधारणतया तकनीकी प्राचल रासायनिक सूत्रों एवं यंत्रशास्त्र के नियमों की अपेक्षा मानवीय चुनाव एवं मानवीय आचरण से अधिक सम्बद्ध हैं। साथ ही, यह मान लेना

देखें इनका "नोट्स ऑन दि इकॉनामिक्स ऑफ टेकनिकल प्रोग्रेस", द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट्सेट्रा, मेकमिलन, लंदन, 1952, पृ० 63 ।

देखें इनकी पुस्तक "ए स्टडी इन दि थियरी ऑफ इकॉनामिक इवोल्यूबन, नॉर्थ हालैंड पल्लिशिंग कम्पनी, अमस्टरडम, 1954, पृ० 49 ।

अधिक सुरक्षित होगा कि निजी उपक्रम की प्रधानता-वाली अर्थ-व्यवस्थाओं में विस्फीति-जनक मरी की अपेक्षा स्फीति-जनक तेजी, नवीन किया के लिए अधिक सहायक होती है। इस संबंध में, जे०ए० गुम्पीटर की तरह कोई भी व्यक्ति उत्पादकता को अधिकाधिक करने अथवा लागत के अल्पीकरण के उद्देश्य से नवीन किया को प्रोत्साहित करने अथवा वित्त-प्रदान में सरकार के बढ़ते हुए महत्त्व की उपेक्षा नहीं कर सकता। (उदाहरण के लिए, प्रमाणस्वहप अमेरिका के विश्वविद्यालयों में सरकारी अनुदान के अतर्गत 'एक घातीय कार्यक्रम' से सबिधत अनुसधान के कार्यों को देखें।)

3. इस प्रकार, यदि नियेश की उत्पादकता (c) यद जाती है, तो सभव है कि संपत्ति से प्राप्त आय (विशेषतः मुनाफा एव लाभाग) से बचाने की सीमात धमता एव इसके साथ ही वचने की सपूर्ण सीमात-धमता (a) मे भी वृद्धि हो जाय। यदि ऐसा हो, तो अतिरिक्तः मुद्ध निवेश के लिए गुणक प्रभाव मे ह्यास होगा, जिससे कि ज 1 की दर से बढनेवाली दी हुई उत्पादन-क्षमता की सुलना मे समर्थ माँग में △1/० की निम्न दर से वृद्धि हो सकेगी। ० वृद्धि के इस गैर-स्फीतिक सघटन के अतिरिक्त बचत की उच्च ओसत क्षमता की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, जिसका उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए लाभदायक प्रभाव होता है। इसके बदले, यदि बचत की सीमात-क्षमता (क) में वृद्धि स्वतंत्र मितव्यय-अभियान के परिणाम-स्वरूप होती है, तो इसका दीर्घकालीन प्रतिरूप (बचत की औसत क्षमता) मे वृद्धि हो मकती है, जो उत्पादन-क्षमता के लिए सभवतः लाभदायक होती है। उन-अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में जिनमें उपभोग का स्तर निम्न होता है, △1/1 की दर से बढता हुआ साख द्वारा व्यवस्थित शुद्ध निवेश, वैयक्तिक आग्र पर अपने वृद्धिशील अभावों के द्वारा, उपभोक्ता इकाइयों में बचत की आदत की प्रारंभ करने का एक-मात्र व्यवहारिक तरीका है। यदि बास्तविक निवेश में वृद्धि की धनात्मक दर की प्रीत्साहित करने के उद्देश्य से, ऋण-पना अथवा स्कधो के रूप में निवेश (वित्तीय) की व्यवस्था सी वर्षों से अधिक तक कार्य करती है, जिससे कि बचाना तथा विनियोग करना एक वडे वर्ग का हर्पजनक कार्य हो जाता है, तो जैसा कि केन्स ने कहा है'-आधनिक अल्प-विकसित, अर्थ-व्यवस्था, बचत की आदत डालने के प्रारंभिक उपाय के रूप में △1/1 की दरसे बुद्धि पर विचार कर सकती है।

इन कारणो से बैंक साख अथवा राजकीय घाटे के द्वारा स्थायी धनात्मक दर $\Delta 1/1$ से विनियोग करनेवाली अर्थ-व्यवस्था में 'सच्ची स्फीति' की टाला जा सकता है। विवेश के उत्पादकता-प्रभाव की उनेक्षा अथवा न्यून-आकलन करने पर ही मौद्रिक

देखे-जे॰एम० केन्स, एसेज इन परस्एशन, प० 84 ।

राष्ट्रीय आय के आचरण पर इसके गुणक प्रभाव से कोई अत्यधिक भयभीत हो. सकता है, डोमर के निवेश की दुहरी प्रकृति इस वात के अनुस्मारक का कार्य करती है कि निवेश के केवल एक पक्ष आय-उत्पादक पहलू पर विचार कर तथा इसके क्षमता-वर्द्धक पहलू की उपेक्षा कर सामान्य मृत्य के अस्थायित्व को कभी वढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए। विश्लेषण के इस अंश को समान्य करने के पूर्व इस वात पर ध्यान देना रुचिकर है कि समर्थ माँग की अपर्याध्तवाली विकसित अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालिक विकास एवं मूल्य-स्थायित्व के लिए आनन्ददायक शक्ति के रूप में माना जाता है।

पूँजी की वृद्धि पर स्फीति का विशिष्ट प्रभाव

हम जन कारणों को सिद्ध कर चुके हैं, जिनके परिणामस्वरूप किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सच्ची स्फीति घटित अयवा वनी नहीं रह सकती है। फिर भी, तक के दृष्टिकोण से, हम यह मान लेंगे कि स्थायी धनात्मक वर $\Delta 1/1$ पर साख से प्राप्त नियेश से कुछ स्फीति उत्पन्न होनी है। अब प्रश्न यह है कि पूँजी की चृद्धि पर स्फीति का संभावित प्रभाव क्या होता है। यह निर्णायक प्रश्न है, क्यों कि औद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्योग्वित करने में पूँजी की वृद्धि कुंजी समभी जाती है। इस प्रश्न का जवाव कई तरीकों से दिया जा सकता है।

1. कोई भी व्यक्ति इस वात से शीघ्र सहमत हो सकता है कि अति-स्फीति की चरम
स्थिति निजी मितव्यय के विरुद्ध काम करती है। केन्स ने भी इस संबन्ध में चेतावनी दी थी
कि इस प्रकार की स्फीति के अनुभव से बचाने एवं विनियोग करने के आचरण के सम्बन्ध
में समाज की मनोवृत्ति में निश्चित रूप से संशोधन होना आवश्यक है। दे इस प्रकार की
अति-स्फीति के अतिरिक्त भी जहाँ तक बचाने एवं विनियोग करने के आचरण पर
स्फीति के संघट्टन का सम्बन्ध है, दो वातों की चर्चा अनियार्य है। प्रथमतः, हमारे
समक्ष यह टिप्पणी है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि उस देश में, जहाँ मौदिक
रूप में व्यक्त परिसम्पत्ति-ऋण-पत्र, वीमा-पॉलिसी और वचत-जमा का परिमाण
अपेकाकृत कम है, वहाँ स्फीति का प्रभाव कम गम्भीर होता है। वास्तव में, यह बात
अधिकांश अवप्रवित्वित अर्थ-व्यवस्थाओं, जिनमें मध्यम वर्ष के वचाने वालों की
संख्या अपर्यान्त होती है, में लागू होती है। इसरा और अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है

^{1.} परसुएशन, पृ० १1।

देखें एच० सी० व्यक्तिच का 'मनी, ट्रेड एण्ड इकॉनामिक ग्रोथ' (जै० एच० विलियम के उपलक्ष्य में) 'अंडर-डिबेल्गड कन्ट्रीज एण्ड दि इंटरनेशनल मानिट्री मेकनिज्म', मैकमिलन, न्यूयार्क, 1951 ।

देखें एस० कुजनेट्स, 'इकॉनामिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्नेलिटि, अमेरिकन इकॉनामिक रिच्यु, मार्च, 1955 ।

कि ऋण एवं इनिवटी वित्त, बाह्य एवं आतरिक वित्त, तथा तिजी एवं सार्वजितिक बचतों के सापेक्षिक महत्त्व के सम्बन्ध में ठोस सूचना अथवा प्रक्षेपण होना चाहिए। क्योंकि, स्फीति का इनिवटी-लामांश, निगम एवं व्यापार के साम तथा कर से प्राप्त राजकीय आय पर अनुकूल प्रभाव पडता है। विकासात्मक वित्त की समग्र योजना में इनिवटी-पूंजी, अवितरित लाग तथा वजट की बचतें इतना अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती है कि निजी बचत पर स्फीति के हानिकारक प्रभाव के सम्बन्ध में सभी आभकाएँ व्ययं हो जाएँ।

शाधारण प्राय. यह तर्क दिया जाता है कि स्फाति वास्तविक सम्पत्ति, स्काधों आभूषण एव स्थापी विदेशी मदाओ जैसे स्फीति-जनक बाड़ी मे अप-सचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। यह दी हुई बचत की प्रकृति को अनुचित रूप मे महत्त्व देना है, जबिक सिनिहित बास्तविक प्रश्न का सम्बन्ध बचत के कुल आकार से है। जहाँ तक दी हुई बचत के विनिधान का प्रश्न है, इसकी अधिक उपयुक्त आलीचना दी हुई बचत के साभदायक, किन्तु दीर्घकालीन दृष्टिकोण से अनुत्पादक कार्यक्रमों में समान के खतरे को बतलाना होगा। किन्तु, जैसा कुछ लेखक सोचते हैं, यह मुनाफा-स्फीति नहीं, बरन् स्वयं लाभ की व्यवस्था है, जो दी हुई बचत के अनुचित विनिधान के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। इस प्रकार, ब्रिटेन के मनीरंजन (अदाहरण के लिए, कुल का रेस-पय) तथा जापान के पाचिनको (पिनबाल) को युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण के युग में दूर्लभ पूँजी के अनुचित उपयोग के उदाहरण के रूप में दिया जाता है। यह सब केन्स के इस तर्क कि 'राज्य, जो दीर्घकालीन विचारो तथा सामान्य सामा-जिक लाभ के आधार पर प्रीजीगत मालों की सीमान्त क्षमता (वर्त्तमान सन्दर्भ में इसे जस्पादकता सम्पर्क) का पता लगाने की स्थिति में है, निवेश की व्यवस्था में सदा अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करे, के पक्ष को प्रवल बनाता है। यहाँ एक मुख्य वात पर जोर देना है कि जहाँ एक पूँजी-विपन्न अर्थ-व्यवस्था को सीमित बचत के उत्पादक विनिधान पर पर्याप्त ध्यान देना माहिए, वहाँ इसे वचत के आकार को और अधिक बढाने की आवश्यक समस्या पर समधिक ध्यान देना चाहिए। वैयक्तिक सपत्ति-धारको के द्वारा आत्म-रक्षा के लिए स्फीति-जनक बाड़ों मे दी हुई बातो के इस प्रकार के अप-सरण का कोई वहत गम्भीर परिणाम नही होगा।

वजट की बचतों के जत्पादक महत्त्व के लिए देखें मेरा योथ मॉडल्स एवं फिस्कल पॉलिसी पैरामीटसं', फाइनान्स पब्लिक (नीदर लेंड्स) नं • 2/1956 ।

श्रीत क्यारी, पृ० 164 । इसके अतिरिक्त यदि और जब कभी बचत की निजी समता-पूँजी में अपेक्षित बृद्धि के लिए अपर्याप्त सिद्ध होती है, तो कैन्स राज्य द्वारा 'सामुदायिक बचत' का भार ग्रहण करने की वाछनीयता पर विचार करते है। (देखें, पूर्व उद्घृत, पृ० 376)।

3. इसका एक अन्य सम्भावित जवाव यह भी है कि स्थायी आय वाले वर्ग के विरुद्ध एवं अस्थिर आय वाले वर्ग के पक्ष में वास्तविक आय के स्फीति-प्रेरित पुनर्वितरण से अस्थिर आय वाले वर्ग की वचत की आदतों में होनेवाली कमी से अधिक वृद्धि होगी । इसका तात्पर्य यह है कि स्फीति-प्रेरित पूर्नावतरण के परिणाम-स्वरूप अस्यिर आय से वचाने की सीमान्त-क्षमता स्थिर आय से वचाने की सीमान्त-क्षमता से अधिक हो जाती है। इस प्रकार, बचाने की अबकल सीमान्त-क्षमता के 'दिया हुआ होने पर, यह स्गमतापूर्वक दिखलाया जा सकता है कि वास्तविक आय के प्रत्येक स्फीति-प्रेरित पुनवितरण से संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए वचाने की शीसत क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार, यदि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए बचाने की औसत क्षमता में वृद्धि हो जाती है, तो प्रकल्पना यह है कि चाहे हम हेरोड के विकास मॉडल का अनुकरण करे अथवा डोमर के विकास मॉडल का , उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दर में वृद्धि होगी। किन-किन आय-वर्गों को क्रमशः अस्थिर श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाय तथा किनको स्थिर श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाय, इस सम्बन्ध में विवाद की गुँजाइश है। किन्तु, यह मान लेना अधिक सुरक्षित है कि मुनाफ़ा प्राप्त करने वाले तथा लाभांश मिलने वाले पहली श्रेणी के अन्तर्गत के महत्त्वपूर्ण वर्ग हैं तथा व्याज या/और लगान प्राप्त करने वाले दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत के प्रधान वर्ग हैं। मजदूरी से प्राप्त आय को अस्थिर माना जाय अथवा स्थिर, यह किसी ठोस अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत संगठित श्रम के विषय में सौदा करने की सापेक्ष शवित पर निर्भर करता है। यदि स्फीति, जैसा कि केन्स ने कहा है, लगान-उपजीवी की सुख मृत्यु को त्वरायित करता है, तो यह साहसी एवं इसी प्रकार के अन्य वर्गों के उत्साह के लिए और भी ठीक है। दूसरे शब्दों में, यदि स्फीति का प्रभाव वास्तविक आय को व्याज प्राप्त करनेवालों से मुनाफ़ा प्राप्त करने वालों के पक्ष में विवर्तन करना है, तो स्कन्धों एवं ऋण-पत्रों में वित्तीय निवेश की तूलना में प्जीगत उपकरणों में वास्तविक निवेश अधिक होगा। यह प्जी-संचय एवं आधिक विकास के लिए दीर्घकालीन लाभ की चीज होगी।

4. इसका एक दूसरा उत्तर इस संभावना में पाया जा सकता है कि उपभोग

देखें आर० एफ० हेरोड, टुवार्ड्स ए डायनिमक इकॉनामिक्स, मैकिमलन, लंदन, 1948, डोमर, पूर्व उद्घृत ।

^{2.} जेनरल थियरी, पृ० 376। केन्स निम्नांकित प्रकार के निवेश-माँग समीकरण $1 = f\left(y, p, r\right)$ तथा मुनाफ़ा को अधिकतम बनाने की स्थिति $e\left(1\right) = r$ मानते हैं, जिनमें 1 वास्तविक निवेश है, y अतिरिक्त पुँजी-सम्पत्ति का प्रतिफल हैं, p पुनस्थापिन व्यय है तथा y व्याज की दर, e पूँजी की सीमान्त क्षमता $\left(e = Y \middle| p\right)$ है।

करने वाले लोग दीर्धकालिक स्फीनि की प्रतिकिया के परिणामस्वरूप, भविष्य मे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में और वृद्धि की प्रत्याशा से वर्तमान समय में अधिक ब्यय करने की अल्पकालीन क्षमता को रोक कर, अपने उपभोग-व्यय को धीरे-धीरे निम्न स्तर पर समायोजित करेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि ए॰ सी॰ पीगू की तरह हम यह मान लेते है कि वचत-मुख्य तल से प्रत्यक्ष रूप में और इसलिए वास्त-विक नकद जमा के आकार (उदाहरण के लिए चचत खाते, सरकारी प्रतिमृतियों एव अन्य तरल साधना - सक्षेप में उपभोक्ताओं में सचय की प्रवृत्ति को प्रोत्माहित करने वाले) से प्रतिलोमत सम्बद्ध है, जो बढ़ने हुए मूल्यो का -- 'पीगू-प्रमाव' के ठीक विव-रीत वास्त्रविक आय में से उपभोग को हनोरमाहित और वास्त्रविक की प्रोक्षाहित करने का प्रभाव पड़ेगा। पीगु यह मान लेने है कि परिसपत्ति के परिमाण को स्थायी रखा जाता है A=A, सथा निजी वचत की मात्रा परिसपत्ति के बास्तविक मस्य का घटता हुआ फलन है, dS/d(A/P) < o, जिसमें S बजत है तथा P मूल्य-सूचनांक है। इन मान्यताओं के आधार पर, यदि सामान्य मुल्यों से परिसपत्ति के वास्तविक मृत्य में हाम हो, जिससे कि सचय को प्रोत्साहित करने वाले वडे आधार की इच्छा में वृद्धि हां ('सुख-सुविधा' के लिए नहीं, जैसा कि विकसित अयं व्यवस्था के संदर्भ में पीग तक देते है किन्तु वर्त्तमान सदर्भ में सुरक्षा के लिए) ती किसी दी हुई वास्त-विक आय एव ब्याज के लिए कुल बचत में अनुमानत वृद्धि होगी।

5. अतत', कंवल वचत पर ही जोर देना, मानो यह पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता एव बत्तंमान अपभोग से विचत रहने की क्षमता दोनों का प्रतिनिधित्व करती हो, अनुचित होगा। क्योंकि, मितव्यय के प्रति समाज की अभिवृत्ति के वावजूद यदि किसी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था का औद्योगीकरण अधिक समजातीय निपज एव अधिक लोचपूर्ण औद्योगिक सगटन की प्रोत्साहित करता है, तो पूँजीगत वस्तुओं को उत्पादन करने की इनकी क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इसका ताल्प्य यह है कि अन्यया निपज की विषय-जातीय बनावट से सबन्ध उपकरणो एव अम की विचित्रता कम हो जाती है, जिससे की उपभोग नहीं होने के कारण मुबन माधनों को यगैर किसी विज्ञाद के पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सके। इस का ताल्प्य यह भी है कि उद्योग के सगठन का विवर्ण इस प्रकार की जटिलता

देखं इनला 'इकॉनामिक प्रोग्नेस इन ए स्टेब्ल इनवायरामेट', इकानामिका
14/1917 । इसमें सिन्निहित आर्थिक व्यष्टिमाव-सम्बन्धी युक्ति यह है कि
वहते हुए मूल्यों के परिणामस्वरूप मौद्रिक बचत के वास्तविक मूल्य मे कमी का
प्रभाव व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए अतिरिक्त वचत की सीमान्त उपयोगिता मे
वृद्धि होती है।

एवं कुसंमंजन की अपेक्षा साधनों की अगतिशीलता, साधनों के अकशल संयोजन, तथा विशिष्ट योग्यता एवं पदार्थों की दुर्लभता से अधिक होता है। एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की कठिनाई यह हो सकती है कि इसकी पूँजीगत वस्तुओं को उत्पन्न करने की क्षमता, न कि बनाने की क्षमता, विकास के अपेक्षित लक्ष्य की दर से बहुत निम्न हो। यदि ऐसा हो, तो इसके लिए स्फीति नहीं, वरन् संरचनात्मक असमंजन को दोप देना चाहिए। क्या यह मान लेना उचित नहीं है कि बढ़ते हुए मूल्य का बातावरण संरचनात्मक स्थार के लिए सहायक होता है।

उपर्युक्त विवेचन इन दोनों वातों को सूचित करता है। प्रथमतः, पूँजी-संचय की क्षमता-वर्द्धक प्रकृति स्वयं एक विस्कीतिक शक्ति है और द्वितीयतः, व्रति-स्क्रीति से कम वृद्धिशील मूल्य, द्रुतगित के बौद्योगीकरण के लिए वावश्यक पूँजी-संचय में, वाधा द्वालने के वजाय इसे प्रोत्साहित करते हैं। यह इस वात को भी वतलाता है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को, स्फ़ीति के भय के वगैर, यानी इस प्रकार के अनुचित भय के वगैर कि इससे मूल्य-स्थायित्व समाप्त हो जायगा, 1 अपने उत्पादक साधनों

कुछ विशिष्ट अर्थ-ब्यवस्थाओं में 'स्फीति के द्वारा विकास' की निम्नांकित सीमाओं की चर्चा की जा सकती है: (1) गुप्त वेरोजगारी अनुपस्थित अथवा गांत हो सकती है, जिससे कि यह मौद्रिक मजदूरी की दर पर थोड़ा अथवा वित्कृत निम्नगामी दवाव नहीं दे सकती और मृल्य-मजदूरी की चकाकार समस्या की उत्तेजित कर सकती है। (2) मुद्रा के घटते हुए वास्तविक मूल्य से हानि की संमावना विकथ-मूल्य एवं लागत-व्यय के वीच अप्रत्याशित अंतर से लाभ प्राप्त करने की आशा से अधिक हो सकती है, जिससे उत्पादन की अभिग्रेरणा क्षीण हो जायगी । (3) स्फीति के चलते वलात्-वचत में वर्धनशील मुद्रा की कम-शक्ति के स्थायित्व में विश्वास की कमी के चलते ऐच्छिक वचत में हास से वित्कुल समाप्त हो सकती है। (4) अपनी स्थायी आय पर बढ़ते हुए मूल्यों के विपरीत प्रभाव से ऋणदाता इतने अधिक हतोत्साहित हो सकते हैं कि वे अन्य सरकारी ऋण-पत्रों अथवा विकास की योजनाओं के लिए वित्त प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किये गये नये निजी ऋण-पत्रों को न खरीदें। (5) मौद्रिक भ्रम का स्थान वास्तविक प्रयोजन ले सकता है, जिससे कि मजदूरी, व्याज, लगान तथा लाभांश सभी को जीवन-मान के साथ समायोजित करना एक सामान्य नियम वन जाय और इस प्रकार नियमों की वचत एवं निवंश के मूल्य पर उपभोक्ता की माँग को प्रोत्साहित किया जाय। (6) स्फीतिक उद्यारकर्त्ता देशों में बढ़े हुए कर, विनिधान की प्राथमिकता विदेशी विनिमय-संबंधी नियंत्रण, तथा सार्वजनिक नीति के अन्य स्फीति-विरोधी उपाय पूँजी-सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा प्रत्यक्ष एवं

अध्याय 9

श्रार्थिक विकास में वित्तीय भूमिका

राजकोषीय सिद्धांत एवं नीति के महत्त्व में राजस्व से कल्याण की और तथा विल्कुल हाल में, चक्रीय स्थिरीकरण से दीर्घकालिक विकास की और ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय का संबंध दीर्घकालिक विकास में वित्तीय भूमिका से है। विशिष्टत:, हम लोग निम्नांकित का पृथक् रूप से विवेचन करेंगे—(क) अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अधिकतम विकास में वित्तीय भूमिका-तथा (ख) विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के स्थायी विकास में वित्तीय भूमिका।

अधिकतम विकास के लिए वित्तीय किया*

आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय तरीकों का सचेत प्रयोग हाल में ही विकसित हुआ है। इसका विकास संभवतः युद्ध के पूर्व के बिशुद्ध रूप से राजकोषीय नीति के प्रतिचकीय पहलू पर केन्स द्वारा दिये गये जोर की प्रति-

यह परिच्छेद मुख्य रूप से हमारे 'दि फिस्कल रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकॉनामिक डिवेलपमेंट, इण्डिया जरनल ऑफ इकॉनामिक्स, जुलाई, 1956 पर आधृत हैं। पाठकों का ध्यान इसी पित्रका के इसी अंक में प्रकाशित निम्नांकित निबंधों को ओर आकृष्ट किया जाता है: ओ० प्रकाश, "टेक्सेशन पॉलिसी इन ए ट्रेनजीशनल इकॉनामी;" डी० फा, 'फिस्कल पॉलिसी ऐंड दि इकॉनामिक डिवेलपमेंट ऑफ अंडरडिवेल्पड कंट्रीज,' एम० एस० भाटिया, 'दी रोल ऑफ पिंट्लक बर्जीटिंग इन एन अंडरडिवेल्पड इकॉनामी,' एस० पाल, 'सम एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनीटरी ऐंड फिस्कल पॉलिसीज फॉर इकॉनामिक ग्रोथ इन अंडरडिवेल्पड कन्ट्रीज।'

किया तथा हेरोड एव डोमर की तरह का केन्सीगौत्तर विकास-सर्वधी विश्वेषण, जो सभवत नीति को व्यावहारिक रूप देने में सहायक होता है, के परिणाम-स्वरूप हुआ है। हेरोड-डोमर के विकास-संबंधी मॉडल विश्वद्धतः अवध-नीति से संवद हैं तथा राजकोपीय तटस्थता की मान्यता पर आधृत है। इनका रूपाकन विकसित अर्थ-व्यवस्था के प्रगतिश्रील साम्य की स्थिति की सूचित करने के लिये किया गया है। अतएव, इनका नीति-संबंधी आश्रय अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की स्थिति के ठीक विपरीत है। फिर भी, हेरोड-डोमर मॉडल केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये केन्स के स्थायी अत्पकालीन वचत-विविधा सिद्धात की गतिश्रील एव वीर्यकालिक बनाने के उत्तेजक प्रयास का प्रतिनिधित्व करते है, वरन् इसलिए भी कि अल्प-विकसित देश के आर्थिक विकास में स्पष्ट परिवर्ती के रूप में राजकीपीय-नीति प्राचलों के प्रयोग के लिए इनमें सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार के सुधार इस विवेचन के कम में किये जायेंगे। इस परिच्छेद में हम लोग अल्प-विकसित वर्थ-व्यवस्थाओं की उत्पादन-धमता के विकास में सरकार के राजकोपीय कार्यों का (क) विनियोवता, (ख) व्यविवाला, तथा (ग) आय के पुर्नावतरक के रूप में विश्लेषण करेंगे।

विनियोवता के रूप में सरकार

विनियोक्ता के रूप में सरकार के राजकोपीय कार्यों को दिखलाने के लिए वास्तिविक सरकारी व्यय (G) को सरकारी निवेध (I_{θ}) तथा सरकारी उपभोग (C_{θ}) में विभक्ष करना अनिवार्य है, यानी

$$G = I_{\sigma} + C_{\sigma}, \tag{1}$$

जिसमे वर्त्तमान सदर्भ में I_s को ऐसे उत्पादक कार्यों एवं उपकरणो—जैसे राजपथ, बन्दरगाहो, पुलो, विद्यालयो, अस्पतालो तथा यातायात एवं संवहन-सबंधी सुविधाओं पर राजकीय व्यय का प्रतिनिधित्व करते हुए तथा C_s को अनुत्पादक मदो, जैसे : उपभोक्ता वस्तुएँ, सामाजिक सेवाएँ, अस्त्र-शस्त्र एवं पिरामिड पर राजकीय व्यय का प्रतिनिधित्व करते हुए, समक्षा जा सकता है। इन दोनो प्रकार के सरकारी व्यय के बीच चुनाव करना बंधानिक ककावट पर निभंद करता है।

पुन', हम यह मान लेंगे कि चिनियोक्ता के रूप मे सरकार के कार्य की बचाने वाते के रूप के कार्य से पृथक् करने के लिए राष्ट्रीय बजट को संनुलित बनाया जाता है, यानी —

$$G=T,$$
 (2)

जिसमें T वास्तविक रूप में करों की मात्रा है। हम लोग करों का शुद्ध धास्तविक राष्ट्रीय आय (Y) के फलन के रूप में उल्लिखित करेंगे:

$$T = z Y; z = \frac{T}{Y}, \qquad (3)$$

जहाँ z सरकार के कर लगान की औसत (= सीमांत) क्षमता अथवा वैद्यानिक नियन्त्रण को ध्यान में रखते हुए केवल कर की दर है।

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की थन्तः कियाओं को प्रविश्वत करने के लिए जिपभोग एवं निवेश फंक्शन को निम्नांकित रूप में उल्लिखित करना लाभदायक है : $C = C_p + C_\sigma = a_p(Y - T) + a_\theta Y = a_p(I - z) Y + a_\theta Y$, (4)

जिसमें C वास्तविक रूप में कुल उपयोग न्यय, C_p निजी उपभोग, a_p खर्च करने योग्य आय (Y-T) में से उपभोग की निजी औसत (= सीमांत) प्रवृत्ति, a_p राष्ट्रीय एवं सरकारी उपभोग न्यय का परिवर्तनीय औसत अनुपात है तथा शेप पहले की तरह परिभाषित रूप में ही है।

$$I = I_{p} + I_{g} = \triangle K_{p} + \triangle K_{g} = \frac{\triangle Y}{\sigma}, \qquad (5)$$

जिसमें I कुल वास्तविक शुद्ध निवेश, तथा I_s निजी निवेश है। यहाँ चूँ कि शुद्ध निवेश-पूँ जी में वृद्धि के बरावर है, $I = \triangle K$ अंतएव, जैसा कि डोमर के समीकरण में उपलक्षित है, हम निजी शुद्ध निवेश $(\triangle K_s)$ एवं सरकारी शुद्ध निवेश $(\triangle K_s)$ एवं सरकारी शुद्ध निवेश $(\triangle K_s)$ दोनों की निपज में वृद्धि $(\triangle Y)$ के साथ प्रत्यक्ष रूप में तथा निवेश की औसत (= सीमांत) उत्पादकता (σ) के साथ विपरीत रूप में परिवर्गित होते हुए मान सकते हैं। (यानी $\triangle Y = \sigma \triangle K$, $\sigma = \triangle Y/\triangle K$ तथा $\triangle K \Rightarrow \triangle Y/\sigma$ समान हैं)।

हम जानते हैं कि साम्यावस्था में कुल निवेश वरावर होता है कुल आय घटांव कुल उपभोग के, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं:

$$I = I_p + I_g = Y - C_p - C_g. (6)$$

समीकरण (5) एवं (6) से हमें निम्नांकित रूप में उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्राप्त होती है :

$$\Delta Y = \sigma \left(I_p + I_q \right) = \sigma \left(Y - C_p - C_g \right), \tag{7}$$

समीकरण (1) से (4) तक ध्यान में रखते हुए एवं समीकरण (7) के दोनों पक्षों को Y से विभाजित करने पर हमें निपज की पूर्ण क्षमता वृद्धि की दर (G_k) प्राप्त होती हैं:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = G_k = \sigma \left[I - a_p (I - z) - a_0 \right] \tag{8}$$

इस समीकरण में तीन स्पष्ट राजकोपीय —नीति प्राचल ठ, व और ति हैं जो उचित क्रियाओं के द्वारा सबन्ध विकास की दरों में वृद्धि के योग्य हैं। अब हम समीकरण (8) के परिचालन —महत्त्व को स्पष्ट करें।

सर्वप्रथम, समीकरण (8) यह बतलाता है कि यदि वर्धनगील सरकारी नवेश (I_s) को यथामाध्य विशुद्ध उत्पादक स्रोतों में लगाने से निवेश की औसत क्षमता (o) में मृद्धि होती है, तो अन्य बातों के समान रहने पर, पूर्ण क्षमता वाली वृद्धि की दर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार, केन्स के अल्पकालीन गुणक सिद्धान्त की तरह जब किसी विकास-सम्बन्धी विश्लेषण में, निवेश की क्षमता-सर्जन पहलू को इसके आयु-उत्पादक पहलू से अधिक महत्त्वपूर्ण समक्षा जाता है, तो I_s में से पिरामिड निर्माण की तरह के व्यय को निकाल देना अनिवायं है। जिस हद्द तक सरकारी निवेश उत्पादक कार्यों तक सीमित है (यद्यपि सार्वजनिक शिक्षा एव स्वास्थ्य-जैसे कम विस्पष्ट सामलों में इसे मापना सुगम नहीं है) उत्सी हदद तक, जैसा कि समीकरण (5) से स्पष्ट है, निवेश की औसत क्षमता (o) में वृद्धि होगी और इसीलिए जैसा कि समीकरण (8) अतलाता है, पूर्ण क्षमता विकास की दर (G_k) में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर थोड़ा खतरा इस वात का है कि o पर उत्पादक सरकारी निवेश का बृद्धिमान प्रभाव o पर अनुत्यादक, किन्तु लाभदायक, निजी निवेश (जैसे सराय, रंगशाला, क्रीडा-मच तथा आमोद-प्रमोद-केन्द्र) के हास-मान प्रभाव से बिस्थित हो जाय। यहाँ उद्धार के लिए प्रत्यक्ष नियन्त्रण (जैसे बिनिधान की प्राथमिकता) का सहारा लेना पड़ सकता है।

दूसरी ओर, औसत कर की दर (2) में वृद्धि के द्वारा भी पूर्ण क्षमता-विकास दर में वृद्धि की जा सकती है। स्पोक्त, जैसा कि समीकरण (4) से स्पष्ट है, 2 में वृद्धि की जा सकती है। स्पोक्त, जैसा कि समीकरण (4) से स्पष्ट है, 2 में वृद्धि से व्यय की जाने वाली आय में से निश्री उपभोग व्यय में कभी होती है और इसलिए समीकरण (6) के अनुसार वास्तविक आय का वह भाग, जो सरकारी निवेश के लिए उपलब्ध है, बढ जाता है। दूसरे शब्दों में, 2 में वृद्धि का तात्वयं Y के दिये हुए स्तर पर कुल करों (T) में वृद्धि है और इसलिए समीकरण (2) के अनुसार कुल सरकारी व्यय में वृद्धि है। यदि स्थायी व के साथ-साथ सरकार के उपभोग की शीसत क्षमता (a2) स्थायी रहे, तो समीकरण (1) के अनुसार T में वृद्धि के साथ-साय G में वृद्धि का सात्पर्य निश्चित रूप से सरकारी निवेश की अधिक मात्रा से है। दूसरी क्रिया केन्स के इस सुमाब के अनुरूप, यद्यपि कि विपरीत दिशा में है कि राज्य को अपनी करों की योजना के द्वारा उपभोग की क्षमता पर निर्देशक प्रभाव डालना चाहिए। (एक विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में केन्स अनुमानतः उपभोग की क्षमता में वृद्धि करना चाहैये)।

अन्ततः, स्थायी व एवं व दिया हुआ रहने पर, सरकार के उपभोग की औसत

क्षमता (a_{σ}) में कमी के द्वारा पूर्ण क्षमता-विकास दर में वृद्धि की जा सकती है। a_{σ} में कमी का प्रभाव सरकारी उपभोग (C_{σ}) में कमी और इसलिए समीकरण (4) एवं (6) के अनुसार सरकारी निवेश में वृद्धि होगी। यहाँ यह वात स्वीकार की जाती है कि Y के किसी भी स्तर के लिए a_{σ} को घटाने के प्रयास में उपभोकता उपदान, सामाजिक सेवाएँ, प्रतिरक्षा-सम्बन्धी व्यय एवं स्पष्ट रूप से अन्य अनुस्पादक, किन्तु सामाजिक दृष्टि से लाभदायक राजकीय व्यय को कम करने की व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से जब अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था कल्याण के प्रति सचेत एवं प्रतिरक्षा के प्रति सचेत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हो।

निष्कर्प के तौर पर यह कहा जा सकता है कि विनियोक्ता के रूप में सरकार पूर्ण-क्षमता विकास की दर में एक सन्तुलित वजट के ढाँचे में, (क) निवेश की औसत उत्पादकता व में वृद्धि, (ख) कर लगाने की औसत क्षमता ट में वृद्धि, तथा (ग) सरकार के उपभोग की औसत क्षमता a_0 में कमी के द्वारा वृद्धि कर सकती है।

वचानेवाले के रूप में सरकार

अव सरकार के बचाने वाले के रूप में राजकोपीय कार्य पर ध्यान देने से, हम लोग अपना विश्लेषण सन्तुलित बजट की मान्यता को समाप्त कर प्रारम्भ करेंगे। यह आवश्यक है; क्योंकि जैसा कि नीचे दिखलाया जायगा, सरकारी बचत बजट के आधिक्य की मान्यता पर आधृत है।

मान लिया जाय कि वास्तविक शुद्ध आय एवं कर, अन्तरणरूप अदायगी एवं सरकारी व्यय के दीच कुछ निश्चित सम्बन्ध है:

$$\frac{T}{Y} = z, \quad \frac{R}{Y} = r, \quad \frac{G}{Y} = g, \tag{9}$$

जिसमें R अन्तरण-रूप अदायगी (जिसमें सामाजिक वीमा-सम्बन्धी लाभ, सहायता, उपदान एवं सार्वजितक ऋण पर व्याज भी सम्मिलित है) के लिए है, r सरकार के अन्तरण-रूप की औसत (= सीमांत) क्षमता है, g सरकार के व्यय करने की औसत (= सीमांत) क्षमता है तथा शेप पहले की ही तरह हैं। यहाँ वैघानिक नियन्त्रण की शतें पर z, r एवं g राजकोपीय नीति प्राचल हैं। समीकरण (g) के सम्बन्ध में दो वातों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए : प्रथमतः सरकारी व्यय (G) को निवेश (I_g) एवं उपभोग (C_g) में विभक्त करने, जैसा कि हम ने सरकार के नियोक्ता के रूप में कार्य के अन्तर्गत किया था, के बजाय यहाँ हम लोग सम्पूर्ण सरकारी व्यय पर विचार करते हैं। द्वितीयतः, अन्तरण-रूप अदायगी का प्रयोग यहाँ = 'शुद्ध वापसी' (T-R) के श्रन्तर्गत करने के वजाय स्पष्ट रूप से आय के पुनर्वितरण के तरीके के रूप में किया गया है।

वजट-सम्बन्धी उपलक्षक स्थितियो को निम्न-रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

- (a) (Z-r) = g: वजट-सम्बन्धी सन्तुलन,
- (ख) (Z-r) > g : बजट-सम्बन्धी आधिवय,
- $(\pi)(Z-r) < g$ ः वजट-सम्बन्धी घाटा ।

यहाँ बजट-सम्बन्धी सन्तुलन (क) को शून्य सरकारी वचत, बजट-सम्बन्धी आधिक्य (ख) को धनात्मक सरकारी बचत तथा वजट-सम्बन्धी घाटे (ग) ऋणात्मक सरकारी बचत तथा वजट-सम्बन्धी घाटे (ग) ऋणात्मक सरकारी बचत समभना चाहिए। वीर्यकालीन गतिशील राजकीपीय नीति मे वजट-सम्बन्धी इन उपलक्षक स्थितियों मे उचिन परिवर्त्तन पाये जाते हैं। जहाँ तक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, यह अन्त-प्रज्ञात्मक रूप से स्पष्ट है कि वजट-सम्बन्धी आधिक्य ही सम्बद्ध स्थिति हैं, जिसे प्राप्त करना तथा बनाये रखना चाहिए। क्योंकि, बचाने वाले के रूप मे सरकार के राजकीपीय कार्य को अपूर्ण निजी बचत के पूरक के रूप में ही समफता चाहिए।

समीकरण (9) को ध्यान में रखने हुए, सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए वचत-निवेश सम्बन्ध को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है:

$$b\triangle Y = sY + zY - rY - gY = (s + z - r - g)Y, \tag{10}$$

जिसमे $s=S_IY$ या निजी धवत अनुपात (औसत = सीमात) एवं b पूँजी-निपज अनुपात (औसत = सीमात) है। समीकरण (10) का दायाँ पक्ष निजी एवं सरकारी कुल बचत तथा बायाँ पक्ष निजी प्रेरित निवेश क्र्यतिनिधित्य अरता है।

सभीकरण (10) से हमे पूर्ण-क्षमता विकास की दर प्राप्त होती है, जो निजी एवं सरकारी वचत अनुपात सथा पूँजी-निपज अनुपात के तकनीकी सम्बन्ध पर निभैर करती है:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = G_k = \frac{s+z-r-g}{b} = \sigma (s+z-r-g), \quad (11)$$

जो यह स्पष्ट करता है कि अन्य सभी स्वतन्त्र परिवक्तियों के स्थायी रहने पर, पूर्ण-क्षमता विकास दर में धनात्मक सरकारी वचत अनुपात, (z-r)>g के परिणाम स्वरूप वृद्धि होगी। फिर भी, जैसा कि समीकरण (11) सूचित करता है, यदि निजी यचत-अनुपात सामाजिक आदर्णतम विकास की दर g_m (तृतीय अध्याय में विणत) के लिए अपेक्षित दर की तुलना में बहुत कम है, तो सरकारी बचत-अनुपात को बढ़ाने के लिए वास्तव में z, r एव g पर बैकल्पिक राजकोपीय कियाएँ हैं। अतएव, $G_k = G_m$ के समग्र उद्देश्य को वैसी विशिष्ट राजकोपीय अधिकारियों के सर्वोत्तम निर्णय के अनुरूप हो, पूर्ण किया जा सकता है और यह अवश्य करना चाहिए।

पूर्ण-क्षमता विकास की दर से सामाजिक आदर्शतम विकास की दर की अधिकता $G_m > G_k$ के दिया हुआ रहने पर $G_k = G_m$ करने के लिए विकासात्मक राजकोपीय नीति का उद्देश्य G_k में वृद्धि करना होना चाहिए। ऐसा निरन्तर वंजट-सम्बन्धी आधिक्य को निम्नांकित उपाय द्वारा वनाये रख कर किया जा सकता है:— (क) सरकार के बचाने की औसत क्षमता g में कमी करके, (ख) कर लगाने की औसत क्षमता z में वृद्धि के द्वारा, अथवा (ग) अन्तरण-रूप अदायगी के लिए सरकार की औसत क्षमता में कमी के द्वारा। किन्तु इनमें से किसी एक किया पर दवाब को कम करने के लिए णायद तीनों कियाओं का सिम्मश्रण उन्तित होगा।

किन्तु, इस वात को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी प्रकार से प्राप्त निरन्तर वजट-सम्बन्धी आधिक्य, सरकार के विनियोक्ता एवं वचानेवालों के रूप में राजकोपीय कार्य के अनुरूप है; क्योंकि राजकोपीय अधिकारी को कल सरकारी व्यय gY = G के उस भाग को कम करने की ? जो उपभोक्ता वस्तुओं (C_{σ}) के कय पर व्यय किया जाता है और इस प्रकार जैसा कि समीकरण (1) से स्पष्ट है, सरकारी निवेश में वृद्धि $(I_{\sigma} = G - C_{\sigma})$ करने की छूट है। साथ ही, इस बात पर भी ध्यान देना हैं कि बचाने वाले के रूप में सरकार की राजकोपीय भूमिका केन्स के इस सुमान के अनुरूप है कि यदि और जब कभी 'उपभोग की वैयिक्तक क्षमता, इतनी अधिक है कि मुद्ध बचत बहुत कम होती है और इसलिए पूँजी की पूर्ति भी कम होती है, तो भी ''राज्य के माध्यम से सामुदायिक बचत का स्तर पर वनाये रखना सम्भव है, जिस पर पूँजी में वृद्धि सम्भव हो सकेगी "।" वजट के लिए आधिनय के द्वारा प्राप्त की जाने वाली इस प्रकार की सामुदायिक वचत की मात्रा सामाजिक आदर्शतम विकास की दर (G_m) के सम्बन्ध में वास्तविक निजी वचत अनुपात (s) एवं पूँजी-निपज अनुपात (b) के अनुमित मृल्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि $G_m = .03$, s = .05, एवं b = 5, 'साम्दायिक वचत' (s^r-s) ν होगी, जिसमें $s^s=bG_m=.15$ (आदर्शतम विकास की दर के लिए अपेक्षित बचत अनुपात), यानी राष्ट्रीय आय के किसी भी स्तर का 10 प्रतिशत (= .15-.05) । इस प्रकार की 'सामुदायिक वचत' की अनुपस्थिति में अर्थ-व्यव-स्था $s_7/b=.03$ की जगह s/b=.01 की दर से विकसित होगी। 'विवृत' व्यवस्था में पूजी के आयात के द्वारा सामुदायिक बचत पर इस प्रकार के दवाब को बहुत अधिक कम किया जा सकता है।

जनरल थियरी, पु॰ 376।

देखें मेरा 'ग्रोथ ऍनेलिसिस एन्ड दि प्रोव्लेम्स ऑफ केपिटल एकुमुलेशन इन अंडर-डिवेक्पड कन्ट्रीज', पूर्व उद्धृत ।

आय के पुनर्वितरक के रूप में सरकार

उपयुंक्त विवेचन मे हम कर की दर एवं अंतरणहप दर की बनायट से पृथक् रहे, किन्तु यह दिखलाना आवश्यक है कि मिन्न-भिन्न आय-वर्गों पर लगाये गये विभिन्न प्रकार के करों की दरों तथा अंतरणहप दरों से निजी वचत अनुपात में परिवर्तन होता है और इसलिए पूर्ण-क्षमता से विकास की दर प्रभावित होती है। तदनुसार, अब हम लोग विकास-कार्यक्रम की सामान्य योजना के अन्तर्गत आय के पुनवितरक के रूप में सरकार के राजकीपीय कार्यों पर विचार करेंगे।

वितरित की जानेवाली वास्तविक राष्ट्रीय आय को दी भागों में विभनत किया जाय—पहली वह, जो निम्न आय वाले वर्ग को प्राप्त होती है (Y_1) और दूसरा वह, जो उच्च आय वालो (Y_2) को प्राप्त होती है, यानी—

$$Y = Y_1 + Y_2, \tag{12}$$

जिसका वितरण अनुपात निम्नाकित है:

$$\frac{Y_1}{Y} = d, \frac{Y_2}{Y} = I - d. \tag{13}$$

और आगे बढ़ने के पूर्व यह मान लिया जाय कि दो पृथक्-पृथक् आय-नगें हैं, जिनके बीच किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं पाई जाती है तथा जिनके बीच मरों, अतरणस्प अदायियों तथा बचत की क्षमता के सबध में पूर्ण विभेद पाया जाता है। इन वर्गों से बाहर सभी आय-उपाजित करने वालों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की सहज मान्यता निम्नाकित विश्लेषण में सन्निहित आय एवं करों, अतरणस्प अदायियों तथा वचतों के स्यायी, किन्तु विभिन्न अनुपातों को न्यायोचित करार करने के लिए की गई है।

कुल करों की दो वर्गों में विभक्त किया जाय—एक वे, जो निम्न आयवर्गों पर लगाये जाते हैं (T_1) , तथा दूसरे वे जो उच्च आय वर्गों पर लगाये जाते हैं (T_2) । भुगतान की योग्यता सिद्धात के अनुसार यह मान लिया जाता है, कि पहले वर्ग पर कर की दर दूसरे वर्ग से निम्न है:

$$T = T_1 + T_2 = z_1 Y_1 + z_2 Y_2 \tag{14}$$

जिसमें 21 निम्न आय वर्गपर एवं Z2 उच्च आय वर्गपर औसत (ंंंसीमात) कर की दर है।

इसी प्रकार, अंतरणहप अदायगियों को भी दो बर्गों में विभक्त किया जाता 5 जो निम्न आय वाले बर्गों को जाती है (R_{1}) , तथा वह जो ऊँची आय वाले

वर्गों को जाती हैं (R_2) । अंतरणरूप दर, मुख्य रूप के प्रति कल्याण से सचेत अर्थ-व्यवस्थाओं में पहले वर्ग में दूसरे की अपेक्षा साधारणतथा अधिक है :

$$R = R_1 + R_2 = r_1 Y_1 + r_2 Y_2, \tag{15}$$

जिस में r_1 निम्न आय वाले वर्ग के लिए तथा r_2 ऊँची आय वाले वर्गों के लिए औसत (=सीमांत) अंतरणरूप दर हैं। $r_1>< r_2$, यह Y_1 एवं Y_2 वर्गों के लिए उपदान को दिये जाने वाले महत्त्व पर निर्भर करता है।

करों एवं अंतरणरूप अदायगियों के पश्चात् निम्न आय वाले वर्गी की निजी वचत निम्नांकित है:

$$S_1 = s_1 (Y - T_1 + R_1) = s_1 (i - z_1 + r_1) Y_{11}$$
 (16)

जिसमें s₁ व्यय की जाने वाली आय में से निम्न आय वाले वर्ग के बचाने की भौसत (=सीमात) क्षमता है। इसी प्रकार, ऊँची आय वाले वर्ग की वचत इस प्रकार है:

$$S_2 = S_2 (Y_2 - T_2 + R_2) = S_2 (I - Z_2 + r_2) Y_2,$$
 (17)

. जिसमें s_2 व्यय की जाने वाली आय में से ऊँची आय वाले वर्ग के वचाने की औसत f(m) क्षमता है। यह मान लेना सत्य प्रतीत होता है कि निम्न आय वाले वर्ग की तुलना में ऊँची आय वाले वर्ग की वचाने की सीमांत क्षमता अधिक है, अथवा $s_2 > s_1$ ।

(12) से (17) समीकरणों से हमें पूर्ण-क्षमता विकास की दर प्राप्त होती है, जिसमें निजी बचत-अनुपात पर राजकोपीय पुनर्वितरण के प्रमाव का समावेश है।

$$G = \frac{\left[s_1(i-z_1+r_1)d+s_2(i-z_2+r_2)(i-d)\right]+z-r-}{b}$$
 (18)

जिसमें s_1 $(i-z_1+r_1)d$ तथा $s_2(i-z_2+r_2)$ (i-d) राष्ट्रीय आय में से क्रमणः निम्न आय एवं ऊँची आय वाले वर्गो की बचाने की ओसत (=सीमांत) क्षमता है।

समीकरण (18) यह वतलाता है कि यदि व्यय-योग्य आय में से (s_1, s_2) दोनों आयवाले वर्गों की वचाने की औसत क्षमता स्थिर रहती है, तो सरकारी वजट संतुलित ही अथवा असंतुलित, (z-r)g इससे स्वतंत्र रूप में, सापेक्ष कर की दरों (z_1, z_2) , सापेक्ष अंतरण-दरों (r_1, r_2) तथा वितरण अनुपात (d) और इसलिए i-d) में परिवर्त्तन से राष्ट्रीय आय में से बचाने की कुल औसत क्षमता और इसलिए पूर्ण क्षमता-विकास दर (G_k) में परिवर्त्तन हो सकता है। और स्पष्ट बनाने के लिए, $G_k=G_m$ करने के लिए पूर्ण क्षमता विकास की दर में वृद्धि के प्रयास के लिए, (π) z_2 , में कमी, (π) r_2 में वृद्धि, (π) z_1 में वृद्धि, तथा (π) r_1 में कमी अथवा थोड़े में एक कम प्रगतिशील कर एवं अंतरणरूप रचना की आवश्यकता होगी। साथ ही, इसी प्रकार के प्रयास के लिए कम प्रगतिशील उत्तराधिकार अथवा मृत्य-करों एवं अन्य तरीकों से वितरण अनुपात d में कमी की आवश्यकता होगी।

यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाती है कि अधिक निजी बचत के उद्देश्य से निम्न से उच्च वर्गों मे आय के पुत्रचितरण की ये राजकीय कियाएँ किसी अल्प-विकसित अर्थ व्यवस्था में प्रचलित समानता के उद्देश्य के विरुद्ध जा सकती हैं। साथ ही, यह भी स्वीकार किया जाता है कि निम्न आय वाले वर्गों से ऊँची आयवाले वर्गों में आय के राजकोषीय पुनवितरण से, प्रतिस्पर्धात्मक कारणो के परिणामस्वरूप, सम्दाय की उपभोग की इच्छा मे वृद्धि हो सकती है और इसलिए कुल निजी बचत में भी कमी होगी, जो पूँजी सचय तथा निपज में बृद्धि के लिए अहिततर सिद्ध होगी। क्योंकि, यह विचारणीय बात है कि मजदूरी उपाजित करनेवाले परिवारो अधवा व्यक्तियों को, जो लाभ उपाजित करने वालों की तुलना से वहत ही कम आय प्राप्त करते है, 'जोन्सो की बराबरी करने' का प्रबल प्रलोमन हो और जी स्वय दूसरे की 'स्मियों से आगे बढ़ने' के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि ऐसा है, ती दोनों निजी बचत अनुपात (s1, s2) मे ह्वास होगा, जिससे उपयांक्त राजकीय कियाओं का समग्र निजी बचत-अनुपात पर जो बृद्धिशील प्रभाव पडेगा, वह विस्थित हो जायगा। इस प्रकार, अग्रत इस समाजशास्त्रीय सघटन (तथाकथित 'प्रदर्शन-प्रभाव') को छोड कर तथा अशत. पूर्ण रोजगार की मान्यता पर ही कोई व्यक्ति अधिक विकास के लिए आय की विषमता की अनिवायता-सम्बन्धी संस्थापको की तर्क-संगति को स्वीकार कर सकता है।

स्थामी विकास के लिए राजकीय कियाएँ*

हम लोग देख चुके हैं कि किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालीन राजकोपीय कार्यों का आश्रय मुख्य रूप से उत्पादन-क्षमता के विकास की दर को अधिकाधिक बनाना होता है। इसके विपरीत एक विकसित बाजारी अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालीन राजकोपीय कियाओं का निरूपण इस प्रकार की दर को स्थायी बनाने के लिए किया जाता है। अब हम एक दूसरे प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता प्रदान करने बाले के रूप में सरकार की राजकोपीय कियाओं पर विकार करेंगे।

इसके लिए पाठक का ध्यान अध्याम 7 की ओर आकृष्ट किया जाता है।
 यह अंश मुख्यतः हमारे 'ग्रीय मॉडल्स एंड फिसकल पॉलिसी पैरामीटसें' फाइनान्सेक पब्लिक (निदरलंड) सं० 2/1956 पर आधृत है।

ए० एव० हैनसेन पहले व्यक्ति है, जिन्हींने विशुद्धतः च्कीयविरोधी क्रियाओं के अतिरिक्त दीर्घकालीन राजकीयीय नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। (देखे, इनकी फिस्कल पालिसी एंड बिजिनेस साइकिल, नीरटन, न्यूयाकं, 1941) । हेरोड, डोमर, केलेकी तथा हबलामी के तटस्य विकास-मॉडली में सिन्हित राजकीपीय सटस्थता की मान्यता ने बाजारी अर्थ-व्यवस्थाओं के विशुव्ध

गतिशील साम्यावस्था का अस्थायित्व

विशिष्ट प्राचलीय कियाओं को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हम लोग विशुद्ध अवैधनीति की परिस्थितियों में गतिशील साम्यावस्था (परिवर्तन की धनात्मक स्थायी दर के साथ) में अन्तिनिहित अस्थायित्व के विश्लेषणों से प्रारम्भ करेंगे। एक विकसित वाजार अर्थ-व्यवस्था मूलतः निरन्तर प्रगति के पथ से दीर्घकालिक रूप में इसलिए यिचलित होती है कि निजी वचत एवं निवेश से संगत विकास की दर जनसंख्या की वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति से संगत विकास की दर के कदाचित् ही अनुरूप होती है। इस विवेचन के उद्देश्य से हम वग्नैर उच्चावचन के निरन्तर प्रगति की साम्यावस्था की दर को निपज में वृद्धि (वास्तिविक शुद्ध) की उस दर से निर्दिष्ट करेंगे, जो अम को बढ़ती हुई उत्पादकतावाली वृद्धिशील श्रम-संख्या को पूर्ण नियुक्ति की स्थिति में रखने के लिए अपेक्षित होती है। किसी भी समाज में प्राप्त करने योग्य विकास की यह सम्भावित अधिकतम दर है। हम इस प्रकार की दर का निम्नांकित तरीके से सिन्नकट अनुमान कर सकते हैं:

औसत वास्तविक मजदूरी की दर को दिया हुआ तथा नियज एवं श्रम के

विकास की मौलिक अंतदृष्टि के प्रति प्रवल अनुतोप लानेवाले के रूप में कार्य किया है। हेरोड नीति के सम्बन्ध में अत्यधिक सचेत हैं, किन्तु रॉविन्सन ने इनकी नीति-सम्बन्धी विवेचना को, इनके नये योगदानों पर बहुत कम निर्भर वतलाते हुए आलोचना की है। (देखें इनका 'मि० हेरोड्स डायनामिक्स', पूर्व- उद्धृत)।

स्पष्ट राजकोषीय नीति-सम्बन्धी प्राचलवाले विकास माँडल बहुत ही कम हैं। इस सम्बन्ध में जि॰ वी॰ गुलें का 'फिस्कल पॉलिसी इन ए प्रोइंग, इकॉनामी 'जरनल ऑफ पोलिटिकल इकॉनामी', दिसम्बर, 1953 ई॰, एक अपवाद है। गुलें ने यद्यपि कि अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा उपेक्षित विकास अर्थशास्त्र के महस्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया है, तथापि इसकी आलोचना इन वातों को लेंकर की जाती है—गतिशील साम्यावस्था की अस्थिरता-सम्बन्धी स्थित के अपारदर्शकंत्व के लिए जिसे सम्भवत: राजकोषीय नीति दूर कर सकती है, दीघंकालिक विकास पर दीघंकालीन राजकोषीय कियाओं के पुनवितरणात्मक प्रभावों की उपेक्षा के लिए; और विकासशील अर्थ-व्यवस्था के दीघंकालिक अस्थायित्व के वदले चक्रीय अस्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए (यानी हैरोड के विभेद के अनुसार, 'अपेक्षित' दर एवं 'प्राकृतिक' दर में अन्तर से उत्पन्न अस्थायित्व की जगह 'वास्तविक' विकास की दर एवं 'अपेक्षित' विकास की दर में अन्तर से उत्पन्न अस्थायित्व की उत्पन्न अस्थायित्व पर)।

अनुपात को तकनीक की दृष्टि से स्थायी मानकर, हमे निम्नांकित सम्बन्ध प्राप्त होते है :

$$\frac{N}{Y} = \nu, \quad N = \nu Y, \quad Y = \frac{N}{\nu}, \tag{19}$$

जिनमें N पूर्ण निमुक्त रहने पर श्रम की मात्रा है, Y वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय निपज और v औसत (=सीमात) श्रम-निपज अनुपाद है।

समीकरण (19) से और चूंकि श्रम की ओसत उत्पादकता श्रम-निपज अनुपात का व्युत्कम है, निपज एव श्रम के सम्बन्ध को निम्नाकित रूप मे व्यवत किया जा सकता है

$$Y = pN, \left(p = \frac{1}{y} = \frac{Y}{N} \right), \tag{20}$$

जिसमे p श्रम की लौसत उत्पादकता को मापनेवाला गुणाक है । यहाँ $\triangle Y = p \triangle N$ क्षन्तिनिहत है ।

समीकरण (19) एव (20) से तया अतिरिक्त श्रम एवं निपज के अनुपात $(\Delta N/\Upsilon)$ की n से सूचित करने पर हमे निपज मे वृद्धि की पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी दर (G_n) प्राप्त होती है :

$$G = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta N}{Y} p = np \tag{21}$$

जो दर 'तटस्थ तकनीकी प्रगति' की सहज मान्यता, एव इसलिए स्थायी पुँजी-निपज अनुपात के अनुरूप स्थायी श्रम-निपज पर आधृत हैरोड के विकास की 'प्राकृतिक' दर के तुल्य है। केवल इसी मान्यता के चलते, नहीं तो पिछले अध्याय की 'सामाजिक आदर्शतम' विकास की दर इसके लिए अच्छा सन्निकटतम मान होती । चुँकि, हैरोड विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए 'प्राकृतिक' एवं 'अपेक्षित' विकास की दरों की पास-पास रखते है, अतएव अधिक जटिल सामाजिक आदर्शतम विकास की दर की तुलना में समीकरण (21) द्वारा दी गई पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी विकास की दर प्रयोग करने के लिए अधिक उचित धारणा जान पड़ती है। इस प्रकार, पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी विकास की दर की प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए पूँजी सचय की एक निश्चित दर की आवश्यकता होती है। इस अनुकुल मान्यता पर कि तकनीकी परिस्थितियों एव साधनों के सापेक्ष मुख्य इस प्रकार हैं कि वास्तविक पूँजी एव वृद्धिशील श्रम-सच्या मे शीध्रतापूर्वक समायोजन स्थापित हो जाता है, यह कहा जा सकता है कि G, ही पूर्ण रोजगार की बनावे रखने की गारन्टी प्रधान करता है। किन्तु, G_n आवश्यक रूप में पूँजी के प्रयोग की गारन्टी नहीं देता। यही पर हमें पूर्ण क्षमता विकास की दर, अथवा हैरोड की शब्दावली में 'अपेक्षित दर' की ओर घ्यान देना चाहिए !

हम जानते हैं कि पूर्ण क्षमता-दर निम्नांकित द्वारा दी जाती है:

$$G_k = \frac{s}{b} = s\sigma; \left(\sigma = \frac{1}{b} = \frac{Y}{K}\right),$$
 (22)

जो वृद्धिशील पूँजी के कोष के साथ श्रम-संख्या के उचित समायोजन की पूर्व कल्पना करता है। श्रम की पूर्ति को सदा लोचदार मानकर यह कहा जा सकता हैं कि G_k पूँजी के वर्तमान कोप के पूर्ण प्रयोग की गारन्टी प्रदान करता है। किन्तु, चूँकि वास्तव में जनसंख्या की वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति सदा इस प्रकार की नहीं होती, जिससे कि पूँजी के साथ मिलाई जानेवाली श्रम की माँग के अनुरूप श्रम की लोच दार पूँति की व्यवस्था कर सके, अतएव G_k आवश्यक रूप से श्रम की पूर्ण नियुक्ति की गारन्टी नहीं प्रदान करता।

मान लिया जाय कि अर्थ-व्यवस्था वास्तव में G_n , यानी पूर्ण नियुक्ति की दर से वढ़ रही है अब कोई कारण नहीं है कि सिवाय संयोग अथवा निश्चित प्रायोजन के, पूर्ण-क्षमता विकास की दर G_k पूर्ण नियुक्ति-संबंधी विकास दर के सदा अनुरूप हो। किन्तु तर्क के लिए यह मान लिया जाय कि अर्थ-व्यवस्था प्रारंभ में जैसा कि जोन रॉबिन्सन ने कहा है, स्वर्णयुग में है, जिसमें पूँजी-संचय की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर में ठीक अनुरूप है, जिससे पूँजी एवं ध्रम दोनों की पूर्ण नियुक्ति है। ऐसा होने पर, स्वर्णयुग को बनाये रखने के लिए आवश्यक ग्रत इस प्रकार से है:

$$G_k = G_n; \frac{s}{b} = np. \tag{23}$$

समीकरण (23) के तुल्यांक दीर्धकालिक विषमस्पता के वर्षेर स्थायी विकास को बनाये रखने के लिए आवश्यक शतों को दिखलाते हैं। मानलिया कि प्रारम्भिक काल के कुछ समय बाद किसी समय वचत-अनुपात हैं स्थायी रूप से ह्रास हो जाता हैं, जिससे समीकरण (22) के अनुसार पूर्ण क्षमता-विकास की दर $G_{\rm k}$ पूर्ण नियुक्तिसंबंधी विकास की दर $G_{\rm m}$ से निम्न हो जाती हैं। $G_{\rm k} < G_{\rm m}$ के रूप में अंतर्जनित आधात से दीर्धकालीन स्फीति की एक पृथक् प्रवृत्ति की शुरूआत होती है; क्योंकि अब पूर्ण क्षमता विकास-दर के अनुरूप वचत-अनुपात जनसंख्या एवं तकनीक की वास्तविक प्रवृत्ति से अभिप्रेरित निवेश की दर से कम हैं, यानी— $bG_{\rm k}=s < bG_{\rm n}$; $dY_{\rm m}/dt=f\left(I_{\rm m}\cdot S_{\rm m}\right)$ की तरह से यंत्र के अनुसार दीर्घकालिक स्फीती की चास्तविक अपसारी हानि मौदिक राष्ट्रीय आय की वृद्धिशील प्रवृत्ति से विशेषित होगी। इसमें Y,I एवं s कमशः आय, निवेश एवं बचत हैं तथा नीचे का लेख m मुद्रा के, रूप में मापे गये परिवर्त्तियों को सूचित करता है।

इसके विपरीत, यह मान लिया जाय कि किसी खास समय में वचत-अनु

स्वायी रूप से वृद्धि हो जाती है। तो पूर्ण-क्षमता-विकास-दर पूर्ण-नियुक्ति-संबंधी विकास-दर से नियवय ही वढ जायगी Gk > Gn। Gn से Gk का यह आधिक्य दीघं-कालिक स्पिरता की एक विपरीत पृथक् प्रवृत्ति को जन्म देता है; क्यों कि इस बार पूर्ण-क्षमता-विकास-दर के अनुरूप बचत-अनुपात जनसंख्या एव तकनीक से वास्तिक वृद्धि से अभिन्नेरित निवेश की दर से अधिक है, यानी bGk = s > bGn। अब dY dt = F(S-t) की तरह के यत्र के अनुसार, दीर्पकालिक स्थायित्व की अपसारी गति बास्तिक आय की घटती हुई प्रवृत्ति से विशिष्ट होगी। प्रति सनुलन-नीति के अभाव मे बचत-अनुपात मे स्थायी परिवर्त्तन के परिणाम-स्वरूप प्रारम्भिक बाधाएँ (अथवा इसके लिए, पूँजी-निपज-अनुपात मे जिसे अभी हम लोग स्थायी मानते हैं, G_k तथा Gn के बीच सदा बढ़ने थाले विकास-सबधी अतर का सर्जन करेगी। इसने सन्तिहत दीर्पकालिक अस्थायित्व की स्फीति-जनक अथवा स्थायित्व की प्रकृति $Gk > < G_n$ पर निर्भर करेगी। अतएव, हम गतिभील साम्यावस्था के अस्थायित्व की स्थिति की बढते हुए विकास-सबधी अतर के स्प मे समक्ष सकते हैं, यानी

$$\triangle (G_n - G_k) = \psi (G_n - G_k)$$
 (24)

जहाँ फंकणन σ की विशेषताएँ \forall (0)=0 और $\alpha'>0$ है (जिसमें $\psi'=dX/dt$; $X=Gn-G_k$) ।

सक्षेप मे एक विशुद्ध अबंध विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सन्तिहित दीर्घेकालिक अस्थायित्व की इस तरह की ही अर्तानिहित प्रकृति है।

स्थायित्व प्रदान करने वाले के रूप में सरकार

स्थायी विकास के लिए गतिशील राजकोपीय नीति के सामान्य उद्देश्यों को बतलाने के लिए उपयुंकत विवेचन पर्याप्त है। क्योंकि, Gk < Gn के परिणामस्वरूप उत्पन्न दीर्घकालिक स्फीति की सभावित स्थिति में राजकोपीय नीति का आगय यह है कि कर एव व्यय-सबंधी क्रियाओं के द्वारा बचत-अनुपात में इस प्रकार वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे की $bG_k = s = bG_m$ हो जाय। दूसरी ओर, यदि $G_k < G_n$ के परिणाम-स्वरूप अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालिक स्थायित्व की प्रवृत्ति की आर्थका है, तो बचत-अनुपात में कमी की जानी चाहिए। किन्तु अब हमें विशिष्ट प्राचलीय क्रियाओं के विचार पर ध्यान देना चाहिए।

समीकरण (22) के अनुसार किसी सयय t> निजी बचत अनुपात ह में स्थायी हास के परिणाम-स्वरुप मान लिया जाय कि पूर्ण क्षमता विकास की दर पूर्ण नियुक्ति-संबंधी विकास-दर से घट जाती है, $G_k=G_n$ । यदि $G_k=G_n$ करना है, तो आवश्यक दीर्पकालीन प्रतिकरात्मक राजकोषीय नीति धनात्मक सरकारी बचत- अनुपात को प्राप्त करने तथा बनाये रखने की होनी चाहिए। इसके विपरीत, यदि A_n अनुपात में स्थायी विद्ध के परिणाम-स्वरुप A_n अनुपात में स्थायी विद्ध के परिणाम-स्वरुप A_n अनुपात में स्थायी विद्ध के परिणाम-स्वरुप A_n

कोषीय नीति को ऋणात्मक सरकारी वचत-अनुपात (यानी वजट-संबंधी घाटा रखने) को प्राप्त करने एवं बनाये रखने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि, निरंतर वजट-संबंधी आधिक्य के परिणाम-स्वरुप पूर्ण-क्षमता-विकास की दर के अनुरूप बचत में इतनी मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे यह जससंख्या एवं तकनीकी वास्तविक प्रवृत्तियों से अभिप्रेरित विकास की दर के बरावर हो जाय। इसके विपरीत निरंतर वजट-संबंधी बाटे के परिणामस्वरुप पूर्ण क्षमता-विकास की दर के अनुरूप वचत की मात्रा में इतनी कमी हो जाती है। समीकरण (11) को ध्यान रखते हुए हम समीकरण (23) को निम्नांकित प्रकार से पुनः लिख सकते हैं:

$$\frac{s+z-r-g}{b} = np, \tag{25}$$

जो गितशील साम्यावस्था की एक नई स्थिति, जिसे राजकोपीय कियाओं द्वारा पूरा किया जाता है, को व्यक्त किया करता है। समीकरण (25) यह वतलाता है कि यदि $G_k < G_n$ के परिणाम-स्वरूप दीर्घकालिक स्फीति का भय है, तो इसे निरंतर वजट-संबंधी अधिक्य (z-r)>g के द्वारा दूर किया जा सकता है। और इसी प्रकार यदि $G_k>G_n$ के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक स्थायित्व की आंग्रका है, तो इसे निरंतर वजट-संबंधी घाटे (z-r)< g के द्वारा दूर किया जा सकता है।

साथ ही. समीकरण (25) यह प्रस्तावित करता है कि अपूर्ण अथवा अत्यधिक निजी वचत को पूरा करने के लिए वजट-सम्बन्धी आधिक्य अथवा घाटे को प्राप्त करने के लिए राजकोपीय अधिकारी द्वारा राजकोपीय नीति-प्राचलों —Z, r एवं g के लिए वैकल्पित कियाएँ की जा सकती हैं। यदि निजी वचत के अनुरूप पूर्ण-क्षमता-विकास की दर पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी विकास-दर से सामान्यतः ऊँची है, तो र्जसा कि हैरोड का प्रस्ताव है, $G_k = G_n$ करने के उद्देश्य से निम्नांकित की आवश्यकता होगी--(क) सरकार के व्यथ करने की औसत क्षमता g में वृद्धि, (ख) कर लगाने की औसत क्षमताz में कमी, तथा (v) अन्तरण-रूप की औसत क्षमताv में वृद्धि— संक्षेप में लगातार वजट-सम्बन्धी घाटे के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इस प्रकार, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तरह यदि निजी पूँजी-संचय की दर की प्रवृत्ति जनसंख्या में वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति की दर का अतिक्रमण करने की होती है, तो वजट-सम्बन्धी घाटे को बनाये रखने का प्रयास, अनैतिक होने के बजाय, दीर्घकालिक स्थायित्व के वग़ैर, श्रम एवं पूँजी दोनों की पूर्ण नियुक्ति से युक्त स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने के सामान्य उद्देश्य के पूर्णतया अनुरूप है। यदि करों में कमी, सरकारी व्यय तथा अन्तरण-रूप अदायगी के उचित सम्मिश्रण के द्वारा लगातार उत्प्लावन अर्थ-व्यवस्था को बनाये रखा जा सकता है, तो बजट-सम्बन्धी घाटा-विषयक सामान्य आक्षेप बहुत हद्द तक तथ्यहीन हो जार्येंगे।

समीकरण (12) से लेकर (18) तक से हम यह जानते हैं कि निजी

बचत दर को प्रभावित करने और इसलिए दी हुई पूर्ण रोजगार-सम्बन्धी विकास-दर की सुलना मे पूर्ण-क्षमता-विकास-दर को स्थायी बनाने के लिए राजकीपीय अधि-कारी कर एव अन्तरणस्य की दरों मे परिवर्तान कर सकते हैं। इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, हम लोग गतिशील साम्यावस्था की मौलिक शतीं को विस्तृत रप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं.

$$\frac{[s_1(I-z_1+r_1)d+s_2(I-z_1+r_2)(I-d)]+z-r-g}{b}=np, (26)$$

जो यह बतलाता है कि यदि $G_* < G_n$ के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न दीधं-कालिक स्फीति को टालना है, तो z_2 एवं r_1 में कभी तथा r_2 एवं z_1 में वृद्धि-यानी कम प्रगतिशील कर एवं अन्तरण-रूप सरचना के द्वारा समग्र निजी क्वत अनुपात में वृद्धि की जा सकती है। ठीक इसके विपरीत यह बतलाता है कि यदि $G_b > G_n$ के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न दीर्घकालिक अस्यायित्व को रोकना है, तो z_2 एवं r_1 में वृद्धि तथा r_2 एवं z_1 में कमी, यानी अधिक प्रगतिशील कर एवं अन्तरण-रूप सरचना के द्वारा समग्र निजी वचत-अनुपात में कभी की जा सकती है। पहले की ही तरह, पृथक् की जाने योग्य प्रकृति की ये प्राचलीय कियाएँ $s_2 > s_1$ की पूर्व करपना करती है।

हमारी इस सम्भावना पर भी स्वीकृति देनी चाहिए कि उन व्यक्तिगत फर्मों अथवा उद्योगो, जो सम्भवतः 'पूँजी प्रयोग करने वाले' अथवा 'पूँजी-बचाने वाले' तकनीको को अपना सकते हैं, को चयनाश्मक उपादान (अन्तरणहप दर म अन्तर्गिहित) को नीति के द्वारा, म के समग्र आकार को प्रभावित किये वगैर, पूँजी-निएज अनुपात b में जान-बूफ कर परिवर्तन किया जा सके 1 इस प्रकार की चयनाश्मक उपादान की नीति को 'पूँजी-प्रयोग' अथवा 'पूँजी बचाने' के आधार पर औद्योगिक विकास के पक्ष में करों की छूट, यानी करों की दर 2 की संरचना में परिवर्तन, स सम्बद्ध किया जा सकता है। अन्तर्गः, एक अधिक विस्तृत दीर्घकालीन राजकोपीय नीति के अन्तर्गत जनसङ्या की वृद्धि की दर वो प्रभावित करने और इसलिए

^{1.} इस सम्बन्ध मे एन० कालडोर का कहना है कि उसने (हैरोड) ने जो स्वोकार नहीं किया था, वह यह है कि विकास की प्राकृतिक दर को निर्धारित करने वाली 'मौलिक शर्वे' आकाश के द्वारा निर्धारित नहीं होती । ये अनाम्य (विस्तृत सीमाओं के अन्दर) है और आधिक व्यवस्था की अन्तर्जनित शक्तियों से बाहर ढकेली जा सकती हैं या अन्दर लाई जा सकती हैं। (देखें इनका 'दि रिलेशन ऑफ इकॉनामिक श्रोथ ऐंड साइक्लिकल पलक्षुएशन्स', इकॉनामिक जनरल, मार्च 1954) । इसी प्रकार का विचार है-सेनो के 'ए स्टडोर इन वि थिमरी ऑफ इकॉनामिक इयोल्यूनान' में व्यक्त किया गया है किन्तु, इनमें से किसी ने भी।

केवल G_k से सम्बद्ध कियाओं पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय पूर्ण-रोजगार-सम्बन्धी विकास दर G_n को परिवर्तन करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। स्थायी विकास के लिए एक अधिक विस्तृत दीर्घकालीन राजकोपीय नीति की उपलब्धि केवल और अधिक सैद्धान्तिक विक्लेषण पर ही निभैर नहीं करती, वरन् इस बात पर भी निभैर करती है कि राजकोपीय नीति की आर्थिक सम्भावनाओं को इसकी राजनीतिक सीमाओं के साथ कहाँ तक समन्वित किया जा सकता है।

इस प्रकार का सुभाव नहीं दिया है कि जनसंख्या की वृद्धि अथवा श्रम-निपज-अनुपात पर राजकोषीय नीति के उद्देश्य के रूप में विचार करना चाहिए। इस प्रकार के सुभाव की ओर जनाधिक्य वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं तथा जनाभाव वाली विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं—दोनों का ध्यान आकृष्ट था।

 राजकोपीय क्रियाओं में सन्निहित कुछ राजनीतिक एवं सांस्यानिक कठिनाइयों के लिए पोस्ट केन्सीयन इकॉनामिक में देखें एच० आर० बोवेन एण्ड जी० एम० मापर 'इन्स्टिच्यशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लकचुऐशन्स ।'

अध्याय 10

विदेशी व्यापार एवं श्रार्थिक विकास*

विश्लेषण की गहनता के तिए सबृत मॉडल जिस प्रकार अनिवार्य है, उसी प्रकार विश्लेषण की व्यापकता के लिए विवृत मॉडल लाभदायक है। वर्तमान अध्याय में विदेशी व्यापार एवं घरेलू विकास के बीच प्राविधिक सम्बन्ध के स्पष्टीकरण के लिए हम ऑधिक विकास के विवृत मांडल का निर्माण करेंगे। इस अध्याय में एक विवृत अर्थ-व्यवस्था, के सदर्भ में जिसमें माँग में, क्षमता से अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप निरन्तर स्फीति तथा असन्तुलन की स्थित उत्पन्न होनी रहती है, विशिष्ट रूप से निम्नलिखित की व्यास्था की जायगी—(क) विदेशी व्यापार एवं माँग की वृद्धि में सम्बन्ध, (ख) विदेशी व्यापार एवं समता की वृद्धि में सम्बन्ध, तथा (ग) सन्तुलन विकास के लिए प्राचल किया।

इस समस्याका यह विशिष्ट उपचार बर्तमान ब्याख्याको घरेलू विकास एव

^{*}यह अप्रैल, 1958 के मेट्रोकोनोमिका (Metroeconomica) के 10-वें बोल्यूम में प्रकाशित मेरे 'इकॉनोमिक डिबेलपमेट ऐंड दि बेलेस आफ पेमेट्स' का बहुत कुछ उपातरित रूप है।

शिलर-क्षेत्र के बाहर अधिकाश अर्थ-व्यवस्थाओं को घरेलू स्फीति एवं विदेश भुगतान-सम्बन्धी कठिनाइयों के बीच चिर-कालिक विकास की युद्धोत्तरकालीन समस्या का सामना करना पढ रहा है। उदाहरण के लिए—देखें 'यू० एन० इकॉनामिक कमिशन फाँर लेटिन अमेरिका', इकानामिक सर्वे ऑफ लेटिन अमेरिका,' 1954, कोलबिया यूनिविस्ति प्रेस, 1955, तथा नवम्बर, 1955 ई० के रिक्यू ऑफ इकॉनॉमिक स्टेटिस्ट्वस मे प्रकाशित मेरा लेख 'आपान ट्रेड पोजिशन इन ए चेजिय बल्ड मार्केट'।

भुगतान सन्तुलन के सम्बन्ध में केन्सोत्तर विवाद से सम्बद्ध करने के लिए चुना गया है। इस सम्बन्ध में दो भिन्न विचार-धाराएँ दृष्टिगोचर हैं। इनमें से एक विचार-धारा भुगतान-सन्तुलन पर इसकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखे विना घरेलू उन्नित पर जोर देती हैं। दूसरी विचार-धारा भुगतान को साम्यावस्था पर जोर देती हैं, चाहे वह बाह्य सन्तुलन आंतरिक विकास में सहायक हो अथवा नहीं। पेशेवर मत में यह अन्तर विदेशी ब्यापार के आय-उत्पादन पहलू (माँग-पद) अथवा क्षमता सर्जनात्मक पहलू (पूर्ति-पक्ष) के सम्बन्ध में एक पक्षीय पूर्वधारणा का परिणाम जान पड़ता है।

आंतरिक स्फीति एवं वाह्य असन्तुलन के वगैर सन्तुलित विकास के लिए आवश्यक शर्तों को स्पष्ट बनाने के लिए यहाँ विदेशी व्यापार के इन दोनों क्षेत्रों के समायोजन का प्रयत्न किया जायगा। इस प्रकार का प्रयत्न अधिक मुक्त व्यापार एवं चतुर्दिक् उच्च जीवन-स्तर के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उपायों पर भी कुछ प्रकाश डाल सकता है।

विदेशी व्यापार एवं मांग में वृद्धि

पूर्ति की दणाओं को दिया हुआ मानकर, विदेशी व्यापार एवं माँग में वृद्धि के प्राविधिक सम्बन्ध के विश्लेषण से प्रारम्भ किया जाय। समर्थ माँग की वृद्धि पर विदेशी व्यापार-सम्बन्धी क्रियाओं के प्रभाव को दिखाने के लिए केन्स के गुणक सिद्धान्त को निम्न प्रकार से गति प्रदान करना तथा लौकिक कार्य में लगाना अनिवार्य है:—

$$\triangle Y^{d} = \frac{I}{s' + m' - b'} (\triangle I + \triangle G + \triangle E), \tag{1}$$

जिसमें Y^a समर्थ माँग द्वारा निर्धारित वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय आय अथवा केवल समर्थ माँग है, I स्वतः प्रेरित शुद्ध निजी निवेश है, G सरकारी व्यय, E स्वतः प्रेरित निर्यात (जिसमें अवृश्य उद्यार मर्दे भी शामिल हैं), s' वचत की सीमांत

^{1.} तुलना करें — फरवरी 1955 के 'वुलेटिन ऑफ ऑक्सफोर्ड इन्स्टीच्यूट ऑफ स्टेटि-स्टिक्स में प्रकाशित "ग्रोथ ऐंड दि वैलेंस ऑफ पेमेंट्स : सिम्पोजियम", मई 1956 के रिच्यू ऑफ इकॉनामिक स्टेटिस्टिक्स में प्रकाशित आर० नक्से का लेख 'दि रिलेशन विटवीन होम इन्टेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल वैलेंस इन दि लाईट ऑफ ब्रिटिश इक्सपीरियेंस 1954-55, अप्रैल 1956 के इकॉनमिक स्टडीज क्वाटलीं (जापान) में प्रकाशित एफ० मैथुलुप का 'दि फाइनांस ऑफ डिवेलपमेंट इन दि पूअर कन्ट्रीज : फारेन कैपिटल एंड होमेस्टिक इन्प्लेशन।'

प्रवृत्ति, m' आयात की सीमांत प्रवृत्ति तथा b' विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति हैं। यहाँ पर $\triangle I$, $\triangle G$ तथा $\triangle E$ गुण बहिर्जनित प्राचल, तथा बचत करने, आयात करने एवं निवेण की सीमांत प्रवृत्तियाँ s', m', b' अन्तर्जनित प्राचल है। $\triangle I$, $\triangle G$ एवं $\triangle E$ का सापेक्षिक महत्त्व विचार की जाने वाली अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति पर निर्मर करता है। अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है कि निर्यात गुण्य $\triangle E$ विकसित अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा अर्थ-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से परिमाणात्मक वृद्धि से अधिक महत्त्वपूर्ण है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि $\triangle I$ एवं $\triangle G$ का सापेक्षिक महत्त्वपूर्ण अवस्थ नीति की परस्परा से प्रस्थान की मात्रा पर निर्भर करता है। वचत, आयात एवं विनियोग की सीमांत प्रवृत्तियाँ अनिवार्यतः अपने औसत प्रतिरूप की ही तरह नहीं है और ने इनका राष्ट्रीय आय से सम्बन्ध ही है। साथ ही, s', m' एवं b' मि विकसित तथा अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से स्पष्ट रूप से अन्तर होता है। यहाँ पर b' को शामिल करने से स्वतं प्रेरिल निवेश के साथ-साथ प्रेरित निवेश की समा-वित उपस्थित भी स्पष्ट होती है।

समीकरण (1) के दोनो पक्षों को Y^a से भाग देने एवं नये क्रम में रखने से, हम समर्थ माँग (G^a) से वृद्धि की दर पाने है:

$$G^{d} = \frac{\triangle Y^{d}}{Y^{d}} = \frac{\alpha + \beta + y}{s' + m' - b'}, \tag{2}$$

जिसमें $\alpha = \triangle I/Y^{\delta}$, $\beta = \triangle G/Y^{\delta}$ और $Y = \triangle E/Y^{\delta}$ के हैं। समीकरण (2) से यह स्पष्ट होता है कि समर्थ माँग-सम्बन्धी वृद्धि की दर राष्ट्रीय आय की तुलना में स्वतः प्रेरित निवेण, सरकारी व्यय एवं निर्यात से प्राप्त आय में परिवर्तन के साथ प्रत्यक्ष रूप में तथा बचत, आयात एवं विनियोग की सीमात उत्पादन-क्षमता के प्रतिक्षोमी दिशा में परिवर्तन होने में सक्षम है। यह वृद्धिणील विवृत्त अर्थ-ध्यवस्था के माँग-पक्ष को बतलाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य वातों के समान रहने पर, राष्ट्रीय आय (y) की तुलना में निर्यात में वृद्धि या आयात की सीमात प्रवृत्ति (m') में कमी होने से समर्थ माँग में वृद्धि की दर में और वृद्धि होगी। किर भी, समर्थ माँग में व्यविक उच्च दर से वृद्धि प्राप्त करना तथा बनाये रखना है अथवा निम्न दर से, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दर, जिसे अभी तन हम स्थिर मानने हैं, के उत्लेख के वर्णर प्रही किया जा सकता है। इस बात पर हम लोग आगे चलकर विचार करेंगे। इसी बीच

देखें, 1951 ई० मे मैकमिलन (न्यू० था०) द्वारा प्रकाशित एच० सी० यालिय की पुस्तक 'मिन, ट्रेड एंड इकॉनामिक धोध' मे 'अन्डरडिवेल्पड कन्ट्रीज एंड दि इण्टरनैशनल मोनेटरी मेकेनिज्म'।

एक विवृत अर्थ-व्यवस्था के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति के लिए दूसरे समीकरण का क्या आजय है, इस पर विचार करना अधिक रोचक होगा।

 $\triangle i = o$, $\triangle G = o$ तथा $\triangle E = i$ मानकर हम लोग प्रेरित आयात से इस निर्यात-सम्बन्धी परिवर्तन की जुलना के लिए निर्यात में परिवर्तन होने के गुणक प्रभाव पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। क्योंकि, हम जानते हैं कि घरेलू आय में निर्यात-जिनत वृद्धि के परिणाम-स्वरूप अतिरिक्त आयात निम्नांकित प्रकार से प्रेरित होती हैं—

$$\Delta M = m' \Delta Y^d = m' \frac{i}{s' + m' - b'} \Delta E = \frac{m'}{s' + m' - b'} \Delta E$$
 (3)

भूगतान-सन्तुलन की साम्यावस्या के मूल स्थान $E-M=\triangle R=0$ (जिसमें M विकलन के अदृश्य मदों को शामिल करते हुए वास्तविक आयात एवं $\triangle R$ विदेशी विनिमय-कोण में कमी या वृद्धि है) से प्रारम्भ करने पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल भूगतान-सन्तुलन उद्गमन तीसरे समीकरण के निम्नलिखित निर्देशनों से स्पष्ट होता है—

यदि o < s' > b' = o, तो $\triangle M < \triangle E$ (अपूर्ण हानिपूर्ति की स्थिति) । यदि o < s' < b' > o, तो $\triangle M > \triangle E$ (अधिक हानिपूर्ति की स्थिति) । यदि o < s' = b' > o, तो $\triangle M = \triangle E$ (समान हानिपूर्ति की स्थिति) ।

इनमें से पहली स्थिति केन्स द्वारा दी गई है तथा जो अधिक क्षमता का मान्यता.पर आधृत है, जो प्रेरित विनियोग को कम या निष्कल बनाती है। इसके परिणामस्वरूप प्रेरित आयात सदा निर्यात में किसी भी मौलिक वृद्धि से कम होता है तथा विदेशी विनिमय कोष में निम्नलिखित रक्रम के वरावर संचयन होता है—

$$\triangle R_n = (\triangle E_{n-1} + E_0) - (\triangle M_{n-1} + M_0).$$

दूसरी स्थिति एक अस्थायी व्यवस्था की ओर संकेत करती है, जिसमें विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति बचत की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक होने की ओर प्रवृत्त होती है। जिस तरह, युद्ध-विनष्ट अथवा अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में, जिनमें पूँजी का आम-तौर पर अभाव पाया जाता है अथवा व्यापार-चक्र की बढ़ती हुई स्थिति, जिसमें निष्कार्य संयत्र एवं उपकरण समाप्तप्राय होते हैं, पाई जाती हैं। अधिक हानि पूर्ति की स्थिति में विदेशी कोप में असंचयन निम्न प्रकार से होता है—

$$-\triangle R_n = (\triangle M_{n-1} + M_o) - (\triangle E_{n-1} + E_o).$$

अन्तिम, यानी समान हानि पूर्ति की स्थिति वचत की सीमांत प्रवृत्ति के विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति के वरावर होने से उत्पन्न होती है, जिससे विनिमय-कोप में न कोई संचयन होता है और न असंचयन ही, जिसमें $\Delta R = o$ । इस अन्तिम स्थिति

को विशुद्ध घरेलू दृष्टिकोण से अपेक्षित नहीं माना जा सकता; क्योंकि इनका तारप्य यह है कि स्वत प्रेरित निर्मात में वृद्धि किसी-न-किसी समय आयात में समान वृद्धि से समाप्त हो जाती है। साथ ही, विकामशील पूँजी के सम्भावित साधन के रूप में विदेशी विनिमय के कोप में भी कोई वृद्धि नहीं होती है। फिर भी, यदि कोई एक अर्थ-व्यवस्था असन्तुलित भुगतान के मूल स्थान से प्रारम्भ होती हो, तो उसके लिए इसे अपेक्षित सममा जा सकता है।

विदेशी व्यापार एव माँग में वृद्धि में इसी प्रकार का पारस्परिक एव अन्मोन्याध्रय-सम्बन्ध है। माँग के साधन के रूप में निर्यात में वृद्धि से चिन्ता केवल इसी-लिए उचित है कि पूर्ति की दी हुई स्थिति में राष्ट्रीय आय में धास्तिविक वृद्धि माँग के ही द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार की चिन्ता बिल्कुल केन्स की परम्परा पर आधृत है, जो इस सस्यापकीय घारणा, कि पूर्ति स्वय अपने माँग का सर्जन करती है, वो अस्वीकार करती है। किर भी, इस प्रकार की चिन्ता बिल्कुल एकपक्षीय है; क्योंकि बिदेशी व्यापारिक सम्बन्ध एक वृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था के पूर्ति-पक्ष को भी प्रमावित कर सकता है। यही पर हमें केन्स की समर्थ माँग की पूर्ण धारणा का परिन्त्या कर पुनः एक बार, से के नियम (Say's Law) के बगैर पूर्ति एव उत्पादकता पर सस्थापकों की दृढ तीवता की ओर उन्मुख होना चाहिए।

विदेशी व्यापार एवं क्षमता में वृद्धि

अव माँग की परिस्थितियों को दिया हुआ मानकर, हम विदेशों व्यापार एवं क्षमता में वृद्धि के अन्य सम्बन्ध का विश्लेषण कर सकते हैं। प्राइतिक साधनों के आकार एवं अस की सख्या दी हुई होने पर, किसी अर्थ-व्यवस्था की कुल पूर्ति अथवा उत्पादन-क्षमता मुख्यतः वास्तविक पूँजी की मात्रा एवं गुण पर निभूर करती है। कुल उपलब्ध पूँजी के पूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

$$\triangle Y^{s} = \sigma \triangle K = \sigma i, \tag{4}$$

जिसमें Y उत्पादन-क्षमता द्वारा निर्धारित शुद्ध राष्ट्रीय निषज अथवा केवल उत्पादन क्षमता है, K पूर्ण उपयोग की स्थिति में पूँजी की मात्रा, । शुद्ध निवेश $(I_i = K_i - K_i - 1)$ एवं σ प्राविधिक रूप में दी गई पूँजी की सीमान्त (ओसत) उत्पादकता ।

किन्तु सामान्यावस्था में, एक विवृत अर्थं-व्यवस्था का शुद्ध विनियोग असा-धारण अर्थ में बचत के बराबर होता है, यानी

$$i=S+M-E; i+E=S+M, (5)$$

ि 🖟 S घरेलू बचत है और अन्य परिवर्ती पहले की ही तरह हैं।

पाँच को चार से प्रतिस्थापित करने पर आयात एवं निर्यात से युक्त उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्राप्त होती है---

$$\triangle Y^{s} = \sigma (S + M - E). \tag{6}$$

पुनः हम S, M एवं E को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं $S{=}sY^s, M{=}m$ $Y^s,$ एवं $E{=}e$ Y^s जिसमें s बचत कम अनुपात, m आयात अनुपात एवं e निर्यात अनुपात हैं, (यानी औसत बचत एवं आयात की प्रवृत्ति तथा दिये हुए आन्तरिक उत्पादन एवं स्वतःप्रेरित निर्यात का अनुपात) उपर्यु क्त परिभाषाओं को ध्यानमें रखते हुए पुनव्यविस्थत करने पर, उत्पादन-क्षमता (G^s) में वृद्धि की निम्नलिखित दर प्राप्त होती है—

$$G^{s} = \frac{\triangle Y^{s}}{Y^{s}} = \sigma (s + m - e), \tag{7}$$

जो एक विवृत अर्थ-व्यवस्था के पूर्ति-पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। समीकरण (7) यह बतलाता है कि जैसे-जैसे पूँजी की उत्पादकता (c) वदलती है और आंतरिक बचत के अनुपात जोड़ व्यापार-संतुलन के अनुपात (s+m-e) बदलते हैं, वैसे-वैसे उपलब्ध पूँजी के पूर्ण प्रयोग से प्राप्त उत्पादन-क्षमता की वृद्धि की दर प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्त्ती होने के लिए सक्षम है। समीकरण (7) का परिचालन-सम्बन्धी महत्त्व निम्नलिखित लोकप्रिय संख्यात्मक उदाहरणों से स्पष्ट होता है—

^{1.} व के मूल्य का अनुमान विकसित एवं अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अभितत पूंजी-निपज अनुपात से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, देखें डक्टयू० फेलर का पूर्व-उद्घृत 'दि कैपिटल आउटपुट रेशियो इन डाइनामिक इकॉनामिक्स'; आई० यामडा का जुलाई, 1956 के इकानामिक रिच्यू में 'दि फाइव ईयर इकॉनामिक प्लान इन जापान ऐंड दि एनालिसिस ऑफ पोस्ट वार जेपेनीज इकॉनामी'; वाई० ओजेकी का मार्च, 1957 के इकॉनामी स्टडीज क्वाटरली में 'ऑन दि कैपिटल-कोएफिसियण्ट इन अंडर डिकेट्पड इकॉनामी लं । विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी निपज अनुपात साधारणतया कम होता है, जिससे श्रेष्ट टेक्नोलॉजी पर आधृत पूँजी गुणक की अधिक क्वमता का आभास होता है। तुलनात्मक वचत-अनुपात के लिए देखें 'एस० कुजनेण्ट्स का पूर्व-उद्धृत इकॉना-मिक ग्रोथ ऐंड इनकम इनइक्वेलिटी'। जहाँ तक कि निर्यात एवं आयात-अनुपात का सम्बन्ध है, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की निम्न उत्पादन एवं निर्यात-क्षमता इनके निर्यात-अनुपात के आयात-अनुपात के निरन्तर अधिक होने की एक आवश्यक प्रकल्पना है। निरपेक्ष रूप में तुलनात्मक निर्यात-आयात-अंकों प्रेच वालिच का पूर्व उद्धृत लेख देखें।

यदि ठ== '5, s=='10, m=='05, e=='07, तो G'=='04 (विकसित अर्थ-व्यवस्था)

यदि $\sigma = 2$, s = 05, m = 015, e = 10, तो G' = 02(अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था)

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि उच्च पूँजी-उत्पादकता गुणक एक उच्च बचत अनुपातवाली विकसित अर्थ-च्यवस्था धनात्मक विदेशा सतुनन-अनुपात (e-m>0) ढारा उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त कर सकती है। इसके विपरीत निम्न उत्पादकता एव निम्न बचतवाली एक अल्प-विकसित अर्थ-च्यवस्था ऋणात्मक विदेशी सतुलन-अनुपात (e-m ∠0) के परिणामस्वरूप उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की निम्न दर ही प्राप्त कर पाती है। ये इस बात को भी लक्षित करते है कि यदि एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में उसकी माँग से अधिक वृद्धि होती है, तो इससे उसके धनात्मक विदेशी सतुलन अनुपात में अवश्य वृद्धि होगी और यदि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की क्षमता में उसकी माँग की तुलना में धीरे-धीरे वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती हो, तो इससे उसके ऋणात्मक विदेशी सतुलन-अनुपात में अवश्य वृद्धि होगी।

इस प्रकार, प्रकल्पना है कि एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में साधारणतथा अनुकूल भुगतान-सतुलन होता है, जो $eY'-mY'=\triangle R>0$ से स्पष्ट होता है जब कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में व्यवहारत प्रतिकूल भुगतान-संनुलन होता है, जो $eY'-mY'=\triangle R \angle 0$ से जात होता है। किन्तु, इसका ताल्पय यह नहीं कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को संतुलित भुगतान-सतुलन को घ्यान में एखें वर्गर अपनी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि का प्रयास नहीं करना चाहिए; बयोकि आगे का विश्लपण इसके ठीक विपरीत बतलाता है। अब स्फीति एवं असतुलन के वर्गर सतुलित विकास की प्राचलीय क्रिया पर विचार किया जाय।

सतुलित विकास के लिए प्राचलीय कियाएँ

सतुनित विकास आगे बढने की आदर्श नीति है, जो पूर्ण होने पर ऐसी बढती हुई वास्तिवक आय की गारन्टी प्रदान करता है, जो न बढते हुए मूल्य से कम होती है, न भुगतान के सतुनन की दीर्घकालिक कठिनाइयों से ही समाप्त होती है। पूर्ववर्त्ती विक्लेपण से यह स्पष्ट है कि सतुनित विकास की स्थित को प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिए निम्नलिखित आधारभूत शर्त की पूर्ति अनिवार्य है।

$$\frac{\alpha + \beta + \gamma}{s' + m' + b'} = \sigma (s + m - e) \text{ at } G^d = G^s$$
(8)

समीकरण (8) यह बतलाता है कि यदि $G^a = G^s$ के, ितो मौद्रिक राष्ट्रीय आय $(Y^a m)$ में निम्नलिखित घातीय रूप में वृद्धि होगी—

$$Y^{d} = Y^{d} = P(t) Y^{s} = Y^{d} (1+g_{m})^{t},$$

$$mo$$

जिसमें P समय में मूल्यसूक्ष्म हैं, Ymo^d मौद्रिक आय का प्रारम्भिक मूल्य है, और gm मौद्रिक आय में वृद्धि की दर $(\triangle Ym^d/Ym^d)$ है। यदि अर्थ-व्यवस्था $G^d=G^s$ संतुलन की प्रारम्भिक स्थिति से बढ़ी हो, तो t>0 समय में, $G^d>G^s$ के रूप में एक आकस्मिक आघात पूर्ण क्षमता-विकास के अपरिवर्त्ती पथ से स्फीतिजनक अन्तर की सृष्टि करेगा। जैसा कि दूसरे समीकरण से स्पष्ट है $G^d>G^s$ के रूप में प्रारम्भिक आघात α , β , γ या B' में साधारणतया स्थायी वृद्धि अथवा विकल्पतः s' एवं m' में इसी प्रकार की कमी के परिणामस्वरूप हो सकता है। $G^d>G^s$ की स्थिति केवल स्फीति की ओर की निरन्तर प्रवृत्ति का ही नहीं, वरन् भुगतान-संतुलन की दीर्घकालिक कठिनाई का भी सूचक है। क्योंकि, उच्च G^d से बड़े पैमाने पर प्रेरित आयात तथा निम्न G^s से छोटे पैमाने पर किये। गये निर्यात की सम्भवना का बोध होता है।

इससे प्रमन यह होता है कि $G^a > G^a$ के रूप में विषमता से युक्त एक विवृत अर्थ-व्यवस्था इस विषमता में निहित सांतरिक स्फीति एवं बाह्य असंतुलन को किस प्रकार से दूर कर सकती है ? इसका सामान्य उत्तर यह है कि यदि $G^a = G^a$ के रूप करना है, तो G^a में साथ-ही-साथ कमी किये वगैर G^a में कमी, या G^a में वृद्धि के वगैर G^a में वृद्धि की जाय । यह वास्तव में एक बड़ी वात है, किन्तु फिर भी समीकरण (8) हारा व्यक्त शर्तों की पूर्ति के लिए दूसरे तथा सातवें समीकरणों के प्राचल के साथ समावित कियाओं का पता लगाया जाय ।

समर्थ माँग का नियंत्रण

 G^d को कम करने की परिचालन-सम्बन्धी सम्भावना, विदेशी भुगतान-जेप के संतुलन को भंग किये वग्रैर आंतरिक आधिक उन्नित को पोषित करने के मूल उद्देश्य से आवश्यक रूप में सीमित है। इस सीमा को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्जनित प्राचल s', m' एवं b' को दिया हुआ मानकर, पहले बिहर्जनित प्राचल α , β एवं γ में कमी की सम्भावना पर विचार किया जाय।

किसी दिये हुए राष्ट्रीय आय के स्तर पर, स्वतः प्रेरित निवेश की कितनी मात्रा से सरकारी व्यय या निर्यात संबंधी आय में कमी होगी, यह गुणक तथ्रा सम्बद्ध समर्थ मांग में वांछित कमी पर निर्भर करता है; क्योंकि पहले समीकरण से हम यह जानते हैं कि इनमें से किसी भी गुण में इच्छित कमी निम्नलिखित रूप से स्पष्ट होती है : $\triangle I = \triangle Yd/k$, $\triangle G = \triangle Yd/k$, अथवा $\triangle E = \triangle Yd/k$ जिसमे, $k = i/(s^1 + m^1 - b^1)$ । उदाहरण के लिए, मान लिया जाय कि $s^1 = 0.05$, $m^1 = 3$, $b^1 = i$, $\triangle Yd = i$ है, तो $\triangle i = Yd/k$ के अनुसार मींग के सम्बन्ध साधन के रूप में स्वतः प्रेरिन निवेश में 1/4 = 25 से कमी होगी। अन्य किसी भी गुण्य के लिए यही सत्य होता है।

इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण यह है कि माँग के किसी विशेष साधन में कभी के लिए चुनाव-भुगतान शेप तथा उत्पादन-क्षमता के दीर्पकालिक विकास के सम्मावित प्रतिपात से प्रभावित होना चाहिए। जहाँ तक भगतान शेष का सम्बन्ध है, अन्य बातों के समान रहने पर, मांग के किसी दिये हुए स्तर (प्र) से सम्बन्ध निर्यात मे स्वत. प्रेरित कभी बाह्य असतुलन को उसेजित किये वगैर Gd में कभी करेगी। किन्तु, ऐसा तभी होगा, जबिक साय-ही साय b' से सम्बद्ध s' में भी वृद्धि ही। किन्त, चूंकि Y में परिवर्तन का ड'पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, अतएव Y में कसी अधिक मांग को अवसदित करने के लिए भुगतान क्षेप की संतुलित करने के उद्देश्य के अनुरुप समभक्तर छोड देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूँकि किसी एक अर्थ-स्यवस्था के निर्मात की मांग मुख्यत दूसरे देशों की आय के स्तर पर निर्मर करती है, इसलिए कोई भी एक अर्थ-स्वतस्या y से अपने इच्छानुसार हेर-फेर नहीं कर सकती है। (केवल संयुक्तराज्य के सम्भावित अपवाद को छोड़कर, जो अपने निर्मात नी दिदेशी मांग को ऋण एवं अनुदान के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है, जैसा कि मार्गल प्लान ने स्पष्ट कर दिया था) । जहाँ तक उत्पादन-धमता में दीर्घकालिक वृद्धि का सम्बन्ध है, α अथवा β में कमी, यदि यह स्वतः प्रेरित निजी निवेश के अनुस्पादक अग अथवा राजकीय व्यय (जैसे पिरामिट का निर्माण अथवा शस्त्रीकरण) में कमी के द्वारा की जाती है, से पूँजी की उत्पादन-क्षमता म (σ) कमी नहीं होनी चाहिए। यदि α अथवा β में कमी महेंगी मुद्रा-नीति के डारा हुई हो, तो यह उत्पादन के चकदार तरीके की हनोत्साहित कर सकती है और इस प्रकार दीर्घकाल में पूँजी की उत्पादकता में कमी कर सकती है। (यह अतिम प्रभाव थम की उत्पादन-क्षमता पर सभवतः पुँजी एव धम के निम्न अनुपात के माध्यम से पड़ता है, जैसा कि Y/K = (Y/N)/(K/N) से स्पष्ट है।

अव σ, β एवं Y को दिया हुआ मानकर तथा भुगतान घोप एवं उत्पादन अमता में दीर्घकालिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हम समर्थ मौंग को नियत्रित करने के उद्देश्य से ही s', m' एव b' की सम्भावित कियाओं का अध्ययन करेंगे।

s' में वृद्धि के द्वारा भुगतान-श्रेष के सतुलन को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन-क्षमता में विस्तार के उद्देश्यों को समाप्त किये वर्णर Gd में कमी की जा सकती है। वर्षोक, जैसा कि पूर्व विश्लेषण से स्पष्ट है, एक और $s' \leqslant b'$ से

 $\triangle M \leq \triangle E$ होता है तथा दूसरी ओर s' में समान वृद्धि से दीर्घकाल में s एवं c में वृद्धि होती है और इस प्रकार m > e के अनुपात में बड़े वाह्य घाटे पर अत्यधिक निर्भरता के वगैर Gs में वृद्धि होती है। इस सम्बन्ध में यहाँ एक आवश्यक आरक्षण यह है कि s' में वृद्धि के उपाय, उपभोग में मितन्ययिता को आवश्यकता से अधिक वतलाने के कारण, अनुचित सिद्ध हो सकते हैं।

बचत की सीमांत प्रवृत्ति के निवेश की सीमांत प्रवृत्ति के वरावर अथवा अधिक होने की स्थिति में आयात की सीमांत प्रवृत्ति m' में वृद्धि भी अपेक्षित हो सकती है। क्योंकि, जैसा कि पूवर्वाणत है, $s' \leqslant b'$ से $\Delta M \ge \Delta E$ होता है। m' वृद्धि से Gd में कमी के अतिरिक्त दीर्घकाल में m में वृद्धि होती है, जिससे Gs की वृद्धि में भी सहायता मिलती है। पुनः यदि उच्च m' का, आय विपाक में किसी क्षितिपूर्ति के परिणामस्वरूप, प्रविस्थापन विपाक उत्पादित उपभोक्ता की वस्तुओं की माँग में ह्यास होता है, तो इससे उस स्तर तक s' एवं s में वृद्धि होगी, जिससे Gd में कमी तथा Gs में और अधिक वृद्धि होगी।

निवेश को सीमांत प्रवृत्ति, b' में कमी पर भी एक वैकल्पिक परिचालन-सम्बन्ध सम्भावना के रूप में विचार किया जा सकता है। b' में हास भुगतान-शेष की स्थिति को और खराव किये वगैर Gd' में कमी उत्पन्न करता है; क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि शून्य या लघु b' से केन्स के अपूर्ण क्षति-पूर्त्त के सिद्धांत की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। साथ ही, चूँकि b' में हास ऐसे उपायों द्वारा किया जाता है, जिनका उद्देश्य नबीन किया-निवेश के क्षेत्र में वृद्धि तथा प्रेरित निवेश में अस्थिधक निभैरता में कमी (त्वरण-सिद्धांत की तरह) होता है, अतएव इससे दीर्घकाल में σ में वृद्धि होती है ॥

इस प्रकार, Gd>Gs से उत्पन्न स्फीतिजनक परिस्थितियों में, भुगतान-शेष के असंतुलन को प्रोत्साहित तथा उत्पादन-क्षमता में दीर्घकालिक विकास में वाधा उत्पन्न किये वगैर माँग में वृद्धि को निम्नलिखित उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है—(1) s' में वृद्धि, (2) m' में वृद्धि, (3) b' में ह्रास, (4) ω में ह्रास, (5) β में ह्रास तथा/या (6) γ में ह्रास । उत्पादन-क्षमता में नियंत्रण का अभी वर्णन करना वाकी है।

उत्पादन-क्षमता का नियंत्रण

उत्पादन-क्षमता के विकास की दर में वृद्धि निश्चय ही समर्थ माँग में विकास की दर में कमी की तुलना में अधिक किठन है। यह किठनाई प्राचलीय किया पर इस निरोध पर कि Gs में इस प्रकार से वृद्धि नहीं करनी चाहिए, जिससे Gd में वृद्धि हो तथा $\triangle R < o$ हो जाय, के परिणामस्वरूप और भी वढ़ जाती है। इस प्रतिवंध

को ध्यान मे रखते हुए समीकरण (7) की सम्भावित प्राचलीय किया की खोज की जाय।

पूँजी की कार्य-क्षमता (०) में वृद्धिका लाभ माँग में वृद्धिके आत्माघाती सहायक तथा बाह्य श्रीप की स्थिति को और अधिक खराव किये वगैर Gs की स्थिति को बढाना होता है। वयोकि, यह एक दी गयी पूँजी के कोप के अधिक योग्य उपयोग, न कि पूँजी में वृद्धि, जिससे अनपेक्षित माँग का सर्जन हो अथवा अनपेक्षित आयत की आवश्यकता हो, के द्वारा अधिक उत्पादन एव निर्मात-सम्बन्धी क्षमता को सूचित करता है। हम इसे निम्नाकित प्रकार से देख सकसे है।

मान लिया कि पूँजी का सपूर्ण कीय (K) दो भागों में विभवत है—एक वह, जो स्वदेश-प्रधान उद्योगों, यानी जो केवल घरेलू बाजार की आवश्यक्ताओं की पूर्ति करते हैं, के द्वारा स्वीकृत तथा प्रयोग किया जाता है (Kh), तथा दूतरा वह, जो नियंति-प्रधान उद्योगों, यानी जो केवल विदेशी बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, के द्वारा स्वीकृत तथा प्रयोग किया जाता है (Ke) है । अतएव—

$$K = Kh + Ke, \tag{9}$$

जिसके वितरण का अनुपात है-

$$\frac{K_{\lambda}}{K} = \eta, \frac{K_{\delta}}{K} = I - \eta. \tag{10}$$

पुन. हम उत्पादन-क्षमता (Y^s) को स्वदेश प्रधान-विपज (Y_s^s) तथा निर्मात-प्रधान निपज (Y^s) के योग के रूप मे परिभाषित कर सकते हैं, जिससे—

$$Y^s = Y_h^s + Y_s^s, \tag{11}$$

इस समीकरण के दाये पक्ष को निजेप रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है-

$$Y_{b} = \sigma_{b} K_{b}. \tag{12}$$

$$Y_{e}^{s} = \sigma_{e} K_{s}, \tag{13}$$

जिसमें ०, समस्त स्वदेश-प्रधान उद्योगों की पूँजी की औसत एवं सीमान उत्पादकता तथा ०, निर्यात-प्रधान उद्योगों में पूँजी की औसत तथा सीमात उत्पा-दकता हैं।

यहाँ हम इस स्वीकार्य आधार पर कि ह्नास-मान लागत (वर्द्धमान-प्रतिफल) वाले उद्योगों को स्वदेणी बाजार के साथ-साथ साधारणतया वृद्धि-शील निर्यात-वाजार (विशेषत वृद्धिशील स्वदेशी सीमा तथा बाजार के अभाव में) की आवश्यकता होती, $\sigma_e > \sigma_b$ मानते हैं। यह मान्यता वितरण के अनुपात, $I - \gamma$ में वृद्धि के पक्ष में वर्तमान तर्क प्रस्तुत करने एवं सपूर्ण अर्थ-स्यवस्था के लिए पूँजी की उत्पादकता तथा निर्यात-प्रधान उद्योगों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए निर्णायक महत्त्व का है।

अब 10वें, 12वें तथा 13वें समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, हम 11वें समीकरण को पुन: इस प्रकार लिख सकते हैं—

$$Y^{s} = \sigma_{h} K_{h} + \sigma_{e} K_{e} = \sigma_{h} \eta K + \sigma_{e} (i - \eta) K. \tag{14}$$

14वें समीकरण से संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी की औसत उत्पादकता प्राप्त होती है---

$$\frac{Y^s}{K} = \sigma = \sigma_h \eta_i + \sigma_\theta (i - \eta_i), \tag{15}$$

जिससे यह स्पष्ट होता है कि $\sigma_e > \sigma_k$ होने पर, संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूंजी की औसत उत्पादकता वितरण के अनुपात $(i-\eta)$ में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि के सक्षम है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वितरण के अनुपात $(i-\eta)$ में इस वृद्धि से निर्यात-प्रदान-निपज में भी $Y_e^* = \sigma_e(i-\eta)K$ के द्वारा वृद्धि होती है। साथ ही, पूंजी-उत्पादकता गूणक (σ) में वृद्धि का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि स्वदेशी वचत अनुपात (S) को संपूरित करने के लिए छोटे आयात-अनुपात (m) की आवश्यकता पड़ती है।

वचत-अनुपात (s) में वृद्धि से m यदि इससे m में भी वृद्धि का प्रतिनिधित्व होता है, G_s में वृद्धि हो जिससे समर्थ-माँग में वृद्धि की दर कम हो जाय, तो यह G_s में साथ-ही-साथ वृद्धि के वग़ैर G_s में वृद्धि कर सकता है। साथ ही, सातवें समीकरण के अनुसार, उच्च पूँजी उत्पादकता की ही तरह, उच्च स्वदेशी वक्त-अनुपात स्वदेशी वास्तिविक पूँजी के संपूरक के रूप में आयात पर निर्भिता में कमी करता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उच्च वचत-अनुपात उच्च

^{1.} किन्तु, निर्यात-संबंधी वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि से निर्यात की माँग में आवश्यक रूप से वृद्धि नहीं होती; क्योंकि निर्यात विदेशी आय, सापेक्षिक मूल्य विनिमय-दर एवं संभवतः ग्रीर-आधिक वैदेशिक नीति पर निर्मर करता है। आर० नम्सें ब्रिटेन के निर्यात उद्योगों में इस प्रकार की वृद्धि की सिक़ारिश करते हैं, यह अधिक-से-अधिक उस विशेष परिस्थिति का परिचायक है, जिसमें यू० के० (U.K.) से निर्यात की विदेशी माँग ठीक उसके अनुरूप होगी जिसकी ब्रिटेन पूर्ति कर सकता है। किन्तु अधिकांश व्यापारी राष्ट्रों (जैसे जापान) के साथ प्रधान किनाई निर्यात की क्षमता का अभाव न होकर विदेशी वाजार (माँग) का अभाव है। अतएव, निर्यात-प्रधान उद्योगों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि, संपूर्ण एवं विकास के क्षेत्र में योगदान करते हुए भी वृद्धिशील विदेशी वाजार के अभाव में निराशजनक सिद्ध हो सकती है।

बचतवाले आय-वर्गों के पक्ष में स्वायत्त आय के पुनर्वितरण या लगातार वजट-आधिन्य का परिणाम होता है।

यदि आयात-अनुपात (m) मे वृद्धि m' मे वृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो इससे G_a मे वृद्धि के वर्गर G^a मे वृद्धि हो सकती है । किन्तु दीर्घ-कालीम भुगतान-भेष के संतुलन के दृष्टि-कोण मे उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की औसत प्रवृत्ति (mc) को स्थायी रखकर पूँजीयत वस्तुओं के आयात की औसत प्रवृत्ति (mi) मे वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहिए। वयोक्ति, आयात-अनुपात वास्तव मे इन्ही प्रवृत्तियों का योग है, यांनी m=mc+m। इसका तात्पर्य यह है कि यदि m स्थायी है, तो mा मे वृद्धि mc मे कभी के द्वारा हो होगी। और यदि =mc के स्थायी है तो m मे वृद्धि mi मे वृद्धि का मूचक है। यदि m मे वृद्धि को जगह mc की जगह mi मे वृद्धि का परिणाम है, तो यह स्वदेशी पूँजीयत वस्तुओं के ज्योग में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगा। ध्यापारिक नीति के सदम में इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि मुल्क-दर तथा अन्य प्रकार के आयात-नियशण की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की सीमात प्रवृत्ति में किसी प्रकार की वृद्धि न हो।

अतत' एक दिये हुए m की तुलना में e में हास से, Gu में वृद्धि के अन्य उद्देश्यों का विरोध किये वर्गर, Gs में वृद्धि होगी; क्योंकि अति अल्पकाल में e में हास प्र में हास का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर भी, e में इस हास का भुगतान ग्रेप के समुलन पर हानिकारक प्रभाव पड सकता है। कोई एक अर्थ-व्यवस्था अपने दीर्घकालीन भूगतान समुलन की स्थित को सुरक्षित करने के लिए अधिक-से-अधिक Y में वृद्धि के e पर वृद्धिशील प्रभावों पर आश्वित रह सकती है। इससे Gs में वृद्धि के लिए, अन्यया बड़े घोटे के अनुपात e—m<0 की टाला जा सकता है। इससे अधिक एक अकेला निर्यातक देश केवल यह आशा कर सकता है कि दिये हुए सापेक्षिक मूल्य एवं विनिमय-दर पर शेप विश्व अपनी आय अथवा अपनी आयात की औसत प्रवृत्ति में वृद्धि करेगा। एक दिये हुए m की सुलना में e में किस मात्रा तक कमी होनी चाहिए, यह o एव s के प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करता है; क्योंकि जब कोई अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था अधिक उत्पादक एवं मितव्ययी हो

श्री इसका नात्पयं यह नहीं कि आयात की गई उपभोक्ता-बस्तुएँ अनुत्पादक होती है, क्योंकि ये चैसे उत्पादक साधनों को. जो अन्यया उपभोक्ता-बस्तुओं के उद्योग में लगे होते हैं, मुक्त कर स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों को परोक्ष स्प में योगदान देती है। किन्तु साधनों की सापेक्ष निश्चलता एव अपर्याप्त विनिमय-कोपवाली अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात पर ध्यान केंद्रित करना ही अधिक व्यावहारिक और महत्त्व की बात है।

जाती है, तो यह अपनी उत्पादन क्षमता को अपने निर्यात से अधिक विदेशी वस्तुओं एवं पूँजी के आयात के वग्रैर ही विकसित कर सकती है।

अंतिम टिप्पणी

एक विकासोन्मुख अर्थं-व्यवस्था के केवल माँग-पक्ष पर जोर देने का तात्पर्य विदेशी व्यापार के क्षमता-सर्जनात्मक पहलू, जिसकी चर्चा आदमस्मिथ के 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' से अब तक के संस्थापक सिद्धांतों में मिलती है, की उपेक्षा करना होगा । इसी प्रकार केवल पूर्ति-पक्ष पर जोर देने का तात्पर्यं विदेशी व्यापार के आय-सर्जनात्मक पहलू की, जिसे केन्स के सिद्धांतों ने वताया है, अपेक्षा करना तथा संस्थापकों की 'पूर्ति' स्वयं अपनी माँग का सर्जन करती हैं—"इस बात की मान्यता-संबंधी भूल को दोहराना है । तदनुकूल पूर्ण रोजगारी (श्रम एवं पूँजी दोनों की) के साथ, किन्तु आंतिरक स्फीति एवं वाह्य असंतुलन के वग्नैर संतुलन विकास की प्राप्ति एवं उसे बनाये रखने के लिए समर्थ माँग एवं उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दरों को एक-दूसरे के समरूप बनाना अनिवायं है । $G^d > G^d$ से उत्पन्न स्फीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने माँग में वृद्ध-संबंधी समीकरण एवं अमता में वृद्ध-संबंधी समीकरण की संभावित प्राचलीय संक्रियाओं का पता लगाया है, जिससे Gd = Gs होता है, यानी उन उपायों एवं साधनों का पता लगाया है, जिससे कि Gs में कमी किये वग्नैर Gd में कमी तथा Gd में साथ-ही-साथ वृद्धि के वग्नैर Gs में वृद्धि की जा सकती है ।

यदि स्वदेशी विकास एवं भुगतान-शेप संतुलन के बीच निश्चित रूप में चुनाव करना हो तो अधिकांश अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ पिछले की तुलना में पहले को ही अधिमान देगी। इसके कारण भी स्पष्ट हैं। क्षमता में वृद्धि धीरे-धीरे उन्नतिशील भुगतान-संतुलन की एक प्रकल्पना है, किन्तु भुगतान-शेप की समस्याओं में अत्यधिक पूर्वग्राह्मता से संपूर्ण उद्योगीकरण की जगह विनिमय उपार्जन-संबंधी उद्योगों के एक पक्षीय विकास को प्रोत्साहन मिलता है। उपनिवेशी इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं।

अपूर्ण रोजगार की ही तरह, अल्प विकास की मुक्त ग़ैर-भेदमूलक ब्यापार के विरुद्ध एक प्रवल प्रकल्पना है। क्योंकि, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ सदा स्वदेशी उद्योगों को, विदेशी वस्तुओं की वास्तविक या संभावित प्रतियोगता से सुरक्षित रखने का प्रयास करतीं हैं और ऐसा करना साधारणतया उनके लिए उचित भी होता है। फ्रेडरिक लिस्ट के संक्षरण के द्वारा उद्योगीकरण के सिद्धांत में सत्य की यही प्रधान मात्रा है जिसे हावेल्मो (Haavelmo) के वाक्यांग "अंतर्राष्ट्रीय सम-

^{1.} देखें इनकी पुस्तक 'दस नेशलन सिस्टम देर पोलिटिशन ओकनोमी।,

^{2.} टी. हावेल्मो, 'ए स्टडी इन दि थियरी ऑफ इकोनामिक इवोल्युशन, ।

स्थितिकरण के उद्देश्य की पूर्ति के सदर्भ मे मुक्त व्यापार के समर्थकों के अतिरिक्त सभी स्वीकार करते हैं। विश्व के अल्प-विकसित क्षेत्रों को विकसित किये वगैर बहु-पक्षीय व्यापार की आणा करना उतना ही निष्फल है, जितना कि सर्वव्यापी पूर्ण रोजगारी को प्रोत्साहित किये वगैर मुक्त व्यापार की वर्षी करना निर्यंक है। इस अतिम तथ्य का हम तोगों ने अभी के स्त के सिद्धात में अध्ययन किया है। इस सबध में यह स्मरण करना शिक्षाप्रद होगा कि केन्स के निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्धा कोष को पूर्ण रोजगार की नीति से सम्बद्ध किया था। साथ ही, उसने विश्व वैत के एक प्रधान रूप में, विश्व के साधनों को सपूर्ण मानवता के लिए और अच्छी तरह में उपलब्ध बनाना तथा इस उद्देश्य से अपनी कियाओं को इस प्रकार सपादित करना माना था, जिससे सभी सदस्य-राष्ट्रों के अतर्राष्ट्रीय भुगतान श्रेप के सतुलन में बृद्धि हो सके। अब हमारा विश्लेपण यह सूचित करना है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को भुगतान-श्रेप के असंतुलन के अनुचित मय के वगैर, उद्योगीकरण के कार्यंकम को चलाना चाहिए। "

देखें, 23 मई, 1944 को हाउस ऑफ लाइंस के समक्ष केन्स का व्याध्यान तथा
 जुलाई, 1944 ई० को वरहं-वैक पर द्वितीय आपोप की प्रथम वैठक में उसकी प्रारंभिक चर्चा।

उद्योगीकरण के सभावित विरोध के सवध में हम निम्नलिखित विशेष 2. टिप्पणी कर सकते हैं . (1) उद्योगीकरण के परिणाम-स्वरूप निर्मित वस्तुओ का अधिक उत्पादन तथा निर्यात से आयात (या उद्योगीकरण अर्थ-व्यवस्था के निर्पात) के लिए विदेशी माँग के आय का लचीलाएन इकाई से भी बहुत अधिक बढ जायगा $(\triangle M_w/M_w)/(\triangle Y_w/Y_w)>1$, जिसमे Mwभोप विश्व का आयात तथा Yw इनकी सम्मिलित राष्ट्रीय आय है। ऐसी स्थिति में निर्यात करने वाली अर्थ-अयवस्था अपने विदेशी संतुलन में सभवतः अत्यधिक अस्थायित्व और विशेषतः सपूर्णं विश्व की राष्ट्रीय आय में कभी आने पर अपने निर्यात में अत्यधिक हानि का अनुभव करेगी। (2) गरि उद्योगीकरण की ओर उन्मुख अर्थ-व्यवस्था के आयात मे पूँजीगत मालों की प्रधानता है, तो आयात को आय मे परिवर्तन की दर पर आश्रित माना जा सकता है, यानी $M_L = \beta \triangle Y$, जिसमें M_L पूँजीयन बस्तुओं का आयात तथा β सम्बद्ध पूँजी-निपज का अनुपात (आयातित पूँजीगत मालो की उत्पादकता का उल्टा) है। इस आयात-सवधी समीकरण के दोनो पक्षों को Y से भाग देने पर निम्नलिखित आयात अनुपात मिलता है : $M_{*}/Y = eta(igtriangle Y/Y)$ इससे स्पष्ट है कि स्वदेशी आय वृद्धि की दर से बढ़ने से आयात-अनुपात मे एक दिये हुए निर्यात-अनुपात (E/Y) से अधिक वृद्धि हो सकती है, जब तक कि पूँजी-निपज अनुपात (P) में आयातित पूँजीगत मालों की बढ़ती हुई उत्पादकता से

कमी न हो जाय । (3) श्रम की वढ़ी हुए उत्पादकता के परिणाम-स्वरूप मौद्रिक मजदूरी की उच्च दर से शीसत वायात-मूल्य (P_m) की तुलना में शीसत निर्यात-मूल्य P_e में वृद्धि हो सकती है, जिससे निर्यात में कमी तथा आयात में वृद्धि होगी । यह अंतिम प्रभाव $\Delta m = m \Delta Y = mk \cdot \Delta E$, के माध्यम से होता है, जिसमें k' विदेशी ज्यापार गुणक, t = Pe/Pm या ज्यापार की शतों का सूचनांक तथा E निर्यात हैं। किन्तु t में इस प्रकार की वृद्धि साधारणतया निर्यातकों को सरकारी उपदान, अथवा निर्यातकों के बीच निर्यात मूल्य नहीं वढ़ने के एकाधिकार-संबंधी समक्षीते के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। (4) पूर्ण रोजगार-के विन्दु तक निर्यात-प्रधान उद्योगों के विस्तार से सामान्य मूल्य (निर्यात मूल्य-सहित) में वृद्धि होती है, जो निर्यात-व्यापार के लिए हानिकारक होता है। किन्तु इन्हीं के पूर्ण रोजगार के विन्दु से कम विस्तार से स्वदेशी वास्तविक आय एवं प्रेरित आय में वृद्धि होती है और आयात के लिए विदेशी माँग की कीमत-लोच जितनी श्रीक तथा आयात की स्वदेशी सीमांत-प्रवृत्ति जितनी ही उच्च होगी, विदेशी संतुलन पर इसका गुद्ध प्रभाव उत्तन ही प्रतिकृत होगा।

अध्याय 11

केन्सीयोत्तर विकास-सिद्धांतों पर उपसंहार

इस अध्याय में हम पूर्वगामी अध्यायों में विकसित सिद्धान्त की अन्य केन्सी-योत्तर विकास के सिद्धान्तों से तुलना कर, इसे समाप्त करेंगे। यह सुलना इस बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से की जायगी कि इनमें प्रमुख अन्तर कहाँ से पाये जाते हैं तथा ये अन्तर, कहाँ तक अल्प-विकमित देशों के आधिक विकास से सम्बन्ध रखते हैं। यह तुलना दो शीपंकों के अन्तर्गत की जायगी: (क) राज्य के विकासात्मक कार्य, तथा (ख) सन्तुलित विकास की प्रकृति एवं यत्र।

राज्य के विकासात्मक कार्य

हमारे विचार मे, सबसे पहिले अल्प-विकसित देशों के निशेष सन्दर्भ में, केन्स के नाम से सम्बद्ध राज्य के स्थायित्व प्रदान करने के कार्य को, इससे विकासारमक कार्य से, पहिले की अपेआ और अधिक पैमाने पर, मिलाना चाहिए। हैरोड, डोमर एवं रॉबिन्सन के अबध-विकास-सम्बन्धी माडलों में इस बात को स्पष्ट करने का निर्धेधारमक गुण पाया जाता है कि किसी अर्थ-व्यवस्था के दीर्घकालिक विकास को, निजी बचत एवं निवेश की मरजी, लाभ से प्रेरित आविष्कार एवं नवीन त्रियाओं के संयोग तथा बाजार की अनियन्त्रित शक्तियों की कार्यवाही पर छोड़ना, कितना अनिश्चत एवं निष्फल है। इन सभी विकास मॉडलों से अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को यह सकारात्मक शिक्षा मिलती है कि आज की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्थाओं को यह सकारात्मक शिक्षा मिलती है कि आज की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्थाओं के अवध नीति के बातावरण में जिस गति से विकास किया था, उससे यदि इन अर्थ-व्यवस्थाओं का अधिक प्रभाव-पूर्ण एवं इत्नाति से उद्योगीकरण करना है, तो राज्य को केवल स्थायित्य प्रदान करने बाले कार्यों के रूप में ही नही, वरन् विकासात्मक कार्य करने चाहिए।

अधिक स्पष्टतः, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को हैरोड के स्वतःप्रेरित निवेश-अनुपात (k) पर उससे अधिक गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा, जितना कि वह स्वयं एक विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में करता है। क्योंकि, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में, जैसा कि हैरोड स्वेच्छा से मान लेता है, स्वतः प्रेरित निवेश अनिवार्यतः केवल एक आय-उत्पादक, वचत को समाप्त करने वाला शस्त्रीकरण-सम्बन्धी व्यय ही नहीं, बरन सम्भवतः क्षमता-वर्द्धक सार्वजनिक निवेश-सम्बन्धी व्यय है। स्वतः प्रेरित निवेश के निर्णायक महत्त्व को कम आंकने से ही हैरोड के निजी निवेश को अभिप्रेरित करने के लिए आय में विद्व की अपेक्षित दर को महत्त्व दिया है। अल्प-विकसित परिस्थितियों में, जहाँ किसी प्रकार भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादक निवेश लाने के लिए निजी अभिप्रेरणा एवं जोखिम बहन करने की वहत न्यूनता होती है, वहाँ, स्वतःप्रेरित निजी निवेश का प्रेरित निवेश पर समावेग, अन्यथा असहा बोक्त को बहुत कम कर देता है। यह दिखलाया जा चुका है कि स्वत:प्रेरित निवेश को हटा देने के परिणाम-स्वरूप, हैरोड के अवस्फीति सकाव को विकास-समीकरणों में स्पष्ट सार्वजनिक नीति-सम्बन्धी प्राचल के रूप में स्वतःप्रेरित निवेश को अपनाने से दीर्घकालिक विकास के प्रारम्भ करने वाले आधार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सरकारी निवेश के रूप में निर्दिण्ट किया हुआ रहने पर स्वतःप्रेरित निवेश उन वाह्य मितव्ययिताओं के सर्जन का कारण होता है, जो निजी उपक्रम को प्रोत्साहित करने तथा सामान्य उत्पादकता की बढाने में वहत अधिक सहायक होती हैं। निजी प्रकृति के स्वतः प्रेरित निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक प्रकृति के निजी निवेशों को वहत अधिक स्यायी होने का अतिरिक्त लाभ होता है।

डोमर द्वारा जोर दी गई निवेध की दुहरी प्रकृति ऐसी अल्प-विकसित अर्थट्यवस्था के सन्दर्भ में, जो राज्य को केन्सीयन तरीके से वचत एवं निवेध को नियंत्रित
करने का कार्य सौंप देती है, एक नया अर्थ-ग्रहण कर लेती है। क्योंकि, केवल अवंध
वचत एवं निवेध की मान्यता पर ही निवेध के क्षमता-सूचक सर्जनात्मक पहलू को
अधिकाधिक उत्पादकता एवं मूल्य-स्थायित्व के लिए एक शक्ति के रूप में अभिनन्दन
करने की बजाय, निवेध की लाभदायकता को और अधिक कम करने के लिए निन्दा
की जा सकती है। एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था, जो केन्स के कुछ अंशों में
निवेध के समाजीकरण और राज्य के माध्यम से सामुदायिक वचत के प्रस्ताव को
गम्भीरता पूर्वक मानती है, समर्थ माँग के उत्पादन-क्षमता से अधिक अथवा कम
होने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्त स्फीति अथवा अवस्फीति की आशंका के स्थायी भय
से मुक्त हो जायगी। हम ने आर्थिक विकास में राज्य के मौदिक एवं राजकोपीय
महत्व की विवेचना में केन्स के उन सुभावों का प्रयोग किया है।

^{1.} जेनरल थियरी, पृ० 378 एवं पृ० 376।

निवेश की माँग एवं वृद्धिशील बाजार के महत्त्व पर आर० नस्कें द्वारा दिया गया जोर केवल अवध नीति के अन्तर्गत ही कछ अर्थ रखता है। आर्थिक विकास मे सरकार के कार्य के निरोध से ही नस्कें के एक ओर घरेलु निवेश के सम्बन्ध में अल्य-धिक निराशा-नादी तथा दूसरी ओर 'बचत सभान्य' के सम्बन्ध में अत्यधिक आणा-वादी विचार को प्रोश्ताहन मिला है। क्योंकि 'प्रदर्शन-प्रमाव,' जिसे नस्कें अल्प-विक-सित बिवत अर्थ-व्यवस्था के घरेलू निवेश के लिए सम्भावित रकावट मानता है, वास्तव में, यदि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था मे प्रभाव-पूर्ण आयात-नियन्ध्रण हो, तो शास्त्रीय है। इसी तरह सम्बद्ध अर्थ-स्थवस्था में 'वचत सम्भाव्य' के रूप में छिपे हए वेरोजगारो की लामवन्दी भी, प्रभावपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम अथदा लोकथम-नियोजनालयों के अभाव में पूर्णतः शास्त्रीय है। इस प्रकार, उपभोग में कमी के द्वारा बचत एव निवेश में वृद्धि की सस्थापक सीमा (पूर्ण रोजगार की मान्यता पर) एव उपभोग तथा निवेश दोनों में साथ-साथ वृद्धि (पूर्ण रोजगार से कम की मान्यता पर) केसीयन सीमा के बीच मध्यम मार्ग के अवलवन करने का नस्कें का प्रयास, केवल अबध नीति के परित्याग, यानी राज्य द्वारा बाह्य रूप से 'प्रदर्शन-प्रभाव' के निय-न्त्रण तथा आतरिक रूप मे सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा थम के विनिधान की सार्व-जिंतक प्रणाली में सुधार के अधिक सिक्रिय कार्यक्षम अपनाने से ही सम्भव हो सकता 훈 :

किन्तु, एव० एव० हैनसेन, जोत रॉबिन्सन, तथा डब्ल्यू० ए० लीविम के विकास-सम्बन्धी विवेचन इस सम्बन्ध में महत्त्वपूणं अपवाद हैं। आधिक विकास में अन्य लेखकों की अपेक्षा लीविस सरकार के महत्त्व पर अधिक जोर देता है, यद्यपि वह सरकार के कार्य को उत्पादन के साधनों के नियन्त्रण की केम्सीयन नीति, न कि इस साधनों को अपने स्वामित्व में लाने की मानर्सीयन नीति के द्वारा अमल में लाना चाहता है। अन्यत्र लीविस इस वात की ओर सकेत करते हैं कि कोई अपूर्ण रोज- नारी वाल थम की अधिकता वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था, स्फीति जनक दबाव में वृद्धि के बगैर अपेक्षाकृत अम प्रयोग करने वाले एवं शीझ फल देने वाले विकासा- सक कार्यक्रमों के विष् वित्त-अवन्ध के उद्देश्य से साख का विस्तार कर सकती

देखें इनका 'प्रोक्लेम्स ऑफ कैंपिटल फारमेशन, एटसेट्रा'।

^{2.} देखें हैनसेन, दि अमेरिकन इकाँनामी, मैकग्रीऊ-हिल, न्यूयाक, 1957; रॉबिन्सन, 'दि एकुमुलेशन ऑफ कैंपिटल,' इरिवन होमबुड, 1956; लीविस, 'वि वियरी ऑफ इकाँनामिक ग्रोय,' एलेन एड अनवीन, सन्दन, 1955; हैनसेन की पुस्तक एवं लीविस की पुस्तक के सम्बन्ध में कमझ: करेंट इकाँनामिक कमेंट (1957 नवम्बर,) तथा इकोनोमैंद्रिका (जनवरी, 1957); में हमारी समीक्षाओं की तुलना करें।

है। पूंजी-वृद्धि के सम्बन्ध में जोन रॉबिन्सन की विवेचना का अति सूक्ष्म प्रभाव यह पड़ता है कि इससे आधिक विकास जैसी महत्त्वपूर्ण समस्या को 'खेल के पूँजीवादी नियमों,' पर छोड़ देने का सम्पूर्ण विचार अविश्वसनीय सिद्ध हो जाता है। क्योंकि, अवंध नीति-सम्बन्धी इनका विकास-मॉडल, हैरोड एवं डोमर के मॉडलों से भी अधिक निश्चयता पूर्वक, इस बात को दिखलाता है कि वढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यक-ताओं तथा जन्नतिशील तकनीक की संभावनाओं के अनुख्य किसी अर्थ-व्यवस्था के स्थायी विकास जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य को निजी मुनाका प्राप्त करने वालों को सींपना कितना संदिग्ध, अयोग्य एवं अनिश्चित है। अतएव यह विल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है कि जोन रॉबिन्सन ने अन्यत्र यह सुकाव दिया है कि अपने उद्योगीकरण-सम्बन्धी कार्य-क्रम के निर्धारण में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी राज्य का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। उ इनके इस वयान पर विचार कर कि "प्रजातन्त्र के पारम्परिक तरीकों को नियन्त्रण की आवश्यक मात्रा के साथ मिलाना वर्तमान समय

^{1.} डब्ल्यू॰ ए॰ लीविस, 'इकॉनामिक डिवेलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाइज ऑफ लेबर', दि मान्चेस्टर स्कूल ऑफ इकॉनामिक एंड सोशल स्टडीज,' मई 1954।

^{2.} देखें इनकी पुस्तक 'दि एक्शूलेशन ऑफ कैपिटल ।'

हितोत्स्वासी युनिवर्सिटी (जापान) के समक्ष इनका व्याख्यान, जैसा कि 30 मई, 3. 1955 के हितोसवासी सीनवन द्वारा सूचित किया गया था; इस सम्बन्ध में एवं भारतीय अर्थ-शास्त्री के बयान के रूप में अत्यधिक रोचक जान पडता है। व्याख्यान का एक अंश इस प्रकार है— "जापान के आर्थिक विकास के इति-हास से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है। हम लोग पाते हैं कि 1868 से 1879 के बीच जापान की सरकार ने उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार की सविधाओं की व्यवस्था में मार्ग-दर्शन का कार्य किया था। इन्होंने पोत-प्रांगणों, लोह-ढलाई घरों, पश्चिमी यन्त्रों से सुसज्जित आदर्श कार-खानों, रेलवे-लाइनों तथा टेलीग्रापस आदि का निर्माण किया तथा नई तकनीकी के सम्बन्ध में शिक्षा-प्रदान करने के लिए विदेशी विशेपज्ञों को आमन्त्रित किया। जापान की सरकार द्वारा प्रदान किया गया यह प्रोत्साहन जापान के आधिक विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था तथा इसने उद्योगीकरण के लिए आवश्यक समय में कई दशाब्दियों की कमी कर दी। आज भारत भी उन्हीं परिस्थितयों से गज़र रहा है, जिनसे जापान उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अपने द्रतगति से विकास की प्रेरणा में से गुजर रहा था। अतएव, सरकार को मार्ग-प्रदर्शन का कार्य करना है तथा देश में आर्थिक विकास के लिए संवेग का सर्जन करना है। (डी० का 'फिस्कल पालिसी ऐंड दि इकॉनामिक डिवेलपमेंट ऑफ अंडरडिवेल्प्ड कन्ट्रीज, इंडियन जनरल ऑफ इकॉनामिक, जुलाई, 1956.)

की प्रधान राजनीतिक समस्या है"। कोई केवल यह सन्देह व्यक्त कर सकता है कि अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था के उद्योगीकरण के लिए तैयार की गई समाजवादी राज्य की जोन रोबिन्सन की धारणा अनिवायत: उत्पादक सुविधाओं के केन्द्रीय नियन्त्रन पर आधृत तथा विकसित अर्थ-व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अनुशासित केन्म के 'राज्य समाजवाद की व्यवस्था" की ही तरह है।

यद्यपि हैनसेन स्पष्ट रूप से विकसित अर्थ-अयस्था के सम्बन्ध में व्याख्या करता है, तथापि वह बहुत साँ ऐसी बातें बतलाता है, जो अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही शिक्षा-प्रद है। 'प्रजानन्त्राय कल्याणकारी राज्य' के साध-साथ 'मिश्रित सार्वजनिक-सह-निजी-अर्थ-व्यवस्था', को जिसका हैनसेन अमेरिका को अर्थ-व्यवस्था के स्थायी विकास के लिए समर्थन करता है, जल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाों के अधिकतम विकास के लिए और प्रवल रूप में प्रभावित किया जा सकता है। क्योकि, जैसा कि हैनसेन मानते हैं, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रधान अस्त्र राज-वोधीय एवं मौद्रिक नीति है, जिसे पूंजी-सचय एवं तकनीकी प्रगति को तीव बनाने लेखा समर्थ माँग को स्थायो बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रजातन्त्रात्मक कल्याणकारी राज्य को केवल 'तैयार स्थायित्व प्रदान करने बाल साधनों' (जैसे सामाजिक बीमा-सम्बन्धी भुगतान, कृषि को समर्थन देने के कार्मक्रम, सार्वजनिक इमारतो, सामृहिक शिक्षा, एवं अन्य, जिनका समर्थन उसने विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में किया है) की व्यवस्था करने वाले के रूप में ही नहीं, वरन् सामान्य उत्पादकता को बढाने के लिए अनिवार्य 'सामाजिक पूंजी' (जैसे विद्यालयो, अस्पताल, सार्वजनिक मनोरंजन केन्द्रो, सार्वजनिक पुस्तकालयो, सार्वजनिक कल्याण-

देखें इनका क्लैक्टेड इकॉनामिक पैपसं, पृ० 113. ।

^{2.} देखे जनरस िययरो, पृ० 378. वहाँ केन्स; जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है, केन्सीय समाजवाद एवं पारम्परिक समाजवाद मे सावधानी पूर्णक निम्नाकित तरीके से विभेद करते हैं: "राज्य के लिए उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को प्राप्त करना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। यदि राज्य उपकरणों को बढ़ाने में लगाये जाने वाले साधनों की कुल माना तथा इनके स्वामित्व के लिए आधारभूत पारिश्रमिक की दरें निर्धारित करने मे सफल हो जाता है, तो यह सभी अपेक्षित घीजों को प्राप्त कर लेता है। साथ ही, समाजीकरण के लिए आवश्यक उपायों को कमधा तथा समाज की सामान्य परम्पराओं को भंग किये वर्णर अपनाया जा सकता है।"

हैनसेन की मिधित 'अथ-व्यवस्था एवं कत्याणकारी राज्य' की योजना की विस्तृत विवेचना के लिए देखें मेरा निवन्ध 'ब्रोफेसर हैनसेन ऑन अमेरिका इकॉ-नामिक रिवोल्यशन,' इकानामिक जनरल, सितम्बर, 1958.

विभाग एवं राज्य द्वारा नियन्त्रित जीवन की अन्य सुविधाओं) प्रदान करने वाले के रूप में समभा जा सकता है। अरूप-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में, हैनसेन की 'मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एवं कत्याणकारी राज्य' की धारणा के अन्तर्गत सम्भवतः प्रत्यक्ष नियन्त्रण (जैसे विनिद्यान की प्राथमिकता की नीति, मूल्य-नियन्त्रण एवं आयात-नियन्त्रण) तथा परोक्ष राजकोषीय एवं मीद्रिक नीतियों का भी समावेश करना पड़ेगा। साथ ही, अरूप-विकसित देशों के द्रुतगित से उद्योगीकरण के लिए सम्भवतः हैनसेन की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एवं कत्याणकारी राज्य की योजना तथा केन्स के 'राज्य-समाजवाद' की कुछ अधिक विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे इनके अन्तर्गत कुछ ऐसे उद्योगों एवं उद्यमों, जिनका जन-कत्याण एवं निजी उपक्रम के प्रोत्साहन में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (उदाहरण के लिए, जनोपयोगी सेवाएँ तथा वैकिंग की सुविधाएँ) का सरकारी स्वामित्व एवं संवालन के अन्तर्गत समावेश किया जा सके।

हैनसेन एवं हमारे बीच प्रधान अन्तर यह है कि वह अधिक परम्परा-निष्ठ केरसीय तरीके से राज्य को मुख्यतः त्रुटि-पूरक संस्था मानता है, जबिक हम को अधिकाधिक बनाने के अतिरिक्त कार्य को राज्य के जिम्मे सुपूर्व करते हैं। क्योंकि, अल्प-विकसित देशों में राज्य का निर्णायक कार्य समर्थ माँग के स्थायित्व को प्रोत्साहित करना नहीं है। वरन्, ऐसे देशों में राज्य का प्रधान आर्थिक कार्य समर्थ गाँग में वृद्धि के दिये हुए स्तर अथवा दी हुई दर की तलना में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसकी उत्पादन-क्षमता की विकसित करना है। इस उपर्युक्त कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय नियन्त्रण एवं केन्द्रीय स्वामित्व की कार्य के अनुसार उचित अनुपात में तथा सम्बद्ध अल्प-विकसित देश के सामाजिक दर्शन के अनुरूप मिश्रित करना अनिवार्य है। अनन्य नियन्त्रण के सिद्धान्त एवं अनन्य स्वामित्व के सिद्धान्त के बीच अव्यावहारिक विलगाव कम-से-कम ऐसे समाज के लिए जिसमें केन्द्रीय अधिकारी की ब्राइयों के विरुद्ध प्रजातन्त्रात्मक वचाव उपलब्ध है, बिल्कुल अर्थहीन है। किन्तू यह एक ऐसा कार्य है, जिसमें तकनीकी अर्थ-शास्त्रियों को राजनीति-शास्त्र के विद्वानों, दार्शनिकों, समाज-शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों का सह-योग मिलना चाहिए, यदि हमें मानव-मूल्यों के रूप में अर्थपूर्ण एवं लाभदायक तक-नीकी सलाह देते हैं।

संतुलित विकास की प्रकृति एवं यंत्र

आर्थिक विकास के लेखकों में संतुलित विकास शब्द के जिक करने का रिवाज-सा हो गया है। किन्तु, अधिकांश लेखक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किस वस्तु को संतुलित किया जाता है तथा इस बात को नहीं समभ पाते हैं कि जहाँ तक अवंध-नीति संबंधी अर्थ-व्यवस्था का संबंध है, संतुलित विकास, यदि पद के रूप मे नहीं, तो सार रूप मे, परस्पर-विरोधी है। इती प्रकार वे लोग उस निश्चित विधि को भी स्पष्ट नहीं करते, जिसके द्वारा 'संतुलित विकास' (कुछ परिभाषाओं के आधार पर) को प्राप्त किया जा सकता तथा बनाये रखा जा सकता है। अतएय, 'सतुलित विकास' की विभिन्न धारणाओ तथा इनमे सन्निहित विकास-सबधी विधियों की आलोचनात्मक समीक्षा लोभदायक जान पडती है।

आधुनिक विकास-संवधी अर्थशास्त्र दीर्धकालीन विकास की विक्षुत्ध प्रकृति एव अल्पकालीन साम्यावस्था की अस्थायी प्रकृति, यानी पूंजीवाद के चनीय विकास में केम्स एव णुम्पीटर की अतःप्रज्ञा व अतद्रृष्टि की परिपालन की वृष्टि से महत्त्वपूर्ण बनाने की व्यादया के प्रयास से प्रारम होता है। मुख्य रूप से अवध-नीति की स्थिति में एक विकसित अर्थ-व्यवस्था के अस्थायी विकास के लिए निवेश की दोहरी प्रकृति पर ह्यान देने के सबध में हैरोड एव डोमर ने नया मार्ग तैयार किया। केम्स के समर्थ माँग के अरूप-कालीन सिद्धात की तरह, बचत एवं निवेश की समानता को साम्यावस्था की पर्याप्त खर्त तभी समभा जा सकता है, जब कि पूँजी के कीप को स्थायी मान लिया जाता है। किन्तु, यदि पूँजी के कीप में यूद्धि होने दी जाय, जैसा कि दीर्थकाल में अवश्य ही होगा, तो क्षमता में परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप निवेश के धनात्मक अथवा ऋणात्मक होने की सभावना उत्पन्त हो जाती है, जिससे निवेश एवं बचत की अस्थायी समानता भग हो जाती है। इस प्रकार वृद्धिशील पूँजी के कीप वाली विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में बचत एवं निवेश को किस प्रकार संतुतित किया जाय, यही प्रधान समस्या है, जिसके समाधान का हैरोड तथा ढोमर ने औपचारिक रूप से प्रयास किया था।

हैरोड तथा डोमर मे उभयनिष्ठ सतुलित विकास का सार यह है कि यदि किसी अर्थ-व्यवस्था को बेकार क्षमता अथवा अतिरिक्त अम के बगैर निपन में निरतर वृद्धि को वनाये रखना है, तो समर्थ माँग एव उत्पादन-क्षमता को किसी भी प्रकार सतुलित बनाये रखना अनिवायें है। हैरोड के विकास-सवंधी सिद्धात में, स्थायो विकास की एक आधारमूत क्षम यह है कि यदि बचत-अनुपात (s) एवं पूँजी-निपज-अनुपात (b) दिये हुए हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय वास्तविक आय (Y) में उत्पादन-क्षमता के वरावर ही वृद्धि होनी चाहिए.

$$\triangle Y = \frac{s}{b} Y,$$

जिसका दायाँ पक्ष उत्पादन-क्षमता तथा बायाँ पक्ष समर्थ माँग मे वृद्धि है। इसी समीकरण से आय मे वृद्धि की निम्नॉक्ति अपेक्षित दर (हैरोड की शब्दावली मे— अमाणित दर) प्राप्त होती है:

$$\frac{\triangle Y}{Y} = \frac{s}{b}$$

जो यह वतलाता है कि यदि अधिक अथवा कम क्षमता के वग्नैर उत्पादन-क्षमता को पूर्ण रूप से प्रयोग करना है तो आय में निश्चित रूप से s/b की स्थायी दर से वृद्धि होनी चाहिए । क्योंकि, उपर्यु वत समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि $\triangle Y/Y < s/b$, जो कि नियमित रूप से समग्र विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रचितत प्रवृत्ति मालूम पड़ती है, तो समर्थ माँग के उत्पादन-क्षमता से अधिक धीरे-धीरे बढ़ने के कारण, यानी $\triangle Y < s/bY$ के परिणामस्वरूप दीर्घकालीन अस्थायित्व की प्रवृत्ति उत्पत्न हो, सकती है।

अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रयोग करने पर माँग से घोरे-घीरे क्षमता में वृद्धि $\triangle Y/Y > s/b$ की विपरीत प्रवृत्ति में स्फीतिजनक भुकाव ही अंतिनिहत है, जो दीर्घकाल में सिम्मिलित होने वाले अल्पकालों में $\triangle Y > (s/b)Y$ को सूचित करता है। यदि स्फीतिजनक प्रवृत्ति को छोटे-से-छोटा बनाना है, तो एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को समर्थ माँग के विस्तार $(\triangle Y)$ को मंद बनाना या उत्पादन क्षमता में वृद्धि ((s/b)Y) को तीच्च बनाना या दोनों कार्यों को करने के लिए उचित उपायों को अपनाना होगा। फिर भी, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के स्फीति-जनक दवाव को कम करने की अपेक्षा वास्तविक पूँजी के संचय एयं दीर्घकालिक अपूर्ण रोजगारी को दूर करने के लिए उपयुंचत समीकरण की पूर्ति अथवा क्षमता-पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। दूसरे शब्दों में, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को केवल समर्थ माँग में वृद्धि की दर तथा स्थायी विकास के लिए उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की दर एवं जनसंख्या में वृद्धि की दर को भी बढ़ती हुई उत्पादकता के साथ वरावर करना चाहिए, यानी—

$$\frac{\triangle Y}{Y} = \frac{s}{b} = n + h,$$

जिसमें n श्रम-संख्या में वृद्धि की दर, h श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की दर है, और अतएव n+h 'विकास की अधिकतम सामाजिक दर' है, जिसकी व्याख्या इस पुस्तक में पहले की जा चुकी है। वहाँ पर यह दिखलाया गया है कि हैरोड की 'प्राकृतिक' दर श्रम की परिवर्तनशील उत्पादकता (अथवा परिवर्तनशील श्रम-निपज अनुपात) से युक्त सामान्य स्थिति की एक विशेष स्थिति है; क्योंकि इनकी 'प्राकृतिक' दर के अनुरूप इनकी 'प्रमाणित' दर पूर्ण रोजगार की व्यवस्था तभी कर सकती है, जबिक श्रम-निपज-अनुपात में इसी प्रकार कमी नहीं होती (अथवा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती), जिससे कि निपज की प्रति इकाई को कम श्रम की आवश्य-कता पड़े। दूसरे शहरों में, जैसा कि स्थायी श्रम-निपज अनुपात की मान्यता पर होता

है, यदि उत्पादन-क्षमता में उसी दर से वृद्धि-विषयक श्रम-संख्या में वृद्धि होती है, तो एक अत्य-विकसित अर्थ-व्यवस्था दोनो पूँजी के अभाव से दीर्घकालिक अपूर्ण रोजगारी सथा वृद्धिणील उत्पादकता के कारण स्थायी जीवन-मान का अनुभव करेगी। अतएव, अत्य-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए हम लोगों की सतुलित विकास की धारणा में समर्थ गाँग, उत्पादन समता एवं श्रम, जिसकी उत्पादकता समय के श्रम से वढ रही हो, के विकास की दरें (हैरोड की प्राकृक्तिक दर की विवेचना की तरह स्थायी रहने के बजाय) सन्निहत हैं।

जहां तक डोमर के 'सतुनित विकास' की धारणा का संबंध है, एक वृद्धिशील अर्थ-अयवस्था के माँग-पक्ष की ओर हैरोड की अपेक्षा यह अधिक स्पष्ट है; क्योंकि डोमर ने माँग-पक्ष के गुणक पहलू की विवेचना की है, जबिक हैरोड ने ऐसा नहीं किया है। पूर्ति पक्ष की ओर, डोमर एव हैरोड के पूँजी-निपण अनुपात के ब्युक्तम के प्रयोग यानी निवेश की उत्पादकता के प्रयोग को लेकर हैं: इस प्रकार, नि सदेह समर्थ माँग के स्तर के रूप में $Y = I/\alpha$ तथा उत्पादन-क्षमता के स्तर के रूप में $Y' = \sigma K$ और इस्रतिए Y = Y' अथवा $I/\alpha = \sigma K$ को स्थायी साम्यावस्था की शर्त के रूप में प्रारम करते हुए (जिसमे Y समर्थ माँग, Y' उत्पादन-क्षमता है। गुद्ध निवेश, K पूँजी का कोप, α बचाने की सीमात (α स्वीकृत औसत) क्षमता एव α निवेश की सीमात (α स्थीकृत औसत) क्षमता है), डोमर स्पष्ट रूप से गरयात्मक साम्यावस्था शर्त की ओर आगे बढता है।

$$\frac{\triangle 1}{1} = \alpha \sigma$$

जो माँग-पक्ष की बोर से $\triangle Y = \triangle 1/\alpha$ तथा पूर्ति-पक्ष की ओर से $\triangle Y' = \sigma \triangle K = \sigma 1$ और अंतएव $\triangle Y = \triangle Y'$ या $\triangle 1/\alpha = \sigma 1$ का अनुकरण करता है।

डोमर का विकास-सम्बन्धी समीकरण $\triangle 1/1=\alpha\sigma$ हैरोड के विकास की 'प्रमाणित' दर की ही तरह है; क्यों कि डोमर के $Y=1/\alpha$ से हमें निम्नाकित प्राप्त होता है:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta 1/\alpha}{Y} = \frac{\Delta 1/\alpha}{1/\alpha} = \frac{\Delta 1}{1} = \alpha \sigma = \frac{s}{b} \cdot (\alpha = s, \sigma = 1/b)$$

इस प्रकार, डोमर के सतुजित विकास की धारणा समये गाँग एव उत्पादन क्षमता को सतुजित रखने की है, जिससे कि कोई अर्थ-व्यवस्था अतिरिक्त अथवा न्यून क्षमता के उत्पन्न हुए बगैर, सतत रूप मे विकास कर सके । हैरोड की नुलना मे डोमर द्वारा सूत्र के रूप मे इसे बणित करने का लाग यह जान पहता है कि सार्व-जिनके निवेश के रूप मे इसकी व्यवस्था को सम्भव बनाने के लिए डोमर ने मौग-पक्ष की कोर स्पष्ट रूप से स्वतःश्रेरित गृथ्य ($\Delta 1$) को शामिल किया है । इसके विप-

रीत इसका दोष हैरोड की तरह की 'प्राकृतिक' दर की व्याख्या का अभाव जान पड़ता है, जो पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण क्षमता की व्याख्या कर सके। साथ ही, डोमर के 'संतुलित विकास' के विरुद्ध भी वे ही आलोचनाएँ दी जा सकती हैं, जो हैरोड के स्यायी तकनीकी गुणांकों (उदाहरण के लिए, स्थायी पूँजी-निपज अनुपात, स्थायी पूँजी-श्रम अनुपात तथा स्थायी श्रम-निपज) की मान्यता के विरुद्ध दी जाती है। अंग्रतः, इसी प्रकार की आलोचनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए हमने गत्यात्मक तकनीकी प्राचलों की व्याख्या से सम्बद्ध एक अध्याय (इस पुस्तक का पाँचवां अध्याय) को सम्मिलत किया है। फिर भी, तकनीकी प्राचलों को इच्छित दिशा में परिवर्तनीय बनाने में बाजार की शिक्तयों तथा साधनों के सापेक्ष मूल्य को परिवर्तनों की विश्वस्तता के प्रति हम ने पर्याप्त मात्रा में संशय व्यक्त किया है। इसके विपरीत इस बात पर हमने कुछ आशा व्यक्त की है कि सार्वजनिक नीति विचारपूर्वक उन तथ्यों को प्रभावित कर सकती है, जो बाजार की शतों से स्वतन्त्र रूप में तथा अन्य प्रचलित विकास-सम्बन्धी परिवर्त्तयों के सन्दर्भ में तकनीकी गुणांकों को प्रभावित करते हैं।

हैरोड तथा डोमर ने विकास के संयंत्रों की अनिवार्य प्रकृति को परिचालन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बनाया है; नयोंकि लोग विकास की अपेक्षित दर की जाँच तथा सम्भवतः हेर-फेर के लिए वचत-अनुपात एवं पूंजी-निपज-अनुपात (या इसके ब्युत्कम) पर मापनीय महत्त्वपूर्ण परवर्तियों के रूप में जोर दिया है। इन महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तियों की व्यापक प्रकृति के चलते हैरोड तथा डोमर द्वारा वर्णित विकास संयंत्र सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में, यद्यपि कुछ सुद्यार के साथ, लागू होता है। इसके विपरीत, जोन रॉविन्सन का विकास-सम्बन्धी संयन्त्र है। जिसमें विशेष रूप से प्जीवादी प्रकृति के मृत्य एवं वितरण-सम्बन्धी प्राचल सन्निहित हैं। यद्यपि जोन रॉविन्सन का विकास-सम्बन्धी संयंत्र पंजीवादी व्यवस्था के ऐतिहासिक विकार को अधिक यथार्थवादी तरीके से व्यक्त करता है, तथापि इसमें कम अनुकूलता है, अतएव इसमें व्यापक आकर्षण का अभाव है। हम ने यह अनुमान लगाया है कि जोन रॉबिन्तन का उददेश्य यह दिखलाना हो सकता है कि आज की किसी अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को उत्पादन के अन्य साधनों की तुलना में श्रम के लिए अधिक प्रतिकूल विकास की पद्धति को अपनाना कितना व्यर्थ एवं असह्य होगा। जोन रॉविन्सन के पूँजी-संचय-सिद्धान्त का आशय यह जान पड़ता है कि आर्थिक विकास की ऐसी पद्धति के लिए, जो पूर्ण रोजगारी एवं मजदूरी कमानेवाले वर्गों के उपभोग की ऊँची आकांक्षाओं के लिए कम-से-कम हानिकारक सिद्ध हो सकती है, 'खेल के पूँजीवादी नियमों को सार्वजनिक नीति से प्रतिस्थापित करना चाहिए । इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि जोन रॉविन्सन 'श्रमवाद'-सम्बन्धी केन्सीय रूपान्तर से सहमत हैं।

अत्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से अधिक प्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध आर० नस्कें

का पुंजी-निर्माण का सिद्धान्त एव 'संतुलित विकास है' । नस्कें की सतुलित विकास धारणा इस प्रकार जान पडती है कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था की मृख्यत. स्वतन्त्र समाज के ढाँचे के अन्तर्गत आतरिक नीतियो एवं विदेशी व्यापार-सम्बन्धी नीतियों के सम्मिश्रण के द्वारा निवेश की माँग एव पूँजी की पूर्ति के बीच सतुलन स्थापित करना चाहिए। पूँजी-सचय के माँग-पक्ष पर इनका जोर संस्थापको की इस धारणा कि 'पूर्ति स्वयं अपनी माँग का सर्जन करती है' के विरद्ध केन्स की प्रतिक्रिया को प्रतिविभ्वित करता है । अल्प-विकसित अर्थ व्यवस्था के आर्थिक विकास के स्पष्ट उद्देश्य मे निवेश की मांग के विस्तार के लिए इनकी पिता अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के बाजार अथवा कच्चे माल के साधन के रूप में समभने की परम्परावादी प्रवृत्ति से एक प्रकार का मुखद अपसरण है। किन्तु निवेध की मांग के लिए इनकी उस चिंता के परिणाम-स्वरूप बचत की पूर्ति के लिए इनकी दूसरी चिता, जो किसी भी दीर्घकालीन विश्लेषण-सस्यापक अथवा केन्सीयन के लिए अधिक सारभूत है, शक्तिहोन हो जाती है । साथ ही, गस्कें की निवेश-माँग विष-पक धारणा की एक प्रधान कमी 'ब्रेरित' एव 'स्वतन्त्र' निवेश के बीच विभेद का अभाव है, जिससे वह विकासात्मक कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से निवेश-सम्बन्धी कार्यक्रमा के सगठन में सरकार के स्पष्ट महत्त्व को छोड़ देता है। वह विवादास्पद ही रह जाता है कि क्या एक अल्प-दिकसित अर्थ-व्यवस्था निवेश-सम्बन्धी निर्णयों की मुख्यतः निजी उपक्रमियों के हाथ में छोडकर उत्पादक कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में निजी निवेश को प्रेरित करने की बाजार-सम्बन्धी प्रारम्भिक कठिनाइयो को दूर कर सकती है, अयवा नहीं । जहाँ तक अल्प-विकसिस अर्थ-ध्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, 'संतुलित विकास' (आय का), जैसा कि नस्कें मानता है, की इच्छा निजी निवेश की प्रेरित करने के लिए नहीं, वरन स्वय इसी के लिए की जाती है। क्योंकि, स्वतन्त्र निवेश की उपेक्षा कर प्रेरित निवेश पर हैरोड द्वारा अत्यधिक जोर देने के विरुद्ध आलीचना में वतलाया जा चुका है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सकुचित वाजारों एव निम्न वास्तविक आय के चलते निवेश की प्रेरणा के मार्ग में अवरोध के विरुद्ध नस्कें की शिकायत विल्कुल अनावश्यक हो जायगी, यदि क्षमता-बद्धंक एव आय-उत्पादक प्रकृति के स्वतन्त्र सार्वजनिक निवेश को अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जायगा ।

पूँजी-सचय के पूर्ति-पक्ष की ओर नस्कें, छिपी हुई बेरोजगारी से मिले हुए 'प्रदर्शन-प्रभाव' को 'दचत सम्भाव्य' मानता है। हम इन विषयों की व्याख्या पहिले ही कर चुके हैं. अतएव यहाँ पुन इस पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, यहाँ कुछ अतिरिक्त विचार व्यक्त किया जा सकता है। प्रयमतः, जनतत्था की वृद्धि तथा पूँजी के विकास के फलनीय सम्बन्ध के विक्लेपण, जैसा कि हम ने विकास की सामाजिक खेटु दर तथा दीर्षकालिक अपूर्ण रोजगारी की विवेचना में तथा हैरोड

वेखे इनकी पुस्तक 'प्रोत्लेम्स ऑफ कैपिटल फॉरमेशन इन अंडर डिवेलपड कम्ट्रीज'।

एवं जोन रॉविन्सन ने अपने 'प्रगतिशील साम्यावस्था' तथा 'स्वर्णयुगीय साम्यावस्था' की विवेचना में किया था, के वग़ैर नस्कें द्वारा जनसंख्या की व्याख्या छिपी हुई वेरोजगारी को 'वचत सम्भाव्य' मान लेने नक सीमित है। द्वितीयतः, नस्कें के 'संतु-लित विकास' की विवेचना में तकनीकी प्रगति के महत्त्व की विल्कूल उपेक्षा की गई है। इसी तकनीकी महत्त्व की उपेक्षा के कारण नस्कें ने पंजी-संचय की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर दिया था, जबिक तकनीक में शम्पीटर की तरह थोड़ी और दिल-चस्पी से उसे यह पता लग सकता था कि एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था किसी दी हुई बचत अनुपात की तुलना में पुँजी-निपज अनुपात को घटाकर विकास की दर में वद्धि कर सकती है। ततीयतः, नस्कें राजकोपीय नीति के कार्यक्षेत्र को अतिरिक्त 'वचानेवाले', 'विनियोग करनेवाले', 'नवीन किया के संचालनवाले' तथा 'पूनवितरक' के रूप में, विभिन्न प्रकार के कार्यों को सौंपने के वजाय, इसे केवल वर्तमान बचतों की गतिमान करने तक ही सीमित रखता है। हम ने उन अल्प-विकसित देशों के लिए, जिनमें निजी उपक्रम, निजी स्वेच्छिक बचत तथा निजी नवीन किया का प्रभाव पाया जाता है, राजकोपीय नीति के इन बादवाले कार्यों के महत्त्व की व्याख्या की है। अंततः, यद्यपि नस्कें पूँजी के आयात को विकासात्मक पूँजी का एक अतिरिक्त साधन मानता है, तथापि 'प्रदर्शन-प्रभाव' के सम्बन्ध में उसका संशययुक्त विवरण तथा 'वचत सम्भाव्य' के रूप में उसकी छिपी हुई वेरोजगारी के आणापूर्ण विवेचन का सम्भवतः ऐसा अनिमप्रेरित प्रभाव पड़ता हुआ दीखता है कि पूँजी के विदेशी साधनों पर निर्भरता महत्त्वहीन हो जाती हैं। हम ने केन्स के 'अन्तर्राष्ट्रीय समस्थितिकरण' की भावना के अनुरूप सम्भवतः राष्ट्र के अभिकरणों के द्वारा विदेणी जधारकरण के अति विस्तृत क्षेत्र का निर्देशन किया है। किन्तु इन सीमाओं के चांवजूद, नस्कें के आधिक विकास का सिद्धान्त इस अर्थ में महत्त्वपूर्ण है कि इसने वास्तविक पूँजी को, जो विकास का एक-मात्र वृद्धि करने योग्य साधन है, अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है।

यदि समग्र मानव-समुदाय के कल्याण के लिए अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, तो हैरोड, डोमर, हैनसेन, जोन रॉविन्सन, नस्कें, लीविस एवं अन्य केन्सीय-उत्तर लेखकों के विकास-सम्बन्धी विश्लेपण में प्रकाशित सम्भावनाओं पर और अधिक अनुसंधान, अध्ययन तथा खोज करनी चाहिए। यदि वर्तमान पुस्तक इस प्रकार के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए कुछ बितिरिक्त प्रेरणा प्रदान करती है, तो लेखक का परिश्रम व्यर्थ नहीं कहा जा सकता!

परिशिष्ट

संयुक्त राष्ट्र एवं आर्थिक विकास*

अपने पूर्ण रोजगार के लिए राष्ट्रीय एवं अस्तर्राष्ट्रीय उपायों के परिणाम-स्वरूप सयुक्त राष्ट्र ने अल्प-विकसित वेशों के आधिक विकास के तरीकों पर एक विवरण प्रकाशित किया है, जो ए० बी० कोज (चिली), डी० आर० गैडिमिल (भारत), जी० हकीम (लेबनन), उस्त्यू० ए० लीविस (इंगलैंड) तथा टी० उस्त्यू० स्वरूप (यू० एस०) दारा तैयार किया गया था। इस विवरण के अध्ययन से गीध ही बहुत बड़ी सब्भावना, कल्पना पूर्ण परिज्ञान एव विस्तृत सूक्ष प्रकट होती है। किन्तु प्रतिवेदन के इन प्रशस्तीय पहलुओं के बावजूद, इस बात की आशका की जाती है कि तकनीकी पाटक इसमें प्रस्तावित विभिन्न उपायों के सैदान्तिक आधार से पूर्ण एप से सतुष्ट नहीं हो सकते। शायद विशेषज्ञ उन लोगों के विरुद्ध, जिन्होंने पूर्ण रोजगार के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार किया था, दी गई इस आलोचना कि वे अपने समक्ष समस्याओं की बहुत कुछ इस प्रकार समक्ष्त थे, मानो वे गणितीय समस्याएँ हो, से बहुत अधिक सचेत थे। के परिचालन की दृष्टि से

^{*}यह हमारा समीक्षा-सम्बन्धी निवन्ध है, जो प्रारम्भ में 'इंडियन इकॉनामिक जन-रल' अप्रैल, 1954 मे प्रकाशित हुआ था।

¹ सयुक्त राष्ट्र, आर्थिक मामलो का विभाग, न्यूयार्क, मई, 1951 :

² देखें समुनत राष्ट्र के इकाँनामिक एंड सोशल कोंसिल ओफ्सिपल रेकड्स, 10-वां सत्र, 358-वी बैठक, 21 फरवरी, 1950, पू॰ 98. । विश्लेषणात्मक, न कि रीति-विधानसम्बन्धी समालोचना के लिए—देखें मेरा निबन्ध 'दि यूनाइटेड नेशन्स एड फुल एम्प्लायमेट' जनरल ऑफ पोलिटिकल इकाँनामी, अगस्त, 1950 ।

सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण फलनीय सम्बन्धों की उपेक्षा में बहुत ह्रव्द तक वे आगे जा सकते थे। ऐसा निस्संदेह अंगतः आधिक विश्लेषण के प्रयोजन के लिए आधिक विकास की समस्या की जटिलता एवं किठनाई के परिणाम-स्वरूप है। फिर भी, चूंिक प्रतिवेदन का अभिप्राय अल्प-विकसित देशों के आधिक विकास की व्याख्या करना है, अतः में मुख्यतः आधिक दृष्टिकोण से इसकी समोलोचना करना तथा गायद इसे कार्योन्वित करना उचित समभता हूँ। ऐसा करने में मैं प्रतिवेदन के नीति-सम्बन्धी विचार को छोड़कर इसके विश्लेषणात्मक पहलू पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ।

प्रयमतः प्रतिवेदन में निम्न 'प्रति-व्यक्ति वास्तिक आय' (जिसका संयुक्त राज्य एवं कैनाडा-जैसे 'धनवान' देशों को 'निर्धन देशों' से पृथक् करने का कार्य अपना ही महत्त्व रखता है), के रूप में अरूप-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की एक सिक्त्य परि-भाषा दी गई है। तब अरूप-विकसित स्थित को (1) आर्थिक संगठन एवं नियोजन, (2) टेक्नोलॉजी, (3) जनसंख्या की वृद्धि, तथा (4) आंतरिक एवं वाह्य पूँजी से सम्बद्ध किया गया है। प्रतिवेदन इन परिवर्तियों पर, पृथक् रूप में तथा एक-दूसरे के सम्बन्ध में सदा व्यावहारिक नीति-सम्बन्धी सिफारिशों के निर्माण के उद्देश्य से विवे-

चना करता है।

विगोपज सम्भवतः अल्प-विकास की स्थिति के हानिकारक सहायक के रूप में जोर देने के कार्य की व्याख्या, वेरोजगारी, विशेपतः उस प्रकार की वेरोजगारी, जो मुख्य रूप से पूँजीगत साधनों तथा अन्य औद्योगिक सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पन्त होती है, यानी 'संरचनात्मक वेरोजगारी' से प्रारम्भ करते हैं। अतएव, वे 'उद्यो-गीकरण' को, इस प्रकार की वेरोजगारी का अत्यधिक तार्किक उपचार बतलाते हैं। इसके विपरीत इसे स्वीकार किया जाता है कि विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में सबसे जटिल प्रकार की वेरोजगारी समर्थ माँग के अभाव की प्रचलित धारणा के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि श्रीमती जोन राँविन्सन ने वतलाया है, तथा-कथित 'संर-चनात्मक वेरोजगारी' जनसंख्या में पूँजी-संचय से अधिक वढ़ने की स्पष्ट प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न मार्क्स के प्रकार की वेरोजगारी की एक-मात्र दूसरी आकृति हैं। यह प्रवृत्ति पूँजीवाद के प्रारम्भिक विकास की प्रमुख विशेषता थी और जो आज औद्यो-गिक दृष्टि से पिछड़े राप्ट्रों में पाई जाती है। किन्तु, प्रतिवेदन में ऐसी सीमांत स्थिति की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें कोई देश मानिसयन वेरोजगारी के दानव तथा केन्सीयन वेरोजगारी के अथाह सागर के वीच हो । जापान इसका ज्दाहरण है; क्योंकि इसका द्रुतगति से उद्योगीकरण कृषि पर आश्रित जनसंख्या की तुलना में कृपि के अवपूँजीकरण, यानी अस्थायित्व एवं समर्थ माँग में कमी के परि-णाम-स्वरूप बड़े पैमाने पर वेरोजगारी के बढ़ते हुए खतरे पर ही सम्भव हुआ है। अतएव फिर भी, अपूर्व रोजगार के मूख्य उपचार के रूप में आर्थिक विकास पर

^{1.} देखें इनका निवन्ध 'मि. हैरोड्स डायनैमिक्स', इकॉन्ग्रमिक जनरल, मार्च, 1949 I

उचित रूप से जोर देने के पूर्व केन्स के इस आरक्षण का प्रयोग करना चाहिए कि जब कोई देश द्वाराति से सपत्तिवान बन रहा है, तो निवन्ध-गीति की स्थिति में नवीन निवेश की प्रेरणाओं की अपर्याप्तता के प्रयोगन से, इस सुखद स्थिति में, आने वाली प्रगति में, सभवतः, कोई अवरोध हो सक्ता है। मिवन्ध-गीति को व्याव-हारिक प्रवृत्ति तथा पूँजी के ह्यासमान फलन के रूप में निवेश की सद्धान्तिक लुप्ति—इन दोनों के विरद्ध इसे चेतावनी के रूप में समभना चाहिए।

'मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक वर्तों की प्रगति-विषयक पूर्वदशाओ' की दूसरी विदे-चना प्राय सामान्य जान पहली है। निश्चय ही अल्प-विकसित देशों की यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इतगति से आधिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती. जब तक कि जनता मे प्रगति की इच्छाओं के साथ-साथ देश के हर-एक स्तर के नेता-गण-राजनीतिज्ञ, शिक्षक, इंजीनियर, व्यावसायिक नेता, मजदूर-सथी के नेता, पुजारी तथा पत्रकार—देश की अधिक प्रगति की इच्छा नहीं करेंगे (पू॰ 16)। सदियों की निर्धनता, वेरोजगारी, तया सामाजिक मुविधाओं के सामान्य अभाव ने सभी पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं को इनके औद्योगिक पिछडेपन के प्रति इतना अधिक सर्वेदनशील वना दिया है कि निष्कपट तरीके से प्रयोग करने तथा भाव-रहित तरीके से बोलने पर भी 'पिछडे हए' शब्द से ये लोग अप्रतिष्ठाजनक अर्थ लगाने लगते हैं। बात यह है कि विश्व के अधिकाश अल्प-विकसित क्षेत्रों में दीर्घकाल तक 'उपनिवेशवाद' के परिणाम-स्वरूप, उद्योगीकरण, विशेषत: तीव राष्ट्रीयवादी एशियाई देशो³ के साथ एक घरेलु गब्द तथा लभानेवाला राजनीतिक नारा हो गया है। आकस्मिक प्रेक्षको को जो-कुछ सहज राष्ट्रीय विधित्र विधार जैसा दीख पडता है, उसके पीछे उनकी सर्व-प्रथम आर्थिक एवं सर्वोपरि लक्ष्य की ओर बढने वाली दृढता, सकल्प एवं इच्छा-शक्ति अवस्थित है। आर्थिक दृष्टि से 'आगे बढने की यह इच्छा', राजनीतिक स्वन-न्त्रता की प्राप्त करने अथवा बनाये रखने के अप्रतिहत आग्रह से और भी बलवती हो जाती है। इन सभी राष्टीयवादी भावनाओं से अल्प-विकसित देशों को अमेरिका के उद्योगीकरण तथा स्वतन्त्रता, जापान की अद्भुत औद्योगिक प्रगति तथा, अच्छा समभा जाम अथवा दुरा, रूस के साहसी आर्थिक प्रयोगी के ऐतिहासिक उदाहरणी से निरन्तर प्रोत्सहन मिलता रहता है। विशेषज्ञ शायद कम की पलट देना चाहते हैं, अब वे यह तर्क देते हैं कि द्वुतगित से आधिक प्रगति के पूर्व प्राचीन दर्शनो को खदित वरना पटेगा, प्राचीन सामाजिक संस्थाओं को समाप्त करना पहेगा, एवं जाति. मत. प्रजाति आदि को तोडना पडेगा । इस बात की सम्भावना अधिक है कि

^{1.} जेनरन थियरी, यु० 355.)

उदाहरण के लिए देखें हमारी पुस्तक 'लेबर इन दि फिलिपाइन इकॉनामी' स्टेनफोर्ड यनिव॰ प्रेस॰, 1945. ।

यह 'दु:खदायी पुन:समंजन' द्रुतगित से आर्थिक प्रगति के परिणाम-स्वरूप होगा, न कि इसकी एक महत्त्वपूर्ण 'पूर्व भतें' के रूप में। इन तथा-कथित अवरोवों पर अधिक जोर देने से केवल इस कृत्रिम धारणा को वल मिलेगा कि अल्प-विकसित देशों को केवल इसलिए पिछड़ा रहना पड़ेगा कि उनके रहन-सहन की प्रणाली पिछड़ी है। यदि, जैसा कि जान पड़ता है, आर्थिक प्रगति में इन सब सामाजिक बाधाओं को समाप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो अल्प-विकसित अर्थ-अ्यवस्थाओं द्वारा 'निर्धा-रंकों के निर्धारक' को दिया हुआ मानकर अतिकमण करने तथा प्राचलीय दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारकों की और प्रत्यक्ष-रूप में जाने को त्यायोचित सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी, किसी को इस बात पर हठ करने की आवण्यकता नहीं है।

'आधिक संगठन' एवं 'विकास-सम्बन्धी नियोजन' की विवेचना से मुफे यह वात खटकती है कि जहाँ एकत्रोकरण की समस्या विचार प्रधान-वस्तु है, वहाँ हम अन्संग्रहण के विलास-भोग में फंसे हुए हैं और जहाँ निपज का आधार ही अत्यधिक आग्रही समस्या है, वहाँ वी हुई निपज की बनावट पर गलत ढंग से जोर दे रहे हैं। हमें ऐसी धारणा हो जाती है कि जहाँ स्थित का तकाजा है कि 'आधिक संगठन एवं नियोजन' आधिक समिटिभाव की नीति के अनुसार हो, वहाँ विशेषक लोग संस्था-पकों के विनिधान-सिद्धान्त को वस्तुतः यंत्रवत् प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार, जन लोगों ने साधनों के अयोग्य विनिधान के खतरे पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया है, मानो अधिकतम निपज एवं पूर्ण रोजगार की समस्या का पूर्व ही समाधान हो चुका है। यहाँ दो बातें विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं: (1) विकास के सन्दर्भ में विदेशी व्यापार की व्याख्या तथा (2) अनुकरणीय विकासात्मक नियोजन के माडल के रूप में जापान का चुनाव।

जहाँ तक पहले का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन इस वात को स्वीकार करता है कि अपूर्ण रोजगारी वाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त का सीमित प्रयोग होता है। इस प्रकार वे देसी शिश्च-उद्योगों के संरक्षण के उपायों को न्यायोचित वतलाते हैं। साथ ही, विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निभरता एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को केवल चकीय दृष्टि से ही अस्थायी नहीं बना देती, वरन् अनेकता एवं उद्योगीकरण की उपेक्षा कर कुछ लाभदायक व्यावसायिक फसलों की खेती पर स्थायी रूप से तत्पर कर देती है। पुनः भुगतान सन्तुलन-सम्बन्धी किठनाइयाँ देश के आधिक विकास को जटिल एवं वाद्या पूर्ण वना देती हैं। इस तरह, अनुमानतः 'विदेशी विनिमय उपार्जन' एवं 'विदेशी विनिमय वचाने वाले' उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ 'प्राथमिकता' निर्धारण को दृढ़ बनाती हैं। किन्तु, आधिक विकास में 'बड़े पैमाने पर क्रय' तथा 'राजकीय व्यापार' के महत्त्व: की विवेचना नहीं हुई—यह विल्कुल स्पष्ट है।

जहाँ तक दूसरे का सम्बन्ध है, विशेषज्ञ पिछली आधी गतान्दी में जापान के विकास को 'व्यापक तथा समाकलित' विकासात्मक नियोजन के सन्दर्भ मे 'अत्यधिक शिक्षाप्रद' मानते हैं (पु. 60) । यहाँ उन लोगो ने जिस बात की उपेक्षा की, वह है सामंतवादी पितृत्व की भावना; यह एक ऐसी 'प्राचीन सामाजिक सस्या' है, जिसे वे विकास के लिए रुकावट मानते थे, तथा 'उत्पादन का एकाधिकारी संगठन', जिसे वे विकासात्मक प्रेरणा के प्रतिकृत भानते थे; ये दो ऐसे तत्त्व है, जिन्होने बाधा उत्पन्न करने के बजाय जापान के दूरायति से उद्योगीकरण में सहायता की। दूसरे याब्दों मे, जहाँ तक जापान का सम्बन्ध हैं, 'अ्यापक तथा समाकलित' नियोजन की प्रकृति के सम्बन्ध मे अधिक स्पष्ट होने की आवश्यकता है : क्योंकि वहाँ नियोजन बहुत सारे 'आधार-भूत' उद्योगों (उदाहरण के लिए इस्पात का निर्माण तथा बस्त का निर्यात) को सरकार द्वारा पित्वत् श्रीत्साहन, आधार-भूत यातायात सेवाओं (उदाहरण के लिए रेलवे) पर सरकारी एकाधिकार तथा निजी एकाधिकारों को सरकार द्वारा प्रारम्भिक अनुदान (उदाहरण के लिए 'जैबासु', यद्यपि यह प्राय: सैनिक कारणों से हैं) पर आधृत था। अतएव, जें ए० शुम्पीटर की इस विरोधामासी उक्ति को, कि एकाधिकार, न कि प्रतियोगिता से, उद्योगोकरण को प्रगति प्रोत्साहित होती है, जापान में सीमित परीक्षा हुई। साथ ही, यह सदिग्ध है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का भविष्य में विकास समाकलित 'घरेतू एवं कारखाना-उद्योग' के आधार पर लाभदायक तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि, यह किसी प्रकार भी स्पष्ट नहीं कि आपान की दूतगति से औद्योगिक प्रगति सरकार द्वारा प्रेरित कारखाना-उद्योग के 'युवतीकरण' से हुई अथवा 'धरेलू एवं कारखाना-उद्योगों' के समाकलन से। में स्वय इनमें से पहले को अधिक महत्त्व देने के लिए -तैयार हैं।

तकनीकी तत्त्व की और ध्यान देने पर, विशेषक्ष अल्प-विकसित देशों में 'तकनीक के निम्न स्तर' पर उतनी ही चिता व्यक्त करते हैं, जितना कि वे विकास के लिए सकनीकी प्रगित की आकस्मिक संभावनाओं की खोज पर जीर देते हैं। यह कहा गया है कि अल्प-विकसित देशों में तकनीक की सामान्य प्रगित में सब-प्रयम बाधा एक चौंक्षणिक एव प्रशासनिक सगठन का अभाव है, जिसके द्वारा उत्पादक नई टेकनोलोंजी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। (प्०29) साधारणत., अधिक जीर के साथ यह तर्क दिया जा सकता है कि सस्ती एव प्रचुर मात्रा में अन की उपलब्धि सामान्य रूप से औद्योगिक प्रगति-एवं विशेष रूप से औद्योगिक युवतीकरण के मार्ग में यदी वाधा सिद्ध हो सकती है; क्योंकि उत्पादकों में आधुनिक धाधार पर नवीन किया अपनाने की प्रेरणा का तब तक अधाव पाया जाता है, जब तक कि वे, सही अथवा गलत, यह विश्वास करते है कि धम की प्रचुरता के चलते निम्न-मजदूरी- उत्पादन के ऐसे कम चक्रदार तरीके, जिसमें पूँजी की अपेक्षा श्रम की अधिकता पाई

जाती है, की उत्पादक अकुशनता को विस्थित कर देती है। कृषि की सीमाकारी स्थिति में 'सहज एवं सस्ती तकरीकी प्रगति' (उदाहरण के लिए, रासायिनक खाद का प्रयोग एवं फसलों के उत्तम हेर-फेर) को बढ़ावा देना, प्रतिवेदन करना जैसा है, और मानो अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की उत्पादन-कुशनता एवं उच्च जीवन-स्तर के लिए उद्योगों में अपेक्षाकृत जिटल एवं खर्चील तकनीकी प्रयोगों पर अधिकाधिक मात्रा में निर्भर रहना, एक प्रकार का धोखा जान पड़ता है।

हमें यह बतलाया जाता है कि 'कुछ-एक अल्प-विकसित देशों में जहाँ पर श्रम की अत्यधिक प्रचुरता रहती है, मुख्य समस्या पूँजी बचाने दाले नये लाभदायक तकनीकों का पता लगाना है' (पृ॰31)। ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि प्रचर श्रम के परिणाम-स्वरूप निम्न मजदूरी की दर 'श्रम वचाने वाले' उपायों को वेकार तथा दुर्लभ एवं मृल्यवान पूँजी के प्रयोग में मितव्ययिता को आवश्यक बना देती हैं। फिर भी, ऐसा कहना उचित होगा कि जहाँ जनसंख्या की अत्यधिक प्रचुरता है, वहाँ पर वचतं अनुपात के दिया हुआ होने पर, निपज में वृद्धि की दर में अपेक्षित वृद्धि उच्च पूँजी-नियज अनुपात की अपेक्षा निम्न पूँजी-निपज अनुपात से अधिक संभव है, चूंकि 'पूँजी प्रयोग करने वाले औद्योगिक आधार (जँसे रेलवे) के निर्माण में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था को अपनी बचाने की सीमित शक्ति की तुलना में वहत अधिक पूँजी की आवश्यक्ता पड़ती है, इसलिए ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था को 'पुँजी बचाने के' तरीकों के आधार पर तकनीकी प्रगति में रुचि रखनी चाहिए। प्रतिवेदन में अल्प-विकसित क्षेत्रों को अधिक तकनीकी सहायता की प्रवल आवश्यकता पर उचित रूप में जोर दिया गया है, किन्तू इसने तकनीकी सहायता के समग्र प्रश्न को फलनीय तरीके से या तो वचत-अनुपात या पूँजी-निपज-अनुपात और इसलिए प्रगति की तकनीक की वृष्टि से संभव दर से सम्बद्ध न करने की भूल के परिणाम-स्वरूप इसे आवश्यकता से कम ही महत्त्व दिया है । संक्षेप में, जब तक जनसंख्या में वृद्धि की दी हुई दर की तुलना में निपज में वृद्धि की दर के निर्धारक के रूप में तकनीक के प्रयन की आकस्मिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रदर्शित नहीं किया जाता, तब तक 'पूँजी बचाने के' उद्योगों के पक्ष में तर्क निर्णयात्मक नहीं हो सकता।

जनसंख्या के संबंध में, प्रतिवेदन जनसंख्या में उत्पादन से अधिक होने की प्रवृत्ति की पारंपरिक निरामावृत्ति को अस्वीकार करता है। इसके विपरीव यह इस मान्यता को स्वीक्वित प्रदान करता है कि उत्पादन में जनसंख्या से अधिक तीव्र गति से वृद्धि की जा सकती है। यह विना संभाय के मान लिया जाता है कि जीवन-स्तर प्रति व्यक्ति निपज की वृद्धि का फलन, यानी निपज की वृद्धि को दर में जनसंख्या की वृद्धि की दर के भाग के वरावर है। अतएव, जहाँ तक निपज में वृद्धि की दर वचत-अनुपात पर फलनीय तरीके से आश्रित है, जीतन-स्तर को उठाने का एक

निश्चित तरीका जनसम्या मे वृद्धि के साथ-साथ पूँजी-संचय की दर मे वृद्धि करना है। जहाँ जनसंख्या की वृद्धि की तुलना मे पूँजी बहुत अधिक दुर्जभ है, वहाँ प्रतिवेदन में जनसंख्या मे वृद्धि से अधिक उत्पादन बढाने की धनारमक नीति के साथ-साथ प्रसवन-दर में कमी की ऋणारमक नीति का अनुमोदन किया गया है (पृ०48)। विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के समर्थ माँग के सभावित प्रोस्ताहन की तरह अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं मे जनसंख्या की वृद्धि के सबध में जैसा कि हैरोड मानते है, ¹ वैसा कोई अम नहीं है। बाद मे प्रतिवेदन इस बात को विल्कुल स्पष्ट कर देता है कि यदि सयुक्त राज्य की तरह, जनसंख्या कि वृद्धि की तुलना में बचत-अनुपात बहुत उच्च हो सो उन्हें विशेषतः जनाधिक्यवाली अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को, जिन्हें इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाना चाहिए (देखें पृ० 77)।

'घरेलू पूँजी-निर्माण'-सबधी अध्याय पूँजी के अभाव तथा उद्योग की प्रगति के विरोध पर सस्थापकीय जोर के साथ-साथ पूर्ण रोजगार मे बहुत अधिक पूँजी की सभावित वाघा पर केन्स जितना जोर देता है, ठीक उसके विपरीत है। यह एक प्रकार से तर्क-सयुक्त विरोधाभास है, क्योंकि पहिला अरुप -विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ के अनुरूप है, जबकि दूसरा विकसित वर्ध-व्यवस्थाओं के लिए हैं। अन्य बातों के साध-साथ आर्थिक प्रगति को नवीन पूँजी-निर्माण की दर का फलन मानते हुए, प्रतिवेदन पुंजी-सचय के मार्ग की उन सीमाओ तथा किठनाइयों की चर्चा करता है; जैसे-वचाने एव विनियोग करने की अपेक्षा गुप्त सचय की प्रवृत्ति, प्रति व्यक्ति निम्न आय, बचत-सबधी संस्थाओं का अपूर्ण विकास, मध्यम एध उच्च आयवाले वर्गी ने प्रदर्शन उपभोग की प्रवृत्ति । फिर भी इसमे पूँजी-निर्माण के मार्ग की कुछ प्रमुख किटनाँइयो की चर्चा नहीं की गई है; जैसे---मितव्यता को हतोस्साहित करने में राजनीतिक अस्थायित्व, टिकाऊ वस्तुओं से रुचि हटाने के लिए उत्तरदायी युद्धोत्तरकालीन अनिष्चयता, उपभोवता वस्तुओं के उद्योगों से पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों में साधनों की सापेक्ष अगतिशीलना तथा समानता के प्रति सामाजिक एव नैतिक प्रवृत्ति (विशुद-वादी व्यष्टिवाद की तुलना मे जिसे मैक्स वेबर के पाठक पूँजी-विर्माण के आधार पर आर्थिक विषमता को ऐतिहासिक औचित्य के रूप में जानते हैं)। ये बाद की कठिताइयाँ अशतः उद्योग की सरचना एवं समग्र माँग की बनावट तथा अंशतः सहकारी जीवन की गहरो सामंतवादी परपराओं के परिणाम-स्वरूप हैं। जब इन बाधाओ को स्पष्ट रूप से स्त्रीकार किया जाता है, तो पूँजी-सचय को दर में वृद्धि का कार्य प्रतिवेदन में वर्णित तरीके से भी अधिक कठिन हो जाता है। सिद्धाततः, यह स्पष्ट है कि निपज में युद्धि की दर को सभवत बचत के अनुपात का नही, बरन् उसी

^{1.} देखें, आर० एफ० हैरोड, 'द्वार्स ए डायनेमिक इकॉनामिक्स,' मैकमिलन, लदन, प० 106-15।

परिवर्त्ती के, जो पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता को व्यक्त करता है तथा जो समुदाय की वचाने की इच्छा से अधिक उद्योग आदि की संरचना के द्वारा निर्धारित होता है, फलन बनाने की आवश्यकता होगी। तब यह समफने में सुविधा होगी कि क्यों, उदाहरण के लिए, युद्धोत्तर काल में जापान बचाने की अपेक्षाकृत ऊँची औसत क्षमता के वावजूद अपनी युद्धोत्तर-कालीन पूँजी की आवश्यकताओं के अनुरूप पूँजी-संचय की दर को प्राप्त करने में असफल रहा है 1

प्रतिवेदन में उन अल्प-विकसित देशों के विकासात्मक कार्यों के लिए 'वलात् वचत' के निर्णायक महत्त्व पर उचित रूप में जोर दिया गया है, जहाँ संस्थानिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से स्वेच्छिक बचत इतनी कम है कि सरकार को कर मुद्रा-स्फीति, साधनों के विनिधान की प्राथमिकता तथा विनिमय-नियन्त्रण (मुख्यतः पूँजी के बाहर जाने के विरुद्ध) आदि के द्वारा विकासात्मक पूँजी प्राप्त करनी पड़ती है। यह अनिच्छापूर्वक इस वात को स्वीकार करता है कि स्फीति के वग्नेर द्रुतगति से आर्थिक विकास सम्भव नहीं है (पृ॰ 42) । ऐसा अंगतः इसलिए है कि जहाँ पहिले से ही जीवन-स्तर बहुत निम्न है, वहाँ उपभोग में राजकोपीय तरीकों के द्वारा अनिवार्य कमी का विकल्प असह्य है और मुख्यतः इसलिए कि मुल्य-स्फीति के परिणाम-स्वरूप 'मौद्रिक अम का प्रभाव' यह पड़ता है कि कागजी मुनाफाखोरों तथा कागजी मजदूरी उपाजित करनेवाले की अपनी वास्तविक आय तथा वांछित समृद्ध स्थिति के सम्बन्ध में भ्रम दूर होने के पूर्व पूँजीगत वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है। पूँजी-संचय पर स्फीति के उत्तेजक प्रभावों के विरुद्ध निम्न तथा मध्यम आयवाले वर्गों का स्वेन्छिक वचत पर हतोत्साहित करने वाला संघात प्रारम्भ हो जाता है। फिर भी, यह संदिग्ध है। प्रयमतः, अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं मैं निम्न तथा मध्यम आयवाले वर्गी की बचत इतनी अधिक नहीं होगी कि उन्हें उच्च मूल्यों के परिणाम-स्वरूप इनके वास्त-बिक मूल्य में कमी के लिए चिन्ता करनी पड़े । दूसरी बात यह है कि सभी स्थायी आयवाले वर्गों में लगान-उपजीवी की वचत ही सर्वाधिक प्रभावित होगी तथा जिनकी वचाने की सीमान्त क्षमता किसी भी प्रकार साहसियों से कम होगी। इस स्थिति में विकासात्मक स्फीतिजनक वित्तीयकरण के परिणामस्वरूप उच्च मूल्यों के वितरणात्मक प्रभाव से स्वेच्छिक वचत में महत्त्वपूर्ण कमी नहीं होगी।

जपभोग में कमी के वर्षर पूंजी-संचय में वृद्धि की सम्भावना विशेषतः उन देशों में स्वीकार की गई है, जिनमें अपेक्षाधिक कृषि-मजदूर होते हैं और जिनके पूंजीगत उद्योगों में स्थानांतरण से उपभोक्ता वस्तुओं की निषज में कमी की सामान्य रूप से कोई आशा नहीं की जाती है; किन्तु, 'अपूर्ण रोजगारवालों' को गतिशील

तुलना कीजिए के० ओकावा का 'दि ग्रोथ रेट ऑफ जापानीज इकॉनामी. हायरन, फरवरी, 1952 ।

वनाने में सन्निहित सम्भावित अवरोधों — जैसे श्रम की अगतिशीलता (यदि पारिवारिक सम्बन्धों के कारण नहीं तो अपर्याप्त परिवहन-सम्बन्धी कठिनाइयों के परिणाम-स्वरूप) तथा 'कम-मजदूरी वालो' को पर्याप्त काम दिलाने में 'किसी कारण-विशेष' के अभाव की कोई चर्चा नहीं की गई है।

घरेल पूँजी के अभाव को पूरा करने के लिए पूँजी के आयात के पक्ष में अपने तक में विशेपज्ञों ने उन तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कठिनाइयों को, जो रास्ते में रकावटें उपस्थित करती हैं, उचित मान्यता दी है। इस प्रकार वे अल्प-विकतित अर्थ-ड्यवस्थाओं की 'वर्तमान राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में इनके जोखिमपूण अनुमान' तथा 'अल्प-साब्यिकीय' सूचना के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं । किन्तु वे उन प्रत्यायात्मक कठिनाइयों के महत्त्व पर, जो बचत की समग्र धारणा में सन्निहित है, जोर नहीं देते। उदाहरण के लिए, कॉलिक क्लॉक की आलोचना जापान के उस बचत-अनुपात के अत्यक्तन के लिए की गई है, जिसके अन्तर्गत कितनी ही उपभोक्ता-सम्बन्धी पुंजी की मर्दे (उदाहरण के लिए, अर्ड-टिकाऊवस्य सम्मिलित है), जिन्हे साधारणतया अलग रया जाता है । वास्तविक राष्ट्रीय सम्पत्ति आंकडो पर आयुत बचत की इतनी विस्तृत धारणा के प्रयोग से साध्यिकी के अर्घ्व विस्तार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे सम्बद्ध देश को भूल से पूँजी आयात करने वाले के बजाय 'अतिरिक्त' वचत को निर्यात करने योग्य समभा जाने लगता है। दूसरी ओर, चूँकि देश को भ्रमदश समुदाय की बचत की क्षमता के अनुरूप पूँजीगत वस्तुओं को उत्पन्न करने योग्य समभा जाता है, इसलिए उपर्युवत उद्योग की सरचना के प्रभाव तथा समग्र माँग की रचना की उपेक्षा से अधोमुख साध्यिकी के भुकाव की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। राप्टीय और एव व्युत्पन्न घरेलू बचत-अनुपात के सम्बन्ध मे 'जोखिमपूर्ण' अनुमान भी लगाने के पूर्व ही इन प्रत्यआत्मक समस्याओं को ठीक कर लेना चाहिए। एक दूसरे अर्थ में भी प्रतिवेदन कमजोर जान पडता है, अर्थात् अल्प-विकसित देशों की पुँजीगत आवश्यकताओं और विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अस्यधिक पूँजी की इति-हास-प्रसिद्ध हासमान सीमात-क्षमता से परिसीमित वर्तमान निवेश-सम्बन्धी अवसरी के अनुपात में अधिक बचाने की प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थायित्व-जनित खतरे के बीच सम्बन्ध जोडने की सम्भवत इन्छित असफलता ही वह कमजोरी है। यह भूल उन लोगो के द्वारा, जो केन्स एव हैन्सेन के स्थायित्व-सम्बन्धी परिकल्पना का दृढतापूर्वक विरोध करते हैं, दुर्वेलता की बजाय कदाचित् दृढता समभी जायनी । भेरा विचार केवल यह है कि जब प्रतिवेदन विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से अविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं मे पूँजी के निर्यात की मिफारिश, उन विकसित देशों के लिए जिनकी प्रवृत्ति हैरोड के पूर्ण रोजगार के साथ 'प्रगतिशील साम्यावस्था' के मार्ग से विचलित होतें की है, इस प्रकार के निर्यात के लाभी (उदाहरण के लिए सम्भावित अत्यधिक ेल बचत के लिए अतिरिक्त विकास तथा निर्यात गुण्य के रूप में कार्य करनेवाले

लाभाँग एवं व्याज का अन्तिम अतः प्रवाह) का वर्णन किये वर्गेर, करता है, तो यह कम विश्वासजनक है।

ऐतिहासिक एवं राजनीतिक तथा कुछ हद्द तक आर्थिक कारणों से प्रतिवेदन अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए पूँजी-निर्यात में बहुत कम लाभ देखता है। इसके विपरीत, यह अन्तर-सरकारी उधारदान तथा वहराष्ट्रीय विकासात्मक वित्त की वांछनीयता एवं सम्भावना पर अधिक विश्वास रखता है। यह कोई आश्चर्य की वात नहीं है कि अन्तर-सरकारी उधारदान पर जोर देने के कारण, 'हस्तारण-समस्या', जो विशेषज्ञों के अनुसार सफल विकास के कम में पूर्णरूप से सदा के लिए समाप्त हो जायगी; वे उसकी परम्परागत चिन्ता से प्रभावित हीने के लिए तैयार नहीं होते। विश्व-वंक कीआलोचना इसकी वर्त्तमान उधारदान नीति की विकास-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर आधारित न होकर विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के अनुमान पर आधृत होने के लिए की जाती है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप की उपलक्षित आलोचना समक्षा जा सकता है; क्योंकि कोप का उद्देश्य विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयों का समाधान करना है, जिससे बैंक अपना घ्यान दृढ़तापूर्वक केवल विकासात्मक उधारदान पर केन्द्रित कर सके, किन्तु केन्स द्वारा जोर दिये गये विशुद्धतः तकनीकी एवं गैर-राजनीतिक आधार पर उधारदान के अभाव से दूर हटने के खतरे के विरुद्ध, विशेषतः आज के अन्तर्राष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष के विक्षुट्य युग में, चेतावनी न देने के लिए प्रतिवेदन की आलोचना की जा सकती है।

ऊपर जो वार्ते कही गई हैं, उनमें किसी का भी ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए, जिससे संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा समस्या के सामान्यतः सुन्दर विश्लेषण पर सन्देह प्रकट किया जा सके। सामान्य अधिमत के तौर पर यह कहना अनुचित न होगा कि समीक्षा से सम्बद्ध प्रतिवेदन आने वाले कई वर्षों के लिए आर्थिक विकास की अत्यावश्यक प्रवेशिका के रूप में कार्य करता रहेगा। किन्तु, इसकी नीति-सम्बन्धी सिफ़ारिशें गतिशील विश्व की अर्थ-व्यवस्था के लिए कम स्थायी महत्त्व की हैं। परन्तु सम्पूर्ण प्रतिवेदन में सबसे बड़ी वात आर्थिक क्षेत्र में सहरोग की नई भावना हैं, जो अर्थशास्त्रियों की संकृचित तकनीकी दृष्टि से बहुत दूर तथा युद्ध के पूर्व राष्ट्रीयता वादियों के 'साम्राज्यवादी' क्षितिज से वहत ऊपर है।